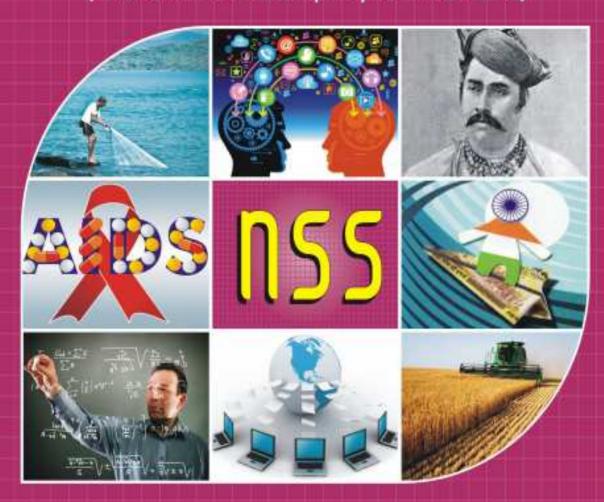
Volume I , Issue II Apr. - June 2013

Reg. No.- MPHIN/28519/12/1/2012- TC ISSN 2320-8767

Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)



नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Sharma

Office Add, "Shree Shyam Bhawan", 795 - Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458 441

Mob. 09617239102 Email nssresearchjournal@gmail.com Website www.nssresearchjournal.com



सम्पादक की अभिव्यक्ति

सम्माननीय शोधार्थियाँ सादर वन्दे,

नवीन शोध संसार के प्रथम संस्करण पर आपके अपार सहयोग, रनेह एवं मार्गदर्शन से, मुझमें नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार हुआ है।

हमारी शोधयात्रा कुल 17 सदस्यों एवं 16 शोध पत्रों के साथ प्रथम संस्करण से प्रारंभ हुई । द्वितीय संस्करण की यात्रा तक हमारे साथ 46 शोध पत्रों सहित कुल 100 सदस्य पथिक बनकर पूर्ण आत्मीय विश्वास के साथ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।

इस प्रगति के लिए आप सभी बधाई के पात्र है। द्वितीय संस्करण में एक और उपलब्धि को जोड़ा गया है। शोध के स्तर की गुणवत्ता एवं श्रेष्ठता हेतु लगभग सभी विषयों में निर्णायकों की नियुक्ति हो चुकी है एवं उनकी स्वीकृतियां भी प्राप्त हो चुकी है।

अत: द्वितीय संस्करण "Refereed Journal" के रूप में प्रकाशित हो रहा है। जिससे प्रत्येक शोधपत्र के कुल 15 अंक API के रूप में शोधार्थियों को लामान्वित करेंगे।

शिक्षा एवं शोध से जुड़े विद्वजनों से विनम्र अनुरोध है कि निरंतर प्रयास, अध्ययन, विंतन एवं लेखन से शोध पथ पर आग्रसर हो, आपके शोध की सामाजिक उपयोगिता हेतु मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके शोध की सार्थकता में गागर में सागर का कार्य करेगा।

आपका



'नवीन शोध संसार' का छोटा-सा अनुरोध-

🗱 पेड-पानी, कर्जा और बेटी बदाएँ

🕸 गुटखा, बीड़ी, सिगरेट एवं शराब को ना कहें, इनसे केंसर होता है।

इस क्षेत्र परिवार को प्रकारित कार्य हुए पूर्व सरकार्यों करती वह है, दिन भी किसी प्रकार की पूर्वी के मिस्रे सम्मादक, प्रकारक, पुरुक विम्मेदार नहीं होंगें / सनका विकार्य का नावकोड़ नीमत होता ('श्री गणेशाय नमः'



नवीन शोध संसार

Reg. No.- MPHIN/28519/12/1/2012-TC ISSN 2320-8767

Volume I, Issue II, April - June 2013



संरक्षक एवं अध्यक्ष निर्णायक मण्डल हाँ. एता.एक. शामाँ 09425974314 प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय. नीमच

सम्पादक आशीध शर्मा मो. ०९६ १७२३ १०२ प्रबंध सम्पादक **अपूर्व शर्मा** मो. 08989670811

मार्गदर्शक एवं संरक्षकगण

- माननीय श्री जे.एन. कांसोटिया प्रमुख संविद उच्च शिक्षा म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
- (2) माननीय श्री ठी.आर. शर्मा अवर सचिव "मंत्रालय" सडक परिवहन शर्डवे, भारत सरकार, नई दिल्ली
- (3) प्रो. हॉ. शिवनारायण यावव (पूर्व कुलप्रति) प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बढवानी (म.प्र.)

'नवीन शोध संसार' का अगला अंक वि. 10 सिलम्बर 2013 को प्रकाशित होगा।

रादरयता शुल्क विवरण

- संस्थागत वार्षिक- ₹ 1000/-
- क्ष शोधार्थी वार्षिक १ 600/-
- 🕸 आजीवन ह 1.1000/--

शोधपुत्र सहयोग राशि (कावत अन्वार है)

- 🕸 एक शोहार्थी १ 600/- (प्रतिशोध पत्र)
- 🜣 दो शोधार्थी १ 1200/- (प्रतिशोध पत्र)
- 😂 तीन शोधार्थी ए 1800//= (प्रति शोध पत्र)

(प्रति शोध पत्र अधिकतम २००० शब्द/ ४ पेज)

अतिरिक्त प्रति पंज १ 200/-

(शोध पत्र संख्योग शशि में वार्षिक सवस्थता शुरूक सम्मिलते नहीं है

1847 - Firence Filtren eerster 1902 (1880) 400 (1674) Album 197 (1880) 41





अनुक्रमणिका/Index

	•
01.	अनुक्रमणिका
02.	क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल/सम्पादकीय सलाहकार मण्डल
03.	निर्णायक मण्डल
04.	प्रवक्ता साथी
05.	शुभकामना संदेश
06.	'नवीन शोध संसार' के प्रथम अंक का विमोचन
07.	उद्य शिक्षा में गुणवत्ता का उन्नयन एवं प्रबंधन (डॉ. लक्ष्मण परवाल)
08.	भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का परिदृश्य, विकास एवं चुनौतियाँ 'एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'
09.	वर्तमान में समाज एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में मीडिया की भूमिका (डॉ. लता जैन)
10.	सेवा कर राजस्व 'एक तुलनात्मक अध्ययन' (डॉ. सपना सोनी)
11.	महाराजा शिवाजी राव होलकर का वैभव ''दरिया–महल'' (डॉ. मंगला ठाकुर)
12.	साहित्य में पर्यावरण चेतना 'एक दृष्टिकोण' (डॉ. अरूणा दुबे)
13.	रूपये का गिरता स्तर तथा विदेशी व्यापार नीति (डॉ. आभा दीक्षित)
14.	बाल-श्रम : एक अभिशाप (प्रो. मीना मावी, विजय मावी)
15.	भाषा का बाजारीकरण एवं मीडिया (डॉ. मंजुला जोशी)
16.	शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर (जोबट) परियोजना से विस्थापित परिवारों का अध्ययन (प्रो. हेमता डुडवे) 36
17.	मप्र में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपलब्धियाँ 'एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'
18.	मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास की आवश्यकता (डॉ. आशा साखी गुप्ता) 4 1
19.	वैश्वीकरण का टार्च उद्योग के विकास पर प्रभाव 'कुक्षी तहसील के रिचार्जेबल टार्च उद्योग के विशेष संदर्भ में'
20.	बारेला-लोकजीवन एवं लोकगीत 'शोध सारांश' (डॉ. सेवंती डावर, प्रो. गायत्री चौहान)
21.	बुंदेली लोक कवि ईसुरी 'शोध सारांश' (डॉ. वन्दना जैन)
22.	लोक साहित्य : कितने रंग, कितने रूप (डॉ. अरूणा दुबे)
23.	कृषि क्षेत्र के विकास में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका (डॉ. लक्ष्मण परवाल) 5 1
24.	उद्य शिक्षा में गुणवत्ता समस्याएं एवं समाधान 'शोध सारांश' (डॉ. कमल जैन, डॉ.महेश गुप्ता)
25.	मोबाइल का समाज पर प्रभाव 'शोध सारांश' (डॉ.पी.पी. पाण्डेय, डॉ. प्रभा पाण्डेय)
26.	निमाड़ी भाषा का स्वरूप एवं क्षेत्र 'शोध सारांश' (डॉ. मनजीत अरोरा)
27.	महिलाओं की रक्षा के लिए उठाया गया कदम (डॉ. नरेंद्र कुमार जैन)
28.	मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का मानकीकरण एवं मूल्यांकन (डॉ. प्रभाकर मिश्र)
29.	मानव विकास सूचकांक में भारत के राज्यों की स्थिति 'एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' (डॉ. रिखबचन्द्र जैन) 60
30.	दशपुर अंचल में भक्ति एवं शृंगार की रससिद्ध कवयित्रियाँ (डॉ. कृष्णा पैन्सिया, डॉ. राजेन्द्र कुमार पैन्सिया) 64
31.	नीमच जिले में जनांकिकीय परिवर्तन (1971 से 2011 तक) 'एक तुलनात्मक अध्ययन'



32.	Effect of Duration of Marriage on Marital Adjustment (श्रीमती कमलेश उपाध्याय)
33.	Rotationally Inelastic Collisions in ${ m N_2} ext{-}$ Ne System and Validity of Two Parameter
	Power-Gap Law (Dr. N.K.Dabkara, Dr. V.K.Ojha)
34.	X-ray absorption studies of some copper (II) mononuclear and binuclear complexes
35.	Importance of Computational Chemistry and Fields of application (Sunil Kumar Sikarwar) 80
36.	Socio-Economic Status of Fishermen in Western Nimar (M.P.)
37.	A Comparative Study Of Organizational Learning Among Public, Deemed And
38.	A Comparative of Succidal Ideation Among HIV Negative, Positive and aids Cases
39.	E- Mart: A Necessity Not A Boon (Dr. Devendra Singh Rathore)
40.	A study of Green Shoe Options in India (Dr. Sanjay Agrawal)
41.	Perception Of Unorganised Retailers Towards Fdi In Multibrand Retailing In India
42.	Rural Women Enterprenership Development in India (Dr. Ravi Prakash Pandey) 113
43.	Indian Agriculture Sector: After Economic Reforms (Dr. Vinod Kumar Sharma) 116
44.	A Correlational Study Of Stress And Adjustment Of Nursing College Students
45.	Impact Of Cotpa Act 2003 On The University And Colleges Of Indore
46.	Ecological conciousness in Kamla Markandaya's Nectar in a sieve (Mrs. ASHA JAIN) 124
47.	Potential of Visual Culture in Voicing Women as Subaltern: Deepa Mehta's Water 127 (Veena Singh)
48.	Alternative Dispute Resolution (ADR) System in India: Problems and Prospects
49.	A Comparative study of job satisfaction & health between female teachers of
50.	A Correlation Study of Self Concept and Adjustment of Adolescents
51.	A Comparative Study Of Depression Among Hiv Negative, Positive And Aids Cases
52.	Awareness Among Adolescent Girls (10-12yrs) Towards Secondary Sexual
53.	प्रथम/द्वितीय संस्करण के सदस्यों की सूची
54	Copyright Agreement Form:
55.	Membership Cum Author's Bio-data Form
56.	Guideline for Authors/Research Scholars
57.	Advertisement



क्षेत्रीय सम्पादक मण्डल (Regional Editor Board) मानद्

(01)	प्रो. डॉ. ज्ञानचंद खिमेसरा प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(02)	प्रो. डॉ. प्रमोद कुमार राघव शोध निदेशक, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्व विद्यालय, जयपुर (राज.)
(03)	प्रो. डॉ. एन.एस.राव संचालक, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(04)	प्रो. डॉ. अनूप व्यास संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), देवी अहिल्या विश्व विद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(05)	प्रो. डॉ. पी.पी. पाण्डे संकायाध्यक्ष, वाणिज्य (डीन), अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
(06)	प्रो. डॉ. संजय भयानी अध्यक्ष, व्यवसाय प्रबंध विभाग, सौराष्ट्र विश्व विद्यालय, राजकोट (गुजरात)
(07)	प्रो. डॉ. तपन चौरे अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, विक्रम विश्व विद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(80)	प्रो. डॉ. बी.एस. झरे प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, श्री शिवाजी महाविद्यालय, आकोला (महाराष्ट्र)
(09)	प्रो. डॉ. राकेश शर्मा अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुड़गांव (हरियाणा)
(10)	प्रो. डॉ. संजय खरे अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, शास. कन्या स्वशासी उत्कृष्ट स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(11)	प्रो. डॉ. आर.पी. उपाध्याय परीक्षा नियंत्रक, शासकीय कमलाराजे कन्या स्वशासी रनातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

सम्पादकीय सलाहकार मण्डल (Editorial Advisory Board) मानद्

(12) प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

(01)	प्रो. डॉ. पंकज त्रिवेदी संचालक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल (म.प्र.)
(02)	प्रो. डॉ. संदीप जोशी निदेशक, म.प्र. सामाजिक शोध संस्थान उज्जैन (म.प्र.)
(03)	प्रो. डॉ. नवीन माथुर प्राध्यापक, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)
(04)	प्रो. डॉ. आदित्य लूनावत निदेशक, स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर (म.प्र.)
(05)	प्रो. डॉ.एस.के. जोशी प्राचार्य, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)
(06)	प्रो. डॉ. राकेश ढण्ड संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(07)	प्रो. डॉ. अनिल शिवानी अध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबंध विभाग श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्व विद्यालय भोपाल (म.प्र.)
(80)	प्रो. डॉ. अशोक वर्मा प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा (म.प्र.)
(09)	प्रो. डॉ. बी.के. मेहता अध्यक्ष, रसायन एवं जैविक रसायन अध्ययनशाला, विक्रम विश्व विद्यालय उज्जैन (म.प्र.)
(10)	प्रो. डॉ. एस.एस. चौहान उपप्राचार्य,NIMS इन्यू ऑफ मैनेजमेंट, अजमेर (राज.)
(11)	प्रो. डॉ. बी.एल. हिरण सेवानिवृत्त प्राध्यापक, श्री मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(12)	प्रो. डॉ. पद्मसिंह पटेल अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग शासकीय महाविद्यालय महिदपुर (म.प्र.)

English Edit by - Arpna Ray, Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)



Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013



निर्णायक मण्डल (Referee Board) मानद्

विज्ञान संकाय

गणित:-प्रो. डॉ.वी.के. गुप्ता, संचालक वैदिक गणित एवं शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

भौतिकी:-**प्रो. डॉ. एन.के. डबकरा**, शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान:-**प्रो. डॉ. उमेश कुमार सिंह** अध्यक्ष कम्प्यूटर अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) **प्रो. डॉ. बी.के. दानगढ़**, समन्वयक राष्ट्रीय इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, केन्द्र नीमच (म.प्र.) रसायन:-

प्रो. डॉ. सुचिता जैन, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.) वनस्पति:-प्राणिकी:-प्रो. डॉ. एस.एन. गुप्ता, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) सांख्यिकी:-**प्रो. डॉ. रमेश पण्ड्या**, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) सैन्य विज्ञान:-**प्रो. डॉ. कैलाश त्यागी,** शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

वाणिज्य संकाय

प्रो. डॉ. बी.एस. मक्कड, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) वाणिज्य :-

प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल, शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

प्रबंध संकाय

प्रो. डॉ.रामेश्वर सोनी, अध्यक्ष अध्ययन शाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) प्रबंध :-

व्यवसाय प्रशासन संकाय

प्रो. डॉ. कपिलदेव शर्मा, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.) व्यवसाय प्रशासन:-

विधि संकाय

विधि:-प्रो. डॉ. एस.एन. शर्मा, शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

प्रो. डॉ. नरेंद्र कुमार जैन, प्राचार्य श्री जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

कला संकाय

प्रो. डॉ. पी.सी. रांका, शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) अर्थशास्त्र:-

राजनीति:-**प्रो. डॉ. रवींद्र सोहोनी,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

समाजशास्त्र:-**प्रो. डॉ. आशुतोष व्यास,** राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.)

हिन्दी:-**प्रो. डॉ. राजीव शर्मा,** शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इन्दौर (म.प्र.)

अंग्रेजी:-**प्रो. डॉ. अजय भार्गव**, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)

संस्कृत:-प्रो. डॉ. वी.के. शर्मा, प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा (म.प्र.)

इतिहास:-**प्रो. डॉ. मदनलाल पंवार,** प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

भूगोल:-**प्रो. डॉ. देवेंद्र कौर,** शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)

दर्शनशास्त्र:-**प्रो. डॉ. हेमंत नामदेव,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

मनोविज्ञान:-प्रो. डॉ. ए.आर. लोहिया, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)

चित्रकला:-**प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय,** शासकीय माधव कला-वाणिज्य-विधि महाविद्यालय उज्जैन (म.प्र.)

भूगर्भ शास्त्र:-**प्रो. डॉ. वी. कुलश्रेष्ठ,** शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)

गृह विज्ञान संकाय

गृह विज्ञान:-**प्रो. डॉ. शारदा त्रिवेदी,** सेवानिवृत प्राध्यापक शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला इंदौर (म.प्र.)





प्रवक्ता साथी (मानद्)

(01)	पो .डॉ आर के गजेटिया	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02)	<u> </u>	. शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03)		. ज्ञानोदय इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नीमच (म.प्र.)
(04)		. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(05)		. शासकीय कन्या महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(06)	प्रो. शशांक दबे	. जैन कला–वाणिज्य–विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(07)	प्रो. डॉ. देवीलाल अहीर	
(80)	श्री आशीष द्विवेदी	
(09)	प्रो. डॉ.सी.एम. मेहता	
(10)	प्रो. डी.एस. फिरोजिया	
(11)		. शासकीय महाविद्यालय, पिपलियामंडी (म.प्र.)
(12)		. शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(13)	प्रो. डॉ. सरेश कटारिया	. शासकीय कन्या महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(14)	प्रो. डॉ. अभय पाठक	. शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
(15)		. शासकीय विक्रम महाविद्यालय, खाचरौद (म.प्र.)
(16)		. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.)
(17)	प्रो. डॉ. जी.सी. मेहता	
(18)	प्रो. डॉ. मालिसंह चौहान	
(19)	प्रो. डॉ. प्रभाकर मिश्र	
(20)		. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(21)		. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
(22)	=	. शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
(23)	प्रो. डॉ. बी.एस. सिसोदिया	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
(24)	प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे	. शासकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(25)	प्रो. डॉ. औंकारसिंह मेहता	
(26)	प्रो. डॉ. एन.एस. भाटी	
(27)	प्रो. डॉ. मंजुला जोशी	
(28)	प्रो. डॉ. प्रकाश कुमार जैन	. शासकीय माधव कला वाणिज्य विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(29)		. शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(30)		. शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(31)		. स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इंदौर
(32)		. शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(33)		. शासकीय कन्या रनातकोत्तर महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)
(34)		. शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(35)		. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला- सतना (म.प्र.)
(35)		. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयं, राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(36)		. शासकीय महाविद्यालय, गंजबासोदा, जिला-विदिशा (म.प्र.)
(38)		. शासकीय महाविद्यालय पचोर, जिला–राजगढ़ ब्यावरा (म.प्र.)
(39)		. शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)
(40)	प्रो. डॉ. स्मृति अग्रवाल	. शोध सलाहकार, नई दिल्ली
(41)		. राजकीय महिला रनातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा (राज.)
(42)	प्रो. प्रदीप सिंग	
(43)		. राजकीय राजऋषि महाविद्यालय अलवर (राज.)
(44)		. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
(45)		. हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी, जिला– प्रतापगढ़ (राज.)
•	-	· <i>'</i>

शुभकामना सर्देश





शिवराजिर्सिह चौहाज मुख्यमंत्री म.प्र. शासन, भोपाल

मुख्यमंत्री म.प्र. शासन, भोपाल

प्रसन्नता का विषय है कि नीमच से ''नवीन शोध संसार''इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल का प्रकाशन प्रारंभ किया जा रहा है।

आशा है यह जर्नल अनुसंधानकर्ताओं के शोध कार्य को प्रोत्साहित करने एवं समाज को नये शोधों की जानकारी देने में उपयोगी होगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित !

(शिवराजसिंह चौहान)

शुभकामना सर्देश





लक्ष्मीकांत शर्मा मंत्री, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्कृति जनसम्पर्क धार्मिक न्यास और धर्मस्व मध्यप्रदेश

निवास: बी–11(74 बंगला) भोपाल दूरभाष: (मंत्रालय) 0755–2441128 निवास: 0755–2551173

फैक्स- 0755-2570175

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ''नवीन शोध संसार'' नीमच से प्रकाशन किया जा रहा है। शोध कार्यों को प्रोत्साहन व्यापक समाज हित में है। शोध कार्यों को प्रकाशित करने के लिये रिसर्च जर्नल आवश्यक है। रिसर्च जर्नल एक महत्वपूर्ण प्रकाशन होता है, इसलिये इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता बहुत आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि नवीन शोध संसार इस दिशा में सार्थक प्रयास करेगा।

प्रकाशन के लिये मरी हार्दिक शुभकामनाएँ

(लक्ष्मीकांते शर्मा)



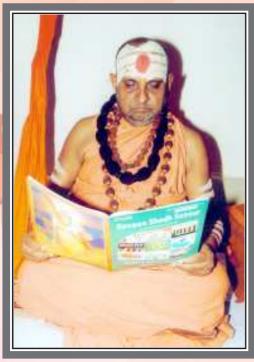


अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी श्री दिव्यानन्दजी तीर्थ भानपुरा पीठाधीश्वर

के करकमलों द्वारा 'नवीन शोध संसार' का विमोचन











उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का उन्नयन एवं प्रबंधन

डॉ. लक्ष्मण परवाल *

प्रस्तावना :-

म.प्र. पहला राज्य है जिसने सेमेस्टर प्रणाली द्धारा वर्ष 2008 से उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। म.प्र. भारत का हृदय प्रदेश है। यहाँ शिक्षा-संस्कृति-कला की बहुत पुरानी परम्परा है। वर्तमान समय में भी यहां के अनेक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्चस्तरीय मानदंड स्थापित किये हैं। यहां के संस्थानों, विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। वर्तमान में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदाय करने का संकल्प आसान नहीं था, किन्तु वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय बहुत जरूरी था।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकता - क्यों ?

उच्च शिक्षा का उद्देश्य सभी संबंधित व्यक्तियों को जागरूक करना व दिशा दर्शन करना है। स्वयं अपने को यह आभास कराना भी है कि कार्य करना एक बात है और कार्य में गुणवत्ता लाना दूसरी बात है। गुणवत्ता लाने के लिए हमें अपनी अच्छाइयों को और अधिक मजबूत करना, कमजोर पक्षों पर ध्यान देना, सुअवसरों का लाभ उठाना, स्वयं में मानसिक दृदता लाना अपेक्षित है। इस तरह स्वयं में और संस्था में ''गुणवत्ता–संस्कृति'' को विकसित करना पड़ता है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकता निम्न कारणों की वजह से अनिवार्य हो गई है :–

- 🗴 बढती तकनीकी निर्भरता।
- 🗱 मूल्य परक रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना।
- 🗱 अधोसंरचनात्मक ढांचे में बदलाव।
- वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये नये विषयों एवं नये पाठ्यक्रमों को लागू करना।
- 🗱 अकादमिक नवाचारों का सृजन।
- 🗴 दृष्टिकोण में परिवर्तन ।
- 🗱 नैतिक मूल्यों की स्थापना।
- 🗱 आंतरिक प्रेरणा को जागृत करना।
- युवाओं को भारतीय परम्परा और प्रगति के बीच सामंजस्य बनाकर अपने विकास के रास्ते को चुनने का विकल्प देना।
- 🗱 अकादमिक डिग्री के साथ-साथ पर्याप्त कौशल और हुनर सिखाना।
- नये क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता का बढ़ना। प्रबंध, वित्त, बैंकिंग, बीमा, विधि, आडिटिग, बजटिग, कंसल्टेंसी, पब्लिक रिलेशन्स, काउन्सिलिंग, पत्रकारिता, प्रकाशन, अनुवाढ, डिजाइनिंग, विज्ञापन, एक्टिंग, फिल्म, संगीत, मनोरंजन, एविएशन, पर्यटन, होटल, पाक कला आढि।
- आवश्यक कौशल अर्जित करने के क्षेत्र का बढ़ना। बौद्धिक, सम्प्रेषणीय, संगठनात्मक, इंटर-पर्सनल रिलेशन, अन्वेक्षण, विदेशी भाषा को समझने की योग्यता, गणनीय क्षमता, कम्प्यूटर

साक्षरता आदि।

व्यक्तित्व विकास की महती आवश्यकता। लिखित और मौखिक संप्रेषण तथा संवाद क्षमता, संगठन करने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, समस्या-समाधान करने की क्षमता, कार्यक्रम आयोजित करने की क्षमता, संचालन की निप्रणता आदि।

उच्चशिक्षा में गुणवत्ता के उन्नयन एवं प्रबंधन हेतु शासकीय प्रयास -

गुणवत्ता किसी भी योजना या क्रियान्वयन के तरीकों को थोपने से नहीं आती, बल्कि नैतिक मूल्यों की स्थापना से आ सकती है। यह प्रबंधन सभी लोगों के सामूहिक, अनिवार्य और स्वैच्छिक क्रियाकलापों का नतीजा होता है। अपनी भावना को कार्य में और कार्य को सम्पूर्ण चेतना और मन से करने में गुणवत्ता स्वयं आती है। किसी भी कार्य में नेतृत्व भावना और एकाग्र दृष्टि का समावेश करने से उसमें निहित गुणवत्ता स्वयमेव प्रकट होने लगती है। उच्च शिक्षा में सेमेस्टर पद्धति एक सुविचारित कार्य योजना है जिस पर चलकर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही शोध और विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के उन्नयन एवं प्रबंधन हेतु किये जा रहे शासकीय प्रयासों की श्रुंखला इस प्रकार है :

- 🗱 एम्बेसेडर प्राध्यापक योजना
- 🗱 प्रतिभावान प्राध्यापकों का रिडिप्लायमेंट
- 🗱 स्मार्ट एवं वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से अध्यापन व्यवस्था
- स्वः श्री लक्ष्मणिसंह गौड़ स्मृति पुरस्कार
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर प्रतिदिन नवीन निर्देशों की जानकारी
- 🗱 शिक्षक-अभिभावक योजना
- 🗱 फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम
- 🗱 वार्षिक पत्रिका एवं न्यूज लेटर का प्रकाशन
- "स्वाट" विश्लेषण (ताकत, कमजोरियों, अवसरों एवं खतरों के बारे में जानना)
- प्राध्यापकों की क्षमता में अभिवृद्धि के अवसर (ए.पी.आई. गोपनीय चित्रावली)
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सेमीनार/कार्यशालाओं का आयोजन
- 🗱 शून्य एवं सेतु कक्षाओं का आयोजन
- 🗱 स्टूडेन्ट चार्टर
- 🗱 प्राचार्य का आत्मावलोकन (38 बिन्दु)
- 🗱 शिक्षक का आत्मावलोकन (19 बिन्द्)
- 🗱 विद्यार्थियों के आत्मविकास हेतु महत्वपूर्ण निर्देश (६ बिन्दु)
- 🗱 सतत समग्र मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शी निर्देश
- 🗱 महाविद्यालयों में गुणवत्ता एवं आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना
- 🗱 रोजगारोन्मुखी परियोजना कार्य हेतु मार्गदर्शी निर्देश
- 🗱 सेमेस्टर प्रकोष्ठ एवं आंतरिक मुल्यांकन प्रकोष्ठ के कार्य
- 🗱 शिक्षक एवं प्राचार्य के दायित्व



- 🗱 सतत मूल्यांकन हेतु सुझाई गई 16 विधियां
- 🗱 ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी, मुख्य लिपिक, लेखापाल के लिये निर्देश
- 🗱 अतिथि विद्धानों की नियुक्तियां
- 🗱 परियोजना कार्य के दौरान विद्यार्थियों के लिये निर्देश
- 🗱 महत्वपूर्ण दिवसों एवं जयंतियों का आयोजन
- शिकायत निवारण प्रकोष्ठ/सुझाव पेटी
- 🗱 प्राचार्य की विवेक निधि
- 🗱 शिक्षक प्रदर्शन का उल्लेख करने वाली दैनंदिनी
- महाविद्यालयों में अलूम्नी एसोसिएशन, प्रतिभा बैंक, बुक रीडिंग क्लब, क्रिएटिव राईटिंग क्लब, डिबेट एवं स्पीच क्लबों का गठन
- 🗱 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विभिन्न योजनाएं
- प्रतियोगी परीक्षाओं के पूर्व विद्यार्थियों को मार्गदर्शन (कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ)
- विद्यार्थियों को प्रोत्साहन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन-सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, भाषा सुधार अभियान, ''अर्न व्हाइल यू लर्न'' विद्यार्थियों के लिये पढ़ाई व कमाई साथ-साथ, साहित्यिक गतिविधियां, रचनात्मक लेखन, प्रभावी संचालन, वाद-विवाद, भाषण व परिचर्चाओं का आयोजन, पाँच रंगों के पृष्ठों वाली डायरी, निजी 'एनसायक्लोपीडिया', खाली समय का सार्थक उपयोग, पुस्तकों का अध्ययन आदि।

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा की दशा एवं दिशा-

भारत जैसे प्रगतिशील देश में कुल बजट राशि का मात्र 4.2 प्रतिशत भाग ही शिक्षा पर व्यय किया जाता है। इसका भी 80 प्रतिशत भाग स्कूली शिक्षा पर व्यय होता है, शेष 20 प्रतिशत भाग उच्च शिक्षा के लिये खर्च किया जाता है। इस 20 प्रतिशत राशि का भी लगभग 95 प्रतिशत भाग वेतन और संचालन पर व्यय होता है, शेष 5 प्रतिशत भाग ही उच्च शिक्षा के विकास हेतु मिल पाता है। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण एवं सोचनीय है।

आजादी के 66 वर्षों के बाद भी मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा की दशा और दिशा पर गौर करें कि हमने किन क्षेत्र में प्रगति की और किन क्षेत्र में गिरावट आई तो तस्वीर कुछ इस प्रकार दिखाई देती है :

उच्च शिक्षण संस्थाओं को गुणवत्तायुक्त बनाने में आने वाली समस्याएं-

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा में सेमेस्टर प्रणाली को लागू हुए 05 वर्षहो गये हैं। विभाग द्धारा प्रतिवर्ष इसमें नये परिवर्तन और संशोधन किये जा रहे हैं। गत वर्ष उच्च शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता वर्ष के रूप में मनाया तथा चालु वर्ष को गुणवत्ता विस्तार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज भी मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थाओं को गुणवत्ता युक्त बनाने में काफी रूकावटें हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:

- 🗱 उच्च शिक्षण संस्थानों में सतत् मानिटरिंग की व्यवस्था नहीं है।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्य के प्रति लापरवाह व्यक्तियों के लिये उचित दण्ड का प्रावधान नहीं है।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों के लिये उचित समयाविध में पुरस्कार या प्रमोशन देने का नियमानुसार कोई प्रावधान नहीं है।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पढ़ों पर स्थाई नियुक्ति के लिये ठोस प्रक्रिया एवं नियम का अभाव है।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों (शिक्षक, कार्यालयीन स्टॉफ, कमरों, फर्नीचर, किताबों, उपकरणों) के अनुपात में विद्यार्थियों के प्रवेश के नियम नहीं है।
- शिक्षकों को नवाचार से जोड़ने हेतु वार्षिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान नहीं है।
- संस्था प्रमुख सभी कार्य क्षेत्र में अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति सजग नहीं होने से संस्था को प्रगतिशील बनाने में सहायक नहीं हो पा रहे हैं।
- स्थानीय राजनीति (सांसद, विधायक, जनभागीदारी अध्यक्ष व सदस्यगण, छात्र संगठन व अन्य) के दबावों के कारण भी संस्था प्रमुख अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों को पूरा करने में अपने आपको असहाय महसूस करते हैं।
- कक्षाओं में उपस्थित नहीं बढ़ना भी एक प्रमुख समस्या है। कक्षाओं में उपस्थित नहीं होने से अन्य पाठयेत्तर गतिविधियों (एन.एस.एस./ एन.सी.सी./क्रीड़ा/ युवा उत्सव / साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों) में भी शून्यता का भाव दिखाई दे रहा है।

	यह बढ़ा		यह घटा
1.	संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या नदी	1.	कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या घटी
2.	कालेजों की संख्या बदी	2_	पदाई की गुणवत्ता घटी
3.	शिक्षा में भ्रष्टाचार बढ़ा	3.	विद्यार्थियों में शिक्षकों के प्रति सम्मान कम हुआ
4.	प्रायवेट ट्यूशन बढ़ी	4.	परीक्षा के स्तर में कमी आई
5.	नोट्स एवं गाइड्स का उपयोग बढ़ा	5.	शिक्षकों की प्रतिबद्धता में कमी आई
6.	ऊर्चे और महंगे सिलेबस बद्धे	6.	ज्ञान की ललक कम हुई
7.	कोर्सेस का विकल्प बद्धा	7.	कक्षाओं में उपस्थिति घटी
8.	नियमित शिक्षकों का बेतन बदा	8.	शिक्षकों में नैतिकता घटी
9.	तकनीकी उपकरनों की संख्या बढ़ी	9.	उपयोगकर्ताओं की संख्या घटी
10.	साहित्यिक एवं कलात्मक गतिविधियां बद्धी	10.	विद्यार्थियों की सहभागिता घटी
11.	व्यक्तित्व विकास के प्रयास बद्धे	11.	विद्यार्थियों की रूचि में कमी आई
12.	संस्थाओं में कागजी कार्यवाही बढ़ी	12.	वास्तविकता में कमी आई
13.	शिक्षकों की पदाईं के अतिस्कित अन्य शैक्षणेत्वर	13.	विद्यार्थियों की कक्षाओं में संख्या घटी
	गतिविधियों में जवाबदेही बद्दी		
14.	संस्थाओं में सेमीनार/कार्यशालाओं की संख्या बढ़ी	14.	शोध के स्तर में गिरावट आई
15.	संस्थाओं में राजनैतिक गतिविधियां बदी	15.	अधिकारियों द्वारा लिये जाने वाले त्वरित निर्णयों नें कमी
			आई

- विद्यार्थियों की उपस्थिति का सही दर्पण बनाने में संस्था प्रमुख अपने अधीनस्थों को उचित मार्गदर्शन देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर भी सभी शिक्षण संस्थाएं इस समस्या पर एकमत नहीं हैं।
- कम उपस्थिति की दशा में छात्रवृत्ति प्रदाय करना/नहीं करना भी एक महत्वपूर्ण समस्या है।
- शिक्षक वर्ग भी शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उलझे रहने से वे शिक्षा के मूल उद्देश्यों से दूर होते जा रहे हैं। वे चाह कर भी अन्य कार्यों को समयावधि में पूरा करने की होड़ में अपने विषय का अध्ययन-अध्यापन नहीं कर/करा पा रहे हैं।
- संस्थाओं के नीतिगत फैसलों में भी संस्था प्रमुख द्धारा सभी शिक्षकों की राय न लेकर अपनी पसंद के शिक्षकों से ही परामर्श करके संस्थाओं को चलाने का प्रयास किया जाता है।
- शिक्षण संस्थानों के अधोसंरचनात्मक ढांचे में बदलाव लाने हेतू पर्याप्त मात्रा में वित्त की उपलब्धता विभाग द्धारा नहीं की जाती है।
- संस्था प्रमुखों में उच्च शिक्षण संस्थानों को आधुनिक उपकरणों व तकनीकी से जोड़ने हेतु उदार मन से कार्य करने की प्रतिबद्धता का न होना।
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगतियों का निराकरण नहीं हो पाना।
- केन्द्र के समान राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को भत्ते व अनुलाभ प्राप्त न होना।
- संस्था स्तर पर जनभागीदारी समितियों द्धारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य योजना बनाकर उद्योगपतियों, सांसदों, विधायकों व अन्य सम्पन्न व्यक्तियों से वित्त उपलब्ध कराकर संस्था के विकास हेतु रचनात्मक कार्यों को पूरा करने की दिशा में उत्साह से काम नहीं किया जा रहा है।
- शिक्षण संस्थानों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों में गुटबाजी व आपसी समन्वय का अभाव होने से भी स्थानीय स्तर पर महाविद्यालयों में कई समस्याएं संस्था प्रमुख के सामने विद्यमान रहती हैं। इस वजह से वे सकारात्मक कार्यों को पूरा करने में अपने आप को असहाय पाते हैं।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं की मौलिक एवं स्थानीय समस्याओं को दूर करने में स्थानीय प्रशासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता है।
- संस्था प्रमुखों को उदार मन से संस्था हित में कार्य करने के लिये अधिकारों व शक्तियों का सम्प्रेशण उच्च अधिकारियों द्धारा शीघ्रता से प्रदाय नहीं किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग भी संस्था प्रमुखों को खुले मन से प्राप्त नहीं हो पाता है।
- महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों से परीक्षाओं के आयोजन, परिणाम व अन्य अकादमिक कार्यों में समय-समय पर रचनात्मक सहयोग प्राप्त नहीं होता है।
- शासन द्धारा निर्धारित अकादिमक केलेण्डर का भी विश्वविद्यालयों द्धारा पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जाता है।
- महाविद्यालयों में नये पाठ्यक्रम व नये विषयों को प्रारंभ करने की अनुमतियां व अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र भी विश्वविद्यालयों से शीघ्रता से प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के उन्नयन हेत् आवश्यक सुझाव-

वैश्विक अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षा जगत में बदलाव लाने के लिये हमें यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारे द्धारा लाया जाने वाला परितर्वन हमारे देश /प्रदेश की परिस्थितियों के अनुकूल हो। उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा गुणवत्ता के उन्नयन हेतु आवश्यक सुझाव इस प्रकार हैं :-

- प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की सतत मानिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। यह मानिटरिंग व्यवस्था जिला. संभाग एवं राज्य स्तर पर गोपनीय विभाग द्धारा कराई जाना चाहिये।
- उच्च शिक्षा संस्थाओं में कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के लिये उचित पुरस्कार एवं लापरवाह व्यक्तियों को दण्डित करने का प्रावधान उचित समयावधि में ही होना चाहिये।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति की * प्रक्रिया प्रारंभ करके उन्हें स्थाई रूप से भरा जाना चाहिये।
- जिन संस्थाओं में आवश्यकता से अधिक स्टॉफ हो उन्हें वहां से कार्यमूक्त * करके अन्य संस्थाओं में जहां उनकी आवश्यकता हो वहां पदस्थ किया जाना चाहिये।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रवेश वहां उपलब्ध संसाधनों (शिक्षक, कार्यालयीन स्टॉफ, फर्नीचर, कमरों, किताबों, उपकरणों) के आधार पर होने चाहिये।
- सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर सेमेस्टरों में कम्प्यूटर शिक्षा व रिसर्च मैथ्डोलॉजी की शिक्षा अनिवार्यत: शामिल की जानी चाहिये. जिससे की विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट बनाने में निपुणता प्राप्त हो सके।
- शिक्षक वर्ग को भी नवाचार से जोड़ते हुए कम्प्यूटर व रिसर्च से संबंधित वार्षिक प्रशिक्षण की व्यवस्था शासन स्तर पर किसी संस्था द्धारा नियमित रूप से की जानी चाहिये।
- उच्च शिक्षण संस्थानों से राजनैतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिये शासन स्तर पर गठित जनभागीदारी समितियों में अध्यक्ष एवं अन्य पढ़ों पर विद्यार्थियों के ही अभिभावकों का चयन किया जाना चाहिये। तभी सही मायने में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण संस्थानों का विकास संभव हो सकेगा।
- अतिथि प्राध्यापकों को नियमित करने हेत् स्थाई रूप से कार्य योजना * बनाई जाना चाहिये।
- कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के सामूहिक प्रयास होने चाहिये।
- महाविद्यालयों में राष्ट्र की सेवा हेतु एन.सी.सी. एवं समाज सेवा हेतु एन.एस.एस. के कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम के एक विषय के रूप में सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्यत: किया जाना चाहिये। इसके लिये क्रीड़ा अधिकारी की तरह ही शासन स्तर पर पद निर्मित करके स्थाई एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. अधिकारियों की नियक्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी चाहिये।
- * प्रत्येक शासकीय महाविद्यालयों का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शासकीय भवन होना चाहिये, जो पूर्णरूपेण साफ सुथरा, सुसज्जित व हरा-भरा हो, जिसमें खेल मैदान, जिम, वाचनालय, ग्रंथालय, बगीचा, विद्यार्थियों के पढ़ने के लिये पर्याप्त कक्ष, कम्प्यूटर सुविधा एवं बाउण्डीवाल अनिवार्यतः होना चाहिये।
- महाविद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिये ड्रेस कोड अनिवार्य किया जाना चाहिये।

nss

- गरीब एवं कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति से बिना ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये, जो विद्यार्थियों से 10 माह में समान किश्तों में वापस ली जाए।
- एम्बेसेडर प्राध्यापक को ग्रामीण एवं दुरस्थ अंचलों के ऐसे महाविद्यालयों में जहां शिक्षकों का अभाव है वहां प्रत्येक सप्ताह में एक दिन अनिवार्यत: अध्यापन हेतु भेजा जाना चाहिये। जिले के वे महाविद्यालय जो शहरों में स्थित हैं एवं जहां पर्याप्त मात्रा में विषय से संबंधित प्राध्यापक उपलब्ध हों, वहां एम्बेसेडर प्राध्यापक को भेजने का कोई औचित्य नहीं है।
- उच्च शिक्षा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को ''आत्म-विश्लेषण'' के आधार पर कार्य करना चाहिये।
- "शैक्षणिक भ्रष्टाचार" को प्रभावपूर्ण एवं नैतिक तरीकों से रोका जाना चाहिये।

कुछ ठोस निर्णयों को लागू करने की आवश्यकता :-

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के उन्नयन एवं प्रबंधन हेतु निम्न ठोस निर्णयों को शीव्रता से अमल में लाया जाना चाहिये, जिससे विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें तथा अर्जित ज्ञान और कौशल से अपना भविष्य बना सकें।

- सी.सी.ई. में फेल/अनुतीर्ण विद्यार्थियों से उसी सेमेस्टर में ढोबारा सी.सी.ई. नहीं लेने का प्रावधान होना चाहिये।
- विद्यार्थियों की उपस्थित निर्धारित प्रतिशत से कम होने पर अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से उनकी उपस्थिति बढ़ाने के स्थान पर उन्हें स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षाओं में शामिल किया जाना चाहिये, तथा ऐसे विद्यार्थियों को महाविद्यालय की सभी सुविधाओं से (छात्रवृत्ति, खेलकूद, एन.सी.सी., एन.एस.एस., ग्रंथालय, वाचनालय आदि) उन्हें वंचित किये जाने का प्रावधान होना चाहिये।
- विद्यार्थियों का नकल प्रकरण बनने पर उन्हें तीन वर्ष तक नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित रखने का सख्त प्रावधान होना चाहिये।
- विद्यार्थियों की रेगिंग व अन्य अनुशासन रहित गतिविधियों में संलग्जता पाये जाने पर उन्हें संस्था से निष्कासित करने का प्रावधान संस्था प्रमुखों द्वारा सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।

- संस्था प्रमुखों की अनुशंसा पर संस्था हित में कार्य नहीं कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण उचित समयाविध में ही अन्य संस्थाओं में किया जाना चाहिये।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप 0 1माह/ 03माह/ 06माह एवं 12 माह की अविध के सर्टिफिकेट कोर्सेस प्रारंभ किये जाने चाहिये, जो विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने में सहायक हो सके।
- संस्था प्रमुखों द्धारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिये केम्पस चयन हेतु स्थानीय स्तर पर फर्म एवं कम्पनियों को आमंत्रित कर केम्पस इंटरव्यू की प्रक्रिया को प्रतिवर्ष आयोजित कराया जाना चाहिये। साथ ही यह भी प्रयास किया जाना चाहिये कि इन इंटरव्यू में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त हो।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में रचनात्मक गतिविधियों एवं नवाचारों के उन्नयन हेत् वित्त की कमी आड़े नहीं आनी चाहिये।
- शिक्षण संस्थानों में नवाचारों हेतु दानदाताओं से दान एवं अनुदान लेकर योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करने के लिये संस्था प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश एवं अधिकार दिये जाने चाहिये।

निष्कर्ष

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उच्च शिक्षा के सभी आयामों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उच्च चिन्तन के बिना भारतीय परम्पराओं और मूल्यों के अनुरूप संस्थाओं को आकार देना संभव नहीं है। मानव संसाधन विकास को गुणात्मक विकास से जोड़ते हुए सेमेस्टर पद्धति को इस प्रकार उपयोगी बनाया जाय जिससे मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों और विद्या परिसरों से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें और अर्जित ज्ञान व कौशल से अपना भविष्य बना सकें।

उच्च शिक्षा के सभी हितग्राहियों – विद्यार्थी, पालक, शिक्षक अर्थात् सारे समाज की चेतना को गहराई से संस्कारित करने में उच्च शिक्षा की महान भूमिका है। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों – कर्मचारियों और प्राध्यापकों को उच्च शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए मिलकर काम करना होगा, तभी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकेगा।

संदर्भ सूची :-

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल व्हारा जारी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन पुरितका वर्ष2011-12 एवं व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर





भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का परिदृश्य, विकास एवं चुनौतियाँ : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. पकाशचन्द्र रांका *

सूचना प्रौद्योगिकी 21वीं शताब्दी का सबसे प्रभावकारी तंत्र है, जिसने दुनिया भर में बदलाव के नये युग का सूत्रपात किया है। यह राष्ट्रीय गौरव की बात है कि हमारे देश ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित भारतीय लोग विदेशों में भी बडे—बड़े काम करके भारतीय युवा प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी प्रशासन, बैंकिंग, व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उपयोगी भूमिका निभा रही है। इससे कार्य तो शीघ्र होता ही है, पारदर्शिता भी बनी रहती है तथा भ्रष्टाचार एवं हेराफेरी पर अंकुश पाने में मदद मिलती है।

हमें यह सुनकर कितना सुखब लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय विशेषज्ञों की कुशलता का लाभ बुनिया के विकसित बेश भी उठा रहे हैं। आज विश्व में भारत को जो नई पहचान मिली है, वह सूचना प्रौद्योगिकी में उसकी प्रगति से ही है। भारतीय प्रतिभाओं की नित नई खोज से विकसित सॉफ्टवेयर और कम्प्यूटर सेवा उद्योग से भारतीय अर्थव्यवस्था के समृद्धशाली संसाधनों और उनसे आय के स्त्रोतों मे तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में आई टी (सूचना प्रौद्योगिकी) उद्योग बेश के आर्थिक विकास में सबसे गतिशील क्षेत्रो में शामिल हो गया हैं।

पिछले दशक में आई टी सेवा उद्योग में अनेक परिवर्तन हुए है। निर्यात राजस्व 1999-2000 के 4 अरब डॉलर से बढ़कर 2011-12 में 69 अरब डालर तक पहुंच गया है। इसी अविध में घरेलू राजस्व भी 1.9 अरब से बढ़कर 19 अरब डालर हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं (आई टी - आई टी इ एस) में काम करने वाले लोगो की संख्या जहां 2000-01 में 5 लाख 20 हजार थी वहीं 2011-12 में 28 लाख हो गई है। अत: भारत के आई टी उद्योग के इतिहास में वर्ष 2012 को एक युगान्तकारी वर्ष के रूप मे याद किया जाएगा। इस वर्ष इस उद्योग का कुल राजस्व एक खरब अमरीकी डालर से भी अधिक हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय आई टी-बी पी ओ उद्योग के विकास के चरणों के साथ, रोजगार की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और अवसरों का गहराई से विश्लेषण करने के साथ भावी परिदृश्य की सम्भावनाओं का भी विवेचन करने का प्रयास किया गया है।

आई टी-आई टी ई एस उद्योग का भारत के आर्थिक विकास में अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पूरे विश्व में 'सॉफ्ट पावर' के रूप में भारत की साख बढ़ी है। फार्च्यून 500 और ग्लोबल 2000 में शामिल अधिकांश कम्पनियां सूचना प्रौद्योगिकी और उस पर आधारित सेवाओं के लिए भारत पर निर्भर है। भारत विश्व भर में अपने ग्राहकों को अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारतीय कम्पनियों ने पूरे विश्व में सेवा प्रदाय केन्द्र खोल रखे है, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जा रही है। 2007 में विश्व के 48 देशों के 184 शहरों में 340 सेवा प्रदाय केन्द्र थे, जबिक वर्तमान में 70 देशों के 200 नगरों में 560 केन्द्र काम कर रहे हैं।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी 5.24 प्रतिशत है। इसमें लगभग 25 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं, जिससे यह सर्वाधिक रोजगार प्रदाय करने वाले क्षेत्रों में से एक बन गया है। पिछले 05 वर्षों में (2006–11) में GDP में वृद्धि के प्रतिशत में 6.6 प्रतिशत योगदान आई टी क्षेत्र का रहा है।

पिछले 10 वर्षो में देश में जो रोजगार उपलब्ध हुआ है, उसका लगभग 40% आई टी क्षेत्र ने ही उपलब्ध कराया है। देश के बाहर स्थित उसके आई टी और आई टी ई एस उद्योग में 13-14% की वार्षिक वृद्धि गौरवपूर्ण है तथा लगभग एक करोड लोगो को रोजगार मिल रहा है और 2020 तक इसके निर्यात से 1 खरब 75 अरब डालर का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

तालिका 1. क्षेत्रवार आई.टी.– आई.टी.ई.एस. का निर्यात (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

सेवा क्षेत्र	विस्ता वर्ष	वित्त वर्ष	नित्त वर्ष
	1999-2000	2006-2007	2011-2012
आई दी सेवाएं	3.1	17.9	39.2
नीपीओ	0.6	8.4	16.6
सॉपटवेयर छत्पाद	0.3	4.9	13.3
/ इंजीनियरी			
योग	4	31.2	69

स्त्रोत- नासकॉम एवं डीआईटी वार्षिक रिपोर्ट

तालिका 2. क्षेत्रवार घरेलू आई.टी.– आई. टी.ई.एस. उद्योग से राजस्व (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

सेवा क्षेत्र	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष
	1999-2000	2006-2007	2011-2012
आई टी संबाएं	1.5	5.5	12.2
गीमीओ	0.0	1.1	3.1
सॉफ्टवेयर उत्पाद /	0.4	1.6	3.7
इंजीनियरी			
योग	1.9	8.2	19

स्त्रोत- नासकॉम एवं डीआईटी वार्षिक रिपोर्ट

भारत निर्माण योजना के तहत् आई टी उद्योग भारत के आर्थिक विकास में मददगार सिद्ध होने के साथ लोगों के जीवन स्तर में क्रान्तिकारी बदलाव लाया है। आई टी उद्योग से प्राप्त सेवायें निम्नलिखित क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयोगी साबित होकर भारतीय जन-जीवन के सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जबर्दस्त परिर्वतन लाकर नये भारत की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है –

- 01. रेल्वे टिकट एवं आरक्षण का कम्प्यूटीकरण
- 02. बैंकिंग कार्यों में कम्प्यूटर एवं एटीएम सुविधा
- 03. इन्टरनेट से रेल टिकट, हवाई टिकट का आरक्षण
- ०४. इन्टरनेट से एफ.आई.आर.

nss

- न्यायालयों के निर्णय ऑनलाईन उपलब्ध कराये जा रहे है।
- 06. किसानों के भूमि रिकार्डो का कम्प्यूटीकरण
- इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन एवं ऑनलाईन काउंसलिंग
- 08. ऑनलाईन परीक्षायें
- 09. कई विभागों में ऑनलाईन टैण्डर
- 10. महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश
- 11. पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस ऑनलाईन बनाना
- 12. कई विभागों में कान्फीडेन्सियल रिपोर्ट ऑनलाईन भरे जा रहे है।
- 13. विभागीय शिकायतें ऑनलाईन की जा सकती है।
- 14. कई विभागों की बहुत सारी जानकारियां ऑन लाईन उपलब्ध है।
- 15. 'सूचना के अधिकार' के तहत् भी बहुत सी जानकारियां ऑनलाईन दी जा रही है।
- आयकर रिटर्न एवं फाइलिंग ऑनलाईन उपलब्ध है।

भारत के आई टी उद्योग के विकास को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है –

- 1. 1998-2000 तक प्रथम चरण वर्ष 1998 में ही इस उद्योग ने भारत में अपना आकार ग्रहण कर लिया। सॉफ्टवेयर एव इन्टरनेट सेवाएं इसके विकास के नये संचालक बने। भारत में इस उद्योग के विकास के पिछे वर्ष 2000 (वाई टू के) की विलक्षता का विशेष योगदान रहा तथा इसकी वार्षिक विकास दर 50 प्रतिशत के लगभग हो गई। इस अविध में सॉफ्टवेयर के विभिन्न 'एप्लीकेशन्स' तथा इसके अनुसंधान एवं विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।
- 2. 2001-05 तक द्वितीय चरण इस अवधि के प्रारम्भ में 'डॉट काम' संकट के साथ-साथ उद्योग के सामने अनेक संकट उपस्थित हुए, परन्तु भारत की आई टी कम्पनियों ने विश्व की नकारात्मक मानसिक स्थिति में भी संकट मोचक बनक वैश्विक एवं स्वदेशी बाजारों को सेवाए प्रदान करना जारी रखा तथा अपनी उच्च विकास दर बनाए रखी।
- 3. 2006 से वर्तमान तक तृतीय चरण विश्व में अपनी सेवाओं का डंका बजाते हुए 05 भारतीय बड़ी आई टी कम्पनियों ने अभूतपूर्व प्रगति को प्रदर्शित किया। विकसित देशों की भारी मांग के कारण इन कम्पनियों ने 45 अरब रूपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया। बी पी ओ सेवाओं के विकास और विदशों में सभी आई टी सेवाएं एक मुश्त प्रदान करने जैसे पैकेज कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से भारतीय आई टी सेवाओं के ग्राहकों में भारी वृद्धि हुई है। अब अमरीका जैसे देश की मांग मे संतृप्ति की स्थिति बन जाने से आई टी उद्योग युरोप जैसे नये क्षेत्रों में सम्भावनाओं की खोज कर रहा है।

विकास के तृतीय चरण में विशेषकर 2010–11 और 2011–12 की अविध में इस उद्योग ने भारत के सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है। इस उद्योग ने वैश्विक कारोबारी परिवेश की अनिश्चितताओं के बादल छितराते हुए 2011–12 में 1000 अरब डालर का राजस्व प्राप्त कर एक अहम मील के पत्थर को पार करने का श्रेय प्राप्त किया। वर्ष 2010–11 के मुकाबले लगातार 14.7 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करके 2011–12 के वर्ष को सूचना प्रौद्योगिकी–बी पी ओ उद्योग का युगान्तकारी वर्ष कहलाने का गीरव हासिल किया।

बढ़ता निर्यात एवं आंतरिक आई टी बाजार का विस्तार -

तालिका 01 एवं तालिका 02 भारत के आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते कढ़म को प्रदर्शित करती है। वर्ष 2011-12 में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं का निर्यात लगभग 69 बिलियन डालर का हुआ जो कि 2006-07 के मुकाबले दुगुने से भी अधिक है एवं 1999-2000 की अपेक्षा 17 गूने से भी अधिक है।

इन निर्यातों में बी पी ओं के निर्यात भी शामिल थे। यदि अकेले सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की बात करें तो हम पाते हैं कि इनके निर्यात में प्रतिवर्ष वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। 2011-12 में आई टी सेवाओं का निर्यात 39.2 बिलियन अमरीकी डालर हुआ जो कि पिछले 05 वर्षो (2006-07) की अपेक्षा दृगृने से भी अधिक है।

आई टी-आई टी ई एस उद्योग का घरेलू राजस्व 2011-12 में 19 बिलियन डालर था, जो कि 1999-2000 के 1.9 बिलियन डालर से लगभग 10 गुना है। सरकार ने राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (NEGP) के तहत अनेक बडे कदम उठाये हैं, जिनसे अगले 05 वर्षों में आई टी सेवाओं के क्षेत्र की घरेलू मांग में भारी वृद्धि होने की सम्भावना है।

निर्यात उद्योग मुख्यत: तीन प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करता है – 1. आई टी सेवाएं 2. बी पी ओ एवं 3. इंजीनियरिंग सेवाएं। आई टी सेवाएं इस उद्योग की सफलता का मुख्य आधार है, जबिक बीपीओं एवं इंजीनियरिंग सेवाओं का क्षेत्र भारत के मूल्य–आधार पर विकसित हुआ है। आज तीनों ही क्षेत्रों में समेकित सेवा प्रदाताओं के साथ–साथ विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियां मौजूद है। (देखिए तालिका 3)

राजस्व एवं रोजगार की स्थिति -

अमरीका हमारी आई टी सेवाओं का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। अमरीका को निर्यात से 2011-12 के दौरान राजस्व में 17 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, यानि उसके बाजारों में हमारी 62 प्रतिशत की सर्वाधिक हिस्सेदारी होगी। 2012-13 तक बिना हार्डवेयर के भी भारतीय आई टी उद्योग की आमदनी के 1200 अरब डालर को स्पर्श कर लेने की क्षमता है, जबकि 2011-12 में उसकी आमदनी 87 अरब 70 करोड डालर थी।

यह लगभग 14 प्रतिशत विकास को दर्शाती है। तालिका-05 में आई टी क्षेत्र के निर्यातों से प्राप्त राजस्व के लक्ष्यों को प्रदर्शित किया गया है।

तालिका के समंकों से ज्ञात होता है कि आई टी क्षेत्र के कुल निर्यात एवं घरेलू बाजार से प्राप्त कुल राजस्व का लक्ष्य बारहवी पंचवर्षीय योजना (2012-17) में 170 बिलियन अमरीकी डालर का रखा गया है जो कि 2007-2011 के लक्ष्य (76.2 बिलियन अमरीकी डालर) की तुलना में दगुने से भी अधिक है।

सुदृढ आधार एवं भारी मांग की सम्भावनाओं के मध्यनजर भारत ऐसी स्थिति में है कि वह 2018 तक आई टी क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हो सकता है। अपने आई टी एवं बीपीओ निर्यात में 13.8 प्रतिशत की समग्र वार्षिक दर से वृद्धि करने की क्षमता रखता है। (तालिका 5)

अपने कुल निर्यातों से 18 खरब 30 अरब डालर का तथा घरेलू बाजार से 40 अरब डालर का राजस्व प्राप्त करने की ठोस सम्भावनाएं है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के समंकों का विश्लेषण (तालिका-03) करने पर स्पष्ट होता है कि कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के क्षेत्र में विदेशी निवेश अप्रेल 2000 से दिसम्बर 2011 की अविध में 490.4 बिलियन रूपये हुआ जो कि दूरसंचार एवं उर्जा क्षेत्र के बाद तृतीय स्थान पर आता है। यह कुल एफ डी आई का 6.9 प्रतिशत है। तालिका-05 के समंको से स्पष्ट है कि पिछले 05 वर्षों की तुलना में आगामी 05 वर्षों में आई टी उद्योग से प्राप्त राजस्व का लक्ष्य दुगुने से भी अधिक है।

आई टी-आई टी ई एस उद्योग में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि पिछले दशक में इस क्षेत्र में 22 लाख 80 हजार रोजगार



के अवसर उत्पन्न हुए। 2011-12 में इस क्षेत्र में कुल 28 लाख लोग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुडे हुये थे जो कि 2000-01 के 5 लाख 20 हजार की

भार	भारत में 8 बड़े आई टी केन्द्र (HUBS) आधुनिक रोजगार के बड़े केन्द्रों के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं –					
रैंक	शहर का नाम	विवरण				
01	बैंगलोर	यह शहर भारत की 'सिलीकॉन वैली' के नाम से तथा 'सॉफ्टवेयर निर्यातक का मुखिया' के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इसे वैश्विक तकनीक केन्द्र भी कहा जाता है।				
02	हैदराबाद	इस बड़ें आई टी केन्द्र को 'साइबराबाद (Cyberabad) के नाम से जाना जाने लगा है, जहां गुगल, फेसबुक, माईक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इलेक्ट्रानिक आर्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कार्यालय है।				
03	चैझई	यह बीपीओ उद्योग का बडा केन्द्र है। यहां टी.सी.एस. एवं कोगनीजेण्ट कम्पनियों के बड़े कार्यालय भी है।				
04	मुम्बई	भारत की वित्तीय राजधानी मुम्बई में भी कई बड़ी आई टी कम्पनियों ने अपने कार्यालय स्थापित किये हैं।				
05	दिल्ली	भारत की राजधानी नई दिल्ली और इसके आस पास गुड़गांव एवं नोयडा सॉफ्टवेयर विकास के समूह केन्द्र बन गए हैं।				
06	पूणे	यहां अनेक बड़ी भारतीय एवं बहुराष्ट्रीय फर्मों के बड़े कार्यालय स्थापित हैं। पूणे 'सी–डेक' के मुख्यालय के नाम से भी जाना जाता है।				
07	कोलकात्ता	भारत का सबसे बड़ा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।				
08	तिरुवनन्तपुरम	केरल की राजधानी यह शहर आई टी निर्यात के योगदान के साथ ऑरेकल, टी.सी.एस. इन्फोसिस आदि कम्पनियों के कार्यो में महत्वपूर्ण सहयोगी है।				

तुलना में 5 गुने से भी अधिक थे अर्थात पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में रोजगार की कुल वृद्धि 81 प्रतिशत हुई जो कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों में महिलाओं का प्रतिशत 30 से भी अधिक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने में कामयाब हुआ है।

तालिका 04 के समंकों से स्पष्ट होता है कि भारत की 05 बड़ी आई टी सेवा कम्पनियों को देखा जाएं तो सर्वाधिक 2,54076 कर्मचारी टी सी एस में कार्यरत है, जिसका कुल राजस्व 2012 मे 10.17 बिलियन अमरीकी डालर है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाली कम्पनियों में टी सी एस, सी टी एस, विप्रो, इन्फोसिस तथा एच सी एल के नाम सबसे ऊपर है। आई टी सेवा निर्यात क्षेत्र एवं घरेलू उद्योग क्षेत्र सबसे बड़े नियोक्ता है। कुल प्रत्यक्ष रोजगारों में इसका हिस्सा 47 प्रतिशत है। जहां तक बीपीओं निर्यातों का

संबंध है, वे उद्योग में कुल रोजगार के 32 प्रतिशत का सृजन करते है। शेष 22 प्रतिशत का सृजन घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ क्षेत्र में होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों जैसे केटरिंग, सुरक्षा, परिवहन, आवास के रखरखाव आदि में लगभग 89 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का श्रेय भी जाता है। इनमें से काफी रोजगार देश के ग्रामीण क्षेत्रों को भी उपलब्ध हो जाते है।

सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ उद्योग को गर्व हैं कि इसने भारत को विश्व के नक्शे में अपनी छाप छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं का खेल बराबर जारी है, फिर भी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी बदलते व्यापारिक माहौल में अपने को ढालते हुए विकास पथ पर अग्रसर है।

भारत के आई टी उद्योग की सेवा क्षेत्र में विशिष्टीकरण एवं वैश्विक सन्दर्भ में सापेक्ष प्रतिस्पर्धा की श्रेणी को परखने के लिए 'बालासा इण्डेक्स' के माध्यम से RCA (Ralative Comparative Advantage) विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि RCA का मूल्य इकाई से अधिक आता है तो इसका आशय यह है कि वह देश उस विशिष्ट सेवा क्षेत्र में शेष विश्व के देशों के मुकाबले तुलनात्मक रूप से लाभ की श्रेणी का सामर्थ्य रखता है। तालिका—06 में सेवा क्षेत्र के विभिन्न भागों का निर्यातों के परिप्रेक्ष्य में RCA के मूल्य की गणना की गई है। तालिका के समंक स्पष्ट करते है कि निर्यातों के सन्दर्भ में भारत के कम्प्यूटर एवं सूचना तकनीक क्षेत्र का RCA सन् 2010 में सर्वाधिक 7.9 है, जो यह सिद्ध करता है कि भारत आई टी जनित उद्योग में तुलनात्मक रूप से विश्व में बहुत ज्यादा लाभ, फायदे एवं मजबुत प्रतिस्पर्धा की श्रेणी में है। अत: आने वाले वर्षों में देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विकसित होने की बहुत अच्छी सम्भावनाएं है।

हमारे ज्ञान का क्षेत्र युवाओं द्धारा संचालित होता है। इस उद्योग के कर्मचारियों की औसत आयु 25 से 30 वर्ष के मध्य है। 2025 में 70 प्रतिशत भारतीय कार्यशील आयु में होंगें जो कि अभी के 61 प्रतिशत के अनुपात से बेहतर हैं। भारतीय श्रम रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 30 करोड़ युवा कार्यशील जनसंख्या में शामिल होंगे तथा अगले 03 वर्षों में विश्व के श्रमिकों में से 25 प्रतिशत भारतीय होंगे। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक युवा छात्र-छात्राऐं आई टी, इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार क्षेत्र के इंजीनियर विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण होकर निकल रहे है। आज अन्य किसी देश में मानव संसाधन का इतना बड़ा एवं कुशल तकनीकी आकार उपलब्ध नहीं है। अत: भारत की आई टी क्षेत्र में अग्रणी रहने की भरपूर सम्भावनाएं है।

प्रमुख समस्याएं एवं चुनौतियां -

उच्च विकास दर के बावजूद भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सामने कई समस्याएं है। 08 बड़े महानगरों में ही सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों का केन्द्रीयकरण होने से आवास समस्या के साथ-साथ कुल लागतों में वृद्धिमान दर से वृद्धि हो रही है, तथा अन्य शहरों में अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कारण प्रतिस्पर्धा में कमी दृष्टिगोचर हो रही है।

चीन ने विनिर्माण क्षेत्र में प्रमुखता के बाद अब सेवाओं का मुख्य केन्द्र बनने की ठान ली है। चूंकि इस उद्योग में अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है। अत: चीन के अतिरिक्त अन्य देशों ब्राजील, पौलेण्ड, हंगरी, फिलीपींस, वियतनाम, मेक्सिको, मिस्र आदि देशों से हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है। ये देश अनेक प्रकार के प्रोत्साहन अपनी प्रतिभाओं को दे रहे है, जिससे हमारे लिए यह खतरा है कि कहीं उनमें से कुछ देश प्राथमिक स्त्रोत में न बदल जाएं। भारत में कुकरमुत्तों की तरह बढ़ते इंजीनियरिंग कॉलेजों के बावजूद

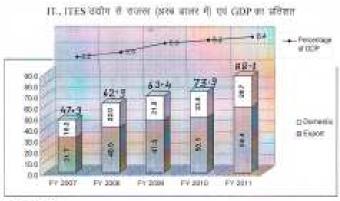


योग्य प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर इंजीनियरों का अभाव भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। हमें शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। शुरू में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का व्यवसाय अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहक वर्ग के लिए था। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एवं अन्य सेवाएं यद्यपि भारत में विकसित की गई. लेकिन इनका उपयोग अन्य विकसित देशों में ही किया जाता था।

इस उद्योग को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में थोड़ा समय लगा। तथा इसमें बहुत सी समस्याएं आई जिनमें से कई अभी भी मौजूद है। बिजली की पर्याप्त आपूर्ति न होना, साक्षरता की कमी, पूंजी लगाने के प्रति उदासीनता, संचार सुविधाओं का अभाव सूचना प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में मुख्य बाधाएं है।

गुणवत्ता युक्त इंजीनियरिंग कॉलेजों की व्यवस्था के साथ कौशल विकास के प्रयासों के माध्यम से रोजगार योग्य युवाओं की कमी को ढूर करने के गम्भीर प्रयासों के साथ सॉफ्टवेयर एवं सेवा क्षेत्र की सम्भावनाओं का देश के विकास और प्रगति के लिए उपयोग किया जाए। निवेश, निर्यात, रोजगार सृजन और जी डी पी में योगदान के लिए सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र का अधिकतम उपयोग हो ताकि विश्व में आई टी/बीपीओ के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व बरकरार रहे। परिपक्त और उभरते बाजारों में आई टी क्षेत्र की मांग बनी रहें। सूचना प्रौद्योगिकी को गांवों तक पंहुचाना, ग्रामीण जनता को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें हमारी सफलता देश के संतुलित विकास एवं जन सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी।

वैश्विकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की नीतियों ने भारत के आई टी उद्योग को गहराई तक प्रभावित किया है। पिछले दशक में निर्माण, संचार, बीमा, बैंकिंग, वित्त और इसके बाद खुदरा कारोबार उद्योग देश के आई टी उद्योग के विकास रथ के महत्वपूर्ण चालक सिद्ध हुए है। लेकिन भविष्य में यह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि 'मोबाईल एप्लिकेशन्स' 'हेल्थ केयर', उर्जा दक्षता एवं सतत विकास आई टी उद्योग एवं इससे जनित सेवाओं के महत्वपूर्ण ईंधन साबित होगें।



indo - mente

References:

- Basu, Kaushik and Annemie Maertens (2007). The pattern and causes of economic growth in india" CAE working paper April 2007
- Chanda Rupa (2002) "Globalization of services india"s opportunities and constraitant" oxford university press, New Delhi.
- DIPP (2011) "Consolidated FDI policy (Effective from April 1, 2011)" Ministry of commerce and Industry Govt. of India March 2011, New Delhi
- DIPP (2012) "Consolidated FDI policy (Effective from April 1, 2012)" Ministry of commerce and Industry Govt.of India March 2011. New Delhi
- Kumar Gulshan and Neeraj Dhingra (2011) "Impact of Libralization in FDI structure in India" Instruction journal on economic research Vol-2 (2), 80-94, March-April 2011
- 6. कुरूक्षेत्र, फरवरी 2006 पृष्ठ 27-28
- 7. कुरूक्षेत्र, जनवरी 2012 पृष्ठ 05-09
- 8. तथ्य भारती, अक्टुबर 2001- पृष्ठ 30-31

तालिका 3. भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का क्षेत्रीय प्रवाह एवं अंश (बिलियन रूपयों में)

亷.	क्षेत्र	1991-95	2000-07	2009	2011	कुल	प्रतिशत	ा भाग
						निवेश	1991-95	2000-11
						अप्रेल		
						2000 से		
						दिसम्बर		
						2011		
1	सेवा क्षेत्र	13.2	398.2	272.4	238.9	1426.3	15.2	19.9
2	दूर संचार	1.4	157.8	123.7	104.9	570.3	1.6	8.0
3	कर्जा	0.0	106.3	101.8	108.6	530.4	0.0	7.4
4	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	0.0	312.3	32.1	31.4	490.4	0.0	6.8
	एवं हार्डवेयर							
5	भवन निर्माण एवं	0.0	83.9	159.7	32.2	488.2	0.0	6.8
	रियल स्टेट							
6	परिवहन	5.3	30.6	19.6	8.8	146.9	6.1	2.0

Source: Calculated on available data compiled from various issues of SIA newsletters, DIPP, Govt of India



-NSS

तालिका 4. भारत की 5 बड़ी आई.टी. सेवा कम्पनियों में राजस्व एवं रोजगार की स्थिति

कम्पनी	राजस्व	कमचारियों	वर्ष	मुख्यालय
		की संख्या		
TCS	\$ 10.17	254,076	2012	मुम्बई
	बिलियन			
CTS	🗦 7.05 बिलियन	185,045	2012	चैन्नई
WIPRO	∮ 5.73 बिलियन	140,569	2012	वैंगलौर
INFOSYS	🗦 6.69 बिलियन	153,761	2012	बैंगलौर
HCL	\$4.3 बिलियन	85,335	2012	नोयडा
technologies				

Source: wikipedia.org/wiki/information_technology_in_india

तालिका 5. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में राजस्व का लक्ष्य (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

विवरण	200711 के लक्ष्य	2012—17 के लक्ष्य
आई टी–आई टी ई एस∕बीपीओ	59	130
निर्यात से राजस्व		
आई टी-आई टी ई एस घरेलू से	17.2	40
राजस्व		
कुल योग	76.2	170

स्त्रोत- आर्थिक समीक्षा, भारत सरकार 2010-11 एवं 2012-13

तालिका 6. सेवा क्षेत्र के निर्यात में भारत का RCA *

क्षेत्र	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
संचार	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.3	1.3	1.2	1.0	0.6	0.5
कम्प्यूटर एवं सूचना	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	9.9	9.0	9.0	8.6	8.8	7.9
तकनीकी											
निर्माण	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	1.2
वित्त	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
सरकारी सेवाए	0.5	0.5	0.01	0.0	1.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
परिवहन	0.5	0.5	8.0	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5

*Relative comparative advantage (as per the Balassa's Index 1965) Calculated from UNCTAD Database on"International Trade Service"

Source: http://unctadstat.org/reportfolder.aspx (last accessed on March 2, 2012)



वर्तमान में रामाज एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में मीडिया की भूमिका

डॉ. लता जैन *

लोकतन्त्र में मीडिया का चौथा स्तम्भ इसीलिए माना गया है, कि वह तीनों अन्य स्तम्भों का संबल बने। उनकी रचनात्मकता बनाए रखे व उन्हें पारदर्शी बनाए। मीडिया की सबसे बडी शान्ति - उसका विवेक है. जो सत्य पर आश्रित व आधारित रहता है। प्रायोजित विवेक मीडिया की साख कम करता है। मीडिया का तकनीकी विकास चाहे जितना हो जाए पर सामाजिक दायित्व के निर्वहन और जवाबदेही से वह मूक्त नहीं हो सकता। इस दायित्व की रक्षा करके ही वह विश्वसनीय हो सकता है, तथा भारत जैसे लोकतन्त्र में अपनी निर्णायक शक्ति अर्जित कर सकता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है।

मीडिया के संदर्भ में यह बात शत प्रतिशत सत्य है कि समाचार पत्र किसी राष्ट्र की दैनन्दिन का इतिहास होता है। यह एक ऐसा आइना है जो देश/ समाज में रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म, परम्पराएँ, कानून, फैशन, जनमत, शासन प्रशासन को प्रतिबिंबित करता है। वर्तमान प्रतियोगितावादी युग में इसे लोकतन्त्र का चतुर्थ स्तम्भ माना गया है।

माध्यमों की सामाजिक भूमिका को लेकर इनके जन्म से ही वाद विवाद होता आ रहा है। आज प्रिन्ट मीडिया की अपेक्षा इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रभाव समाज में परिलक्षित हो रहा है। उदारीकरण तथा भ्रमंडलीकरण के प्रभावों के कारण माध्यमों की भूमिका भी प्रभावित हुई है तथा आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने की और प्रवृत्त हुई है। आम धारणा यह बन रही है, कि मीडिया काफी कुछ प्रचारात्मक तत्व अतिरंजित कर प्रस्तुत करने लगा है।

माध्यमों की सामाजिक भूमिका को समझने का प्रयास करने पर तीन सामाजिक भूमिकाएँ हमारे सामने आती है- 1. समाजीकरण 2. सामाजिक परिवर्तन ३. सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही धीमे रूप में दिखती है, किन्तु समाज में मान्यताओं और परम्पराआं के परिवर्तन में इस भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान है।

सामाजिक नियंत्रण के रूप में मीडिया विचारधाराएं, रीति रिवाज, लोक प्रथा, फैशन, परम्परा, नैतिक मुल्य, धर्म आदि के साथ सामाजिक भूमिका निभाकर जनमत् बनाने में मदद करते हैं। अत: माध्यमों की एक सामाजिक भूमिका है तथा इस भूमिका को अत्यंत जिम्मेदार, महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक रूप में देखा जाता है।

वर्तमान आधुनिककरण, उदारीकरण एवं पूँजीवाद के कारण आज समाचार पत्रों में विषय वस्तु का गहराई से विश्लेषण करने के स्थान पर आकर्षक प्रस्तृतीकरण पर जोर दिया जा रहा है। धीरे-धीरे पाठकों को इसका आदी बनाया जा रहा है। ''आईज ऑन द न्यूज'' सर्वेक्षण से यह बात स्पष्ट हुई है कि पाठकों की मानसिकता समाचार पत्रों को रोचक चित्रों व साज सज्जा की वजह से पसंद करने की बनती जा रही है। प्रिन्ट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक मीडिया भी पूरी तरह से बाजारवाद पर आश्रित है। बीसवी शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दस्तक दी और टी.वी., कम्प्यूटर, इंटरनेट तथा वेबसाइट ने घरों में झांका ही नहीं वरन अपना एक विशेष स्थान भी दिनचर्या में शामिल किया।

समाज में बदलाव के वाहक -

समाज में बदलाव के कई मीडिया वाहक है जो नई तकनीकी के साथ सामाजिक प्रगति को दशति हैं। सबसे प्रथम स्तर पर दूरदर्शन है। दूरदर्शन की स्थापना के समय से ही इसका लक्ष्य था, शिक्षा के प्रसार के साथ जागृति उत्पन्न करना तथा समाज को नई दिशा प्रदान करने के साथ स्वास्थ्य मनोरंजन एवं शिक्षा के कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाना।



आज दूरदर्शन मात्र सरकारी दूरदर्शन नहीं रहा। विभिन्न चैनलों के माध्यम से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ प्रकृति, ब्रम्हाण्ड का रहस्य खोलने वाले चैनल भी उपलब्ध है। समाज के हर वर्ग को देश की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास दूरदर्शन के माध्यम से अच्छी तरह से हो रहा है।

कार्यक्रमों के माध्यम से जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि, परिवार नियोजन, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूल शिक्षा विकास की योजनाएं, महिला, युवा एवं विकास से सम्बन्धित समस्या जैसे - अशिक्षा, कम उम्र में विवाह, यौन शोषण, मजदूर एवं मजदूरी, जमीन का हक, पंचायत में सहभागिता की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्रों में आम आदमी से जुड़ने के कार्यक्रम, शहरी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं आम वर्ग से जुड़ी पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं पर भी सीरियलों के माध्यम से फोकस किया जा रहा है।

ज्ञानवर्धक चैनलों जैसे- नैशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनीमल प्लेनेट तथा यूजीसी के कार्यक्रमों के व्हारा किशोरों, युवाओं में उज्जवल भविष्य के साथ आशा का संचार किया जा रहा है।

लगभग सभी कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं। तकनीकी विकास एवं हस्तांतरण के माध्यम से आम आदमी के जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन आये हैं। दूरदर्शन के विकास के साथ समाज कल्याण के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। दूरदर्शन परिवार जिस प्रकार बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार इसके दायित्व भी बढ़ते जा रहे है, ताकि सामाजिक परिवर्तन सही दिशा में हो सकें।

सामाजिक बदलाव की दूसरी वाहक आकाशवाणी है। माना कि दूरदर्शन के प्रभाव ने आकाशवाणी का महत्व कम किया है, किन्तु दूरदर्शन के कार्यक्रमों से उबते दर्शकों ने आकाशवाणी की ओर पून: रूख किया है आज भी देश के लाखों गाँवों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आकाशवाणी उच्च तकनीकी से युक्त ट्रांजिस्टर,

nss

रेडियो के माध्यम से सर्व सुलभ है। ट्रांजिस्टर के आविष्कार से रेडियो निर्माण में क्रांति आ गई है, कम कीमत में इससे सस्ता, सुगम साधन उपलब्ध नहीं है। समाज एवं आकाशवाणी के सम्बन्ध एवं प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखने



पर स्पष्ट है कि आकाशवाणी सामाजिक बदलाव की वाहक है कार्यक्रमों में विशेष महिला कार्यक्रमों में कानूनी अधिकारों, कल्याण कार्यक्रमों एवं विकास कार्यक्रमों की चर्चा प्रमुख है।

भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को समान आधार पर लाकर सभी प्रकार के भेदभावों, जन्म, धर्म और लिंग पर आधारित असमानताओं को समाप्त करने का जो वचन दिया है, संविधान का यह संदेश लोगों तक पहुँचाने में आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सच तो यह है कि आज आकाशवाणी को कोई कितना भी नकरात्मक सिद्ध करे मगर जनसामान्य में चेतना जगाने एवं परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के रूपक भी सामाजिक परिवर्तन कर रहे है। आकाशवाणी ने बाल विवाह, दहेज, मादक पदार्थों का सेवन, घर परिवार, ग्रामीण विकास, कृषि सशक्तिकरण कूरीतियों के खिलाफ सतत् आन्दोलन चलाया है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु फिल्में हैं। फिल्मों की सामाजिक उपयोगिता पर चर्चा करें तो यह भी यह भौतिक एवं कलात्मक वस्तुओं की तरह सामाजिक जीवन से प्रस्फ़्टित होती है। उसी का चित्रण करती है तथा नकारात्मक या सकारात्मक रूप में सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। संयुक्त परिवारों का महत्व, टूटता ग्रामीण परिवेश, भौतिकता की यथार्थता, धार्मिक समर्पणता, भय एवं पारलौकिकता, युवाओं का दिग्भ्रमित होना आदि की कई समस्याओं पर फिल्मों में प्रकाश डाला है।

आजकल फिल्मों में जहां एक ओर पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं को बहुत ही उम्दा तरीके से प्रस्तुत किया है वहीं चकाचौंध से उपजी फिल्मों ने युवाओं में परिवारों में विभाजन के बीज बोये हैं। धार्मिक विषयों, संतों की जीवनी, इतिहास आधारित फिल्में, स्वतंत्रता आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में आई फिल्में, विज्ञान आधारित फिल्में, सामाजिक बुराईयों पर प्रहार करती फिल्में आदि में भारतीय सिनेमा का ऐतिहासिक योगदान है। निरंतर उन्नत प्रौद्योगिकी ने फिल्मों के निर्माण को सरल तो किया ही है साथ ही स्पेशल इफेक्ट के माध्यम से नई क्रांति उत्पन्न की है। आज दूरदर्शन एवं संचार माध्यम के विकास के साथ फिल्मों की जिम्मेदारी और बढ़ गई हैं। संचार माध्यमों के विकास के साथ फिल्मों की जिम्मेदारी और बढ़ गई हैं। संचार माध्यमों के विकास के साथ सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। दूरदर्शन, आकाशवाणी के कार्यक्रम जिस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रकार इनके दायित्व भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों में आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए।

मिडिया आधारित तथ्यों और आँकड़ों से मुख्य बिन्द् -

- 01. भारतीय फिल्म उद्योग का कुल आकार 8,500 करोड़ रू. का है तथा इसका विदेशी बाजार करीब 750 करोड़ रू. है।
- 02. एशिया प्रशान्त क्षेत्र में करीब 73 प्रतिशत फिल्मों की आपूर्ति भारत से ही होती है।
- 03. भारत के 12000 सिंगल स्क्रीन और 350 मल्टीप्लेक्स हर साल 1000 से ज्यादा फिल्मों को प्रदर्शित करते हैं।
- 04. भारतीय डिजिटल म्यूजिक उद्योग का कोरिया के बाद दूसरा स्थान है।
- 05. 109 मिलियन टेलीविजन और 61 मिलियन केवल टीवी वाले घरों के साथ भारत में टेलीविजन का संसार अमरीका के बराबर है आशा है कि सन् 2015 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया प्रशान्त का सबसे बडा 'पे टीवी' मार्केट बन जाएगा।
- 06. भारत का प्रथम समाचार पत्र 'बंगाल गजट' 27 जनवरी, 1780 को जे.ए. हिझी द्धारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया।
- 07. समाचार -पत्र पंजीयक (1 जुलाई 1956 को स्थापित) द्धारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2007 तक देश में पंजीकृत समाचार पत्र/पत्रिकाओं की कुल संख्या 65032 थी, इनमें 7.131 दैनिक 374 त्रि/द्धि साप्ताहिक, 22116 साप्ताहिक, 8547 पाक्षिक, 19456 मासिक, 4470 त्रेमासिक, 605 वार्षिक तथा 2333 अन्य समयाविधयों के थे।
- 08. भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (पी.टी.आई.) की स्थापना 27 अगस्त, 1947 को हुई और इसने 1 फरवरी, 1949 से एक सहकारी संस्था के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी।
- 09. देश में United News of India UNI की स्थापना 19 दिसम्बर 1959 को हुई और इसने 21 मार्च 1961 से कार्य आरंभ किया। इसने 1982 से 'यूनिवार्ता' का शुभारंभ किया।
- 10. जन-संचार राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र (MDCMC) की स्थापना 1976 में की गई।
- 11. भारत में रेडियो प्रसारण की शुरूआत 1920 के दशक में हुई, पहला कार्यक्रम 1923 में मुम्बई के रेडियो क्लब द्धारा प्रसारित किया गया।
- 12. भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितम्बर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधा घण्टे के लिऐ शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में हुआ था, टेलीविजन की नियमित शुरूआत दिल्ली– 1965 में, मुम्बई–1972 में, कोलकता–1975 में, चैन्नई–1975 में हुई रंगीन प्रसारण की शुरूआत सन 1982 में नई दिल्ली में हुई।
- 13. देश में 16 दिसम्बर 2004 को 33 टीवी चैनलों तथा 12 रेडियो चैनलों के साथ DTH (Direct to Home Service) शुरू हुई वर्तमान में इस सेवा को पूरे देश में अनिवार्य किया जा रहा है।
- 14. वर्तमान में दूरदर्शन के 5 अखिल भारतीय चैनल, 11 क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल तथा 11 राज्य नेटवर्क चैनल संचालित किए जा रहे हैं।
- 15. देश में 24 घण्टे के समाचार चैनल 'DD News' की शुरूआत 3 नवम्बर 2003 से हुई और 18 मार्च 1999 को खेल चैनल 'DD Sports' की शुरूआत हुई।
- देश का सार्वजिनक सेवा प्रसारक दूरदर्शन आज विश्व के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क की श्रेणी में आता है।
- 17. दूरदर्शन और आकाशवाणी की गतिविधियों के संचालन व नियंत्रण



हेतु 23 नवम्बर 1997 को सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में 'प्रसार भारती' का गठन किया गया।

- 18. वर्तमान में देश में आकाशवाणी के 231 केन्द्र हैं।
- 19. आज देश के 14 बड़े शहरों में 'न्यूज ऑन फोन सेवा' उपलब्ध है।
- 20. विश्व में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिहाज से भारत प्रथम तीन राष्ट्रों में शामिल है।
- 21. भारतीय विज्ञापन उद्योग प्रति चार वर्ष में दोगूनी वृद्धि दर्शा रहा है।
- 22. सन् २०१३ तक भारतीय विज्ञापन उद्योग के ६१ प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है।
- 23. फिक्की द्धारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर 2009 तक 2200 करोड़ रू. में तब्दील होने वाली 'Event Industry' हर वर्ष करीब 300 प्रतिशत की दर के साथ बढ़ रही है।
- वर्तमान में 500 से ज्यादा बड़ी इवेंट फर्म और हजारों छोटी फर्में भारत में सक्रिय हैं।
- 25. वर्ष 2006 में भारतीय मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग लगभग 437 बिलियन रूपए रहा है, जो 2011 तक 1 ट्रिलियन रू. का होकर इस उद्योग के 2012 तक 1.157 ट्रिलियन रूपए तक पहुँचा।
- आज भारत में रेडियों का सालाना बाजार करीब 500 करोड़ रू. का है और इसमें हर वर्ष 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है।
- विशेषज्ञों के मतानुसार 'FM-II Policy' की वजह से रेडियो उद्योग
 मौजूदा 5 बिलियन से 2011 तक 17 बिलियन रूपए का हो गया।
- 28. भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग के संदर्भ में फिक्की द्धारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2007-08 में भारतीय गेमिंग उद्योग को 270 करोड़ रू. की आमदनी हुई, जो कि 2006-07 में 205 करोड़ रू. से 32 प्रतिशत ज्यादा है।

मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग (भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार)

मीडिया और मनोरंजन उद्योग Media and Entertainment (M&E) Industry) एक प्रकार का चक्रीय उद्योग है जो आर्थिक विकास और आय-स्तर में वृद्धि के साथ तीव्र गति से प्रगति के सोपान रेखांकित करता है।

आज यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्रतम विकासोन्मुखी उद्योगों की श्रेणी में शामिल हो चुका है, टेलीविजन, सिनेमा, रेडियो, विज्ञापन, संगीत, इविंट प्रबन्धन जैसे अनेक संघटकों को समाहित करने वाला भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 19 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर [Compounded Annual Growth Rate-CAGR] से बढ़ रहा है, यह उद्योग आज 530 अरब रू. का हो गया है जबिक वर्ष 2006–2007 में 438 अरब रू. का ही था, 'प्राइस वाटर हाऊस कूपर' (PWC) द्धारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सन् 2012 तक भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग 1.157 खरब रू. का हो चुका है।

एसोचैम [Associated Chembers of Commerce and Industry of India] व्हारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिहाज से भारत विश्व के प्रथम तीन देशों में शामिल है, जहाँ तक एशियाई देशों की बात करें तो वहाँ यह क्षेत्र 8.8 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ रहा है और सन् 2012 तक सम्पूर्ण एशिया का यह बाजार 508 अरब डॉलर तक पहुँचेगा। गौरतलब तथ्य यह भी है कि आने वाले समय में इण्डोनेशिया, सऊदी अरब, वियतनाम, टर्की, पाकिस्तान आदि राष्ट्रों का मीडिया और मनोरंजन उद्योग भी 'हॉट क्षेत्र' बन जाएगा, अत: नि:संदेह यह

कहा जा सकता है कि एशिया प्रशान्त क्षेत्र मनोरंजन के लिहाज से विश्वभर में काफी अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है।

समग्र रूप से देखा जाए तो यह कहा जा सकता हे कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग के मुख्यत: दो स्वरूप हैं- एक मनोरंजन और दूसरा समाचार मनोरंजन क्षेत्र, विज्ञापन के लिहाज से काफी आकर्षक है और यह देश में आज प्रतिवर्ष करीब 26 हजार करोड़ रू. की राशि के विज्ञापन बटोर रहा है, जबकि समाचार से जुड़ा मीडिया 17 हजार करोड़ रू. के लगभग विज्ञापन जुटा रहा है। 17 फरवरी, 2009 को फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) और के.पी.एम.जी. नामक सलाहकार कम्पनी द्धारा जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार आज अमरीका के बाद न्यूज का दूसरा बड़ा बाजार भारत बन गया है।

भारत में अभी प्रिंट मीडिया से 60 हजार अखबार जुड़े हुए हैं और 67 न्यूज चैनल संचालित हो रहे हैं, उल्लेखनीय है कि आज देश में अखबारों की कुल प्रसारित प्रतियाँ 9.95 करोड़ के करीब है और इनकी दैनिक पाठक संख्या 31 करोड़ के लगभग है, दूसरी ओर 67 न्यूज चैनलों को 11.5 करोड़ से अधिक टीवी सेट पर 58 करोड़ लोग देखते हैं। साथ ही आज देश में मोबाइल फोन भी मीडिया का बड़ा माध्यम बनता जा रहा है।

अनेक मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनियाँ मोबाइल के जरिए खबरें भी प्रेषित करती हैं, गौरतलब तथ्य यह भी है कि मोबाइल ग्राहकों की संख्या के लिहाज से आज भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा आज भारत में 6 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं तथा 13 लाख लोग ब्लॉगर्स बने हुए हैं जो इंटरनेट सर्फिंग के समय प्रसारित की जाने वाली खबरों पर नजर रखते हैं तथा प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते है।



विशेषज्ञों के मतानुसार करीब 12.5 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि करने वाला भारतीय विज्ञापन उद्योग का आज वार्षिक कारोबार 22,800 करोड़ रू. है जो सन् 2010 तक 36,731 करोड़ रू. तक पहुँच चुका है।

भारतीय विज्ञापन उद्योग प्रति चार वर्ष में दोगुनी वृद्धि दर्शा रहा है और इसमें से सबसे अधिक इजाफा टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देखा जा रहा है, लन्दन आधारित मीडिया प्लानिंग एवं एडवरटाइजिंग समूह 'जैनिथ ऑप्टीमीडिया' की रिपोर्ट के अनुसार विज्ञापनदाता द्धारा जब प्रति 100 रू. विज्ञापन पर खर्च किया जाता है, तो 91 रू. टेलीविजन और प्रिंट विज्ञापन पर, 5 रू. आउटडोर विज्ञापन पर तथा शेष 4 रू. अन्य विज्ञापन माध्यमों पर खर्च किया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्लोबल स्तर पर विज्ञापन उद्योग 17 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज कर रहा है।

22

nss

भारतीय मीडिया के विभिन्न संघटकों की सहभागिता (एक नजर में)

संघटक	वर्ष 2006-07	वर्ष 2011-12
1. टेलीविजन	45 प्रतिशत	६१ प्रतिशत
 सिनेगा/फिल्म 	19 प्रतिशत	18 प्रतिशत
3. म्युजिक	02 प्रतिशत	01 प्रतिशत
4. ईवेंट मैनेजमेंट	02 प्रतिशत	02 प्रतिशत
 रेडियो 	01 प्रतिशत	02 प्रतिशत
६. अन्य	३१ प्रतिशत	26 प्रतिशत

Source: www.watplog.com

माध्यम और समाज में परिवर्तन का एक नकारात्मक पहलु-

नकारात्मक दृष्टिकोण से देखे तो मीडिया ने नई पीढ़ी के सामने तर्क, बुद्धि, चिन्तन, मनन एवं मौलिक मानवीय मूल्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है जिसमें मान्यताओं व परम्पराओं को तोड़ने के लिए नए-नए सीरियल लंच व डिनर के साथ-साथ प्रस्तृत हो रहे हैं। लव गुरू मटूक नाथ चौधरी,



गुड़िया की क हानी, धनंजय चटर्जी ऐ से कर्ड उदाहरण है जो बच्चों युवाओं की मानसिकता को प्रभावित कर रहे है। युवा पीढ़ी को साबुन, शैंपू, विज्ञापन एक्शन थ्रिलर दिखाक र जडवत भी तिक वादी सोच की ओर ले जाया जा रहा है। परिवार में अढब

कायदे के अर्थ भी पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थहीन होकर समाजीकरण के पराभव पर प्रभाव डाल रहे हैं।

चमकदार विज्ञापन बाजारवाद के शिकंजे को और भी मजबूत कर रहे है, जिसके प्रभाव से सामान्य वर्ग अपने आपको बहुत छोटा और मजबूर महसूस करने लगता है, अर्निद्धन्द में लाकर रखता है, जो सच नहीं है उसे ही सच करके दिखाया जा रहा है। दृश्य मीडिया का टेलीविजन छोटा परदा एक प्रभावी माध्यम है। इसने न केवल हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को प्रभावित किया है अपितु, व्यक्ति की अस्मिता और उससे भी आगे प्रतिदिन बालात्कार, सेक्स कॉलगर्ल तथा हर क्षेत्र में महिलाओं का शोषण नारी अस्मिता पर दोयम श्रेणी की मानसिकता को चित्रांकण कर रहा है।

मीडिया ने अपने अस्तित्व, प्रतियोगितावाद को बचाने के लिए हर उस दृश्य व सामग्री को अपनाया है, जिसे उसने 'आधुनिकीकरण' का जामा पहनाने का नाम दिया है। जो युवक-युवतियों को आधुनिक मानसिकता के बदले रीति-रिवाज व संस्कारों से तटस्थ कर रहे हैं।

इसी के कारण 75 युवा वर्ग अपने ही परिवार में बगावत का बिगुल बजा

रहे हैं। सन् 2006 में किए गए एक सर्वे से यह तथ्य सामने आया कि, मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चे व युवा दृश्य मीडिया से प्रभावित हो आत्महत्या व हत्या करने में भी नहीं हिचकते।

आज मीडिया ने संपूर्ण समाज के लिए अनगिनत चुनौतियां और अनेक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। दिखाए जाने वाले बहुचर्चित सीरियल्स आम आदमी की स्थिति, पेंडुलम की तरह कर जीवन मूल्यों में टकराहट पैदा कर पथभ्रष्टता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

जो निराशा व हताशा को जन्म दे रहे हैं क्योंकि मध्यमवर्ग जीवन में कुछ एवं परदे पर कुछ और देख रहा है। जीवन के सारे मूल्य संक्रमित हो रहे है। फास्ट फुड कल्चर एवं पारिवारिक संबंधों की विकृति व प्रदूषण (विवाह तलाक बहुविवाह) आने वाली पीढ़ी इसे स्वच्छंद मानसिकता व अधिकार के रूप में देख रहा है।

नई तकनीकी का एक नकारात्मक पहलू जिसने परिवार एवं समाज पर जो नकारात्मक प्रभाव डाला है वह हैं सामाजिक संबंधों में दूरियाँ। अब व्यक्ति एक दूसरे के घर आते जाते नहीं है, जबिक सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने की विवशता आपसी प्रेम, प्रगादता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं।

हाल ही के वर्षों में दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों ने बड़ी संख्या में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। वहीं उसने दूसरी और लोगों के बीच सम्बन्धों को कमजोर किया है। इसका प्रभाव परिवारों एवं समाज पर कैसा पड़ेगा यह तो आने वाला भविष्य ही बतायेगा।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि मीडिया बाजार के दबाव में है जबकि आवश्यकता है बाजार में दबाव बढ़ाने की। माध्यमों की एक सामाजिक भूमिका है, इसे जिम्मेदार, महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक बनाने के लिए इन्हें कठपुतली की भूमिका परिधि से निकलकर सही अर्थों में सामाजिक भूमिका अदा करनी होगी, जो सामाजिक मानसिकता को विकृत होने से बचाने के साथ–साथ भारतीय संस्कृति सभ्यता को स्थापित कर सकें। मीडिया का सामाजिक दायित्व अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ने नहीं देना एवं सामाजिक, नैतिक मूल्यों की रक्षा करना है।

वह यह कह कर मुक्ति पा सकता की जैसा समाज है, वैसा ही वह दिखा, पढ़ा रहा है। यदि साहित्य समाज का दर्पण है तो दर्पण की मैला नहीं होने देने एवं समाज के चेहरे पर कालिख नहीं लगने दने की कुछ प्रतिशत जिम्मेदारी मीडिया की है। अत: मीडिया को प्रोद्यौगिकी एवं विज्ञान का सही इस्तेमाल कर लोगों को नई जानकारियाँ देना, प्रश्नों के प्रति जागरूक बनाना है। ''सामाजिक प्राणी'' होने के नाते, सामाजिक सम्बन्धों को जीवित रखना अनिवार्य हैं, अन्यथा आदमी एकाकी हो जायेगा, समाज बिखर जायेगा। अत: नीति निर्धारित करने वालों को यह भी सोचने की जरूरत है कि मीडिया की दिशा क्या हो। ''स्थायित्व सहभागिता के स्वरूप और उसकी गुणवत्ता से आता है। क्या सोशल मीडिया की भाषा बदलाव की भाषा बन पायेगी ? यदि हाँ तो फिर किस तरह का बदलाव ? यह जानने के लिये भी हमें प्रतीक्षा करनी होगी।''

सन्दर्भ अध्ययन -

- 1. स्वामी रंगनाथानंद, परिवर्तनशील समाज के लिये शाश्वत मूल्य रामकृष्ण, नागपुर।
- 2. दैनिक अखबारों की सुर्खिया एवं लेख।
- इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली।
- एकेडेमी ऑफ रेडियो मेनेजमेंट दिल्ली
- पायनियर मीडिया स्कूल नई दिल्ली के बुलेटिन

ากรร

सेवा कर राजस्व -एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सपना सोनी *

प्रस्तावना :- भारतीय कार्य-बल में कृषि व उद्योग की अपेक्षा सेवा क्षेत्र तेजी से उभर रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी व आविष्कारों के चलते आई सूचना क्रांति ने इस क्षेत्र को तीव्र गति प्रदान की है। सेवा क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 10% के लगभग है। यह क्षेत्र कुल रोजगार का लगभग 35% रोजगार उपलब्ध कराता है। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 60% तथा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 55.6% भाग सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में आता है जबिक आजादी के समय यह मात्र 15% था। इन सेवाओं पर लगने वाले कर से लगभग 80000 हजार करोड़ रूपया का राजस्व प्राप्त होता है। जिस प्रकार वस्तुओं के विक्रय पर विक्रयकर लगाया जाता है। इसी प्रकार सेवाओं के प्रदायगी पर लगाया जाने वाला कर सेवाकर कहलाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसकी वसूली केन्द्र सरकार का उत्पाद व सीमा शुल्क विभाग सेवा प्रदाता से करता है किन्तु इसका अंतिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है। आउसोर्सिंग ने सेवा क्षेत्र को नवीन ऊंचाइयाँ प्रदान की है। टेलीकॉम, शिक्षा, बैंकिग, बीमा तकनीकि परामर्श, वित्तीय व विधिक परामर्श, चिकित्सीय सेवाओं आदि ने भारत को सेवा बाजार में अंतराष्ट्रीय पहचान दिलाई है।

सेवा क्षेत्र से जुड़े वृहद मानव बल व इस क्षेत्र की भावी संभावनाओं को देखते हुए भारत में सेवाकर का प्रारंभ 1994 में तीन सेवाओं अंशो की दलाली, टेलीफोन बिल, व सामान्य बीमा प्रीमियम को सम्मिलित करते हुए, किया गया, यह कर जम्मु एवं कश्मीर में प्रदान की गई सेवाओं को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लगता है इस कर की दर शुरूआती वर्षो में 5 प्रतिशत थी, जो सन् २००४-०५ में 10 प्रतिशत और 2006-07 से 12 प्रतिशत 2008 की वैश्विक मंदी को देखते हुए 10 प्रतिशत कर दी गई, वैश्विक मंदी का असर पूरे भारत पर रहा उसके बावजूद हमारी विकास की दरें 7 से 9 प्रतिशत के बीच रही इस दर को बनाये रखने में सरकार की मौद्धिक नीति एवं वित्तीय नीतियों के साथ इस सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कर की दृष्टि से प्रतिवर्ष नवीन सेवाओं को दायरे में लाया जाता रहा। जिनकी संख्या गतवर्ष तक लगभग 125 थी। वर्तमान में 17 सेवाओं को छोडकर समस्त सेवाएँ सेवा कर के दायरे में है। मार्च 20 12 कर की दर में 2% का इजाफा कर इसे 10% से 12% कर दिया गया है। एक अनुमान के अनुसार सरकार को इससे 19000 करोड़ रू. के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य -

- 1– सेवा कर से प्राप्त राजस्व की जानकारी लेना
- 2- सेवा कर की विभिन्न मढ़ों का तुलनात्मक अध्ययन कर अधिकतम राजस्व प्रदान करने वाली सम्भावी मढ़ों को ज्ञात करना एवं आवश्यक सुझाव देना।
- 3- सेवा कर की दरों में तीन वर्ष के अंतराल पर ही पुन: वृद्धि करने की आवश्यकता क्यो महसूस हुई, को जानने का प्रयास करना।

शोध कार्य पद्धति -

प्रस्तुत शोध पत्र द्धितीय समंकों व सूचनाओं, इंटरनेट, विभिन्न विभागों, सम्बन्धित पुस्तकों तथा शोध-पत्रिकाओं एवं इससे जुड़े अन्य साहित्य का अध्ययन कर संकलित की गई। समंको के संकलन के आधार पर अध्ययन के 1994-95 से 2010-2011 वर्ष तक के सेवा राजस्व को जानने के प्रयास किया गया है तथा तुलनात्मक अध्ययन के 2008-09 से 2010-2011 वर्ष को विश्लेषण का आधार बनाया गया है क्योंकि इस अविध में सेवा कर की दर को सन् 2008-09 में 12 से 10 प्रतिशत घटाकर तथा मार्च 2012 में पुन: 10 से 12 प्रतिशत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? को जानने का प्रयास किया गया। एवं सरकार को किन सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र -

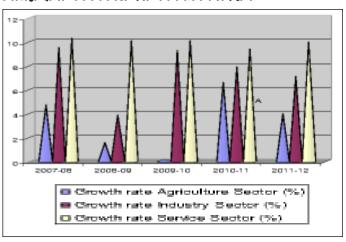
सेवा क्षेत्र की गत 5 वर्षों की वार्षिक वृद्धि दर पर नजर डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर उद्योग व कृषि क्षेत्र से बेहतर व स्थिर रही है।

वर्ष	क्षेत्रवार विकास दरे					
	क्षि क्षेत्र (%)	उद्योग क्षेत्र (%)	सेवा क्षेत्र (%)			
2007-08	4.7	9.5	10.3			
2008-09	1.6	3.9	10.1			
2009-10	0.2	9.3	10.1			
2010-11	6.6	7.9	9.4			
2011-12	4.0	7.1	10			

स्त्रोत – इकोनामिक आउटलुक रिपोर्ट 2011–12

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि सेवा क्षेत्र औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर से अधिक है। वर्ष 2010-11 में कृषि व उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर जहाँ क्रमश: 6.6 और 7.9 रही वही 2011-12 में 4 प्रतिशत एवं 7.1 प्रतिशत रही है। इन क्षेत्रों में प्रतिशत दर में कमी आयी है। जबिक सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 10 प्रतिशत रही जबिक भविष्य में इसके और अधिक होने की संभावना है।

विभिन्न क्षेत्रों की विकास दरों का चित्रमय प्रदर्शन





येता कर गानस्त -

अग्र तालिका के अंतर्गत प्राप्त सेवा कर राजस्व व सेवा कर दाताओं की प्रगति को आसानी से समझा जा सकता है।

वर्ष	कर	कर दावरे में	राजस्व		कर	दाता
	बर	आनेवाली	₩.	गतवर्ष की	करदाताओं	गतवर्ष की
		सेवाओं की	करोड	त्तलना में	की संख्या	तुलना में
		संख्या	में	% वृद्धि		% वृद्धि
1994-1995	5%	3	410	Base Year	3943	Base Year
1995-1996	5%	6	846	106	4866	23.41
1996-1997	5%	6	1022	21	13982	187.34
1997-1998	5%	18	1515	48	45991	228.93
1998-1999	5%	26	1787	18	107479	133.7
1999-2000	5%	26	2072	16	115495	7.45
2000-2001	5%	26	2672	23	122326	5.91
2001-2002	5%	41.	3305	26	187577	53.34
2002-2003	5%	52	4125	25	232048	23.71
2003-2004	5%	62	7890	91	403856	74.04
2004-2005	10%	75	14196	80	774988	91.89
2005-2006	10%	84	23053	62	846155	9.18
2006-2007	12%	99	37482	63	940641	11.17
2007-2008	12%	100	51133	36	1073075	14.08
2008-2009	12%	106	60702	19	1204570	8.78
2009-2010	10%	117	58336	-3.9	1307286	8.53
2010-2011	10%	120	71190.5	22	-	-

सेवा कर से प्राप्त राजस्व व सेवा करदाताओं की प्रगति को तालिका 1 से समझा जा सकता है। सेवा करदाताओं व राजस्व में निरंतर वृद्धि होती रही है। वर्ष 1994 में 3943 करदाताओं से कुल 410 करोड़ रू. का कर राजस्व प्राप्त हुआ जो 3 सेवाओं के बदले था। इनमें निरंतर वृद्धि होती रही। गतवर्ष तक सेवाओं की संख्या 3 से 125 तक पहुँची जबिक वर्तमान में 17 सेवाओं को छोडकर समस्त सेवाएँ कर दायरे में है।

वर्ष 2009–10 में प्रथम बार कर प्राप्ति ऋणात्मक रही (-3.9), जिसका मुख्य कारण कर दर का गतवर्ष अधिक (12%) होना था। 2010–11 में सेवाकर से कुल प्राप्ति 71190 करोड़ रू थी जो 2011–12 में लगभग 82000 करोड़ रूपए रही। भविष्य में रोजगार की नयी असीम संभावनाएँ दृष्टिगोचर होती है जिससे करदाताओं व राजस्व में ओर वृद्धि का अनुमान है। वर्तमान में सेवा कर की दर बढ़ाकर 12% कर दी गई है एजुकेशन सेस और उस पर सरचार्ज के बाद यह 12.36% प्रतिशत होगा।

सेवा कर, राजस्व प्राप्ति व भावी संभावनाओं का तुलनात्मक अध्ययन –

विश्व में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या व उनकी आवश्यकताएँ कुशल पेशेवर सेवाओं की मांग करते है। भविष्य में ढूरसंचार, उपभोक्ता सेवाएँ, प्रबंध परामर्श, बैंकिंग व बीमा सेवाएँ, वित्त व लेखा संबंधी सलाह, कानूनी परामर्श, एनीमेशन/मल्टीमीडिया, फैशन व फोटोग्राफी, स्वास्थ्य, जैव प्राद्योगिकी, शिक्षा आदि तमाम क्षेत्रों में सेवा विशेषज्ञों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएँ है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन क्षेत्रों का भारतीय सेवा बाजार वैश्विक स्तर का हो चला है कारण कि भारत में अपेक्षाकृत सस्ता व स्तरीय मानव श्रम सहज ही उपलब्ध हो जाता है।

भारतीय बौद्धिक सम्पदा विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी है, हम विश्व में अग्रणी स्थान रखते हैं। नाश्काम की एक रिपोर्ट में वर्ष 2004-05 में भारत को सॉफ्टवेयर के निर्यात से 18 अरब रूपए की आय हुई जो बढ़कर 2012 तक 50 अरब होने की संभावना है। वर्ष 2006-07 में सेवा निर्यात की वृद्धि दर जहाँ 14% थी वहीं अब हमारी वृद्धि दर 26% के लगभग है, जो कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अधिक रही। यह अर्थव्यवस्था का तेजी से उभरता क्षेत्र है इसके वृहद दायरे के कारण इससे प्राप्त होने वाले रोजगार व

प्राप्त राजस्व में अपार संभावनाएँ निहित है।

गत तीन वर्षों के सेवाकर से प्राप्त राजस्व के आकड़ों का अध्ययन किया जाए तो यह अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष 2008-09 में सेवा कर दर 12% थी जबकि वर्ष 2009-10 व 2010-11 में यह दर 10% रही। जिसका सीधा असर राजस्व प्राप्ति पर हुआ फलस्वरूप 2009-10 में राजस्व प्राप्ति पर हुआ फलस्वरूप 2009-10 में राजस्व प्राप्ति 2008-09 की अपेक्षा कम रही। वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक लगभग 120 सेवाओं पर सेवा कर वसूला गया। संदर्भित संमकों का अध्ययन करने पर काफी हद तक भावी तस्वीर साफ होती है। प्रस्तुत शोधपत्र में सेवाओं की प्रवृति (Trends) का अध्ययन व विश्लेषण करने के लिए "प्राप्त राजस्व के आधार पर" इन सेवाओं को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है जो निम्न है -

- 1. राजस्व प्राप्ति के हिसाब से प्रथम दस सेवाएँ।
- 2. सेवाएँ जिनमें उल्लेखनीय वृद्धि दर रही।
- सेवाएँ जिनमें वृद्धि दर बढ़ते क्रम में रही।
- सेवाएँ जिनमें वृद्धि दर घटते क्रम में रही।
- 5. सेवाएँ जिनमें वृद्धि दर धनात्मक से ऋणात्मक रही।
- 6. सेवाएँ जिनकी राजस्व प्राप्ति दर ऋणात्मक रही।
- 7. सेवाएँ जिनकी राजस्व प्राप्ति दर ऋणात्मक से धनात्मक रही।

सेवाओं के इस विश्लेषण को सहजता से समझने के लिए तालिका क्रमांक 3 में इन सेवाओं को स्पष्टत: श्रेणीवार व्यस्थित किया गया है। सभी सेवाओं का उल्लेख न करते हुए प्रत्येक श्रेणी की कुछ विशिष्ट सेवाओं को तालिका– 1 में दर्शाया गया है। (पीछे पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रमांक 1 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि-

1-विश्लेषित अविध में प्रथम बारह सेवाओं का प्रत्येक वर्ष का राजस्व 4 हजार करोड़ रूपए से अधिक रहा। 120 सेवाओं से प्राप्त कुल राजस्व का 50: इन्हीं सेवाओं से प्राप्त होता है। जबिक 1/4 अर्थात् 25% प्रारंभिक 4 सेवाओं टेलीकाँम, बैंकिंग, बिजनेस सर्पोटेड सर्विसेज व बीमा से ही प्राप्त हो जाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सेवाएँ भविष्य में राजस्व प्राप्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2008-09 व 2009-10 में जहाँ प्रथम दस सेवाओं की सूची कुछ फेरबदल के साथ अपरिवर्तित रही वहीं 2010-11 में दो नवीन सेवाओं ने इस सूची में स्थान बनाया।

वर्क्स कान्ट्रेक्ट सर्विसेज 67.51% व बिजनेज सपोर्ट सर्विसेज 38.93% वृद्धि दर के साथ क्रमश: 5 वें और 9 वें स्थान पर पहुँच गयी। कंसिल्टंग, इंजीनियरिंग व इंश्योरेंस सर्विसेज न्यूनतम वृद्धि दर के कारण इस सूची से बाहर हो गयी किन्तु कुल राजस्व मात्रा के आधार पर ये सेवाएँ अभी भी शीर्ष सेवाओं की सूची में है। प्रारंभिक 12 सेवाओं में बैकिंग सर्विसेज, इन्श्योरेंस आग्जिलरी सर्विसेज, वर्क्स कान्ट्रेक्ट व बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज ने कर की दर में कमी पर भी सकारात्मक प्रदर्शन किया।

बैंकिंग सर्विसेज की प्रगति दर धीमी रही पर इन सेवाओं ने अपना स्थान बनाए रखा। वर्क्स कान्ट्रेक्ट सर्विसेज व बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज का



प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। इंश्योरेंस आग्जिलरी सर्विसेज भले ही प्रथम दस की सूची से बाहर हो गई, किन्तु उनकी प्रगति दर धनात्मक ही रही जो भविष्य में उनकी प्रगति के लिए सकारात्मक संकेत है।

2- तालिका अनुसार क्रमांक 13 से 15 के सेवा प्रक्षेत्र जिनमें विधिक परामर्श सेवाएँ, कॉस्मेटिक्स सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी ट्रांसपोर्ट ऑफ कोस्टल गुड्स सर्विसेज है, इनकी प्रगति आश्चर्यजनक रही है। प्लास्टिक सर्जरी से प्राप्त रेवेन्यु 2009-10 में 5.85 करोड रू. था, जो 1220% बढ़कर 77.23 करोड़ रूपए हो गया। इसी प्रकार गतवर्ष की तुलना में लीगल कंसल्टेंसी में 260% व ट्रांसपोर्ट आफ कोस्टल गुड्स सर्विसेज में 154% राजस्व वृद्धि रही।

3- तालिका अनुसार सेवा प्रक्षेत्र क्रमांक 16 से 22 जिनमें, खनन सेवाएँ (तेल व गैस) सिक्युरिटी एजेंसी, रिक्नाइजड एसोसिएशन, केबल आपरेटर, ऑनलाइन इन्फोमेशन, C & F एजेण्ट, सर्विस स्टेशन, टी.वी. रेडियों प्रोग्राम, विलनिंग सर्विसेज, वलब एण्ड एसोसिएशन, साइट प्रिपरेशन, रिकवरी एजेंट आदि जैसी सेवाएँ सकारात्मक वृद्धि दर के साथ प्रगति कर रही है। कर की दर 12% से 10% होने पर भी उनसे प्राप्त कर राजस्व में गिरावट नहीं आई, विपरीत इसके उनकी राजस्व वृद्धि दर गत वर्ष की तुलना में अधिक थी अर्थात् इन सेवाओं में सकारात्मक रूख दृष्टिगोचर होता है।

4- तालिका अनुसार सेवा मद 23 से 28 जिनमें रेल ट्रेवल एजेण्ट, एसेट मैनेजर, ट्रांसपोर्ट आफ पर्सन बाय क्रुजिशप में रही। ये सेवाएँ जिनमें वर्ष 2008-09 की सेवाकर दर 12% से 2009-10 में 10% होने पर भी 2010-11 में हुई वृद्धि दर, 2009-10 में हुई गतवर्ष की वृद्धि दर घटती हुई थी, जबिक 2009-10 व 2010-11 में कर की दर समान (10%) थी। कार्गो हैंडलिंग्स सेवाओं से 2009-10 में गतवर्ष की तुलना में 980% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ जबिक 2010-11 में इनकी राजस्व वृद्धि दर 10.25% ही रही।

5 – तालिका क्रमांक 29 से 33 में वर्णित सेवा प्रक्षेत्र जिनमें एटीएम आपरेशन मैनेजमेंट और मेंटेनेंस, आकशनर्स सर्विसेज, फ्रेचाइंजी सर्विसेज, स्टाक ब्रोकर, इंटरनेट टेलीफोन, पब्लिक रिलेशन सर्विसेज, शेयर ट्रांसफर सर्विसेज, सर्वे व मेंपिग सर्विसेज आढि सेवाओं से 2009–10 में राजस्व प्राप्ति गतवर्ष की तुलना में वृद्धि लिए हुए थी जबिक 2010–11 में इनसे प्राप्त राजस्व ऋणात्मक स्थिति में पहुँच गया अर्थात् गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष इनसे प्राप्त राजस्व कम रहा।

6- तालिका अनुसार क्रमांक 34 से 38 के अंतर्गत वर्णित कास्ट एकाउण्ट, साइंटिफिक व टेक्नालॉजी कंसलटेंसी सर्विसेज, शिप मैनेजमेंट, अण्डरराइटर, आनलाइन पोल कुछ ऐसी सेवाएँ रही जिनमें प्रतिवर्ष राजस्व वृद्धि दर ऋणात्मक ही रही है। कास्ट एकाउण्ट से राजस्व प्राप्ति अत्यधिक ऋणात्मक रही थी वर्ष 2009-10 में 50% व 2010-11 में 27% तक गिर गयी। इन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

7- तालिका अनुसार क्रमांक 39 से 43 के अंतर्गत वर्णित कंस्ट्रवशन ऑफ रेसीडेंसियल सर्विस, कमर्शियल कंस्ट्रवशन पोर्ट सर्विसेस प्रमुख थी, की वृद्धि दरें ऋणात्मक से धनात्मक की ओर परिलक्षित हुई।

8- तालिका अनुसार क्रमांक 44 के अंतर्गत वर्णित इनमें तालिका में दी सेवाओं के अतिरिक्त इंटरनेट कैफे, पंडाल शामियाना, फोटोग्राफी, एयरपोर्ट सर्विसेज, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट, बिजनेस एक्जीबिशन, इंडस्ट्रीयल कन्ट्रक्शन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंसियल कॉम्पलेक्स, साइबर कैफे इायक्लिनेंग, ब्युटीपार्लर, हेल्थ एण्ड फिटनेस, स्टोरेज/वेयर हाउसिंग आदि

सम्मिलित है। इनकी संख्या लगभग 50 है। इन सेवाओं से प्राप्त कर राजस्व में 2009-10 में कमी जबकि 2010-11 में प्रगति देखी गयी।

सुझाव: – सेवा कर दायरा नवीन व वृहद किया जा चुका है। कर की दर भी 2% बढ़ा दी गयी है। निश्चित रूप से यह सेवा कर राजस्व को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। सेवा कर से राजस्व में वृद्धि हेतु सेवा क्षेत्र को न केवल आगे बढ़ाते रहना होगा अपितु उसे मजबूत भी करना होगा। इस हेतु निम्न सुझावों पर अमल किया जाना चाहिए –

- (1) सूचना प्रौद्योगिकी का समग्र विकास किया जाना चाहिए। देश के छोटे से छोटे गाँव/कस्बे में भी सूचना प्रौद्योगिकी की पहुँच हो जिससे ग्रामीण कुशल पेशेवर मानव संसाधन सस्ते दामों पर उपलब्ध हो।
- (2) प्रयास किए जाने चाहिए कि बैकिंग, बीमा, परिवहन इंटरनेट जैसी मूलभूत सेवाएँ गांवो में मजबूत पकड बना ले अन्य सेवाओं का विकास स्वतः ही हो जाएगा।
- (3) सेवा प्रदाताओं का सर्वेक्षण कर पूर्ण पारदर्शिता के साथ वस्तुस्थिति को ज्ञात किया जाना चाहिए जिससे नवीन सेवाएँ व चूक करने वाले करदाताओं का पता लगाया जा सके।
- (4) सेवाकर के भुगतान व कर संबंधी समस्त कार्यों के लिए इलेक्ट्रानिक सिस्टम तैयार किया जाना चाहिए व स्टॉफ को कार्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- (5) ऐसी सेवाएँ जिनकी राजस्व वसूली कम होती जा रही है, कमी के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। व सुधार के प्रयास लिए जाने चाहिए।
- (6) सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर निरंतर बढ़ती रहे इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- (7) सेवा कर के प्रशासन, निर्धारण एवं वसूली उत्पाद शुल्क विभाग ही करता है इस विभाग के अपने स्वयं के दायित्व निर्धारित है अतः कार्यभार की अधिकता को देखते हुए प्रभावी क्रियान्वयन एवं नियंत्रण हेतू पृथक अधिनियम व विभाग की स्थापना की जानी चाहिए।
- (8) सेवा संबंधी लंबित विवादों को न्यायालय द्धारा शीघ्र हल किया जाना चाहिए।
- (9) सेवाओं के प्रतिफल के बदले में होने वाले व्यय पर कटौती नहीं दी जाती है। अत: आयकर की भ्रांति ही सेवा व्यय की कटौती का प्रावधान निर्धारित है।

निष्कर्ष: – हमारे राष्ट्र का वृहद जनसांख्यिकीय आकार व उसकी अतुल्य बौद्धिक क्षमता सेवा क्षेत्र में असीम संभावनाओं के लिए एक मजबूत मंच तैयार करती है। उदारीकरण व वैश्वीकरण के इस युग में जहाँ वैश्विक सीमाएँ अपना अस्तित्व खोती जा रही है, भारत का कुशल कार्यबल उसे ऐसी स्थिति में ला सकता है जहाँ वह सम्पूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करता नजर आएगा। सेवा क्षेत्र व इससे प्राप्त कर राजस्व भारतीय राजस्व और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों ही के लिए मुख्य आधार होगा।

टेलीकॉम, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यवसाय सहायक सेवाएँ, इंटरनेट, सेवा क्षेत्र का आधार है। जैसे ही ये सेवाएँ स्वयं को स्थापित करेगी अन्य क्षेत्रों के लिए भी द्धार खुल जाएगें और इनका भी विकास संभव होगा अर्थात् अन्य सेवाएँ स्वतः ही इनके साथ हो जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि इन सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

संदर्भ सूची -

Economic Survey Report 2011-12 www.servicetax.gov.in www.taxindia.com कराघात एवं करापात -डाँ. विनोद त्रिपाठी -ISBN- 978-81-92425





(Table 1.) Comparison of Service wise Revenue (Rs. in Crore)

N.	gervices	Revenue	Kit	Revenue	/Deares	Increase	Ka	Davianus	,	Decrease	Dont
М.		Kevenue	nk	Kevenue	/Decreas e	Decrease %	nk	Revenue	Decreas e	%	Rank
1	Telecom	5853.97	I	4031.04	-1822.93	-31.14	П	4734.98	703.94	17.46	I
2	Busi Aux. Services	4130.76	II	3642.56	-488.2	-11.81	Ш	4202.86	560.3	15.38	Ш
3	Banking & others	3914.32	III	4063.58	149.26	3.81	1	4344.59	281.01	6.91	II
4	Insurance	3876.57	IV	3125.49	-751.08	-19.37	IV	3876.57	751.08	24.03	IV
5	GTO/GTA	3211.82	V	2628.62	583.2	-18.16	V	3027.7	399.08	14.87	VI
6	Renting of Immovable Property	2577.14	VI	2015.05	-562.09	-21.81	Х	2829.24	814.19	40.4	VIII
7	Maint & Repairs	2280.31	VII	2207.2	-63.11	-2.76	VI	2522.38	305.18	13.76	X
8	Coas. Engineer	2257.73	VII I	2077.76	-179.97	-7.97	VI II	2095.92	18.16	0.87	-
9	Manpower Requirement Agency	2097.52	IX	2077.4	-20.12	-0.95	IX	2869.87	792.47	38.15	VII
10	Insurance Aux. Services	2086.96	Х	2126.23	39.26	1.88	VI I	2185.28	59.06	2.78	-
- 11	Works contract	1305.97	-	1845.89	539.92	41.34	-	3092.08	1246.19	67.51	V
12	Business support Services	1603.23		1935.29	332.06	20.71		2688.86	735.57	38.93	IX
	Total of Top 10 Services										
13	Cosmetic Surgery or Plastic Surgery Services			5.85		•		77.23	71.38	1220.17	2. चल्लेखनीय
14	Legal consultancy services	-	-	54.11	-		-	195.08	140.97	260.52	वृद्धि
15	Transport & coastal goods	•		76.66	•			195.17	118.51	154.59	
16	Mining of Mineral oil/ gas	822.69		1059.15	236.46	28.74		1632.15	573	54.09	3.
17	Security Agency	830.91		1046.55	215.64	25.95		1359.66	313.11	29.91	वृद्धि दर
18	Recognised registered Association	18.25		23.17	4.92	26.95		32.32	9.15	39.49	बद्धते क्रम में
19	Cable Operator	51.63		56.3	4.67	9.04		80.63	24.33	43.21	
20	Transport of goods in container	112.65		119.24	6.59	5.85		134.71	15.47	12.97	
21	Online information	353.94		370.99	17.05	4.82		409.49	38.5	10.37	
22	C & F Agent	375.97		381.83	5.86	1.56		436.96	55.13	14.44	
23	Rail Travel Agent	5.16		13.01	7.85	152.13		13.78	0.77	5.91	_4.
24	Asset Manager	1.33		4.19	2.86	215		6.1	1.91	45.58	वृद्धि वर
25	Transport of Persons by cruiseship	0.81		1.49	0.68	83.95		1.57	0.08	5.36	घटते क्रम में
26	Cargo Handling	44.79		484.01	439.22	980.62		533.61	49.6	10.25	
27	Supply of Tengible goods, Equipments	458.35		989.53	531.18	53.68		1042.73	53.2	5.38	
28	Information Technology	868.41		1529.53	661.12	76.13		1742.53	213	13.93	
29	On life Insurance	42.79		241.64	198.85	464.71		157.93	-83.71	-34.64	5.
30	Auctioneer Services	8.16		19.32	11.16	136.76		15.39	-3.93	-20.34	धनात्मक से ऋणात्मक
31	ATM Operations, Maitenance, Managt.	58.67		59.37	0.7	1.19		56.73	-2.64	-4.44	-व⊝-।।१.चयः
32	Franchise Services	132.26		169.35	37.09	28.04	_	147.25	-22.1	-13.05	
33	Stock Broker	795.26		1000.32	205.06	25.79		926.6	-73.72	-7.36	
34	Under writer	14.65		6.45	-8.2	-55.97		4.89	-1.56	-24.19	6. ऋणात्यक ही रही
35 36	Cost A/c Scientific or Technology	10.82 365.28		5.36 309.72	-5.49 -55.56	-50.74 -15.21		3.91 292.01	-1.45 -17.71	-27.05 -5.72	iĝi vaĝi
30	Consultancy Services	0.54		0.35	0.33	40.01		0.27	8.88	20.11	
37	Mech. slaughter Ship Managemet Services	0.54		0.32	-0.22	40.74		0.23	-0.09	-28.13	
39	Construction of	70.9 369.14		65.85 262.35	-5.05 -106.79	-7.12 -28.92		62.81 1145.63	-3.04 883.28	-4.62 336.68	7.
40	Residential Services Commercial or Industrial	1809.12		1580.12	-228.31	-12.61		1825.08	244.09	15.43	ऋणात्यक से धनात्मक
41	Construction Commissioning & Instalation	1547.5		1450.35	-97.15	-6.27		1745.63	295.28	20.35	
42	Managt, consultant	1801.26		1597.79	-203.47	-11.29		1785.39	187.6	11.74	1
43	Port Services	1068.05	\vdash	1030.34	-205.47	-3.53		1194	164.41	15.96	1
44	All Other Services	13466.3		12536.38	-01111	-0400		15193.02	107171	20.00	8.
╨											अन्य सेवाई
	TOTAL REVENUE	60701.89		58336.74	-2365.15	-3.9		71190.5	12853.76	22.03	

nss

महाराजा शिवाजी राव होलकर का वैभव - ''दरिया-महल''

डॉ. मंगला ठाकुर *

बड़वाह की मानचित्र में भौगोलिक स्थिति 22° 15" उत्तर तथा 76° 02" पूर्व हैं। 11 मध्यप्रदेश की जीवन दायिनी पतित पावनी नर्मदा के उत्तर पूर्वी छोर पर मात्र 04 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं। उज्जैन-खण्डवा मीटर गेज रेल्वे लाईन यहाँ से गुजरती है।

प्रकृति ने अपने – वरदानों की बड़वाह को मुक्त – हस्त सौगात दी हैं। धीर गंभीर नर्मदा, चंचल, चपल उफनती पहाड़ी नदी चोरल एवं बड़ाली, वन्य प्राणियों से युक्त विनध्य पर्वत के पठार कल – कल करते झरने सरोवर, शान्ति सुरम्य वातावरण के साथ नर्मदा के मोक्षमार्गी उत्तर तट पर स्थित पौराणिक एवं अत्याधूनिक कई छोटे – बड़े आश्रमों एवं सिद्धमठों की श्रृंखला विद्यमान है।

बड़वाह नगर के पूर्व में चोरल नदी के पूर्वी तट मॉ जयंती का ख्याति प्राप्त मनोकामना पूर्ण करता प्राचीन मन्दिर हैं, वही नगर के मध्य भूत-भावन भगवान महादेव भोले का मंदिर नागेश्वर कुण्ड अपनी विशिष्ट संरचना के लिये प्रसिद्ध हैं, जिनका बड़वाह वासियों पर वरद हस्त रहा है।

बड़वाह का प्राचीन नाम बाबुली खेड़ा, तत्पश्चात् जैतगढ़ या जैतपुरी भी रहा हैं। जैतगढ़ किले होने के अवशेष आज भी जंयित माता मंदिर के समीप विद्यमान हैं। सत्रहरवीं शताब्दी में तोमर वंश के राणा दुर्जनसाल ने 1646 ईस्वी में परगना जैतपुरी (बड़वाह) की जमीदारी मुगल सम्राट शारजहाँ के शासन काल में प्राप्त की थी।⁽²⁾

1710-11 में राणा जयमल को मुगल सम्राट बहादुरशाह द्धारा परगना जैतपुरी के आस-पास का क्षेत्र उपहार स्वरूप दिया गया, जिसे उन्होनें ''बइवाह'' के नाम से आबाद किया।⁽³⁾

नगर के पूर्व में ''बड़ाली'' नदी के प्रवाहित होने से जैतपुरी, वर्तमान में बड़वाह नाम से जाना जा रहा है। एक अन्य मत के अनुसार बड़ अर्थात वट वृक्ष की अधिकता के कारण इस करने का नाम बड़-वाह! हो गया।

दिया महल, बड़वाह के पूर्व मे, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नर्मदा में समाहित चोरल नदी के पश्चिमी तट एवं बड़ाली नदी के पूर्वी दिशा पर निर्मित है। नदी को फारसी में दिया कहा जाता हैं, चूंकि यह महल इसके किनारे स्थित हैं, इसलिए इसे दिया-ए-महल कहा जाता था, जो कालान्तर में दिखा महल के नाम से विख्यात हो गया। इसका निर्माण होलकर शासक महाराजा शिवाजीराव (1886–1903) द्वारा बनवाया गया था। (4) महाराजा, होलकर शासको में विख्यात भवन निर्माता थे। बड़वाह में नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर 'नर्मदा-कोठी' महल का निर्माण करवाया गया था।

दरियाव महल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य-

- दिरया महल का निर्माण महाराजा शिवाजीराव होलकर ने अपनी निजी सम्पत्ति से करवाया था।⁽⁵⁾
- यह विश्राम स्थल (पेलेस) 750 मीटर लम्बा उत्तर से दक्षिण की ओर 123.21 एकड़ में चोरल घाटी के ऊपरी पठार पर स्थित आवसीय भवन था।⁽⁶⁾
- चोरल नदी की सर्पिल बहती धारा के साथ-साथ महल का निर्माण किया गया हैं, इसलिए सरल रेखा में न होकर घुमावदार हैं। यही कारण है कि पूरे महल को एक फोटोग्राफ में लेना असंभव था।
- 4. इस महल का निर्माण खुली नींव (ओपन फाउण्डेशन) पर स्थित लगभग

- 3 फीट ऊँची कुर्सी पर किया गया हैं। नींव ''घटिया'' नामक स्थान के सेंड स्टोन पत्थरों से निर्मित हैं, जो अपनी मजबूती के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। खेड़ीघाट पर स्थित नर्मदा नदी पर ब्रिटिशकालीन मीटरग्रेज रेल्वे पुल भी इन्हीं पत्थरों से बनवाया गया हैं।⁽⁷⁾
- 5. बड़वाह नगर की भूमी चूने की खढ़ानों के लिये प्रसिद्ध रही हैं, इसी चूने का प्रयोग दिखा महल बनाने के लिये किया गया हैं। इसी चूने में सरस, बेलफल, सन, सुर्खी मिलाकर जुड़ाई के लिये मसाला (मार्टर) तैयार किया गया और रेत के साथ 2 : 1 में जुड़ाई एवं प्लास्टर का कार्य किया गया, इस हेतुईटों अथवा पत्थरों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया गया हैं।(8)
- 6. पूरे महल की छत जेक आर्च से निर्मित हैं। पैलेस भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट एवं बेजोड़ नमूना है। महल की साज-सज्जा के लिये विलसियों का प्रयोग बहुतायत किया गया था, जो विदेशों से बुलवाई गई थी। जो एक शताब्दी से वैसे ही हैं (जस की तस)। महल के बाह्य स्वरूप की सजावट के लिये ज्यामिति की सरल रेखाओं का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया हैं, जो मुस्लिम स्थापत्य कला के प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं।
- 7. दिखा महल की बाह्य दिवारें गहरे गेरूवें रंग से और इंगलिश विलिसयों की सफेद रंग से पुताई होती चली आ रही है। प्रमुख महलों के मुख्य द्वार के बरामदों के सामने वाले दोनों स्तम्भों के पत्थर पर आकर्षक एवं कलात्मक नक्काशी की गई हैं।
 - इस महल में 198 कमरें सहित कुल पाँच महल बनें हुए है, महल द्धिमंजिला हैं, जबकि शेष कक्ष भ्रतल पर अवस्थित हैं। इन पॉच महलों में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रथम पेलेस का उपयोग शिकार के लिये ''गाला'' बॉधने एवं अन्य आखेट सम्बन्धित सामग्रियों को रखने के लिये किया जाता रहा हैं। रियासत कालीन आखेट विशेषज्ञ जनाब बाबू शिकारी के अनुसार लगभग 800 से 1000 वाट विद्युत बल्ब से महल को रोशन किया जाता था, जिसकी विद्युत आपूर्ति इंजन से की जाती थी। द्धितीय महल का प्रयोग राजकीय अतिथियों एवं शिकार टोलियों के रहने हेतुकिया जाता था। तृतीय महल महारानी का निजी निवास स्थान था। जिसमें लगभग साढ़े छह फीट की आकर्षक बीन (सपेरे का वाद्ययंत्र) रखी हुई थी। चतुर्थ महल महाराजा का खास-महल था। जिसमें महिफलें एवं अन्य मनोरंजक गतिविधियाँ होती थी। पाँचवा महल राजकीय-सेवकों के लिये प्रयुक्त होता था, यह अकेला महल पत्थरों से निर्मित है, और वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुका हैं।⁽⁹⁾ दरिया महल के ये पॉचों महल, के प्रथम एवं द्धितीय तल में 9-9 कमरें है। 198 कक्षीं सहित मूलरूप से आपस मे जुड़े हुए थे। कक्ष क्रमांक 01 से प्रवेश करने पर भीतर ही भीतर कक्ष क्रमांक 198 कमरो में पहुँचा जा सकता था। कक्षों का औसत क्षेत्रफल 20-30 है। साथ ही चार बड़े सभागृह थे। इस पेलेस मे लगभग 800 लकड़ी (सागवान) के दरवाजे हैं, जिन्हें बन्द करने के लिये डेढ़ फीट लम्बी पीतल की चटकनियाँ लगी हुई हैं। इस प्रकार महल की साज-सज्जा के कार्य हेतुसागवान जैसी मंहगी लकड़ी



एवं धातु के रूप में पीतल का प्रयोग किया गया हैं।(10)

- दिरया महल को अपनी लम्बाई के कारण एशिया की सबसे लम्बें आवासीय भवन होने का गौरव प्राप्त हैं। अपनी वास्तु शिल्प एवं विशिष्ठ निर्माण शैली की यह ईमारत अद्धितीय हैं।⁽¹¹⁾
- 10. पेलेस के पीछे पूर्व की ओर चोरल की सुरम्य वनाच्छिद घाटियों को निहारने के लिये इतना ही विशाल-लम्बा बरामदा भी बनवाया गया था, जो आज भी वैसा ही हैं।
- 11. प्रत्येक महल में ऊपरी मंजिल पर पहुँचने के लिए लकड़ी के घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, जिन पर लकड़ी के हीं रैलिंग हैं, किसी अन्य धातु का प्रयोग नहीं किया गया था। पीछे की ओर बरामदों में भी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। पीछे की ओर बरामदों में भी चमकदार धातु का गोल जीनें (चढ़ाव) बने हुए हैं, जिनसे छत पर पहुँचा जा सकता हैं। उनकी पॉलिश इतनी शानदार हैं कि आज भी वे नवीन से प्रतीत होते हैं।
- 12. महल के पीछे पूर्व की ओर ढलान पर रमणीक, रख-रखाव युक्त बगीचा था। बाग की सुरक्षा (बंबरों से) हेतु लोहे की जॉली से भी कुछ भाग आच्छादित था। बगीचे के ऊपर संगमरमर के छोटे-छोटे अंलकृत छज्जे बने हुए थे। लगभग 60-65 वर्ष पूर्व तक यहाँ रख-रखाव होता था।⁽¹²⁾
- 13. महल एवं बगीचे में पानी की आपूर्ति चोरल नदी से की जाती थी। नदी पर एक स्टॉप डेम भी निर्मित किया गया थां, जो आज भी देखा जा सकता हैं। महल के उपर 2000 गैलन की पानी की टंकियॉ बनाई गई थी। जिनसे पूरे महल में पाईप लाईन के द्धारा जल वितरण होता था, आज भी इन्हीं टंकियों का उपयोग किया जाता हैं। गर्म पानी के स्रोते हेतु बॉयलर की ञ्यवस्था भी थी।
- 14. महाराजा शिवाजीराव होल्कर को यह स्थान अत्यंत प्रिय था, अतः अपने अवकाश के क्षणों को वे यहाँ सुकून एवं शान्ति से जिया करते थे, उन्हें घूमने-फिरने एवं सैर-सपाटे करने का शौक था, ऐसा कहा जाता हैं, कि होलकर राज्य की द्धितीय राजधानी के रूप में इस महल को उपयोग किया जाता था। 31 जनवरी 1903 में महाराजा शिवाजीराव होलकर ने अपने एकमात्र अञ्यस्क पुत्र तुकोजीराव तृतीय के पक्ष में गद्दी का परित्याग कर दिया। महाराजा को रूपयें चार लाख सालाना की दर से पेंशन देना तय हुआ, चूँकि अभी महाराजा तुकोजीराव बालिग नहीं थे। अतः होलकर प्रशासन ''कान्सिल ऑफ रिजेन्सी'' के माध्यम से अंग्रेजों को मिल गया जो 1911 तक जारी रहा था। (13) महाराजा शिवाजीराव ने सेवा निवृत्ति के पश्चात् अपना स्थायी निवास बड़वाह स्थित दरिया-महल को बनाया और मृत्यु पर्यन्त वे यहीं पर रहें (13.10.1908 ई.)।
- 15. महाराजा शिवाजीराव को अंग्रेजों ने ''विक्षिप्त मानसिकता वाला व्यक्ति'' घोषित किया गया था, उन्हें प्रशासन से बेदखल करना अंग्रेजों का कूटनीतिक षडयन्त्र था, अत: दिरया महल में रहते हुए महाराणा ने अंग्रेजों के विरुद्ध गोपनीय अभियान आरंभ किया। अन्य देशी राजाओं का ब्रिटिश विरोधी संघ बनाने हेतु कवायद में संलब्ज हो गये। उन्होंनें कई स्थानों की गुप्त यात्राऍ की और अनेक लोगों से व्यक्तिगत पत्र–व्यवहार किया। उनके ब्रिटिश विरोधी रवैये को देखते हुए अंग्रेजी हुकुमत ने उन्हें दिरया–महल में लगभग नजर बन्द ही कर दिया था। (14)
- 16. महाराजा तुकोजीराव तृतीय (1903–1926) एवं अंतिम शासक महाराजा यशवन्तराव होलकर (1926–1948) के भी प्रिय रिसोर्ट के रूप में दरिया महल शामिल था। उन्हें रालामण्डल-इन्दौर से भी यह

- स्थान अधिक आकर्षित करता था।
- 17. महाराजा के मुख्य आखेट सहायक बाबू शिकारी थे, जिनके पिता पिंटू शिकारी महाराजा तुकोजी राव तृतीय तथा ढाढा नईम शिकारी महाराजा शिवाजी राव के प्रमुख शिकार सहायक थे। इस प्रकार यह परिवार (बाबू शिकारी) अपनी तीन पीढ़ियों से होलकर शासकों के शिकार का सहभागी रहा था। जनाब बाबू शिकारी को शेर के शिकार के लिए ले जाने हेतुमहाराजा रू. 4प्रतिदिन के हिसाब से मेहनताना देते थे।
- 18. महाराज तुकोजीराव तृतीय एवं महारानी शर्मिष्ठा देवी की पुत्री सीताराजे का विवाह दरिया-महल से किया गया था, जिसमें आकर्षक विद्युत सज्जा की गई थी।⁽¹⁶⁾
- 19. जनश्रुति यह भी हैं कि दिया-महल से नर्मदा कोठी तक गुप्त सुंरग बनी हुई थी। नर्मदा तट (नावघाट खेड़ी) पर आज की 'रानी घाट' बना हैं, जो होलकर परिवार की महिलाओं के निजी उपयोग हेत् आरक्षित था (17)
- 20. होलकर रिसायत के विलयीकरण के बाद दिया-महल ''राजकुमारी-उषाराजे ट्रस्ट'' से भारत सरकार ने 6 लाख रूपयें में अधिगृहित किया था।
- 21. नेशनल डिसिप्लीन स्कीम (एन.डी.एस.) का प्रशिक्षण केन्द्र यहाँ खोला गया, उसके बाद म.प्र. वन विभाग का प्रशिक्षण केन्द्र भी कुछ समय तक यहाँ रहा था।
- 22. 1 अगस्त 1968 को CRPF ने अपना रिक्रुट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया जिसका विधिवत उद्घाटन 11 जुलाई 1969 को हुआ।
- 23. 1 अगस्त 1984 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रथम आरिक्षत वाहिनी ने दिरया-महल को अधिगृहित किया। 1 अप्रैल 1985 से यहाँ पुरुष-महिला दोनों वर्गो हेतुरिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित हो गया। 31.07.1999 तक यहाँ 27 पाठ्यक्रम चलाये जाते रहे हैं।
- 24. बदलते हुए परिदृष्य, आतंकवादी गितविधियों आदि के कारण "दिरया–महल" का सी.आई.एस.एफ. केन्द्र अत्यंत संवेदनशील रहा हैं। सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने "दिरया–महल" का रख–रखाव की अत्युत्तम व्यवस्था के द्धारा इसके मूल स्वरूप, शैली को बरकरार रखा हैं। दिरया–महल अपनी पूरी शान– ए–शौकत एवं बुलंदी से होलकर वंश की गौरव–गाथा एवं वैभवशाली इतिहास का सजीव प्रतीक हैं।

सन्दर्भ सूची -

- 1. पश्चिम निमाइ स्टेट गजेटियर पृ. ४३२।
- 2. पश्चिम निमाड़ स्टेट गजेटियर पृ. 4321
- 3. राणा परिवार,बड़वाह से प्राप्त जानकारी अनुसार, बी.एस.राठौर-बड़वाह एक सफर-प्र.241
- 4. एल.सी.धारीवाल, इन्बीर स्टेट गजेटियर -पृ. 35, डॉ. एस. एन. यादव- संपादक-अपना इन्बीर-पृ. 162।
- जनाब बाबूखॉ शिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार।
- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभिलेखानुसार।
- 7. जनाब इकबाल मोहम्मद अली के कथानानुसार।
- 8. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर से चर्चानुसार।
- 9. जनाब बाबुखॉ शिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार।
- 10. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर से चर्चानुसार।
- 11. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अभिलेखानुसार।
- 12. श्रीमदन सिंह सिकरवार की स्मृति से साभार।
- 13. डॉ. एस.एन.यादव-संपादक-अपना इन्दीर-पृ. 1631
- 14. डॉ. एस.एन.यादव-संपादक-अपना इन्दीर-पृ. 1631
- जनाब बाबूखॉ शिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार।
- श्री राणा राजेन्द्र सिंहजी तोमर की स्मृति से साभार।
- 17. श्री जयप्रकाश जोशी के अनुसार **।**



साहित्य में पर्यावरण चेतना : एक दृष्टिकोण

डॉ. अरूणा दुबे *

साहित्य में पर्यावरण चेतना की चर्चा करते समय हमें साहित्य पर विचार करना होगा। 'सहित स भाव: साहित्यः,' 'हितेन सहितम् इति साहित्यम्' अर्थात जिसमें हित की भावना हो, वह साहित्य हैं।

पर्यावरण चेतना प्रकृति का ऐसा संतुलन है जो प्रकृति तथा मानव के हितों का संवर्धन करें। वेदों और उपनिषदों में पंच तत्वों पर चर्चा की गई है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने शरीर को पंच भौमिक तत्वों पृथ्वी, जल, अन्नि, वायु, गगन आदि निर्मित माना है। इन पंच तत्वों को उनके मूल रूप में स्वीकार कर समस्त जीवों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, तभी सभी को शुद्ध जल, वायु, हवा, पानी, अनाज उपलब्ध होगा और शिक्षा का प्रसार निश्चित रूप से पर्यावरण चेतना को जाग्रत करने में सहायक होगा।

साहित्य में पर्यावरणीय चेतना आदिकाल से मुनष्य को स्वस्थ पर्यावरण के संरक्षण के लिये प्रेरित करती रही है। साहित्य में पर्यावरण चेतना सर्वत्र व्याप्त है। वेद, उपनिषद, पुराण, धार्मिक ग्रन्थों के साथ-साथ महाकवि वाल्मिकी तुलसीदास व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, बाणभट, भर्तहरि आदि रचनाकारों के साहित्य में पर्यावरण का चित्रण उनकी तद् विषयक चिन्ताओं को स्वर देता है। बौद्ध साहित्य में प्रकृति न केवल जीवन का पोषण करती है, अपितु उसका निर्देशन भी करती है। रामायण में क्रोंच पक्षी के वध पर सारस को बिलखते देख महर्षि वाल्मिकी का हृदय दया से भर गया और उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े।

श्मॉ निषाद प्रतिष्ठात्वम्, गमः शाश्वती समा। यत्क्रौंच मिथुनाद्रेक, वधी काम मोहितम्॥

श्लोक में पर्यावरण एवं परिस्थिति के संतुलन के प्रति जागरूकता को स्पष्ट किया है। पौराणिक महाकाव्यों में भी पर्यावरण चेतना की भावना परिलक्षित होती है।

श्रीमब्भगवतगीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं – वृक्षों में में अस्वस्थ हूँ। पीपल को संस्कृत में अस्वस्थ कहा गया है। महाभारत में वेब व्यास ने लिखा है –

> पुष्पिताः फलिता वृक्षा तर्पयन्तीह भगवान् वृक्षदं पुत्रवद् वृक्षास्तारयन्तित्र तु ॥

अर्थात फूलों फलों से परिपूर्ण वृक्ष मानव को इस लोक में तृप्त करते है जो व्यक्ति वृक्ष का दान करता है उसे ये वृक्ष पुत्रों की ही भ्रांति परलोक तार देते है। 'पृथ्वीसूक्त' में पर्यावरण चेतना के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें पृथ्वी, जल, अन्ति, वायु, गगन आदि से संसार वासियों को सुखी रखने के लिये मंगलकामना की गई है। कालिदास के मेघदूत में यक्ष मेघ के माध्यम से अपनी प्रिया को संदेश देते हुए कहते है कि हे मेघ जब तुम आम्रकूट पर थक कर पहुँचोंगे तो वहाँ रेवा का जामुनी जलपान करना। आम्रकूट भी आदर सहित तुम्हे अपने शिखर पर ठहराएगा।

कबीरदास लिखते है कि पत्ती में ब्रम्ह्म, पुष्प में विष्णु और फुल फल में महादेव है। फिर तुम इसे तोड़कर किस अन्य देव की पूजा करने जाते हो –

> 'पाती ब्रम्ह पुहुपे विष्णु, फूल फल महादेवा। तिनी देवौ एक मूर्ति करै किसकी सेवा'॥

वनस्पतियों में जीवन है और जीव मात्र के प्रति सदय होना उसकी सेवा

एवं सुरक्षा करना मानवीय कर्तव्य है कबीर पुन: लिखते है कि – भूली मलिन पाती तोडे, पाती पाती जीव। संत मूलकदान भी इसी ओर संकेत करते है – हरि डार मत तोड़िये लागै छूटा बाण। दास मूलका यों कहें, अपना-सा जीव जान॥

इसी तरह रसखान ने कहा है कि – कौशिक हूँ कलधौल के धाम करीब की कुंजन पर हूँ बारौं। कलधौल के जीवन न्यौछावर करना रेगिस्तानी भौतिकता से प्राकृतिक श्यामलता की ओर आना है सूरदास का प्रकृति प्रेम इन पंक्तियों में हष्टव्य है –

मैया री मोहि बाउ टेरत ।
मौको बनफल टोरि देत है, आपुन गैयन धेरत ॥
इसी प्रकार प्राकृतिक विपदाओं पर सूरदास ने कहा है –
गहरात महरात दावानल आयो है।
तुलसीदास ने स्वस्थ पर्यावरण की कामना निम्नानुसार की है–
तुलसी बिरला बाग में सींच से कुम्हलाय ।
रामभरोसे छोरि दे, पवनत में हरियाय ॥

बिहारी ने प्रचण्ड ग्रीष्म से बचने के लिये पशु पक्षी सरिसृप को एक स्थान पर बैठा हुआ वर्णित किया है –

> कहिलानें एकत बसत, अहि मयूर मृग बाध। जगत तपोवन सो कियो दीरथ दाध निर्दाध॥

प्रकृति के सुखद आनन्द और मनोहारी रूप का चित्रांकन राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने पंचवटी में इस प्रकार किया है –

गोदावरी नदी का यह तट, ताल दे रहा है अब भी। आँखों के आगे हरियाली, रहती है हर घड़ी यहाँ॥ तथा चारूचन्द्र की चंचल किरणें, खेल रही है जल-थल में। स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है, आविन और अंबर में॥ प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने एक पल के लिये भी प्रकृति से स्वयं को अलग नहीं किया है –

> छोड़ ढुमों की मृदछाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल-जाल में, कैसे उलझा दूँ लोचन ?

आधुनिक कवि अज्ञेय की 'असाध्य वीणा' और 'साम्राज्ञी का नैवेद्य' दान जैसी रचनाओं में भी पर्यावरण संरक्षण के स्वर मुखर हुए है। भारतीय साहित्य में सर्वत्र वनदेवी-वनदेवता का वर्णन मिलता है। इन्हें वनरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार साहित्य विविध प्रकार से पर्यावरण के संरक्षण का संदेश देता है। साहित्य में वर्णित विषय केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। वे मनुष्य को सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी बनाने का प्रयत्न भी करते हैं। लोक जीवन में भी यही विचार प्रमुखता से चित्रित किया गया है। पर्यावरण की उपेक्षा से व्यथित कवि ने अपनी पीड़ा इस तरह व्यक्त की है -

> यह सूचना पाया चमन, हजार साल पर। नर्गिस नही खिलाएगी, अब फूल डाल पर॥ जबसे किया तेन्दुओं, चीतों, शेरों का सफाया। तब से नजर टिकी हई, गेंडों की खाल पर॥

की ओर बढ रहे है -



पकड़े जाने पर ऐंठकर, बोला था शिकारी। हमको भरोसा है अपने, नेता की ढाल पर।। (1) डॉ. शरद मिश्र ने पर्यावरण चेतना पर लिखा है कि – हरियाली चारों और थी, पहले की सृष्टि में, सब कुछ हरा हरा दिखा करता था दृष्टि में। जल मृदा वन विनाश और ध्वनि का प्रदूषण, अंतर बहुत बड़ा है आज वृष्टि में। (2)

पर्यावरण प्रदूषण में सबसे महत्वपूर्ण कारक मानवीय प्रक्रियाओं द्धारा परिवर्तित वातावरण भी है जिससे हमारे परिवेश को पूर्णता मिलती है, किव की दृष्टि पर्यावरण प्रदूषण के लिये बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर भी गई है – यि जनसंख्या की तुलना में, इस विश्व में पौधे कम होगें। तो इतना रखना याद सजन, न तुम होंगे न हम होंगे। (3) हमारी प्रगति की दिशा रेखांकित करने वाली निम्नांकित पंक्तियाँ इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि हम विकास की दृहाई देते हुए उत्तरोत्तर विनाश

धुआँ उगलती चिमनियाँ, कुआँ निगलते खेत। शहर-गाँव ढोनों हुए, भुखे नंगे प्रेत।। पेड़ कटे, जंगल जलें, गाँव हुए बरबाद। शहरों बीच सीमेन्ट के, जंगल है आबाद।। (4)

इसी प्रकार शहरों में मॉल की जो संस्कृति पनप रही है उस पर किव ने अपनी पीड़ा इस तरह व्यक्त की है – 'खेतों में माल है किसान बेहाल है।' वर्तमान में मनुष्य की चिन्तन की दिशा इतनी अधिक भोगवादी हो गई है कि उसने बनावटीपन के आवरण के बीच अपने अस्तित्व को खो दिया है –

> कीमती कालीन जब से मेरे घर आ गये, बेहिचक घर आने-जाने की अदा जाती रही।

बाथरूमों के नई, कल्चर में इतना बंद हूँ, खुलके बारिश में नहाने की अदा जाती रही॥ (5)

पर्यावरण चेतना की संपुष्टि के लिये समाज में सौन्दर्य की भावना जाग्रत करने की आवश्यकता है यदि मनुष्य वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के प्रति पूज्यभाव विकसित कर ले तो उसके संवेग उनकी संवेदनाएँ पुन: प्रकृति से रागात्मक संबंध स्थापित कर सकती है, और तब वह इस दिशा में पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने में सही प्रयत्न कर सकता है। काव्य में प्राकृतिक सौन्दर्य को पर्याप्त प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे अंशों के प्रचार प्रसार से भी पर्यावरण चेतना के भाव को जाग्रत किया जा सकता है। साहित्यकारों के दिशा निर्देशक सिद्धान्तों को हदता से अपनाना आवश्यक है क्योंकि उन्होंने हमेशा स्वस्थ्य आनन्दमय भविष्य की कल्पना इन पंक्तियों के माध्यम से की है –

> बेला कहती रात, उजालें आएँगें, सच है मेरी बात उजालें आएँगें। सीख रही है ऊषा अँधेरों से लड़ना, रवि के लिये हठात् उजाले आएँगें। (6)

इस प्रकार पर्यावरण के संबंध में समुचित चिन्तन की सतत् आवश्यकता है मुनष्य का स्वस्थ चिंतन उसके कर्म और श्रम को पवित्र बनाकर पर्यावरण संरक्षण की विभिन्न वैकासिक योजनाओं के स्वप्न को निश्चित रूप से साकार कर सकता है। वेद वाणी शतन्मेमन: शिवसंकल्पमस्तुश – यही संदेश देती है।

- काग के भाग बड़े सजनी डॉ. लक्ष्मीनारायण वाजपेयी पृष्ठ 35
- 2. दैनिक जागरण
- 3. हिन्दी भाषा और विज्ञान बोध डॉ. टी.एन. शुक्ल पृष्ठ 174
- ऑधियों के पेड़ डॉ. कुँवर बैचेन पृष्ठ 35
- सीस पगा न झगा तन पे डॉ. कुवॅर बैचेन पृष्ठ 15



रूपये का गिरता स्तर तथा विदेशी व्यापार नीति

डॉ. आभा दीक्षित *

किसी भी बजट की सबसे बड़ी खासियत इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए किए जाने वाले इंतजाम होते हैं। नवीनतम बजट के अंतर्गत वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने इसका ध्यान रखा तथा स्वीकार किया कि चालू खाते का घाटा और राजकोषीय घाटा उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है क्योंकि देश में निर्यात से ज्यादा आयात हो रहा है। उन्होंने बजट में कई प्रावधान भी रखे।

इसके बावजूद रूपये के मूल्य में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमी आ रही है। भारतीय मुद्रा की कीमत जून 2013 में 11 महीनों में नए न्यूनतम स्तर 56.76 रूपये प्रति डॉलर पर आ गई। हाल में पूरे एशिया में सबसे ज्यादा अवमूल्यन रूपये का ही हुआ है। विश्व भर में सबसे ज्यादा अवमूल्यन दर्शाने वाली मुद्राओं की सूची में रूपया चौथे स्थान पर है। इसका नकारात्मक असर हमारे विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन पर किस प्रकार पड़ रहा है (देखिये तालिका)

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि हमारी निर्यात वृद्धि दर व आयात वृद्धि दर दोनों ही नकारात्मक है। रूपये के अवमूल्यन से क्रूड ऑयल का आयात बिल अब और ज्यादा बढ़ जायेगा तथा इससे भारत की राजकोषीय घाटे के भी और बढ़ जाने का अंदेशा है। जो पहले से ही 6.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है।

इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि रूपये में तेज गिरावट से जो ढुष्चक्र पैदा हो रहा है वह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आयातों के महंगा होने से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है जिससे, मांग में कमी आ जाती है। कंपनियों के सामने और एक संकट पैदा होता है। जिन कंपनियों को विदेश से कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है उन्हें अब ब्याज के तौर पर ज्यादा रकम अदा करनी होंगी। बहुत सारी कंपनियाँ डॉलर में कर्ज ले रही है। उनके कर्ज रूपये में गिरावट से महंगे हो जाएंगे। कंपनियों ने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड के जरिये भी फंड जुटाए है यानि अब बांड धारकों को ज्यादा रकम अदा करनी होंगी।

रूपये के मूल्य में गिरावट के कई कारण है जिनमें प्रमुख है – पहला, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के मद्देनजर विदेशी संस्थागत निवेशकों द्धारा अपना पैसा घरेलू बाजार से निकाले जाने के चलते डॉलर की मांग काफी बढ़ जाने से ही रूपये की हालत दयनीय हो गई है।

इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले यूरो मुद्धा के कमजोर पड़ जाने से भी रूपये की गिरावट को बल मिला है। दरअसल यूरोप का कर्ज संकट जारी रहने के कारण डॉलर को ज्यादा सुरक्षित निवेश विकल्प माना जा रहा है। जिससे अमेरिकी मुद्धा की मांग बढ़ गई है। लेकिन, यूरोप और अमेरिका में बरकरार आर्थिक संकट की वजह से भारतीय निर्यातकों को कोई मजबूती नहीं मिल रही है तथा भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। सरकार द्धारा महंगाई को काबू न कर पाने, सामाजिक योजनाओं पर अंधाधुंध खर्चा करने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत ना कर पाने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादक शक्तियाँ कमजोर हो गई है, मौजूदा हालात इसी का परिणाम है। हालांकि, भारत उपाय के तौर पर डॉलर खरीद सकता है लेकिन विदेशी मुद्धा रिजर्व सीमित है तथा वर्तमान विश्व की वित्तीय स्थित में पूंजी जुटाना इतना आसान प्रतीत नहीं हो रहा है। अत: रूपये की मजबूती के लिए आंतरिक

प्रबंध के साथ-साथ विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने खासकर निर्यात को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है।

भारतीय सरकार द्धारा 2009–14 के लिए पूर्व घोषित विदेशी व्यापार नीति के तहत् चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वार्षिक अनुपूरक नीतिगत उपायों की घोषणा जून 2012 में की गई। जिसकी मुख्य बातें निम्न है –

- 🗱 जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम लाई गई।
- ब्याज दर में दो प्रतिशत की छूट की अविध अब 31 मार्च 2014 तक कर दी गई। जिसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों को तो शामिल किया गया साथ ही इसका विस्तार अब श्रम आधारित क्षेत्रों जैसे – खेल के सामान, प्रसंस्कृत, कृषि उत्पाद व सिले-सिलाए वस्त्र के क्षेत्रों में भी किया गया है।
- फोक्स मार्केट स्कीम, फोक्स प्रोडक्ट स्कीम व विशेष कृषि ग्रामीण उद्योग योजना के तहत् जारी किए गए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का इस्तेमाल सेवा कर को चुकाने के साथ विदेश व्यापार, महानिदेशालय की फीस चूकने के लिए भी किया जा सकेगा।
- एसटीपीआई स्कीम के तहत घर से काम कर, आई टी निर्यात की सहलियत प्रदान की गई।
- मार्केट लिंक्ड फोक्स प्रोडक्ट स्कीम के तहत् ब्रुनेई व यमन को शामिल किया गया, स्कीम के तहत इंजीनियरिंग ऑटो कंपोर्नेट्स वे टेक्सटाइल के 47 नए आयटम को जोडा गया।
- हाईटेक उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अलग से इंसेटिव प्रदान किए गए।
- गुजरात के मोरबी व हिरयाणा के गुड़गांव को टाऊन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस की सूची में शामिल किया गया।
- इंक्रीमेंटल स्कीम की अविध अगले साल मार्च तक बढ़ाई गई, अमेरिका, यूरोप व एशिया के साथ अफ्रीका के 53 नये देश शामिल हुए।
- कार आयात के लिए कस्टम पोटे की सूची में फरीदाबाद व एक्नोर (तमिलनाडु) को शामिल किया गया।
- 🔅 ्रॉजेक्शन कॉस्ट में कमी के लिए ढूसरी टास्क फोर्स कमेटी का गठन।
- कॉटन, कॉटन यार्न, गैर बासमती चावल, गेहूँ व चीनी के निर्यात के लिए ऑन लाईन पंजीयन सर्टिफिकेट की सुविधा दी गई।
- हैंडलूम व खेलकूढ़ सामान के निर्माण के लिए शुल्क मुक्त कच्चे माल के आयात की सूची में पाँच अतिरिक्त आयटम जोड़े गये।

हालांकि, अनुपूरक विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का उद्योग व्यापार जगत व निर्यातकों के संगठनों द्धारा स्वागत किया गया है उनका कहना है कि इस नीति से ऐसे समय में जब अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में दिक्कत है निर्यात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा इन उपायों को देश के व्यापार पर लंबे समय तक सकारात्मक असर होगा। यह घोषणाएँ निर्यातकों की उम्मीद से अधिक है। कपड़ा जैसे श्रम आधारित क्षेत्र पर नीति में विशेष जोर दिया गया है। परिधान क्षेत्र को जोरदार प्रोत्साहन मिलेगा। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन के लिए भी यह नीति असरदायक है तथापि, आलोचकों का

nss

कहना है कि यह नीति बड़ी कंपनियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें छोटे व मध्यम निर्यातकों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिनका निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान है। नई विदेश व्यापार नीति में कुछ खास बदलाव न कर पुरानी योजनाओं में विस्तार और समय में वृद्धि की गई है। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार को इंनसेंटिव के तौर पर ड्यूटी ड्रॉ बैंक बढ़ाना चाहिए था या फिर निर्यातकों को सस्ते कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये थी।

बढ़ते आयात बिल से मुकाबला करने के लिए निर्यात बिल को शक्तिशाली बनाना ही काफी नहीं है हमें मंदी के माहौल में चीन के सस्ते और तेज निर्यात से मुकाबला करने के लिए पूंजीगत निवेश के लिए कर्ज पर ब्याज घटाना पड़ेगा। इसके अलावा चीन में निर्यातकों को शतप्रतिशत ड्यूटी ड्रा बैंक दिया जाता है जबकि भारत में सिर्फ 20 प्रतिशत इसे बढ़ाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात की डिलीवरी तय समय पर पहुँच सके। इसके लिए जतन करने होंगे तभी यह नीति कारगर सिद्ध होंगी।

महंगाई दर पर काबू पाना तथा राजकोषीय घाटा कम करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार कर भ्रष्टाचार आदि को खत्म करके ही हम रूपये को मजबूती दे सकते हैं। आंतरिक तथा बाह्य उपायों के साथ–साथ क्रियान्वयन हो जिससे निवेशकों को विश्वास अर्थव्यवस्था पर जम जाए तभी आर्थिक स्थिरता और विकास का मूल उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

संदर्भ सूची -

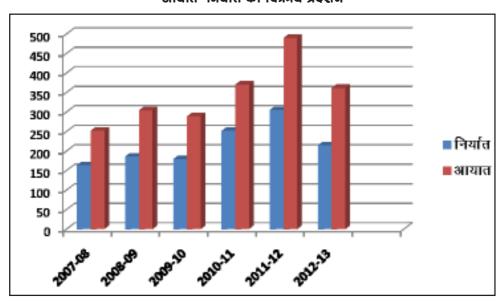
- (1) जी सिंघई भारतीय आर्थिक नीति।
- (2) 2012-13, आर्थिक सर्वेक्षण।
- (3) 2012-13 ৰ্জান
- (4) भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण, २०१३।
- (5) 22 नवम्बर 2011, बिजनेस भास्कर।
- (6) 20 अप्रैल, 2013, बिजनेस भास्कर।

भारत का विदेशी व्यापार (अरब डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार	निर्यातवृद्धि	आयातवृद्धि
			घाटा	दर (प्रतिशत)	दर (प्रतिशत)
2007-08	163.132	251.654	88.522	29.0	35.5
2008-09	185.295	303.696	118.401	13.6	20.7
2009-10	178.751	288.373	109.622	(-) 3.5	(-) 5.0
2010-11	251.136	369.769	118.633	37.55	21.61
2011-12	304.624	489.181	184.558	20.9	32.1
2012-13	214.100	361.272	147.172	(-)5.50	(-) 0.71
(अप्रैल–दिसंबर)					

स्त्रोत - आर्थिक समीक्षा 2012-13

भारत का विदेशी व्यापार (अरब डॉलर में) आयात-निर्यात का चित्रमय प्रदर्शन





बाल-श्रम : एक अभिशाप

प्रो. मीना मावी *विजय मावी **

परिचय:-

शिशु इस सृष्टि का सर्वोतम उपहार है। इस उपहार की देखभाल समाज के हाथ में है। अभिभावक, समाज और राज्य इसके प्राकृतिक विकास को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। बच्चे जितना अधिक स्वस्थ, शिक्षित, क्रियाशील, अनुशासित और प्रशिक्षण युक्त होंगे उसी अनुपात में देश और समाज की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, क्योंकि बच्चें देश और समाज के भविष्य होते हैं।

गाँधी जी ने कहा था, ''बच्चें भगवान का रूप होते है और वे देश के भविष्य के निर्माता है। प्रत्येक बालक की आँखों में देश के भविष्य की तस्वीर होती है। अत: बालक की रक्षा करना राष्ट्र की रक्षा करना है।'' किन्तु आज के इस आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण के युग में अनिगनत पुष्प रूपी बालक खिलने के पूर्व ही मुरझा जाते हैं। हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू सदैव कहा सकते थे– ''आज के बच्चे कल के जिम्मेदार नागरिक होगे। भारत के भाग्य विधाता होंगे। लेंकिन आज भी नेहरू की कल्पना साकार नहीं हो पायी है। फैक्ट्री मालिक, ठेकेदारों, दलालों रईसों के मकड़जाल में उलझकर बच्चें आज भी बालश्रमिक के रूप में जीवन जीनें को अभिशत है।

बाल-श्रम व शोषण एक ऐसी जटिल सामाजिक और आर्थिक समस्या है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज यह किसी एक विशेष देश या समाज की समस्या नहीं, अपितु विश्वन्यापी समस्या हैं, किन्तु भारत जैसे विकासशील देश में बालश्रम की समस्या जिस तरह विशालता ग्रहण करती जा रही है और इससे जो दुष्परिणाम सामने आ रहे है वे हमारे पत्रकारों, न्यायाधीशों विधानकारों, राजनीतिज्ञों, सामाजिक विचारकों अर्थशास्त्रियों एवं मानव प्रेमियों का मस्तिष्क समय समय झकझोरते रहे है।

बाल-श्रमिक अवधारणात्मक परिप्रेक्ष्य:-

बाल-श्रम से आशय ऐसे 'बाल रोजगार' या 'काम करने वाले बालक से है। जो लाभ के लिए किसी भी प्रकार के कार्य में लगे है। बाल कार्य और बाल-श्रम में अन्तर है। बाल-कार्य बच्चों से घर, खेत या विद्यालय में छोटे-छोटे कार्य कराने के अर्थ से लिया गया है, जबकि बाल श्रम का अभिप्राय बच्चों से कुटीर या लघु उद्योग या ठेके पर कार्य कराकर उनके काम के बदले उन्हें कुछ आर्थिक लाभ देकर उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी या आर्थिक शोषण करना है।

संयुक्त राष्ट्र संघ बालश्रम आयोग के अध्यक्ष होमर फॉक्स ने :-

बालश्रम को परिभाषित करते हुए कहा है कि ''बच्चों द्धारा किया जाने वाला कोई भी कार्य जिससे उनके पूर्व शारीरिक विकास और न्यूनतम वांछित स्तर की शिक्षा के अवसरों या उनके लिए आवश्यक मनोरंजन में बाधा उत्पन्न होती है।

समाजशास्त्र कोष के अनुसार:-

जब मजबूरी के लिए नौकरी करने या खुद काम करने या परिवार की सहायता के लिए काम करने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकास या शिक्षा में बाधा पड़े तो नतीजा बाल श्रम होता है। अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व के कुल श्रमिकों में से 50 प्रतिशत बालश्रमिक भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में है।

आज पूरे विश्व में 25 करोड़ बाल श्रमिक है। जनवरी 2000 में विश्व बैंक द्धारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक (6 करोड़) बालश्रमिक भारत में है, जो कि कृषि कार्य, कॉच उद्योग, चूड़ी उद्योग, कालीन उद्योग, बीड़ी उद्योग, पैकिंग कार्य, मोटर गैरज, स्लेट पेंसिल उद्योग, ढ़ाबे, होटले एवं घरेलू नौकरों के रूप में लगे है। जिसमें डेढ़ करोड़ बंधुआ बाल श्रमिक भी समाविष्ट है।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान भारत सरकार के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार इनकी संस्था अधोलिखित है।

''भारत में बालश्रम:एक अनुदृष्टि''

35.	स्त्रोत	वर्ष	वालश्रमिकों की संख्या
1	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (43 वॉ दौर)	1987-88	11.70 करोड
2	गैर-सरकारी संस्था	1998	10.00 करोड
3	अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन	1998	11.00 करोड
4	यूनिसेफ	2001	11.12 करोड़
- 5	भारतीय जनगणना	2001	2.69 करोड
6	वास्तविक संख्या (अनुभानित)	2001	6.00 करोड

कारण एवं व्यापकता:-

यह विदित है कि आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा में बालश्रम की समस्या जन्म लेती एवं पनपती है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। बाल श्रमिकों की समस्या हमारी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की ही देन है उपरोक्त सामाजिक स्थिति के अतिरिक्त बढ़ती जनसंख्या एंव कम आय आदि मजबूरियों के चलते बच्चों को जोखिम भरे कामों में लगना पड़ता है। कई बच्चे अनाथ होने के कारण बाल श्रमिक बन जाते है,तो कई पारिवारिक आय की कमी के कारण भरण-पोषण के अभाव में मजदूरी करने के लिए बाध्य है। विकास के निचले स्तर पर भूमि और सम्पति के असंतुलित विवरण के कारण बहुसंख्यक जनता के गरीबी की रेखा के नीचे होने जैसी बातों का असर भी इस समस्या का एक अहम पहलू है।

बाल श्रम के बढ़ने का एक प्रमुख कारण सस्ती मजदूरी है। ठेकेदार बच्चों को कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम करवाना चाहता है। बच्चों की यूनियन नहीं होने से उन्हें अनुशासन में रखना या काम से निकालना आसान होता है। बच्चे बड़ों की अपेक्षा ज्यादा ईमानदारी से व निपुणता से कई काम करते है जैसे– माचिस बनाना,कालीन बुनना, साड़ी बुनना आदि।

आज तो अपराधी तत्वों के संगठित गिरोहों द्धारा तस्करी, ड्रग्स व्यापार, वेश्यावृति, भ्रिक्षावृति से लेकर विदेशों में ऊँट दौड़ जैसे घिनौने कार्यों में भी बालकों का इस्तेमाल हो रहा है।

बाल श्रमिकों का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है। इसमें अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय भी है। जहाँ जोखिम कम है, वहाँ कार्य के लम्बे घण्टे तथा अन्य परिस्थितियाँ उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इन स्थानों पर बाल श्रमिकों के बेहतर भविष्य के अवसरों को



nss

छीनने के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। बाल श्रमिकों का शोषण: बाल श्रमिकों का शोषण कई प्रकार से होता है-

- 1. दैहिक शोषण
- 2. लौकिक शोषण
- 3. सामाजिक शोषण
- 4. फूटपाथीय बच्चों का शोषण
- 5. मनोवैज्ञानिक शोषण
- आर्थिक शोषण
- 7. राजनैतिक शोषण
- अन्य शोषण

बाल-श्रम के उन्मूलन एवं पुनर्वास हेतु प्रयास:-

बालश्रम सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त ऐसी सामाजिक समस्या है, जो अपनी उपस्थिति के कारण अनेक सामाजिक—आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। यह समस्या सम्पूर्ण जगत को त्रस्त कर रही है। यह बात और है कि कही इसके परिणाम की तीव्रता अधिक है और कहीं कम। आज पूरे संसार में लगभग 25 करोड़ बालश्रमिक है ,जिसमें 6 करोड़ अकेले भारत में है। ऐसा नहीं है कि बालश्रम को रोकने के लिए शुरू से कोई प्रयास नहीं किए गर्ये, किन्तु किसी कारणवश या तो वे अप्रभावी हो गये या उतनें प्रभावी नहीं हुए जितना कि उन प्रयासों से अपेक्षाएँ थी। इन प्रयासों का हम दो भागों में विभक्त करके अवलोकन कर सकते हैं—

- (क) अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास
- (ख) राष्ट्रीय प्रयास
- (क) अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास: इस प्रयास के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठन, यूनेस्कों एवं विश्व के अन्य देशों द्धारा किये गए प्रयास सम्मिलित हैं।

''संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार घोषणा पत्र''

20 नवम्बर 1959 को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी महासभा में बच्चों के अधिकारों की घोषणा, घोषणा पत्र के माध्यम से की, जिसमें सम्पूर्ण विश्व के बच्चों कों नाम, राष्ट्रीयता, स्नेह, सहानुभूति, सर्वांगीण विकास का अवसर एवं सुविधा, नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा और प्रत्येक दशा में शोषण से मुक्ति का अधिकार प्रदान करने की घोषणा की।

यह बात और है कि इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में इसका पूर्ण परिपालन परिलक्षित नहीं हो सका। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण जैसे – यूनेसेफ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O.) द्धारा अनेक सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय व अन्य प्रकार की सहायता के साथ ही बाल-श्रम के आयात-निर्यात के लिए प्रतिबंधित कर बाल-श्रम रोकने एवं उनके उन्नयन पुनर्वास के लिए उल्लेखनीय प्रयास किये है।

(ख) राष्ट्रीय प्रयास: – राष्ट्रीय प्रसास के अर्न्तगत हम सरकार व्हारा बाल-श्रमिकों के कल्याण हेतु समय-समय पर बनाये गये विभिन्न अधिनियम ले सकते है जो निम्न लिखित हैं–

संवैधानिक प्रावधान: – संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद बालश्रम के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सोच एवं सम्बद्धता पर प्रकाश डालते हैं –

- 🗱 अनुच्छेद-23- जबरन मजदूरी व मानव व्यवसाय पर रोक।
- अनुच्छेद-24-कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक। 14 वर्ष की आयु से नीचे के बालकों के कारखानों या खदानों में खतरनाक कार्यो पर नहीं लगाया जा सकता है।

- अनुच्छेद-39 (ई और एफ) श्रमिक स्त्री पुरुष एवं बच्चों के स्वास्थ्य और शाक्ति के साथ दुर्व्यवहार न किये जाने का प्रावधान है।
- अनुच्छेद-45- 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर जोर।

अधिनियम- बालश्रम से संबंधित निम्न लिखित अधिनियम भी पारित किये गये है-

- (1) कारखाना अधिनियम 1948– रोजगार की न्यूनतम आयु 14 वर्ष
- (2) बागान श्रम अधिनियम 1951– 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कार्य पर रोक।
- (3) खदान अधिनियत 1952- 16 वर्ष पूर्ण करने पर ही कार्य करने की अनुमति।
- (4) कारखानों संशोधन अधिनियम 1954 17 वर्ष के बच्चों का रात्रिमें रोजगार पर प्रतिबंध
- (5) जहजरानी अधिनियम 1958- 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध।
- (6) बीड़ी तथा सिगार श्रमिकों (रोजगार की शर्त) अधिनियम 1966 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बीड़ी बनाने पर रोक।
- (7) प्रशिक्षु अधिनियम 1975-
- (8) बच्चों के रोजगार संशोधन अधिनियम 1978-रेल्वे लाईन व रेलवे में 15 वर्ष से कम बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध
- (9) बालश्रम प्रतिशेध एवं नियमन अधिनियम 1986-

यह अधिनियम बालश्रम अधिनियमों के इतिहास में सार्वाधिक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। इसके अंतर्गत ऐसे खतरनाक उद्योगों एवं उपक्रमों में बालकों का नियोजन प्रतिबंधित किया गया है। संशोधनों के पश्चात् ऐसे 13 उद्योंगों एवं 51 उपक्रमों की पहचान की गई है जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया गया है। इन उद्योगों में कालीन उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपडा रंगाई छपाई, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि प्रमुख है। बाल श्रम की समस्या (अभिशाप) को दूर करने हेत् सुझाव:-

- (1) बालश्रम समस्या एक गहन सामाजिक-आर्थिक समस्या है। इसके समाधान हेतु बहुआयामी कार्य नीति के माध्यम से दीर्घकाल एवं सतत प्रयास की आवश्यकता है, जिसमें बालश्रम कानूनों का प्रवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, बालश्रम का पुनर्वास, गरीबी उन्मूलन आदि बातें शामिल करनी चाहिए।
- (2) देश के ग्रामीण एवं शहरी परिवारों में प्रत्येक परिवार को अलग-अलग आर्थिक रूप से इतना समक्ष बनाया जाए कि उन परिवारों में बच्चों को रोजगार में संलब्ज करने की आवश्यकता ही महसूस न हों।
- (3) ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मजदूरी का शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए औद्योगिक एवं व्यावहारिक इकाईयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाए।
- (4) बाल श्रमिकों से काम लेने वालों के लिए कानून में कठोर ढण्ड का प्रावधान होना चाहिए, साथ ही उनकी सामाजिक निंदा व उनकी सेवाओं तथा बालश्रम से बने सामानों व उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए।
- (5) बालश्रम समस्या की जड़ वस्तुत: गरीबी, अशिक्षा एवं बेरोजगारी है। इन तीनों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना चाहिए।
- (6) बुढ़े, अपंग, बीमार अभिभावकों को जीवन यापन की सहायता देनी चाहिए।

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013

- जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाना चाहिए।
- शिक्षा की उचित व्यवस्था करके इस सामाजिक अभिशाप एवं अपराध के प्रति जागृति फैलानी चाहिए।
- रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। (9)
- (10) ऐसे बच्चे को जो सार्वजनिक रूप से भिक्षावृति करते है तथा परिवार विहीन होकर फुटपाथों पर रहते हो उनके पुनर्वास का कार्यकम चलाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:- जो बच्चे राष्ट्र के भविष्य का आधार है उनका सतत् शोषण आज हमारे देश के लिए एक अभिशाप है। यह गहन चिंतन का विषय है। बाल शोषण एवं बालश्रम के ऑकडे चोकाने वाले हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार, समाज, गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया सभी को मिलकर गंभीरता से विचार मंथन करने की आवश्यकता है, जिससे इस समस्या का समूल निर्मूलन हो सकेगा और भावी पीढ़ी इस अभिशाप से बच सकेगी। करोड़ो बालक जो फूल की तरह पलने चाहिए जो कल के नागरिक है, उन्हें गरीबी, बेकारी और अत्याचार की भार कुम्हला देती है। मासूमों के सपने चूर-चूर हो जाते है। तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी यदि बाल मजब्री जारी है, तो इसके लिए जिम्मेदार वे सभी लोग है, जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बाल-श्रमिकों के अस्तित्व को बनाये रखे है।

हम सभी को मिलकर बच्चों को उचित अधिकार, उचित सुविधा, उचित वातावरण देना होगा। देश के करोड़ों बाल-श्रमिकों की आँखे उस सुनहरे दिन की टकटकी लगाकर प्रतीक्षा कर रहीं है जब वे शाषण से मूक्त होंगे और उनको सपने साकार हो सकेंगे।

संदर्भ:-

01.समाज शास्त्रीय निबंध- डॉ. डी.एस.बघेल

(i) अंक 63-(नव.दिसं.-2006) 02.रचना-

(ii) अंक 81 -(नव. दिस.-2009)

(iii) अंक 86-(सिंत.अक्टूबर-2010)

03. रिसर्च जनरल ऑफ सोशल एवं लाइफ साइसेंज अंक-11 वर्ष-6

04. मानवाधिकार और कर्तव्य-प्रकाशनारायण नाटाणी

05.मानव अधिकार एवं भारतीय लोकतंत्र-पूनीत कुमार

06. जाँच श्रम समिति मुख्य रिपोर्ट 1946

07. कारखाना अधिनियम- 1948 एवं संधोधित 1954

08. बागान श्रम अधिनियम 1951

09. खदान अधिनियम 1952

10. जहाज रानी अधिनियम 1958

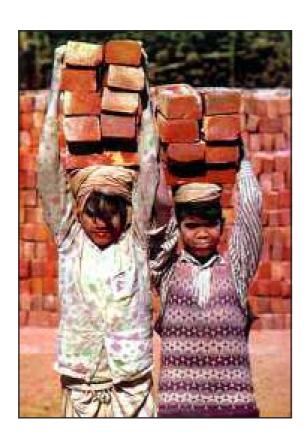
11. बीड़ी तथा सिगार श्रमिक अधिनियम 1966

12. प्रशिक्षु अधिनियम 1975

13. बच्चों के रोजगार संशोधन अधिनियम 1978

14. बाल श्रम प्रतिशेध एवं नियमन अधिनियम 1986

15. भारतीय संविधान की अनुच्छेद 23, 24, 39, 45







भाषा का बाजारीकरण एवं मीडिया

डॉ. मंज़ुला जोशी *

इक्कीसवीं सदी ग्लोबल विलेज की मानसिकता का युग है, और हिन्दी इस देश की सहज संपर्क की भाषा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसे सीखना और व्यवहार में लाना अन्य भाषाओं की अपेक्षा ज्यादा सुविधाजनक और आसान है।

भ्रमण्डलीकरण एवं निजीकरण के चलते आज पूरे विश्व की निगाह भारत पर है; क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है। इस दृष्टि से सारी कंपनियों ने अपने प्रचारतंत्र के लिये भारतीय भाषाओं को चूना। इलेक्ट्रानिक मीडिया ने हिन्दी को काफी प्रचारित प्रसारित किया है। भले ही विज्ञापनदाता कंपनियों का इसके पीछे लाभ कमाने वाला उद्देश्य रहा हो।(1)

आज के जनसंचार माध्यम अपनी भाषा को विकसित करते दिखाई दे रहे है; यह भाषा न हिन्दी है न अंग्रेजी है न अन्य भाषा है, इसकी भाषा बाजार की भाषा या इसे हम हाट बाजार की भाषा कह सकते है।

जिस प्रकार मुगलों और हिन्द्रस्तानियों ने बाजार से माल खरीदने बेचने (क्रय - विक्रय) करने की परिस्थिति में खड़ी बोली और उर्दू को विकसित किया। उसी प्रकार आज के संचार माध्यम विश्व बाजार के संदर्भ में एक नई भाषा का विकास करने की दिशा में निरन्तर अग्रसर हैं। यह भाषा बाजार की ताकतों के दबाव में विकसित हो रही है। यह तकनीक अपने संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से नई भाषा की रचना कर रहे है। यह भाषा हमारी संस्कृति आचरण और व्यवहार से पृथक होकर अपना कार्य कर रही है, क्योंकि इस भाषा पर बाजारवाद हावी है।

पिछले दिनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस बात का सर्वे किया की यदि हमें अपना माल ज्यादा लोगों तक पहुँचाना है तो उसी भाषा में उत्पादों की जानकारी देना होगी। यही कारण है कि आज विदेशी कंपनियों ने जहाँ प्रचार सामग्री हिन्दी में छपवाई है, वहीं भारतीय भाषाओं में जानकारी भी उपलब्ध करवाई है।

''इस दुनिया में संपर्क की बड़ी भाषाएँ अंग्रेजी और स्पेनिश है। अंग्रेजी की पहुँच करीब 5 1 करोड़ लोगों तक हैं। स्पेनिश 42 करोड़ तक पहुँचती हैं। तथा हिन्दी का आकड़ा 49 करोड़ को छूता हैं। चीनी भाषा को बहुत बड़ा तबका बोलता है, लेकिन वह उस तरह संपर्क की भाषा नहीं है। वह अपने लोगों से आगे नहीं जाती। जैसे अंग्रेजी और स्पेनिश जाती है और हिन्दी भी उस रास्ते पर आगे बढ रही है।'(2)

''हिन्दी का कोई भी रूप रहा हो लेकिन वह कम से कम हजार साल से तो इस समाज की संपर्क भाषा है। कारोबार तो संपर्क भाषा में ही होता है; इसलिये हिन्दी यहाँ के बाजार की सहज भाषा है।''(3) हिन्दी तो ऐसी भाषा है जिसे आम आदमी ने बनाया है, उसी ने बरता है। हिन्दी आम आदमी की भाषा है यह अभिमान करने वाली बात है। क्योंकि इसी आम ने बाजार को उपभोक्ता दिये व्यवसाय को गति दी, उत्पादनों में अभिवृद्धि की है। इसिलिये वह आम से खास हो जाती है। हिन्दी भाषा की जीवन्तता, निरन्तरता ही उसकी विशिष्टता है।

''हिन्दी के मनोरंजन चैनल 38 फीसदी भारतीय बाजार पर हावी हो रहे

है। इस वर्ष 4 फीसदी और बढ़ गये है। वर्तमान में ये चैनल ग्लोबल होते जा रहे है। अमेरिका, इग्लैण्ड और खाडी के देशों में भी इसका असर है।''(4)

अंग्रेजी इस देश के खास लोगों की संपर्क भाषा है। हिन्दी इस समाज के आम लोगों के आपसी बात व्यवहार की भाषा है। जबकि अंग्रेजी में सारा कारोबार थोपा थोपी पर चला है। आज टी.वी. के सारे चैनल हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। बडी – बडी कंपनियां जो हिन्दी के नाम से नफरत करती थी। अब अपने विज्ञापन हिन्दी में दे रही है। बी.बी.सी. तो अपने वैज्ञानिक कार्यक्रम ''डिस्कवरी'' तक को हिन्दी में प्रसारित कर रहा है।

आज हिन्दी विश्वभाषा के रूप में उभर कर सामने आई है। जब सूचना क्रांति के इस आक्रमण से दुनिया भर की भाषाएँ विलुप्तीकरण की ओर जा रही है तब हिन्दी का परचम विश्व बाजार पर फहरा रहा है।

''सूचना विस्फोट के इस युग में हर चीज तेजी से बदल रही है भाषा, संस्कृति, विचार और फैशन सभी की समन्वित कड़ी है मनोरंजन। संचार क्रांति ने मनोरंजन को और अधिक मनोरंजक बनाने का यथा योग्य प्रयास किया।''(5)

नवें दशक में जो केवल टी.वी. कुछ महानगरों के होटल में शुरू हुआ था उस केबल नेटवर्क का मकड़ जाल अब शहरी में ही नहीं अपितु कस्बों और गॉवों तक पहुँच गया है। वर्तमान में हमारा देश जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है, क्योंकि यही उनके लिये अच्छा बाजार है, और बेहतर कारोबार की संभावनायें भी है।

वर्तमान में कई देशों में हिन्दी की विदेशी शैलियां प्रयुक्त होने लगी जैसे सरनामी हिन्दी (सूरीनाम) फीजी बात (फीजी) जेटाली (दक्षिणी अफ्रीका) पार्चा (उज्जबेकिस्तान) आदि में।''(6)

हिन्दी का क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा टेलीविजन उपग्रह चैनल इत्यादि पर मनोरंजक तथा सूचना प्रधान कार्यक्रम दिखाने की होड़ मची है। विदेशी भाषाओं की फिल्में 'डब' की जा रही है। व्यावसायिक कंपनियों बैचेन है अपने विज्ञापन बाजार में लाने के लिये यही कारण है कि किसी भी सीरियल के प्रसारण के मध्य कमर्शियल ब्रेक ढेर सारे विज्ञापन पेश कर देता है। आज जब सारा व्यापार व्यवसाय हिन्दी पर आश्रित और आधारित हो गया है तब भाषा की शुद्धता पर विवाद खंडा हो जाता है कि हम कैसी हिन्दी का प्रयोग कर रहे है? आलोचकों की राय माने तो यह हिन्दी इन्लिश का समन्वित रूप है हिग्लिश या यूं कहे की शब्दों का घालमेल।

यह घालमेल बाजारीकरण एवं मीडिया की प्रमुख देन हैं। क्योंकि मीडिया भी बाजारीकरण से प्रभावित हुये बगैर नहीं रह पाता है। अत: इस घालमेल युक्त शैली प्रयुक्त होने के कई कारण है।

- 1. भाषा में रोचकता लाने के लिये।
- 2. वस्तु की बिक्री बढ़ाने हेतू।
- 3. उपभोक्ता को आकर्षित करने हेत्।
- विज्ञापनों में हिन्दी अंग्रेजी का प्रयोग। 4.
- पाठकों तक अपनी भाषा के माध्यम से उत्पादक को पहुँचाना। 5.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013



115

 फिल्मी गीतों और संवादों में हिग्लिश अथवा क्षेत्रीय भाषाओं का बढ़ता प्रभाव।

कतिपय उदाहरण इन विशेषताओं को रेखांकित करने में सहायक होगे। उदाहरण देखिये–

- 1. नया दूथ पेस्ट ट्राय किया
- 2. कमर दर्द नो लापरवाही (मूव)
- 3. ठंडा ठंडा कूल कूल
- ठंडा मतलब कोका कोला

हिन्दी भाषा के साथ विज्ञापनों में प्रयुक्त अंग्रेजी हिन्दी भाषा के प्रवाह के साथ चलनी है। बात सिर्फ विज्ञापनों की नहीं है। दैनिक बोलचाल में भी ये शब्द घुलमिल गये हैं और इनका शब्द प्रवाह देखते ही बनता है। कई फिल्मों में हिन्लिंश का आकर्षक रूप देखने को मिलता है। जैसे –

- ईलू-ईलू ईलू-ईलू ईलू का मतलब ILU आय लव यू
- 2. ए.बी.सी.डी. छोड़ों
- वन टू का फोर, फोर टू का वन माय नेम इज लखन सजनों का सजन मेरा नाम है लखन
- 4. फस्ट टाइम देखा तुम्हें, हम खो गया
- 5. लवेरिया हुआ

इस सारे शाब्दिक घालमेल के बावजूद हिन्दी में एक बात बहुत स्पष्ट

देखने में आती है कि मनोरंजन के कार्यक्रमों में चाहे हिन्लिश का प्रयोग होता हो किन्तु सूचना प्रधान ज्ञानवर्धक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों की भाषा मानक ही होती है।

भाषा का बाजारीकरण निश्चित रूप से प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि बाजार के साथ 'कीमत' (मूल्य) जुड़ जाता है। किसी भी देश की भाषा वहाँ की सभ्यता, संस्कृति और जीवन मूल्यों की साक्षी होती है, पहचान होती है। यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत है जिसे सहेजना संरक्षित करना संवर्धन करना हर नागरिक का कर्तव्य है क्योंकि यह हमारी राष्ट्रभाषा भी है।

कोई भाषा जब व्यापार विनिमय का माध्यम बनती है तो वह उस देश के युवाओं का मार्गदर्शन करती है, रोजगार देती है, वस्तुओं का उत्पाद बढ़ाती है, जीविका उपार्जन का साधन होती है, राष्ट्रीय आय में अभिवृद्धि भी करती है। अत: यहाँ भी भाषा का रूप मंगलकारी है, शुभ – लाभ की प्रदाता है। भारतीय जन मानस सदैव भाषा के उसी मंगलकारी रूप की वंदना करता है। मंदर्भ-

- 1. भूमण्डलीकरण निजीकरण व हिन्दी डॉ. माणिक मृगेश पृष्ठ 17
- 2. कादम्बिनी सितम्बर 2010 पृष्ठ 12
- 3. कादम्बिनी सितम्बर 2010 पृष्ठ 12
- 4. कादम्बिनी सितम्बर 2010 पृष्ठ 15
- 5. सूचना क्रांति और विश्व भाषा हिन्दी प्रो. हरिमोहन पृष्ठ ९३
- 6. कादम्बिनी सितम्बर 2010 हिन्दी तेरे कितने रूप पृष्ठ 25



शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर (जोबट) परियोजना से विस्थापित परिवारों का अध्ययन

प्रो. हेमता डुडवे *

प्रस्तावना:-

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भांखडा नांगल बाँध के उदघाटन के पश्चात् इसे आधुनिक ''भारत का मंदिर कहा'' तभी से हमारे योजनाकारों ने कृषि एवं उद्योग के विकास हेतु अनेक छोटे व बड़े बाँधों पर लगातार बल दिया है। इस क्रम में म.प्र. में भी अनेक बाँध बनाये जा रहे हैं। इन बाँधों का बनाने के लिये भूमि विशिष्ट के अनिवार्य अर्जन की आवश्यकता महसूस हुई। जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों के स्वामी परिवारों को अपने पैतृक स्थान से मजबूरन विस्थापित होना पड़ा एवं विस्थापन की पीड़ा बड़े व छोटे बाँध के नकारात्मक पहलू के रूप में सामने आई।

अपनी भूमि से मनुष्य का लगाव एव सर्वकालीन सत्य है, यह लगाव ही लोगों को कष्टों एवं संकटों के बावजूद अपने घर एवं धरती से बाँधे रखता है। इस लगाव का बंधन इतना पवित्र एवं सशस्त है कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी अपने शरीर का अंतिम संस्कार अपनी धरती पर करने की इच्छा रखते हुवे शरीर को त्यागता है तो वह अपने हाथों उस संवेदनशील बंधन को तोड़ने की पीड़ा झेलते हुए जनहित मे एक महान बलिदान करता है। अपने घर और जमीन से विस्थापित आदमी की पीड़ा की अनुभूमि और उसके बलिदान का मूल्यांकन ही उसे सही अर्थों में पुनर्वास देने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

भारत सरकार की पुनर्वास नीति:-

केन्दीय मंत्रीमंडल ने राष्ट्रीय पुनर्वास 2007 को मंजूरी दे दी जो परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए वर्ष 2003 में बनाई गई राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की जगह लेगी। इस नीति के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है:—

- 1. विस्थापन के लिए ग्राम सभा या जन सुनवाई अनिवार्य।
- जहां तक संभव हो सके, मुआवजे के रूप में जमीन के बदले जमीन।
- परियोजना की नौकरियों में एक व्यक्ति प्रति मूल परिवार को, प्राथमिकता और कुशलता विकास की व्यवस्था।
- 4. जमीन या नौकरी के बदले पुनर्वास अनुदान।
- 5. सभी प्रभावित परिवारों (भूमिहीन भी शामिल) को मकान सुविधा।
- मौद्रिक लाभ को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा व समय-समय पर पुनरीक्षण।

मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति :-

नर्मदा सागर (इंदिरा सागर) कॉम्पलेक्स प्रोजेक्ट के डूब से प्रक्षावित परिवारों के पुनर्वास से संबंधित शासन की नीति फरवरी 1985 में प्रसारित की गई थी। इसके बाद इसे और उदार बनाने के लिए समय-समय पर अनेक संशोधन किए गए। मुख्य संशोधन 1987 और 1989 में किए गए और अन्तत: म.प्र. राज्य सरकार पुनर्वास नीति को स्वीकार किया गया। यह नीति सरदार सरोवर से प्रभावित राज्य के परिवारों को म.प्र. में बसाने के लिए भी लागू होगी। इस नीति के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है:-

- राज्य सरकार का यह उद्देश्य है कि परिभाषित विस्थापित परिवारों की पुनर्वास व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी की नए स्थान पर उचित समय के पश्चात् अपने जीवन स्तर मे वे सुधार करेगें या कम से कम अपना पूर्व जीवन स्तर प्राप्त करेगें।
- विस्थापित परिवारों को परिचित स्थान से नए स्थान व नए जीवन यापन में प्रवेश करने में कष्ट न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- विस्थापितों को जहां पर बसाया जाएगा वहां पर पूर्व से ही बसे हुए परिवारों के द्धारा सामाजिक,आर्थिक या पर्यावरण संबंधी कोई विपरीत असर न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- पुनर्वास के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विस्थापित परिवारों पर तथा छोटे व सीमांत किसानों के विस्थापित परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।
- 5. भूमि आवंटन के हकदार परिवारों को नए स्थान पर बसाते समय भूमि को विकास सक्षम इकाई का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा।

परियोजना का परिचय:-

म.प्र. के पश्चिम में स्थिति जिला अलीराजपुर के वास्केल गाँव में हथनी नदी पर बाँध बनाया गया है बाँध की दूरी धार जिले की कुक्षी तहसील से 24 कि.मी. और भोपाल से 400 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

हथनी नदी अलीराजपुर जिले की आजाद नगर (भाबरा) तहसील के सेजावाड़ा ग्राम से इसका उद्भम है यह वहीं तहसील है जिसमें अमर वीर सैनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जन्म भूमि के समीपवर्ती ग्राम सेजावाडा को अपना उद्भम स्थान बनाती हुई आदिवासी क्षेत्र की यह पावन गंगा "हथनी" नाम को धारण कर अपने आंचल में आदिवासी का प्यार समेट कर एवं उन्हें सौगात के रूप में अमूल्य उपहार देती हुई अंत में अलीराजपुर जिले के ग्राम ककराना में पवित्र नर्मदा में समाहित होती है। यह ककराना गाँव गुजरात में बन रहा सरदार सरोवर परियोजना से डूब क्षेत्र में आता है।

बाँध की आधारशिला तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल ने रखी है इस परियोजना का नाम शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर परियोजना है इस बाँध का नाम अमर सेनानी पर इससिये रखा है कि नदी और सेनानी दोनों का जन्म अलीराजपुर जिले आजाद नगर(भाबरा)तहसील में हुआ है।

परियोजना मुख्य बाँध की स्थिति :-

इस परियोजना की परिवाहक बाँध के रूप में बनाया गया है। इस बाँध की कुल लंबाई 169.50 मीटर है तथा परिवाहक बाँध के अतिरिक्त पानी के निकास हेतु 8 द्धार (गेट) है और इस बाँध की अधिकतम ऊंचाई परिवाहक से हैं। इस परियोजना के बांयी तट पर एक मुख्य पक्की बहाव नहर जिसकी लंबाई 29.73 कि.मी. है तथा इसके अन्तर्गत 10 वितरण नहरें एवं 57 शाखा नहरें एवं 126 उपनहरें बनाई गई।



nss

परियोजना से भू-अर्जन:-

जोबट परियोजना के पूर्ण जलाशय का स्तर 260.17 मीटर है, पर इस परियोजना से 13 गाँवों में आंशिक रूप से डूब में आ रहे हैं। कुल गाँवों की कुल 1324.73 हैक्टेयर भूमि प्रभावित हो गई है इसमें से 813.13 हैक्टेयर निजी भूमि पर अधिग्रहण पर मुआवजा राशि वितरित किया जा चुका है।

शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर परियोजना से प्रभावित भूमि का विवरण:-

क्र.	भृमि का प्रकार	तहसील अलीराजपुर	तहसील जोबट	योग
1.	निजी कृषि भूमि	203.45 है.	609.68 ਵੇ.	813.13 हे.
2.	शासकीय भूमि	147.42 है.	240.97 हे	388.38 हे.
3.	वन भृमि	47.12 है.	76.10 हे.	123.22 हे
	योग	397.99 हे.	926.74 हे.	1324.73 हे.

स्त्रोत:- कार्यालय शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर(जोबट) परियोजना नानपुर जिला अलीराजपुर म.प्र.

शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या विवरण:-

丣.	गाँव	आशिक	quf	योग	25%	25 % से	योग	25%	योग
		प्रभावित	प्रभावित		से कम	প্রথিক		कम	
		परिवार	परिवारों		भूमि	भृमि		भृमि	
			के		प्रभावित	प्रभावित		प्रभावित	
			संख्या		परिवारों	परिवारों		परिवारों	
					কী	की संख्या		কী	
					संख्या			संख्या	
अली	राजपुर त	इसील के							
1.	माछितिया	270	100	370	236	52	52	13	13
2.	वास्केल	76	90	166	107	09	09	22	22
3.	पलासदा	74	06	80	72	06	06	-	-
4.	मसनी	24	-	24	24	09	09	-	-
जोब	ट तहसील	के							
5.	चन्दा	490	204	694	239	90	90	157	157
6.	सिन्धी	26	-	26	26	-	-	-	-
7.	छोटी	212	68	280	175	33	33	15	15
	खद्दाली								
8.	बद्धी	64	04	68	68	-	-	-	-
	खद्दाली								
9.	भानपुर	43	06	49	29	02	02	_	-
10.	बगदी	05	-	05	05	_	-	-	-
11.	इन्दवन	07	-	07	-	03	03	-	-
12.	डाबडी	07	-	07	07	_	-	-	-
13.	भीति	173	70	243	122	02	02	06	06

स्त्रोत:- कार्यालय शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर(जोबट) परियोजना नानपुर जिला अलीराजपुर म.प्र.

शहीद चन्दशेखर आजाद सागर (जोबट) परियोजना से आंशिक रूप से डूब में आया उम्दा गांव में पुनर्वासित परिवारों को अध्ययन में लिया गया है।

उद्देश्य:-

- . विस्थापितों परिवारों को प्राप्त आधारभूत सुविधाओं का मूल्याकंन।
- 2. सरकार द्धारा विस्थापितों परिवार के पुनर्वास का अध्ययन करना।
- विस्थापन के पूर्व व विस्थापन के पश्चात् की आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना।
- समस्याओं से अवगत होकर सुझाव प्रस्तुत करना।

परियोजना से लाभ:-

सिंचाई: – यह योजना भारत सरकार द्धारा घोषित सूखा उन्मुख क्षेत्र में स्थिति है, तथा नर्मदा घाटी के विकास हेतु जल का उपयोग करने वाली योजना आयोग द्धारा स्वीकृत माध्यम सिंचाई योजना है।

इस परियोजना से धार जिले कुक्षी तहसील सिंचाई का लाभ होगा। इस परियोजना सिंचाई के लिये नहर की लंबाई 29.73 कि.मी. है तथा इसके अन्तर्गत 10 वितरण नहरें एवं 57 शाखा नहरें एवं 126 उपनहरें बनाई गई है। परियोजना से 24 गाँवों का लाभ होगा। इससे कुल 12799 हैक्टेयर में सिंचाई होगी। जिसमें खरीफ फसल हेतु 5614 हैक्टेयर तथा बारह मासी फसल हेतु 7185 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

मत्स्य उत्पादन :- इस परियोजना से अपार क्षमता वाला जलाशय होने के कारण प्रचुर मात्रा में मत्स्य उत्पादन होगा जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

पर्यावरण में सुधार:-इस परियोजना के डूब क्षेत्र के स्थान पर नये क्षेत्र में वनरोपण किया गया साथ ही जल का स्तर वृद्धि होने से पर्यावरण में भी सुधार हो रहा है।

कृषि उत्पादन: - इस परियोजना से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई साथ ही आसपास के क्षेत्र में भी जल स्तर में भी वृद्धि हुई। इस परियोजना के आने से लोगों को रोजगार प्राप्त भ हो रहा है।

सुझाव:- 1. विस्थापन के बाद रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए ताकि विस्थापित परिवारों को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

- 2. विस्थापन के बाद इन परिवारों के लिये कल्याणकारी योजना चलाना चाहिए। ताकि इन लोगों को दुख न रहे।
- 3. पर्यावरण क्षिति को कम करने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए।
- 4. विस्थापन के बाद में, स्थापना के स्थान पर, सरकार को विस्थापित परिवारों को, कोई समस्या तो नहीं है। इसके बारे में सरकार को समय–समय पर पुनर्वास स्थान जाकर देखना चाहिए।
- 5. विस्थापन के बाद आधारभूत सुविधाओं का पूर्ण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए।
- ____ 6. कृषकों को डूब में आने वाली भूमि के स्थान पर उचित तथा उपयुक्त गुणवत्ता वाली कृषि भूमि उपलब्ध कराना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- कार्यालय शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर(जोबट) परियोजना नानपुर जिला अलीराजपुर म.प्र.
- 2. ''नायक जे.पी. विस्थापन एवं पुनर्वास'' 1990

मध्यप्रदेश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपलब्धियाँ- एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. मालिसंह चौहान *डॉ. अर्जुन सोलंकी **

प्रस्तावना:-

भारत गाँवों का देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गाँवो में निवास करता है। इसलिये प्राय: कहा जाता है कि⁽¹⁾ भारत के ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख समस्या व्यापक स्तर पर बेरोजगारी है।⁽²⁾ राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने परतंत्रता काल में ग्रामीण भारतवासियों की दुर्दशा को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। उनकी यह मान्यता थी कि भारत की आत्मा गाँवों में ही निवास करती है। यदि भारत के गाँव विनष्ट हुए तो पूरा देश नष्ट हो जाएगा (if villages perish India will Perish too) अर्थात् गाँवों के विकास के अभाव में भारत की समृद्धि, सम्पन्नता व आत्मनिर्भरता अर्थहीन है।⁽³⁾ पराधीनता के लम्बें दौर में भारत के गाँवों की बिल्कुल उपेक्षा हो गई थी जिससे देश की अर्थव्यवस्था तो जर्जर हुई ही, ग्रामीण भारत में गरीबी और बेरोजगारी ने स्थायी डेरा डाल लिया था। यह स्थिति भयावह और दुखमई थी जिसे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने एक बडी चुनौती के रूप में लिया और गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम शुरू किए।⁽⁴⁾

यहाँ यह बताना उचित होगा कि (5) सन् 1951 में जब पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू की गयी थी उस समय भारत के ग्रामीण क्षेत्र में श्रम का आधिक्य, पूँजी एवं उद्यम की कमी तथा व्यापक स्तर पर गरीबी जैसी मुख्य समस्याएँ थी। लेकिन (6) पचास के दशक के शुरू में (1952) सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) के अन्तर्गत भारत के गाँवों में विस्तार व विकास सेवाओं (NES) का जाल बिछाया गया। साठ के दशक में पैकेज कार्यक्रम (1960), गहन जिला कृषि कार्यक्रम (1960), ग्रामीण उद्योग परियोजना (1962), गहन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम (1964), कुआ निर्माण कार्यक्रम (1966), आदि चलाया गया। सत्तर के दशक में सूखा क्षेत्र पीड़ित कार्यक्रम (1970), लयु कृषक विकास एजेन्सी (1971), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1972), सूखा क्षेत्र कार्यक्रम (1973), विशेष दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम (1975), मरूभूमी विकास कार्यक्रम (1977), काम के बदले अनाज (1977), सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1979), अन्त्योद्धय कार्यक्रम (1979), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1979) चलाया गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1979) चलाया गया।

अस्सी के दशक के पूर्वाद्ध में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम (1980), नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम (1982), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (1983), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (1983), आदि चलाया गया। 1980 के उत्तराद्ध में ग्रामीण विकास की जो योजनाएँ प्रारम्भ की गई है उनमें इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, सामूहिक बीमा योजना, जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, जलधारा एवं कुटीर ज्योति कार्यक्रम आदि उल्लेखनीय है।⁽⁷⁾ 1980 से 1990 के दशक में भारत सरकार की आर्थिक नीति ने निजीकरण को

मान्यता दी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में आयात – निर्यात नीति में दिलाई दी गई लेकिन अनिवासी भारतीयों ने (जैसी कि उनसे अपेक्षा की गई थी) कृषि क्षेत्र तथा प्राथमिक उद्योगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नौवी योजना में अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं में समन्वय किया गया जैस⁽⁸⁾ एकीकृत ग्राम विकास योजना, ट्रायसेम योजना, ड्वाकरा योजना, उन्नत टूल किट योजना, गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कूप योजना को समाप्त कर 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999' के नाम से एक नई योजना अवधारित की गई। 'शे इसी प्रकार 'सम्पूर्ण ग्राम समृद्धि योजना' एवं 'रोजगार आश्वासन योजना' को समाहित कर 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरआई) चालू की गई। '10' वर्तमान में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के 'समाहित कर दिया गया है।

इस योजनाकाल में ही ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोडने हेतु पूरे देश में 'प्रधानमंत्री सडक योजना,2000' को संचालित किया गया। दसवी पंचवर्षीय योजना (2002-07) काल में ग्रामीण विकास की दिशा में अभी तक के सर्वाधिक तेज प्रयास किए गए और इस अवधि मे ग्रामीण विकास की रफ्तार काफी तेज हुई। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि में गाँववासियों को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी सूनिश्चित किए जाने के उद्धेश्य से 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना २००६' जिसे अब 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)' कर दिया गया है। विशेष रूप से उल्लेखनीय⁽¹¹⁾ योजना है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम आधारित उपयोगी निर्माण एवं रचनात्मक परियोजना कार्य सम्पादित कराने की व्यवस्था रखी गई है जिसमें प्रमुख रूप से जल-संरक्षण,जल संग्रहण, भूमि संरक्षण, सूखा और बचाव कार्य, पौधरोपण, तालाबों, पोखरों की सिल्ट सफाई, ग्रामीण सड़कों और नालियों का निर्माण आदि कार्यो का पूर्ण कराया जाना सम्मिलित है। यह उल्लेखनीय है कि यह योजना अस्थायी तोर पर शारीरिक श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण को न्यूनतम निर्धारित मजबूरी दर पर रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करती है।

इस योजना के अन्तर्गत⁽¹²⁾पुरुष-स्त्री को समान मजदूरी का प्रावधान है। और साथ-साथ किसी स्कीम में कम-से-कम तैंतीस प्रतिशत रोजगार महिलाओं को उपलब्ध होगा।⁽¹³⁾ रोजगार के लिए आवेदन करने वाले वयस्क को पंद्रह दिन के अंदर रोजगार प्रदान किया जाता है। रोजगार नहीं देने की स्थित में उसे बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है।⁽¹⁴⁾ यहाँ यह भी बताते चले कि⁽¹⁵⁾मध्यप्रदेश में इस योजना की शुरूआत 2 फरवरी 2006 से की गई थी। ओर इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में 18 जिले, द्वितीय चरण में 13 जिले तथा तृतीय चरण में शेष 17 जिले सम्मिलत किये गये थे। इस प्रकार वर्तमान में यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है।⁽¹⁶⁾

प्रस्तृत शोध-पत्र मध्यप्रदेश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार



गारंटी योजना की उपलब्धियों पर आधारित है।

अध्ययन का उद्धेश्य:-

उक्त योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में विभिन्न वित्तीय वर्षों में जॉबकार्ड धारक परिवार, रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार, 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार एवं सृजित मानव दिवस (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परिवार के साथ-साथ महिला) की संख्या ज्ञात करना अध्ययन का उद्धेश्य रहा है।

समंक संकलन:-

प्रस्तुत शोध-पत्र मध्यप्रदेश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपलिब्धियों पर आधारित है। यह द्धितीयक स्रोतों से प्राप्त समंको पर आधारित अध्ययन है। उक्त अध्ययन हेतु विभिन्न वित्तीय वर्षों के समंको का संकलन मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल स्थित कार्यालय से किया गया है। संकलित समंकों का वर्षवार गहनता से विश्लेषण करते हुए उक्त योजना की उपलिब्धियों को ज्ञात करने का पूरा प्रयास किया है।

समंकों का विश्लेषण:-

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से मध्यप्रदेश मे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपलिब्धियाँ जैसे विभिन्न वर्षो में जॉबकार्ड धारक परिवार, रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार, 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार एवं सृजित मानव दिवस (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परिवार के साथ–साथ महिला) की संख्या को अग्रलिखत तालिका मे दर्शाने एवं उनका विश्लेषण करने से पूर्व यह बताना उचित होगा कि उक्त योजना में जॉबकार्ड के आधार पर ही किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो सकता है। अर्थात् जॉबकार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिससे आवेदक को रोजगार की पात्रता मिलती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पंजीकृत परिवार को पंचायत द्धारा जॉबकार्ड जारी किया जाता है जिसमें सम्बंधित परिवार के वयस्क सदस्यों की फोटो एवं परिवार का पूर्ण विवरण होता है। यह पत्र जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए वैध होता है एवं कार्ड पर सम्बंधित परिवार की पंजीकरण संख्या दर्ज होती है।

(देखिये तालिका क्रमांक 1)

संलग्न तालिका से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश मे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल 4446 195 परिवारों को जॉबकार्ड उपलब्ध करवाया गया था जिसके आधार पर 2863903 परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ था। उक्त परिवारों में से 531556 परिवार ऐसे थे जिन्हें 100 दिवस का रोजगार प्राप्ता हुआ था। इसी वित्तीय वर्ष में सृजित मानव दिवस की कुल संख्या 1981.45 लाख थी जिसमें से 313.95 लाख अनुसूचित जाति, 962.90 लाख अनुसूचित जनजाति एवं 704.60 लाख अन्य परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ था।

इसी वित्तीय वर्ष में महिला सृजित मानव दिवसों की कुल संख्या 852.53 लाख थी। वर्ष 2007-08 में जॉबकार्ड उपलब्ध करवाये गये परिवारों की संख्या बढ़कर 7238784 हो गई जिसके आधार पर कुल 4346916 परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ था। उक्त परिवारों में से 912107 परिवार ऐसे थे जिन्हे 100 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ था।

इसी वित्तीय वर्ष ने सृजित मानव दिवस की कुल संख्या 2753.01 लाख थी जिसमें से 491.96 लाख अनुसूचित जाति, 1342.46 लाख अनुसूचित जनजाति एवं 918.59 लाख अन्य परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ था। इसी वित्तीय वर्ष में महिला सृजित मानव दिवसों की कुल संख्या 1147.29 लाख थी।

इसी प्रकार वर्ष 2008-09 में भी जॉबकार्ड उपलब्ध करवाये गये परिवारों की संख्या तीव्रगति से बढ़ी और वह बढ़कर 11229546 हो गई जिसके आधार पर कुल 5204924 परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ। उक्त रोजगार प्राप्त परिवारों में से 979026 परिवार ऐसे थे जिन्हें 100 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ था। इसी वित्तीय वर्ष में सृजित मानव दिवस की कुल संख्या 2946.97 लाख थी जिसमें से 525.07 लाख अनुसूचित जाति, 1379.54 लाख अनुसूचित जनजाति एवं 1042.35 लाख अन्य परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ था। इसी वित्तीय वर्ष में महिला सृजित मानव दिवसों की कुल संख्या 1275.39 लाख थी।

वर्ष 2009-10 में पूर्व वर्षानुसार जॉबकार्ड उपलब्ध करवाये गये परिवारों की संख्या बढ़कर 11292252 हो गई परन्तु इसके आधार पर रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में कमी आई अर्थात् वह घटकर 4722409 हो गई। उक्त रोजगार प्राप्त परिवारों में से 731518 परिवार ऐसे थे जिन्हें 100 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ था। इसी वित्तीय वर्ष में सृजित मानव दिवस की कुल संख्या 2623.12 लाख थी जिसमें से 484.35 लाख अनुसूचित जाति, 1188.25 लाख अनुसूचित जनजाति एंव 950.52 लाख अन्य परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ था।

इसी वित्तीय वर्ष में महिला सृजित मानव दिवसों की कुल संख्या 1171.38 लाख थी। वित्तीय वर्ष 2010-11 में जॉबकार्ड उपलब्ध करवाये गये परिवारों की संख्या मे ओर वृद्धि हुई अर्थात् वह बढ़कर 11384370 हो गई परन्तु इसके आधार पर रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या में पूर्व वर्ष के समान ही कमी आई अर्थात् उक्त वित्तीय वर्ष में कुल 4384683 परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ था। इन परिवारों में से 465391 परिवार ऐसे थे जिन्हें 100 दिवस का रोजगार प्राप्त हुआ था। इसी वित्तीय वर्ष में सृजित मानव दिवस की कुल संख्या 2204.01 थी जिसमें से 428.19 लाख अनुसूचित जाति, 954.72 लाख अनुसूचित जनजाति एवं 821.1 लाख अन्य परिवारों को रोजगार प्राप्त हुआ था। उक्त वित्तीय वर्ष में महिला सृजित मानव दिवसों की कुल संख्या 978.32 लाख थी।

निष्कर्ष:-

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में प्रारम्भिक तीन वित्तीय वर्षों में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपलिधयाँ बहुत संतोषजनक रही है अर्थात् वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में जॉबकार्ड उपलब्ध करवार्ये गये परिवारों, रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों एवं 100 दिवस का रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों की संख्या में सराहनीय वृद्धि हुई है। उक्त वित्तीय वर्षों में ही सृजित मानव दिवस (जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परिवारों के साथ-साथ महिला) की संख्या में भी आशानुरूप वृद्धि हुई परन्तु बाद के दो वित्तीय वर्षों में योजना की उपलिब्धियों में गिरावट आई है। अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में केवल जॉबकार्ड उपलब्ध करवारें गये परिवारों की संख्या में ही वृद्धि दृष्टिगत हो रही है जबिक रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों एवं 100 दिवस का रोजगार प्राप्त कर चुके परिवारों की संख्या के साथ-साथ सृजित मानव दिवसों की संख्या में निरंतर गिरावट दिखाई दे रही है।

उक्त स्थिति के बावजूद मध्यप्रदेश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का एक उजला और उपयोगी पक्ष भी है क्योंकि इस योजना से ग्रामीण जनजीवन के कई स्तरों पर खुशहाली आई है, कई पिछडे



इलाकों से गरीबों का पलायन थमा है, मजदूरी दर में सुधार आया है तथा आर्थिक स्थिति ने नई करवट ली है। अंत में यह यह कहना उचित होगा कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण जनजीवन को अपनी छतरी से लाभान्वित करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही इस योजना के प्रारम्भिक तीन वित्तीय वर्षों के बाद दो वर्षों में आई गिरावट पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि प्रदेश के लाखों ग्रामीण बेरोजगार लोग इस योजना की और आशा भरी निगाहों से देख रहे है।

संदर्भ सूची

- यादव, सुबहसिहं (1991) ''ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था'' रावत पिलकेशन्स नई दिल्ली पृष्ठ 6
- 2. डॉ. मामोरिया, चतुर्भुज (2009) ''भारत का आर्थिक विकास एवं नियोजन'' एसबीपीडी पब्लिसिंग हाउस 3/20-इ, निकट तुलसी सिनेमा, आगरा-मधुरा बाईपास रोड आगरा पृष्ठ 101
- डॉ. सिंह, सुदामा एवं डॉ. सिंह, राजीवकृष्ण (२००७) ''भारतीय अर्थव्यवस्था''
 राधा पिलकेशन्स अंसारी रोड़ दिरयागंज, नई दिल्ली पृष्ठ 346
- 4. त्यागी, सत्यवीर (अक्टूबर 1998) ''कितनी कारगर' है ग्रामीण विकास योजनाएँ'' कूरूक्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली पृष्ठ 57
- 5. डॉ. सोलंकी, अर्जुन एवं डॉ. बकावले, सुनीता (नवम्बर 2011) ''बड़वानी विकास खण्ड में ''मनरेगा'' की प्रगति–एक अध्ययन'' ग्रामीण विकास समीक्षा, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनयम विशेषांक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान राजेन्द्रनगर, हैंदराबाद (आंध्रप्रदेश) पृष्ठ 82

- 7. डॉ. सिंह, सुदामा एवं डॉ. सिंह, राजीवकृष्ण (२००७) तदैव पृष्ठ ३४७
- 8. डॉ. पन्त, डी.सी. (२००१) ''भारत में ग्रामीण विकास'' कॉलेज बुक डिपों त्रिपोलिया जयपुर पृष्ठ २४४
- डॉ. अग्रवाल, उमेशचन्द्र (मार्च 2010) ''ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर-एक आकलन'' प्रतियोगिता दर्पण, 2/11 अ स्वदेशी बीमा नगर, आगरा पृष्ठ 1441
- 10. डॉ. पन्त, डी.सी. (2009) तदैव पृष्ठ 244
- 11. डॉ. अग्रवाल, उमेशचन्द्र (मार्च 2010) तदैव पृष्ठ 1441-1442
- 12. भण्डारी, जयंतीलाल (2008) ''दो वर्ष पहले मारा मीर'' राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र, 10 अप्रैल पृष्ठ 4
- 13. दत्त, विजयरंजन (अगस्त 2010) ''नरेगा से गाँव में रोजगार'' प्रतियोगिता दर्पण, 2/11 अस्वदेशी बीमा नगर, आगरा पृष्ठ 94
- 14. भण्डारी, जयंतीलाल (2008) ''कैसी गारंटी, कैसा रोजगार'' नवभारत टाइम्स समाचार पत्र (मुम्बई संस्करण) 25 अगस्त पृष्ठ 6
- 15. मिश्र आशीष, बबेले पीयूष एवं मिश्र वीरेन्द्र (23 मई 2012) '' दम तोड़ती मनरेगा'' इंडिया टुडे, लिविगं मीडिया इंडिया लिमिटेड घ-9 कनॉट सर्कस, नई दिल्ली पृष्ठ 23
- 16. डॉ. सोलंकी, अर्जुन एवं झा, साधना कुमारी (जुलाई-सितम्बर 2012) ''आदिवासी बहुल बड़वानी जिले में मनरेगा के लाभार्थियों का अध्ययन'' माइन्ड एण्ड सोसायटी जर्नल, मानव नवनिर्माण संस्थान, 60-कंचनबाग, राजनंदगाँव (छत्तीसगढ़) पृष्ठ 52

(तालिका 1) मध्यप्रदेश में विभिन्न वित्तीय वर्षो में रोजगार उपलब्धता की स्थिति

सं.	विस्तीय	जॉबकार्ड	रोजगार	100	सृरि	जत मानव	दिवस (व	नाखों में)
क्र.	वर्ष	धारक परिवार (संख्या)	प्राप्त करने वाले परिवार (संख्या)	दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवार (संख्या)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य परिवार	कुल	महिला
1	2006-07	4446195	2863903	531556	313.95	962.90	704.60	1981.45	852.53
2	2007-08	7238784	4346916	912107	491.96	1342.46	918.59	2753.01	1147.24
3	2008-09	11229546	5204924	979026	525.07	1379.54	1042.35	2946.97	1275.39
4	2009-10	11292252	4722409	731518	484,35	1188.25	950.52	2623.12	1171.38
5	2010-11	11384370	4384683	465391	428.19	954.72	821.1	2204.01	978.32

स्रोतः महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र., प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष २००७-०८ एवं २०१०-११ पुष्ठ क्र. क्रमशः ३९ एवं २०।



nss

मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास की आवश्यकता

डॉ. आशा साखी गुप्ता *

पिछले दशक से विकास के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। आज के संदर्भ में किसी भी देश का उद्देश्य मात्र उत्तरोत्तर विकास को प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिये, वरन् विकास को सतत् बनाये रखना तथा विकास को प्राप्त करने का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है।

समावेशी विकास एक व्यापक आधार विकास है इसका उद्देश्य देश के विकास में लोगो की भागीदारी बढ़ाना, साधनों के आवंटन के साथ समाज के हर वर्ग के लिए, न्यायोचित व्यय करना है, इसके साथ ही समाज में आजीविका व रोजगार के समान अवसर प्राप्त होने चाहिये।

डाँ. देवेन्द्र प्रसाद एवं डाँ.चितरंजन ओझा (2010) के मत में देश में रोजगार व आय के माध्यम से समाज के हर वर्ग को लाभ प्राप्त होना जरूरी है, क्योकि देश में क्षेत्रीय असमानताएँ है, राज्यों के भीतर असन्तुलन है, लिंग भेद तथा शहरी ग्रामीण विकास के बीच खाई है।

वर्तमान में देश का सकल घरेलू उत्पाद 8 से 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। इसमें कृषि की तुलना में सेवा क्षेत्र व निर्माण क्षेत्र का योगदान अधिक है। विकास के दृष्टिकोण के अनुसार संसाधनों का द्धितीयक व तृतीयक क्षेत्र की ओर हस्तांतरण होता है, पर भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या में बहुत कमी नहीं आयी है।

राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट (2010) के अनुसार कृषि क्षेत्र में 84 प्रतिशत छोटे व सीमांत कृषक है उनकी मासिक अर्जित आय 2115 रू. है जबकि उनका खर्च 2770 रू. है।

अत: कृषक कर्ज के चक्र में है बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में देश की आबादी का 40 प्रतिशत भाग निवास करता है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 20 प्रतिशत योगदान है। अत: देश को विकास की एक व्यापक नीति पर चलना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश तथा समावेशी विकास -

मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। प्रदेश औद्योगिक व सेवा क्षेत्र के विकास में धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा है।

प्रदेश के समावेशी विकास हेतु प्रदेश स्थित प्राकृतिक संसाधन व मानवीय संसाधन का उचित प्रयोग आवश्यक है। समावेशी समाज की संकल्पना को मजबूती देने हेतु निम्न पाँच तत्व महत्वपूर्ण है –

- 1. कृषि का विकास
- 2. रोजगार सृजन व गरीबी में कमी
- 3. सामाजिक क्षेत्र में विकास
- 4. क्षेत्रीय व अन्य असमानताओं में कमी
- 5. जैविक खेती के उन्नयन विस्तार से

विकास के संबंध में स्वतंत्रता पश्चात् प्रदेश की स्थित बहुत बेहतर नहीं रही है। राज्य के विभिन्न वर्षों में विकास दर निम्न रही –

तालिका क्रमांक - 01

वर्ष	विकास दर प्रतिशत में
2004-05	3.0
2006-06	5.3
2006-07	9.2
2007-08	4.6
2008-09	12.3
2009-10	10.5
2010-11	8.1
2011-12	12.0

स्त्रोत – योजना आयोग डाटा

प्रदेश में कई वर्षो तक विकास की दर बेहतर नहीं रही थी, पिछले चार वर्षो में विकास की दर का औसत 7.6 प्रतिशत रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया 29 जून 2012 के अनुसार मध्यप्रदेश विकास की दृष्टि से पिछले चार वर्षो में तीसरी स्थित पर है। वर्तमान में प्रदेश की विकास दर राष्ट्र की औसत विकास दर से अधिक है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000-01 में 11150 रू. रही। वहीं 2010-11 में बढ़कर 22382 रू. हो गई। इस प्रकार इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में दुगनी वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बावजूद प्रदेश में लगभग 36.7 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। जो राष्ट्रीय औसत 29.8 प्रतिशत से अधिक है।

उद्देश्य -

- 1. प्रदेश की कृषिगत स्थिति को ज्ञात करना
- 2. कृषि का समावेशी विकास के दृष्टिकोण से अध्ययन करना।
- 3. यह ज्ञात करना कि समावेशी विकास के माध्यम से गरीबी व क्षेत्रीय विषमता की स्थिति को कम किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश में कृषि तथा समावेशी विकास -

प्रदेश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार नहीं हुआ है। कृषि पर निर्भरता अधिक है। NSDP में तीनों क्षेत्रों का योगदान निम्न है –

NSDP में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2009-10 तालिका क्रमांक - 02

क्षेत्र	नध्यप्रदेश (प्रतिशत में)	भारत (प्रतिशत में)
কৃষি	26.50	14.62
चलीग	16.87	20.16
शेवा	57.63	65.22

स्त्रोत - भारत की आर्थिक सर्वेक्षण सांख्यिकी पुस्तिका 2010

स्पष्ट है कि देश की तुलना में प्रदेश में उद्योग व सेवा क्षेत्र का योगदान NSDP में कम है। वहीं कृषि क्षेत्र का NSDP में योगदान देश की तुलना में अधिक है। कृषि क्षेत्र में प्रभावी नीति के कारण वर्ष 2011-12 में 18



प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं 17 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र में तथा 8 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। यह मध्यप्रदेश के विकास की यात्रा में बेहतर अवसर है। पर इसे जनसंख्या के संदर्भ में अध्ययन करने पर निम्न परिदृश्य उभर कर आता है –

NSDP तथा जनसंख्या की निर्भरता (तालिका क्रमांक - 03)

वर्ष	कृषि क्षेत्र का NSDP	प्रतिशत जनसंख्या
	में योगदान	की निर्भरता
196061	59.9	79.3
1970-71	55.9	79.4
1980-81	43.6	76.2
1990-91	38.2	75.3
2000-01	25.8	72.9
2009-10	26.50	70.0

स्त्रोत - NSSO

स्पष्ट है कि NSDP में कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर कम हुआ है मात्र वर्ष 2009 – 10 में इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार 32 प्रतिशत तक कृषि क्षेत्र के योगदान में गिरावट आयी है। जबकि कृषि क्षेत्र में निर्भर जनसंख्या में 8.6 प्रतिशत तक की कमी आंकी गई है।

भू-भाग की दृष्टि से प्रदेश एक बड़ा राज्य है। यहाँ पैदा होने वाली फसलों में विविधता है प्रदेश में मुख्य रूप से उत्पादित की जाने वाली फसलों को दो वर्गों में बाटा जा सकता है –

- 1. खाद्याञ्च फसले गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरी, चना, दाले व तिल्हन
- ठ्यापारिक या नकदी फसले कपास, गङ्गा, तम्बाकु, अफीम, अलसी, तिल, मिर्च, सोयाबीन प्रमुख है।

प्रदेश में फसल का क्षेत्र व उसकी गहनता निम्न है-

प्रदेश में कृषि क्षेत्र (तालिका क्रमांक-04)

হার	इकाई (लाख हेक्टेयर में)
1. शुद्ध क्षेत्र	150.70
2. दो फसलीय क्षेत्र	53.49
कुल क्षेत्र	204.19
अ— खरीफ क्षेत्र	109.36
ब— रबी क्षेत्र	94.83
3. सिंचित क्षेत्र	58.28 (28.5 प्रतिशत)

स्त्रोत - कृषि विभाग मध्यप्रदेश २०१०

प्रदेश में 204.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र है इसमें मात्र 28.5% भाग ही सिंचित क्षेत्र है। इस प्रकार से सिंचित क्षेत्र को बढ़ाकर तथा फसल गहनता में वृद्धि करके उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

प्रदेश में पिछले 4 दशकों में कृषि क्षेत्र में फर्म के आकार में निरंतर कमी आयी है। प्रदेश में 66.37 लाख कृषकों के पास स्वयं की भूमि है। प्रदेश में औसत फार्म साइज 2.5 हेक्टेयर है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इसमें निरंतर कमी हो रही है। अधिक उत्पादन को प्राप्त करने के लिए भूमि के विभाजन व अपखण्डन को रोकना होगा।

राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में राज्य की भागीदारी -

कृषि विकास के संदर्भ में मध्यप्रदेश श्रेष्ठ स्थिति में है। निम्न फसलो के संदर्भ में मध्यप्रदेश का योगदान एवं देश में स्थिति बेहतर है-

प्रदेश की भागीदारी (तालिका क्रमांक - 05)

फराल	देश में प्रविशत मानीवारी	वेश में विश्वति
शोवाबीन	59.0	I
ग्राम	38.5	1
विसहन	21.0	1
दलहन	20.0	I
सिनसीड	20.8	1
मक्का	13.4	1

स्त्रोत - कृषि विभाग मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश की कृषि क्षेत्र में श्रेष्ठता का कारण सिंचाई क्षमता का विस्तार, अच्छा बीज समय पर खाद्य आदि की उपलब्धता रही है। कुछ खाद्यान फसलों के संदर्भ में प्रदेश ने पंजाब, उत्तरप्रदेश व हरियाणा जैसे प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। आज मध्यप्रदेश नेहूँ, मसाले, आलू, प्याज व लहसन का निर्यात करने की स्थित में है। इस कारण प्रदेश को जनवरी 2013 में कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है।

कृषि क्षेत्रीय समावेशी विकास -

प्रदेश में कृषि क्षेत्र से रोजगार व आय में अधिक वृद्धि की संभावनाएँ है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में समावेशी विकास के दृष्टिकोण से आय व रोजगार की और अधिक वृद्धि के लिए निम्न क्षेत्रों का अधिक विस्तार महत्वपूर्ण होगा-

- 1. पशुपालन
- 2. शीतगृह की स्थापना
- 3. भण्डारगृह की स्थापना व विस्तार
- 4. खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करना जैसे सोया ओट, सोया मिल्क, बिस्किट, तेल उद्यम आदि।
- 5. जैविक खेती को बढावा।

उक्त क्षेत्रों के विकास से रोजगार का सृजन होगा, गरीबी में कमी होगी, साथ ही क्षेत्रीय व अन्य असमानता में कमी होने के साथ पर्यावरण की रक्षा कर हम समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

सुझाव -

प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाकर निम्न तरह से समावेशी विकास की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है।

- 1. सिंचित क्षेत्र व क्षमता का विस्तार करना
- 2. फसल गहनता को बढ़ाना
- 3. श्रमिकों की कुशलता व क्षमता को बढ़ाना
- 4. कृषि विपणन में सुधार
- 5. जल स्त्रोंतो का सहीं उपयोग करना
- 6. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार करना
- 7. भूमि के अपखण्डन को रोकना

इस प्रकार हम प्रदेश में कृषि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार कर एवं क्षेत्रीय विषमताओं को कम कर समावेशी विकास की बेहतर कदम की ओर बढ़ेगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची ::-

- भारत की आर्थिक सर्वेक्षण सांख्यिकी पुस्तिका 2010
- Development Dynamics of a Backword Economy-Dr. Ganesh Kawadia. - Shree Suneeta Prakashan,Indore.
- मध्यप्रदेश का आर्थिक एवं भौगोलिक अध्ययन-डाँ.विशम्भर प्रसाद सती/ डाँ.आई.के.मन्सूरी -कैलाश पुस्तक सदन,भोपाल
- 4. मध्यप्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइड



वेश्वीकरण का टार्च उद्योग के विकास पर प्रभाव

(कुक्षी तहसील के रिचार्जेबल टार्च उद्योग के विशेष संदर्भ में)

डॉ. नटवरलाल गुप्ता *डॉ. रामेश्वर गुप्ता **

प्रस्तावना:-भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत सन् 1991 के नई औद्योगिक नीति लागू होने के साथ ही हुई थी तथा देखते ही देखते न केवल भारत अपितु समूचा विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। अनेक बड़े व समृद्ध देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विश्व में चारो तरफ अपने पैर फैलाने लगी है। जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक शीतयुद्ध ने जन्म ले लिया है। भारत जैसे विकासशील देशों पर तो इसके प्रभाव को ओर अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यद्यपि भारत ने पिछले दो दशकों से कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है,जिसका प्रमुख कारण वैश्वीकरण रहा है। तथापि बेरोजगारी, निर्धनता, महंगाई, भ्रष्टाचार व तीव्र जनसंख्या वृद्धि से दो चार हो रहे देशों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है।

आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए ही हमारे देश में उदारीकरण व वैश्वीकरण को महत्व दिया जा रहा है। प्रारंभ में इसका विरोध भी किया गया किंतु विश्व अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तथा तीव्र आर्थिक विकास हेतु हमने मुक्त अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। किंतु मुक्त अर्थव्यवस्था से जो डर था वह धीरे-धीरे उजागर होने लगा है। अन्य उद्योगों के साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बंद होने की कगार पर खड़ा कर दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमारे लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आज के दौर में देश के लघु एवं कुटीर उद्योग अपना अस्तित्व बचाने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं।वैश्वीकरण के परिणाम स्वरुप अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के बाजार पर अपनी धाक जमा रही है। देश के उद्योगों को इन कंपनियों से कडी प्रतिस्पर्धा करनी पड रही है तथा जो उद्योग इन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके, उनका पतन हो गया है।

आज वैश्वीकरण की प्रवृति को आंख मूंदकर अपनाने और उसे जनता पर थोपने की नीति ने इस पर गंभीर चिंतन करने के लिए विवश कर दिया है। विगत कुछ वर्षों से देश में विदेशी वस्तुऐं, सेवाऐं, वित्तीय संस्थाएँ, नवीन तकनीकी व संस्कृति का आगमन तीव्र गति से हुआ है व देश के उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए नित्य नए प्रलोभन दिये जा रहे है। वैश्वीकरण रुपी दानव ने हमारे देश के अनेक उद्योगों को निगल लिया है व लाखों लोगों के हाथों से रोजगार छिन लिया है। वैश्वीकरण के कारण एक तरफ जहां विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है तो दूसरी तरफ देश में आर्थिक असमानता में वृद्धि भी हुई है।

अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे है तथा गरीब लगातार पिछडते जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 27.5 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहीं है। कई लोगों को न तो दो वक्त की रोटी नसीब हो रहीं है और न ही तन ढंकने के लिए कपडे। वैश्वीकरण की चकाचौंध ने अनेक घरों के चिराग बुझा दिये हैं। आज चीन ने भारत के वस्तु बाजार को काफी नुकसान पहुंचाया है। मध्यप्रदेश के उद्योगों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है।

भारतीय उद्योगों को कमजोर करने मे सबसे बडा हाथ वैश्वीकरण का ही है। इसकी नीतियों ने पहले से औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध राज्यों (महाराष्ट्र, केरल, गुजरात,आदि) की सहायता की है किंतु आर्थिक दृष्टि से पिछडे व गरीब राज्यों (मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, राजस्थान आदि) की उपेक्षा की है। आज देश की स्थित आय के आधार पर यह है कि 20 प्रतिशत लोगों के पास देश की 80 प्रतिशत आय है और 80 प्रतिशत लोग मात्र 20 प्रतिशत आय से गुजारा कर रहे है। देश की इस दशा को सुधारने के लिए वैश्वीकरण के मोह से निकलकर देश के उद्योगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आज समृद्धि व गरीबी के बीच की खाई और अधिक गहरी हो गई है। वैश्वीकरण ने देश के अनेक लघु, मध्यम व कुटीर उद्योगों पर कुठाराघात किया है। मध्यप्रदेश के धार जिले की कुक्षी तहसील में रिचार्जेबल टार्च उद्योग भी इसकी भेट चढ़ गया है। औद्योगिक दृष्टि से पिछडे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का भी ह्यस हुआ है। इस उद्योग की समस्याओं पर चिंतन करते हुए प्रस्तृत शोध पत्र को तैयार किया गया है।

समग्र का आकार - प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल धार जिले की कुक्षी तहसील के रिचार्जेबल टार्च उद्योग का चयन किया गया है व निष्कर्षों का निरुपण किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र निम्नांकित उद्देश्यो को ध्यान मे रखकर तैयार किया गया है –

- कुक्षी तहसील के रिचार्जेल टार्च उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव को ज्ञात करना।
- 2. रिचार्जेबल टार्च उद्योग के पिछड़ने के कारणो को ज्ञात करना

क्क्षी तहसील के रिचार्जेबल टार्च उद्योग का उदय - मध्यप्रदेश में रिचार्जेबल टार्च उद्योग की शूरुआत धार जिले की कुक्षी तहसील मे सन् 1982-1983 से हुई। एक साधारण किसान श्री लखन लाल कुमावत ने फोटो फ्लश की बैटरी जो फोटो खिंचने वाले कैमरे मे प्रयुक्त होती है को देखा । जिसे देखकर उनके मन मे टार्च बनाने का विचार आया। उन्होने श्री लक्ष्मीनारायण भाई काग के साथ मिलकर श्री टीकम भाई पटेल (पटेल स्टेट बड़ीदा) की विशेष सलाह से सेविका टार्च (4वाल्ट क्षमता मे) का सफल निर्माण किया। यद्यपि इस कार्य में उन्हें अनेक परेशानियों व मुसीबतों का सामना करना पडा किंतु उनके बुलंद हीसले व कर्तव्यनिष्ठा के आगे सारी मुश्किलें आसान हो गई। इस प्रकार कुक्षी तहसील मे टार्च उद्योग की नींव रखी गई। रिचार्जेबल टार्च उद्योग के विस्तार मे श्री रमेश मुकुंद पाटीदार की महत्तवपूर्ण भूमिका रही है। धीरे-धीरे बाजार मे इस टार्च की मांग मे वृद्धि होने लगी जिसके परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति इस उद्योग के प्रति आकर्षित होकर जुड़ने लगे। कोई व्यक्ति श्रमिक के रूप इससे जुड़ा तो किसी ने अपनी पूंजी का निवेश इसमें किया। जिसके परिणामस्वरूप पूनम टार्च उद्योग,सम्राट टार्च उद्योग ,किसान टार्च उद्योग ,कृष्णा टार्च उद्योग,मारुति टार्च उद्योग,शुभ्रम



टार्च उद्योग,एवन टार्च उद्योग,आदि उद्योगो का विकास हुआ। सन् 1990से 2005 तक का समय इस उद्योग के लिए स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इस समय कुक्षी तहसील मे रिचार्जेबल टार्च की लगभग 40 फेक्ट्रीयां व लगभग 300 घरों मे टार्च के छोटे –छोटे हिस्सो मे संयोजन का कार्य किया जाता था। इनमे साल्डर कार्य,वायर संयोजन,टांसफार्म संयोजन,साइड पिन,साकेट, संयोजन, चार्जिंग पिन संयोजन आदि कार्य किये जाते थे।

इस उद्योग की सबसे बडी विशेषता यह थी कि लोगो को अपने घरो पर ही कार्य मिल जाता था तथा वे अपने अतिरिक्त समय का उचित उपयोग कर पाते थे। घरेलु महिलाओं के लिए तो यह उद्योग बहुत ही सुविधाजनक साबित हुआ। इस प्रकार रिचार्जेबल टार्च उद्योग ने इस क्षेत्र के लगभग 3000 लोगो को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया है, जो निश्चित ही महत्त्वपूर्ण है। इस उद्योग का विपणन मुख्यत गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यो मे किया जाता है।

रिचार्जेबल टार्च उद्योग में रोजगार की स्थिति – प्रत्येक उद्योग कुछ व्यक्तियों को रोजगार अवश्य देता है। रोजगार की उपलब्धता उद्योग के आकार ,वस्तु की मांग, विपणन क्षेत्र का विस्तार व वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस उद्योग ने भी क्षेत्र के अनेक लोगो को रोजगार प्रदान किया है। सन् 1990 से 2005 तक तहसील मे अन्य उद्योगो की अपेक्षा इस उद्योग से सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध हुआ है। इस उद्योग मे अकुशल व अषिक्षित व्यक्तियों के लिए भी आसानी से रोजगार का सृजन होने की वजह से यह अधिक महत्वपूर्ण उद्योग साबित हुआ। इस उद्योग मे रोजगार की रिथति का आकलन निम्न तालिका के माध्यम से किया जा सकता है –

विश्लेषण तालिका रिचार्जेबल टार्च उद्योग में रोजगार के अवसर

वर्ष	उद्योगो	उद्योग में	उद्योग के	उद्योग से
	की	कार्यरत	बाहर कार्यरत	प्राप्त
	संख्या	श्रमिक	श्रमिक	कुल रोजगार
1982-1987	10	60	40	100
1987-1992	18	300	100	400
1992-1997	22	650	350	1000
1997-2002	40	2200	800	3000
2002-2007	28	450	250	700
2007-2012	10	70	20	90

स्त्रोत – उद्योगो के सर्वेक्षण से प्राप्त समंको के आधार पर

रिचार्जेबल टार्च उद्योग की वर्तमान स्थित – वर्तमान समय में रिचार्जेबल टार्च उद्योग की स्थित अवनित की ओर है जहां एक समय 30 से 40 उद्योग कार्यरत थे वहीं आज मात्र 05 उद्योग शेष है। व इसी कारण रोजगार के अवसर भी कम हो गये है। अपने घरो मे जिन व्यक्तियों को आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाता था वह भी लगभग समाप्त हो गया है। अनेक व्यक्ति बेरोजगार हो गये है तथा विवश होकर कई लोगो ने अन्य शहरो मे पलायन का रास्ता अपना लिया है। इस प्रकार हम कह सकते है कि कई व्यक्तियों को रोजगार देने वाला यह उद्योग अब बंद होने की कगार पर खडा हो चुका है।

रिचार्जेबल टार्च उद्योग के पिछडेपन के कारण - रिचार्जेबल टार्च उद्योग का पिछडेपन की ओर धकेलने के लिए अनेक कारण जिम्मेदार है जिनमें से प्रमुख निम्न है -

- 1 चायना निर्मित वस्तुओं के बाजार का विस्तार भारत की केन्द्रीय सरकार की वैश्वीकरण की नीति ने चायना वस्तु बाजार का भारतीय बाजार मे प्रवेश कराया है। चीन की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्यारा निर्मित LED टार्च भारतीय बाजार मे आने से रिचार्जेबल टार्च की मांग मे तेजी से कमी होने लगी। चायना निर्मित टार्च तकनीकी रूप से श्रेष्ठ , लंबी अविध तक सेवा देने वाली, देखने मे सुन्दर व मूल्य मे तुलनात्मक दृष्टि से अधिक सस्ती होने के कारण उपभोक्ता को लुभाने मे सफल रही है। और अन्तत: रिचार्जेबल टार्च उद्योग पर इसका विपरित प्रभाव पडा व यह धीरे-धीरे इस टार्च उद्योग को कमजोर करते चला गया तथा आज इसका परिणाम हमारे समक्ष मौजुद है।
- 2 अशिक्षित व अकुशल व्यक्तियों द्वारा उद्योग का संचालन रिचार्जेबल टार्च उद्योग का संचालन करने वाले अधिकांश उद्यमी अकुशल व अशिक्षित थे। उद्योग के विकास के लिए शासकीय योजनाओं की न तो उनको पर्याप्त जानकारी हो पाती थी और न ही वे उद्योग के तकनीकी पहलूओं के बारे मे समझ पाते थे। पर्याप्त ज्ञान के अभाव मे रिचार्जेबल टार्च की उत्पादन लागत अधिक हो जाती थी। इसका विपरीत प्रभाव टार्च उद्योग के विपणन पर पडा व वर्ष दर वर्ष उद्योग पिछडता ही चला गया।
- 3 यातायात व संचार के साधनों का अभाव अनुसूचित जनजाति बहुल इस औद्योगिक व आर्थिक दृष्टि से पिछडे क्षेत्र में यातायात व संचार के साधन अपर्याप्त है। यातायात के साधनों के नाम पर केवल सड़क परिवहन ही उपलब्ध है और वह भी अनेक गड़ों से युक्त। इस क्षेत्र में संचार के साधन भी पर्याप्त नहीं है। जिसके कारण उद्यमी अपने द्वारा उत्पादित टार्च के विपणन बाजार का फैलाव नहीं कर पाये।
- 4 तकनीकी शिक्षा का अभाव चुंकि वर्तमान मे प्रत्येक उद्योग के लिए तकनीकी जागरूकता का विकास हुआ है और न ही उद्योग में उनके प्रशिक्षण की ही कोई व्यवस्था है। कर्मचारियों में तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण उत्पाद की गुणवत्ता में कमी होना स्वाभाविक है। और कम गुणवत्ता की वजह से यह उद्योग विदेशी व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाया व लगातार पिछडता चला गया।
- 5 रिचार्जेबल टार्च उत्पादको मे संगठन का अभाव रिचार्जेबल टार्च उद्योग से जुडे हुए उद्यमियों मे आपसी तालमेल व संगठन का अभाव होना भी इस उद्योग के पिछडने का एक कारण रहा है। उद्यमियों मे वैचारिक मतभेद व टीम भावना की कमी के कारण उद्योग की प्रगति के बारे मे कोई विशेष रणनीति नहीं बन सकी। अत: शने:–शने: उद्योग कमजोर होता चला गया।
- 6 कुशल प्रबंधन का अभाव वर्तमान समय मे प्रत्येक उद्योग की प्रगति के लिए कुशल प्रबंधन का होना, अनिवार्य शर्त है। किंतु रिचार्जेबल टार्च उद्योग मे अनियोजित रूप से उत्पादन कार्य किया जाता था। इस वजह से उद्योग की उत्पादन लागत मे वृद्धि होने लगी जिसका प्रभाव उद्योग की विक्रय क्षमता पर पडा व उद्योग पिछडने लगा।
- 7 कृषि उपकरण के रूप में सम्मिलित न किया जाना रिचार्जेबल टार्च को मुख्यरूप सें एक किसान टार्च के रूप में तैयार किया गया था। इसका उपयोग अधिकांशत: कृषको द्धारा खेत में सिंचाई के दौरान व फसलो की रखवाली करने तथा रात के समय खेतो तक पहुंचने के लिए होता था। रिचार्जेबल टार्च का उपयोग कृषि कार्य में मुख्य उपकरण के रूप में होने से उद्योगपतियों द्दारा इसे कृषिक्षत साधन घोषित कराने हेतु प्रयास किये गये जिससे की करों में राहत प्राप्त हो सके, किंतु उनके प्रयास सफल नहीं हो सके। इस कारण से यह उद्योग अन्य उद्योगों की अपेक्षा निरंतर पिछडता जा रहा है।



- 8 ग्यारंटी की सुविधा का अनुचित लाभ रिचार्जेबल टार्च उद्योग में एसिड यूक्त बेटरी व ड्राय बेटरी प्रयुक्त होती है जिसकी ग्यारंटी 6 माह से लेकर एक वर्ष तक दी जाती थी। अनेक उपभोक्ता बेटरी की ग्यारंटी की अविध नजदीक आने पर इस सुविधा का अनुचित लाभ लेने से नहीं चुकते थे। वे जानबुझकर बेटरी को लंबे समय तक चालु ही छोड देते थे व बंद होने पर वापस कर नई बेटरी प्राप्त करने में सफल हो जाते थे। तथा इस प्रकार उन्हें नई बेटरी पर पुनः ग्यारंटी प्राप्त हो जाती थी। इस कारण से यह अप्रत्यक्ष हानि दीमक की तरह उद्योग को कमजोर करती गई जिसके परिणामस्वरूप आज यह उद्योग पिछडता जा रहा है।
- 9 रिचार्जेबल टार्च के स्थान पर इनवेटर्स का चलन वर्तमान में रिचार्जेबल टार्च उद्योग को दोहरी परेशानी का सामना करना पड रहा है। एक ओर जहां कृषकों में इसकी मांग कम हो गई है तो दुसरी ओर घरेलु रिचार्जेबल टार्च का स्थान छोटे इनवर्टर्स ने ले लिया है। इससे इस टार्च की मांग में दोहरी कमी होने लगी। कुछ वर्षों में ही अनेक टार्च उद्योग इसकी मार नहीं सह सके व बंद होने लगे तथा बहुत से उद्यमियों ने दुसरे उद्योगों में की और कदम बढाना प्रारंभ कर दिया। यहीं से इस उद्योग का पतन प्ररंभ हो गया।
- 10 शासन की उपेक्षा इस उद्योग की इस स्थित के लिए कुछ हद तक शासन की नीतियाँ भी जिम्मेदार है। पिछले कुछ वर्षों से शासकीय नीतियों ने इस उद्योग को हतोत्साहित किया है। इस तहसील मे न तो टार्च उद्योग के लिए भूमि आबंटित है ओर न ही कोई विशेष सहयोग। यह उद्योग लगातार शासन की उपेक्षा का शिकार होकर पिछडता जा रहा है।
- 11 करों का अधिक भार अप्रत्यक्ष करों के अधिक भार ने रिचार्जेबल टार्च उद्योग की कमर ही तोड़ दी है। इस उद्योग पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व मध्यप्रदेश वेट लागू किया गया है। वर्तमान में इस टार्च पर 13 प्रतिशत की बड़ी हुई दर से वेट लगाया जाता है। इस प्रकार करों के प्रभाव से इस टार्च के विक्रय मूल्य में वृद्धि हो गई और अन्य समानान्तर उत्पादों से यह उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं कर सका।
- 12 टार्च की उपयोगिता में कमी होना -चीन की कम्पनियों ने आज रिचार्जेबल टार्च की उपयोगिता लगभग समाप्त ही कर दी है। चायना टार्च अब पेन में, मोबाइल में, हाथ के छल्ले में व हाथ की घडी मे भी उपलब्ध है। इस कारण अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले रिचार्जेबल टार्च का बाजार कमजोर होने लगा। इस कारण से यह उद्योग औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में अन्य उद्योगों से पिछड गया।

सुधारात्मक सुझाव व शासकीय अपेक्षाएँ-

- 1 कर भार में कमी करना -शासन से उद्योग की यह अपेक्षा है कि इसे कर भार मे मुक्त कर उद्योग को प्रोत्साहित करे। कर भार मे कमी करने पर रिचार्जेबल टार्च की विक्रय लागत मे कमी हो सकेगीं व उपभोक्ताओं मे इस टार्च की मांग उत्पन्न हो सकेगी।इस प्रकार यह छोटा सा उद्योग विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने मे सक्षम हो सकेगा।
- 2 विदेशी टार्च पर कर मे वृद्धि चायना निर्मित टार्च कीमत मे अधिक सस्ते होने की वजह से भारतीय बाजार मे अधिक पसंद किये जा रही है। और इसी कारण से चायना कम्पनियां भारतीय बाजार पर मजबूत पकड बना चुकी है। सरकार अपनी राजकोषीय नीति मे विदेशी कम्पनियों पर कर की दरों में वृद्धि कर देश के उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकती है।
- 3 तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्यमियों व कर्मचारियों को नवीन तकनीकी से आवगत कराने तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त कर कर्मचारी ओर अधिक कुशलता से कार्य कर सकेंगे

- । इससे टार्च की लागत में कमी हो सकेंगी व उपभोक्ता इस टार्च के क्रय हेतु प्रेरित हो सकेंगे। जिसके परिणामस्वरूप रिचार्जेबल टार्च उद्योग चायना कम्पनियों द्धारा निर्मित टार्च से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगा।
- 4 वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस उद्योग से जुडे उद्यमियों की शासन से यह भी अपेक्षा है कि इस छोटे से उद्योग को वित्तीय व तकनीकी सहयोग शासन द्धारा प्रदान किया जाना चाहिए। उद्योग की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता, नवीन तकनीकी यंत्रों की प्राप्ति तथा उद्योग के विस्तार हेतु वित्तीय सहयोग से निश्चित ही यह उद्योग विकसित हो सकेगा।
- 6 प्रबंधकीय कीशल का विकास प्रबंधकीय गतिविधियों के बढते प्रभाव को देखते हुए उद्योग के संचालको मे प्रबंधकीय कीशल का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। योग्य प्रबंधक सीमित संसाधनों के बावजुद भी श्रेष्ठ उत्पादन कर सकते है। अतः इस उद्योग के उद्यमियों के प्रबंधकीय कौशल में वृद्धि करने हेतु उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, तािक इस उद्योग को पिछडेपन से मुक्ति दिलाई जा सके।

निष्कर्ष -

प्रस्तुत शोध अध्ययन में हमने रिचार्जेबल टार्च उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया है। अध्ययन के पहलुओं से स्पष्ट होता है कि दोष केवल वैश्वीकरण या उदारीकरण का नहीं है अपितु उनके क्रियान्वयन का है। देश के जिम्मेदार राजनेताओं व अधिकारियों को अपनी नीतियों का निर्माण करते समय रिचार्जेबल टार्च जैसे अनेक छोटे उद्योगों की रिथति को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही देश में स्थापित उद्योगों के पिछड़ने के कारणों का गंभीरता से अध्ययन कर उनके समाधान हेतु उचित रूप रेखा तैयार करनी चाहिए व उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे देश में अनेक हुनरमंद व्यक्ति है जिनकी प्रतिभा दबी पडी है।

उनको उचित संसाधन व अवसर उपलब्ध करवाने के लिए शासकीय प्रयास होने चाहिए, तभी वैश्वीकरण का लाभ हमारे देश को सही अर्थो में प्रस हो सकेगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का फैलता काला साया अनेक लघु, कुटीर व मध्यम उद्योगों के पतन का कारण बनता जा रहा है इसे रोकने के लिए हमारे देश के उद्योगों को तकनीकी दृष्टि, आर्थिक दृष्टि, व प्रबंधकीय दृष्टि से सुदृढ करने की जिम्मेदारी शासन व जनता दोनों की है। यदि हमारे देश को औद्योगिक रूप से सक्षम बनाना है तो विदेशी वस्तुओं के मोह से हटकर देश में ही इनके विकल्पों की खोज करनी चाहिए।

संदर्भ -

1. उद्योग में संलग्न उद्यमियों से प्राथमिक समंकों का एकत्रीकरण।





बारेला-लोकजीवन एवं लोकगीत (शोध सारांश)

डॉ. सेवंती डावर * प्रो. गायत्री चौहान **

''बारेली लोक जीवन और प्रकृति का सबसे करीबी सम्बन्ध रहा है। बारेला समुदाय की जीवन शैली प्रकृति के प्रत्येक रूप से जुड़ी है। बारेला की नींद मुर्गे की बांग के साथ खुलती है, तो चिड़ियों के चहकने के साथ काम की शुरूआत हो जाती है। हम यह कह सकते हैं, कि बारेलाओं की मूल आवश्यकताएं प्रकृति से पूर्ण हो जाती है।''

बारेली पर्व, त्यौहार में पर्यावरणीय चेतना-बारेला समुदाय में वर्ष में अनेक पर्व, त्यौहार मनाये जाते हैं। सभी पर्व त्यौहार में पर्यावरणीय पुट देखे जा सकते हैं।

बारेला अधिवास क्षेत्रों में दित्वारिया पर्व मनाया जाता है दित्वारिया पर्व में फसलों की सुरक्षा हेतु मनोवैज्ञानिक टोटकों को अपनाया जाता है, जो कपास की फसल के खेत में चूने से रंगी मटकी लगायी जाती है इस टोटके के पीछे यही आशय है कि कपास में फफूंद जनित रोग नहीं लगे। ज्वार की खेती में पशुओं की हड्डी को लगाया जाता है। काला फटा जूता मिर्ची की फसल के बीच में लगाया जाता है। जिस प्रकार नवजात शिशु के गले, हाथ या पैर में काला धागा या काले मोती बाँधे जाते हैं। उसी प्रकार मिर्ची के कोमल पौधो को भी नजर नहीं लगे, इसलिए काला जूता फसल के बीच लगाया जाता है।

नवाई, दिवासा, दिवाली, इंदल, भगोरिया, होली आदि के गीतों में ऋतुएँ, नदी, पर्वत, वृक्ष आदि का वर्णन मिलता है।

वर्षा ऋतु लोक-गीत :-

झिरी-झिरी पाणी पोड़े डॉसे घुणी छोतरी चौणाय लेजी वा ऽऽ। वृक्ष से संबंधित लोक-गीत:-

उचो आम्बो कोल्यू डिरू, आम्बा मां बोसिन सेवाया कोरो वा ऽऽ माथे दाहड़े सेवाया कोरो वा ऽऽ आजुन दाहड़े रोयजा दादा सेवाया खायलीन जाती रोहजी रे ऽऽ

गरबा लोक-गीत : – म्यारा खेतोन सेड़े तेल्यों तोलावे, बलदया न पाणी पावा, जावा रे लोल ऽऽ

बलदया न पाणी पावा, ऐखली नी जाउ रे दादा,

जुवाण्यों नौयणा रावे रे लोल ऽऽ

इंदल लोक-गीत :-

पीते वियों लोटो जोले भोर यो

आमू डाळू पाणी लेणे चाल्या रे लोल, ऽऽ

काचो सूते सूती दे दो, चोटे दिने चोड़ी गोयौ

कुवारयौ भायौ ऽऽ

कोटे दिने काटी दे दो

कुवारयौ भायौ ऽऽ

चोटे दिने झेली लेदो

कुवारयौ भायौ ऽऽ

इंदल उत्सव बहुत ही श्रद्धा व शिद्धत के साथ मनाया जाता है। बारेला समुदाय में सबसे बड़ा उत्सव इंदल को माना जाता है इंदल उत्सव मनाने के पीछे वर्षा, फसल उत्पादन, पशुओं का स्वस्थ्य रहना व जनमानस का स्वास्थ्य एवं सम्पन्न समृद्ध हो इसी भावों-विचारों से परिपूर्ण होकर इंदल उत्सव मानाया जाता है।

बारेली लोक कथा, लोक गाथा, गायणा, लोक वार्ता, कहावतें आदि में भी पर्यावारणीय पुट मिलते हैं। बारेली में ज्वार को कोणसोर माता कहा गया है। लोकवार्ता में प्रकृति को सर्वोपिर माना गया है प्रकृति प्रदत्त ज्वार माता के पूजन में 'खोळो पूजणो' अनुष्ठान किया जाता है 'खोळो पूजणो' अनुष्ठान नहीं करने पर अनिष्ठ की आशंका बनी रहती है।

निष्कर्ष:-

विभिन्न साहित्यकारों ने साहित्य और प्रकृति के घनिष्ठ संबंध का उल्लेख अपने कथनों में किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी का कथन ''भारतीय जनता का सामान्य स्वरूप जानने के लिए पुराने परिचित ग्राम गीतों और साहित्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। केवल पंडितों द्धारा परिवर्तित काव्य परम्परा का अनुशीलन ही अहम नहीं है।''

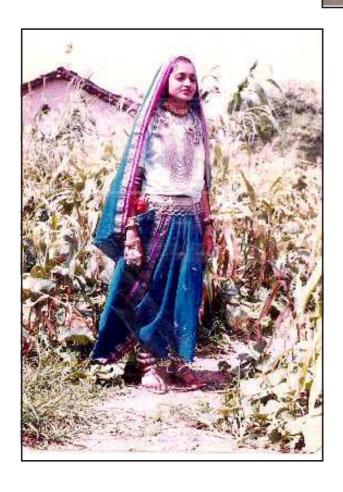
निमाइ अँचल के बारेला आदिवास कुटुम्ब केन्द्रीत है। उनके फल्या ग्राम एक ही कुटुम्ब के होते हैं। ये कृषि, मजदूरी ओर वनोपज पर निर्भर है। नीम, पीपल रेहकुली, भूताकोसन, कलम, बड़, इमली, टेमरू, गुलर आदि के वृक्ष प्रत्येक घर के आसपास या बागड़ में लगाये जाते हैं। गाँव ही प्रकृति का सच्चा दर्पण है। गाँव में सभी प्राकृतिक मनोरम दृश्य के दर्शन होते हैं। गाँव के संबंध में पंडित रामनरेश त्रिपाठी का कथन है –''गाँव सही अर्थो में पृथ्वी की संपदा है। क्योंकि इनके जीवन का प्रत्येक आचरण पृथ्वी धरती का आश्रय लेकर संवर्धित है, ग्राम संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करें।''

संदर्भ -

- 1. निमाड़ का सांस्कृतिक इतिहास-पंडित रामनारायण उपाध्याय
- 2. हिन्दी और उसकी बोलियाँ-डॉ. दीपकचन्द्र जैन
- 3. लोक साहित्य और संस्कृति –दिनेश्वर प्रसाद
- 4. लोक साहित्य की भूमिका- डॉ. कृष्ण देव उपाध्याय
- 5. आदिवासी भाषा विज्ञान-डॉ. हीरालाल शुक्ल

बारेला-लोकजीवन की झलकियाँ









बुंदेली लोक कवि ईसुरी (शोध सारांश)

डॉ. वन्दना जैन *

ईसुरी को यदि बुंदेलखण्ड का जयदेव कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। ईसुरी का जीवन सहज एवं सरल था, वे लोक संस्कृति के सच्चे पारखी थे। ईसुरी ने लोक गीत की एक विशिष्ट विधा ''फाग'' को अपनाया है। वे चौकड़िया फाग के पुरस्कर्ता थे। बुंदेली लोक किवयों में शिरोमणि ईसुरी जीवन की मस्ती के किव है। जीवन के बसंत का मद, उन्मुक्त यौवन, मांसलता और दैहिक सौंदर्य की बहुरंगी अभिन्यिक्त इनकी फागों में मिलती है। वे मदन महीप के चारण थे। ईसुरी ने अपने युग की तत्कालीन परिस्थितियों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने लोक कल्याण को प्रमुखता दी। ग्राम में बसे किसानों और गरीबजन की समस्याओं से वे बहुत परिचित थे। गांव में अकाल पड़ने पर ग्रामीणजन और किसान दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा, दो दिन तक चूल्हे नहीं जले इस चिंता से वे चिंतित युगहष्टा किव की भांति लोकजन को सम्बोधित करते हुए कहते हैं–

''आसीं हींस सबई के भूले, कइयक कांखे फूले, कच्चे बेर बचे हैं नइयां, कंगीरन ने रुले। फॉके परत दिना दो-दो के, परचत नइयां चूले, मारे-मारे फिरत ईसुरी, बड़े-बड़े दिन दूले''

समाज का चितेरा और जागरुक किव ही ऐसी सशक्त अभिव्यक्ति कर सकता है। सच्चे अर्थों में कहा जा सकता है कि ईसुरी बुंदेलखण्ड के लोकनायक है उन्हें सदैव लोक कल्याण की चिंता रहती थी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। आज पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या देश के सामने खड़ी हैं। उसके निदान हेतु वन संरक्षण का दृढ़ संकल्प कितना जरुरी है इसकी चिंता किव ईसुरी को भी आज से दो सौ वर्ष पूर्व उस युग में थी। उन्हें आने वाले कल का आभास था इसलिए महुए के वृक्ष को काटते हुए देखकर उसकी पीड़ा चीत्कार कर उठती है –

'' इन पै लगे कुलरियां घालन, मउवा मानुस पालन। इनै काटवी न चाइयत ते, काट देत जे कालन। ऐसे रुख भूंख के लाने, लगवा दवे नंदलालन जे करदेत नई सी 'ईसूरी', मरी मराई खालन''

लोग अनावश्यक की हरे-भरे वृक्षों को काटते है ये हमारे जीवनाधार है। हमारी भूख शांत करने के लिए ही इन्हें प्रकृति ने उत्पन्न किया है। आज की युवा पीढ़ी नशे को फैशन के रूप में अपना रही है। इससे अनेक परिवार टूट रहे है, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। गांजे की आदत का सबसे बुरा प्रभाव स्वयं व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जीवन धीरे-धीरे नष्ट होने लगता है। घर सम्भालने वाली गृहिणी अपने पति को नशा मुक्त कराने हेतु बड़े ही आत्मीय ढंग से कहती है –

'' गांजौ पियौ न पीतम प्यारे, जरजै कमल तुमारे। जरत काम, बिगारत सूरत, सूकत रकत नियारे। खॉसत खॉसत फटैं पसुरिया, कफ के वहैं पनारे। जौ तौ आय साधु संतन कौ, अपुन गिरस्ती वारे। 'ईसुरी' कात छोड़ दो संइयां, अबै उमर के बारे''

किव ईसुरी में देश भक्ति की प्रबल भावना थी। उन्होंने वीरों का उत्साहवर्द्धन कर देश रक्षा हेतु सजग रहने की प्रेरणा दी। अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में युवा पीढ़ी आगे आये और तन,मन,धन से भारत माता को स्वतंत्र कराने का आव्हान किया है –

'' जो कोउ समर भ्रम लड़ सोवे, तन तरवारन खोवै।

देय न पीठ, लेय छाती में, घाव सामने होवै। ऐई ज्वान खों करो चाइये, अदा नोन से होवै। ऐसे नर के मरें ईसुरी, जस गंगा की होवे''

राष्ट्र का ऋण चुकाकर यश प्राप्ति हो सकती है। देश के लिए बलिदान देने वाले की सदगति होती है ऐसी मान्यता है। ईसुरी का हदय बहुत संवेदनशील है उनके हदय में समस्त मानव समाज के लिए करुणा, दया का भाव है। वे सभी को दया के रास्ते पर चलने को प्रेरित कर रहे हैं –

> ''ढीपक ढ्या धरम को जारी, सद्धा रात उजयारों। धरम करे बिन करम खुलै न, ज्यों कुंजी बिन तारी। समझा चुके करै न रइयो, दिया तरै अंद्यारी। कात ईसुरी सुनलो भइया, लग जै यार न वारो''

ईसुरी धार्मिक प्रवृति के थे वे देश की जनता को सदैव धर्म परायण रहने का उपदेश देते है। राम नाम को संजीवनी बूटी कहते है –

रसना राम राम कह जारी, कोन जात है हारी। जौ हरनाम संजीवन बूटी, खात बनै तो खारी।

जीवन के अंतिम क्षणों में ईसुरी आध्यात्मिक एवं दार्शनिक हो गए थे उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता को एक रुपक के माध्यम से व्यक्त किया है-

> ''बखरी रईयत हैं भारे की, दई पिया प्यारे की। कच्ची भींट उठी माटी की, छाई फ़ूस चारे की। वे बंदेज बड़ी बेबाड़ा, जीमें दस द्वारे की किवार किवरियाँ एकउ नइयां, बिना कुची तारे की। ईसूर चाय निकारी जिदना, हमें कीन उबारे की''

इस भौतिक शरीर रुपी बखरी (मकान) की बात कहकर ईसुरी ने देह की नश्वरता और दसों इन्द्रियों पर नियंत्रण करना ही जीवन का सार तत्व बताया है। ईसुरी की मान्यता है कि दुर्लभ मानव योनि में आकर सभी को सत्कर्म ही करना चाहिए। यह जीवात्मा प्रियतम परमात्मा से मिलकर एकाकार हो जायेगी। लोक किव ने इहलोक को मायके और परलोक को ससुराल की उपमा देते हए कहा है कि एक दिन सभी को परलोक जाना ही पड़ेगा। चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा –

''इक दिन होत सभी को गोनों, होनों अर अनहोनी। जने परत सासरे सांसउ, बुरो अले चाय नोंनी। राखे चायै जोली ईसुर, देय उनई भर सोनी।

इस प्रकार ईसुरी को संसार की असारता का आभास हो जाता है वे माया-मोह छोड़ कर परलोक जाना उचित समझते है। तभी तो सांसारिक मायाजालों से ऊब कर आत्मा को संबोधित करते हुए कहते है-

> ''हंसा उड़ चल देस विराने, सरवर जायें सुखानें। इतै रये की कौन भलाई, जितै बकन के थानें। समुद भरे हैं अगम उतै चल, सुख पावै मनमानें। बचत बनें तो बचौ ईसुरी, तानें काल कमानें''

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ईसुरी अपने युग के संवेदनशील प्रगतिशील, यथार्थवादी और क्रांतिकारी लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध है।

सन्दर्भ ग्रन्थ -

- ा. मधुकर पात्रका
- 2. बुन्देली लोक संस्कृति –अप्रकाशित शोध प्रबन्ध –डॉ. वन्दना जैन
- 3. मामुलिया- सम्पादक- डॉ.नर्मदाप्रसाद गुप्त
- ईसुरी प्रकाश (प्रथम भाग) सम्पादक–गौरीशंकर द्विवेदी 'शंकर'



लोक साहित्य : कितने रंग, कितने रूप

डॉ. अरूणा दुबे *

लोक शब्द संस्कृत के लोक दर्शने धातु में प्रत्यय लगने से बना है इसका अर्थ देखना है। अत: लोक शब्द का अर्थ है कि देखने वाला। इस प्रकार समस्त जनसमुदाय जो इस कार्य को करता है वह लोक कहलाएगा। लोक शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में जन के लिये हुआ है –

> य इमे रोबसी उभे अहिमन्द्रमनुष्टवं। विश्वामित्रस्य रक्षति वृह्मेबं भारतं जनं॥⁽¹⁾

डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय के मतानुसार आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथाकथित अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को लोक कहते हैं। जिसका आचार विचार एवं जीवन परम्परा युक्त नियमों से नियंत्रित होता है। वेद व्यास के अनुसार जो व्यक्ति लोक को स्वतः अपने चक्षुओं से देखता है, वही उसे समयक रूप से जान सकता है।

प्रत्यदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नर: I⁽²⁾

जो लोक को स्वयं अपनी ऑखों से देखता है वहीं व्यक्ति लोक को समझ सकता है। लोक में भूत, भविष्य एवं वर्तमान का सहचर्य रहता है। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है। इससे स्पष्ट होता है कि जो लोग संस्कृत तथा परिष्कृत लोगों के प्रभाव से बाहर रहते हुए अपनी पुरातन स्थिति में वर्तमान में है उन्हें लोक की संज्ञा दी गई है। इन्हीं के साहित्य को लोक साहित्य कहा जाता है। यह मौखिक और परम्परागत है। मौखिक होने के कारण ही यह जीवंत होता है। लोक साहित्य को जन जीवन का दर्पण कहा जाता है। सामान्यतः सर्वसाधारण की अनुभूति का प्रकाशन लोक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। ग्रामीण जनता विभिन्न संस्कारों और ऋतुओं के गीत गा–गा कर अपना मनोरंजन करती है। किस्से गाथा, कहानियाँ, कहावतें, मुहावरे द्धारा ग्रामीण जनता अपने हृदयगत विचारों को अभिव्यक्त करती है। इसका निर्माण जनता के अनुभृत के आधार पर होता है।

लोक साहित्य में प्रचुरता और व्यापकता के कारण लोक गीतों का स्थान प्रमुख है, मौलिक और मौखिक रूप से गाये जाने वाले लोक गीतों का स्थान वाचिक परम्परा में महत्वपूर्ण है। लोक गीत लोक संस्कृति के संवाहक है। इसमें जीवन की धड़कनों का एहसास देखा जा सकता है। लोक गीतों में हदयगत भावनाओं को कहने की परम्परा सबसे अधिक प्रिय और सम्प्रेषणीय रही है। गाना मन की सहज प्रवृत्ति है। इसलिये लोकगीत मनुष्य के हृदय का स्पंदन है। लोक कंठ की धरोहर है।

लोक जीवन का स्फुट काव्य है। लोक गीतों में समूहगत रचना शीलता विद्यमान रहती है। इनमें मार्मिकता, काव्यात्मकता, रसोद्रेकता अधिक सरल और व्यापक होती है। लोक साहित्य में आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख आदि की अभिव्यंजना लोक गीतों के माध्यम से होती है। जिनमें संस्कार परक लोकगीत, देवी देवताओं संम्बधी गीत, ऋतु, व्रत, श्रम, बालगीत और खेलगीत मुख्य है।

संस्कार परक गीतों में भारतीय जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है, इसलिये संस्कार परक लोक गीत का स्थान महत्वपूर्ण है, जो जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक लोगों के जीवन में विभिन्न संस्कारों से संबंध रखते है। जिसमें शोडस संस्कारों का विधान है। गर्भाधान, पुंसवन, जन्म, मुडंन, यज्ञोपवित, विवाह और मृत्यु प्रमुख है। इन अवसरों पर स्त्रियाँ अपने कोकिल कण्ठ से गा–गा कर अपने उल्लास और आनन्द को प्रगट करती है। पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को श्सोहरश गीत कहते है –

गावउ मंगल मंजुल बानी। सुनि करलब कलकंठ लजानि॥⁽³⁾

विवाहोत्सव में विभिन्न नेगों के सम्पन्न होने के बाद जब बेटी की बिदाई का अवसर आता है तो माँ की करूण पुकार इस गीत में ध्वनित होती है –

> कच्ची सी ईट बाबुल देहरी न धरियों। बिटिया न दीजों परदेश मोरे लाल।।

इसमें संबेह नहीं कि पुत्री की बिबाई का समय बड़ा बुखबाई होता है इस कारूणिक दृश्य को देखकर कठोर हृदय व्यक्ति भी पिघल जाता है। इसी प्रकार मृत्युगीत बहुत ही हृदय विदारक होते हैं जिसमें स्त्री अपने प्रिय पिता, पुत्र, मॉ की मृत्य होने पर उनके गुणों का वर्णन करती हुई विलाप करती है।

लोक गीतों में विभिन्न रसों की अभिव्यक्ति हुई है इसके अर्न्तगत शृगांर रस, वीर रस, हास्य रस, शान्त रस की प्रधानता है। विभिन्न ऋतुओं में जन-जन के अनुरंजन के लिये लोक गीत गाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। जिसमें वसंत ऋतु, होली के फाग, चैत्रा, वर्षाऋतु से संबंधित लोक गीत है। बुन्देलखण्ड में वर्षाऋतु में श्कजरीश् गाने की प्रथा हैं सावन में प्रकृति सर्वत्र हरी भरी दिखाई देती है-

> जहाँ देखों तहँ श्याममयी है श्यामकुन्ज, वन यमुना श्यामा, श्याम-श्याम घन घटा छाई है।। (4)

लीलाराम नगर की भारी, श्कजलीश बुन्देली सरनाम।। (5)

वर्षाऋतु में आकाश में काले-काले बादल दिखाई पड़ते हैं इन्ही काले बादलों के काल में गाये जाने के कारण इन गीतों का नाम श्कजरीश पड़ा। इसी प्रकार विभिन्न व्रत, कार्तिक स्नान, हरतालिका तीज, गणगौर, महालक्ष्मी पूजन, गोधन, छटी माता के गीत बहुत प्रचलित है।

देवी देवताओं के संबंध में अनेक गीत उपलब्ध है जिसमें गणपति, तुलसी, राम, कृष्ण, हनुमान, देवी स्तुति के गीत गाकर इष्ट की महिमा का वर्णन किया जाता है –

खोलो किवाडी मैया देखू तेरी बाड़ी, दर्शन की अभिलाषी।



इस लोक गीत के माध्यम से माता के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की गई है। कुछ लोक गीतों को विशिष्ट जाति के लोग ही गाते है। इसमें श्विरहा गीतश् जो अहीर जाति के लोगों द्धारा गाया जाता है। श्रम परिहास के लिये श्रम संबंधी गीत मजदूर वर्ग के द्धारा गाए जाते है। इससे काम करने में मन लगा रहता है और परिश्रम का पता ही नहीं चलता है। इस प्रकार गीतों में कृषि कार्य रोपनी, सोहनी, जतंसार आदि गीत प्रधान है।

बालगीत बच्चों के समस्त क्रियाकलापों जैसे उठना, बैठना, घुटनों के बल चलना, थिरकना, मचलना आदि से संबंधित होते है जो स्वाभाविक बाल सुलभ चेष्टाओं से परिपूर्ण होते है –

> पा ! पा ! पगली मामा नी 'डगली' डगमग डगमग डमला भरता हरजी मंदिर आठ्या । ⁽⁶⁾

महाकवि सूरदास ने भगवान श्रीकृष्ण की क्रीडा का बड़ा सरल तथा सजीव चित्रण किया है –

यशोदा हरि पालने झुलावे

खेल संबंधी गीतों में वहाँ के निवासियों के स्वभाव, साहस और शक्ति रूचि का पता चलता है। खेलकूढ़ लोक संस्कृति का प्रधान अंग होते हैं खेलों से सहयोग की भावना परिलक्षित होती है –

> ए कबडिया रेता भगत मोर बेटा। भगताईन मोरी जोरी, खेलाबि हम होरी॥ ए कबडिया आइले तबला बजाईले। तबला में पइसा. लाल बगईचा॥⁽⁷⁾

इन गीतों के अध्ययन से बालकों की मनोवृत्ति का पता चलता है।

लोक साहित्य में जीवन के विविध पक्षों का चित्रण हुआ है। लोक साहित्य में सामाजिक जीवन के साथ ही धार्मिक और आर्थिक परिस्थित का चित्रण सहज और स्वाभाविक हुआ है। झूमर के सभी गीत श्सोने की थाली में जेवना परोसने से प्रारम्भ होते है जिसमें प्रियतम की थाली तो सोने की बनी हैं और उसकी जल पात्र सुवर्णमय है। वह चंदन की लकड़ी के पलंग पर सोता है। जो रेशम की रस्सियों से बुना है।

जहाँ एक ओर लोक साहित्य में वैभव ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है वही सामान्य वर्ग की गरीबी का चित्रण भी स्वाभाविक रूप से हुआ है। लोक साहित्य में श्सर्वजन सुखायश् की भावना विद्यमान है जो हमारे हृदय में ''सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया:''की भावना जाग्रत होती है।

लोक साहित्य 'लोक का साहित्य' है जो मांगलिक भावनाओं से ओतप्रोत है। यही कारण है कि आज भी हम लोक से जुड़े हुए है लोक गीत मुनष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़े हुए है इसलिये उसे मनुष्य का सहजन्मा कहा जाता है लोक गीतों में वसुधैव कुटुम्बकम का भाव सदैव विद्यमान रहता है और हम प्रत्येक सुख-दुख के अवसर पर लोक गीतों को गाकर प्रसन्न और मुदित होते है। लोक गीतों में अन्तर्निदिष्ट मंगल की यह प्रवृत्ति संसार के कल्याण की आधारिशला है। लोक गीत, लोक संस्कार, लोक गृत्य सभी मनुष्य की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के सहज माध्यम है जिनकी प्राचीनता और मधुरता अवर्णनीय है।

संदर्भ ग्रन्थ -

- ऋग्वेद पृष्ठ -3/53/12
- लोक साहित्य की भूमिका डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय पृष्ठ 11
- 3. रामचरित मानस बाल काण्ड
- 4. 4-5 लोक साहित्य की भूमिका डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय पृष्ठ 82-83
- 5. 6-7 लोक साहित्य की भूमिका डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय पृष्ठ 188-189

कृषि क्षेत्र के विकास में किसान क्रेडिट कार्ड की भूमिका

डॉ. लक्ष्मण परवाल *

प्रस्तावना : -

हमारे देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है। इसलिए जब तक ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, तब तक देश में पूरी तरह से समृद्धि नहीं आ सकती है और इस समृद्धि की धुरी है किसान। ग्रामीण जनजीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में खेती से जुड़ा हुआ है। गांवों में रहने वाली आबादी में हर परिवार का कोई न कोई सदस्य खेती से जुड़ा हुआ है। जब तक खेती करने वाले किसान समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश की पूर्ण समृद्धि की कल्पना अधूरी है।

जब किसान खाद, बीज, पानी, कृषि उपकरण आदि के लिये किसी पर आश्रित न होकर स्वआश्रित होंगे तो उनमें खेती के प्रति उत्साह रहेगा। इसी उत्साह को कायम रखने के लिये सरकार की ओर से समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई गई है, परन्तु इन योजनाओं से किसानों का पूरी तरह भला नहीं हो पाया है। किसान अपने हिसाब से जब चाहे तब खेती से संबंधित आधारभूत सुविधाएं प्राप्त कर सकें, इसके लिये उन्हें पूंजी उपलब्ध कराने की आवश्यकता रहती है। ऐसी पूंजी जो सस्ती ब्याज दर पर मिल सके और किसान अपनी सुविधा के अनुसार उस पूंजी की वापसी भी कर सके। इस विषय पर निरंतर विचार-विमर्श चलता रहा और वर्षों के प्रयासों के बाद यह पूंजी किसानों को क्रेडिट कार्ड के रूप में प्राप्त हुई।

सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जाने के बाद भी सूदखोरों का जाल टूट नहीं रहा था क्योंकि किसानों को कई चरणों में पैसे की जरूरत पड़ती है। कभी बीज के लिए तो कभी खाद के लिए। ऐसे में वे अपनी पूरी उपज बेचने के बाद भी सूदखोर का ब्याज नहीं चुका पाते हैं।

इस समस्या को देखते हुए सरकार ने सर्वेक्षण के माध्यम से इस तथ्य का पता लगाया कि किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उनको फसलवार पैसा मिल सके। सरकार ने इसके लिए सन् 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की। पहली बार वर्ष 1998-99 में 6,07,225 कार्ड जारी हुए। वहीं 1999-2000 में 51,34,081 और वर्ष 2001-02 में यह आंकड़ा 93,40,534 तक पहुंच गया। किसान क्रेडिट कार्ड में तेजी से हो रही बढ़ोतरी का ग्राफ यही नहीं सका बल्कि वर्ष 2008-09 में 8,46,67,000 एवं मार्च 2010 में यह संख्या 9,36,73,000 तक पहुंच गया। इस योजना में किसानों को उनकी जोत के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया गया।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्य :-

- बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिये उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
- इस योजना के माध्यम से किसान सरल प्रक्रिया के तहत आसानी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- इस योजना के लागू होने के बाद किसानों को फसलों के लिये अलग-अलग आवेदन करने की प्रक्रिया के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है। अब

- एक बार जोत बही के आधार पर तैयार किये गये कार्ड से वे आसानी से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
- किसान सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक से सम्पर्क कर जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिये किसानों को अधिक भागदौड़ की भी जरूरत नहीं है। योजनांतर्गत वे अपने क्षेत्र में स्थित बैंक में जायें और आवेदन कर सकते हैं।
- किसानों को बैंक द्धारा पासबुक दी जाती है। पासबुक पर किसान का नाम व पता, भूमि जोत का विवरण, उधार सीमा, वैद्यता अविध, एक पासपोर्ट आकार का फोटो लगाया जाता है, जो किसान के लिये पहचान-पत्र का भी काम करता है।
- योजनांतर्गत खाते का उपयोग करते समय किसान को अपना कार्ड-सह-पासबुक दिखानी होती है।
- इस योजना में ऋण सीमा के अनुरूप जो किसान 10,000 रूपये तक ऋण लेते हैं उन्हें मार्जिन मनी नहीं देना पड़ती है, लेकिन जो किसान 25,000 रूपये से अधिक ऋण लेते हैं उन्हें 15 से 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी बैंक में जमा करने का प्रावधान खा गया है।
- इस योजना के अंतर्गत किसान खरीफ एवं रबी सीजन में 50,000 रूपये तक का ऋण ले सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ :-

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि गांवों से सूदखोरी प्रथा खत्म हो गई हैं। इस योजना के पूर्व किसान गांवों में रहने वाले साहूकारों पर आश्रित रहते थे। खेती के लिये वह यह जानते हुए भी कि साहूकार मनमाने तरीके से वसूली करता है फिर भी उसके पास कर्ज लेने जाता था। इसी तरह खाद, बीज के व्यापारी भी किसानों से मुंहमांगी कीमत वसूल करते थे। फिर भी किसान उनसे खाद, बीज खरीदने के लिये विवष होता था। इसका असर यह होता था कि किसान कड़ी मेहनत करने के बाद भी जो उपज पैदा करता था वह साहूकारों को कर्ज चुकाने में पूरी हो जाती थी। कई बार उपज कम होने पर साहूकार का कर्ज भी वह नहीं उतार पाता था। ऐसे में किसान आत्महत्या का रास्ता चुनने को विवष हो जाते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को निम्न लाभ प्राप्त हो रहे हैं:-

- 🗱 सरल ऋण वितरण प्रक्रिया।
- 🗱 नगद आपूर्ति के लिये बहुत ही आसान प्रक्रिया।
- 🗱 प्रत्येक फसल हेत् ऋण के लिये आवेदन करने की आवश्यकता नहीं।
- किसानों के लिये किसी भी समय ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना व किसानों के लिये ब्याज के बोझ को घटाना।
- किसानों की सुविधा और विकल्प के अनुसार खाद और उर्वरक की खरीढ करना।
- तीन वर्षों तक ऋण सुविधा यानी हर मौसम में मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं।



- 🗱 आपूर्तिकर्ता से नगद खरीद पर छूट प्राप्त करना।
- 🗱 कृषि आय के आधार पर अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाना।
- 🗱 ऋण सीमा के भीतर बैंक से कई बार राशि का निकालना संभव।
- 🗱 फसल कटाई के बाद अदायगी का प्रावधान।
- 🗱 🌣 🌣 कृषि अग्रिम के अनुसार ब्याजदर लागू।
- कृषि अग्रिम के अनुसार प्रतिभूति, मार्जिन मनी एवं प्रलेखन के नियम लागु ।

सरकारी प्रयास :-

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सरकार द्धारा किसानों को सस्ती दर ऋण उपलब्ध कराने, बीमा योजना को प्रोत्साहित करने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:-

किसानों को सस्ती दर पर ऋण :-

केन्द्र सरकार की हमेशा कोशिश रही की किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान किया जाए। इस वजह से वर्तमान बजट में एक तरफ किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। वर्ष 2011–12 के बजट में केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान समय पर ऋण चुकायेंगे उन्हें मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान परिवेश में अधिकांश खेतीहर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण ले रहे हैं। ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड से लिये जाने वाले ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लेने का सरकार का फैसला ऐतिहासिक है। इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। इससे पहले गतवर्ष सरकार ने 4.50 करोड़ किसानों को ऋण माफी योजना में शामिल कर उन्हें राहत प्रदान की थी। अभी तक किसी भी अन्य योजना में इतने सस्ते दर पर ऋण देने का प्रावधान नहीं है।

कार्ड धारको के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना :-

किसान क्रेडिट कार्ड को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है। कार्ड धारक किसान की मृत्यु पर 50,000 रूपये स्थाई, पूर्ण अक्षमता पर 50,000 रूपये दो अंग या दो आंख या एक अंग तथा एक आंख के खो जाने पर 50,000 रूपये, अस्थाई विकलांगता पर 25,000 रूपये की व्यक्तिगत दुर्घटना रक्षा दी जाती है। इस योजना में प्रत्येक किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिये लागू 15 रूपये वार्षिक प्रीमियम में से 10 रूपये बैंक द्धारा तथा 5 रूपये किसान क्रेडिट कार्ड धारक को देना होता है।

किसान क्रेडिट कार्ड से स्वरोजगार :-

किसान क्रेडिट कार्ड ने स्वरोजगार की दिशा में भी अहम भूमिका निभाई है। इस कार्ड के जिरये सिर्फ खेती के लिये ऋण लिया जा सकता है ऐसे में अधिकांश किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ती दर पर ऋण लिया। खेती की उपज बेचकर बैंक का पैसा अदा करने के साथ ही अपनी पूंजी भी तैयार की। इस तरह धीरे-धीरे पूंजी इकट्ठी होती गई और फिर इस एकत्रित पूंजी से किसानों ने अपना व्यवसाय शुरू किया। इस तरह किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि जीविकापार्जन की दिशा में दूसरे विकल्प भी उपलब्ध करा रहा है।

निष्कर्ष :-

किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के बाद किसानों को कई प्रकार से फायदा मिला है। उन्हें खेती के लिये अब दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। वे मनचाही खेती करते हैं और मुनाफा कमाते हुए बैंक का पैसा चुका देते हैं। इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति में भी निरंतर सुधार हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के पश्चात् अब किसानों की पैसे के अभाव में ऐन वक्त पर खेती नष्ट नहीं हो पाती है। खाद की जरूरत पर खाद मिल जाती है और पानी की जरूरत होने पर पानी। इस तरह फसल को बर्बाद होने से बचाने में किसान क्रेडिट कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसान स्वयं यह महसूस करने लगे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड में दी गई सुविधाओं की वजह से उनकी कृषि संबंधी अधिकांश समस्याओं का निराकरण हो गया है।

संदर्भ सूची :-

- 1. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, नई दिल्ली, जून 2011
- 2. योजना मासिक पत्रिका, नई ढिल्ली, जनवरी 2011
- बजट प्रकाशन 2011-12
- 4. इन्टरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर





उच्च शिक्षा में गुणवत्ता समस्याऐं एवं समाधान (शोध सारांश)

डॉ. कमल जैन * डॉ.महेश गुप्ता **

भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण,वैश्वीकरण,भूमण्डलीयकरण की नीति अपनाई है। इस नीति के कारण आज विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही विविध क्षेत्रों के ज्ञान की भी जरूरत है,जिससे उसके सम्पूर्ण व्यक्तिव का विकास हो सके।

म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग द्धारा रोजगारोन्मुखी शिक्षा को प्राथमिकता देने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके लिये महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम,गतिविधियाँ,परीक्षा पद्धित मे परिवर्तन किया है। शासन ने सन् 2008 से सेमेस्टर पद्धित लागू की है,जिसमें विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन होता है,साथ ही परियोजना कार्य एवं कार्य स्थल प्रशिक्षण को भी पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धित में सम्मिलत किया है।

उच्च शिक्षा विभाग द्धारा वर्ष 2011-12 को गुणवता वर्ष एवं 2012-13 को गुणवता विस्तार वर्ष घोषित किया है,जिसमें 18 सूत्रीय कार्य योजना के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा है,अनेक समस्याओं से ग्रस्त होकर भी महाविद्यालय लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयास कर रहे है। महाविद्यालयों को निम्नांकित विपरित परिस्थितियों का सामना करना पडता है:-

- कक्षा में उपस्थित :- महाविद्यालय की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थित को शासन ने अनिवार्य किया है। शासन के इस विषय का कठोरता से पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि निर्धन एवं निम्न मध्यवर्ग के विद्यार्थी परिवार की आर्थिक सहायता हेतु पार्ट-टाईम काम भी करते है।
- 2. सतत् आंतरिक मूल्यांकन सेमेस्टर पद्धति में सतत् आंतरिक मूल्यांकन को भी परीक्षा अंक विभाजन में 15 प्रतिशत महत्व दिया गया है। सतत् आंतरिक मूल्यांकन की 12 विद्याऐ निर्धारित की गयी है किंतु महाविद्यालयों में आसानी से सम्पन्न होने वाली विद्या ही अपनाई जाती है। कुछ महाविद्यालय इसे परीक्षा परिणाम सुधारने का साधन मानकर चलते है।
- 3. **परियोजना कार्य :-** सेमेस्टर पद्धित में, पहले प्रत्येक सेमेस्टर में परियोजना कार्य एक प्रश्नपत्र के समकक्ष माना जाता था। प्रथम,तृतीय एंव पॉचवें सेमेस्टर में भी आंतरिक परीक्षक द्धारा मूल्यांकन होता था तथा द्धितीय,चतुर्थ एवं षष्टम सेमेस्टर में बाहा परीक्षक द्धारा मूल्यांकन किया जाता था।
 - परियोजना कार्य का स्तर कैसा होता था यह एक शोध का विषय हो सकता है और इसी कारण शासन ने अब नये नियम के तहत केवल अंतिम सेमेस्टर में परियोजना कार्य / कार्य स्थल प्रशिक्षण रखा गया है जिसमें गणवता बढ़ने की संभावना है।

उच्च शिक्षा विभाग द्धारा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये सार्थक निर्णय लेकर दशा निर्देश जारी किये गये हैं किंतु अनेक समस्याओं एवं कमियों के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। लक्ष्य प्राप्ति हेतु शासन को निम्नांकित प्रयास करना होगा :-

- . कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता के विषय का सख्ती से पालन कराना होगा।
- सतत् आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था केवल औपचारिक मूल्यांकन व्यवस्था नही रहे इसके लिये प्राचार्य एवं शिक्षकों को अधिकार सम्पन्न बनाना होगा।
- पिरयोजना कार्य/कार्यस्थल प्रशिक्षण पर कड़ी निगरानी रखना होगी जिससे विद्यार्थी वास्तव में अनुभव प्राप्त करें। विद्यार्थी के प्रतिवेदन को मूल्यांकन उपरात ग्रंथालय में रखना चाहिए।
- महाविद्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत सभी पढ़ों पर नियुक्ति करना चाहिए ताकि शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्य समयसीमा में सम्पन्न हो सकें।
- 5. महाविद्यालय की प्रयोगशालाओं को साधन सम्पन्न करना होगा ताकि विद्यार्थी प्रेक्टिकल ज्ञान प्राप्त कर सके।
- 6. खेलकूढ की गतिविधियों में विद्यार्थियों की रुचि कम हुई है,क्योकि क्रीड़ा-अधिकारी के पढ अनेक महाविद्यालय मे रिक्त पडे है। इन पर शीघ्र नियुक्ति करना चाहिए।
- 7. शासन द्धारा शैक्षणिक कैलेंडर का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्ती करना चाहिए।
- 8. विश्वविद्यालय द्धारा निर्धारित कैलेण्डर के तहत परीक्षा लेना,परिणाम घोषित करना,उपाधि प्रदान करना सुनिश्चित करना होगा। विश्वविद्यालयों में पर्याप्त स्थायी स्टॉफ न होने के कारण कैलेण्डर का पालन नहीं कर पाते हैं,नियक्ति पर प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए।
- ग्रंथालय में पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा संदर्भ पुस्तके,रिसर्च जर्नल,पत्रिकाएँ क्रय करने हेतु अलग से राशि का उल्लेख करना चाहिए एवं विद्यार्थियों में इनके अध्ययन करने की रूचि उत्पन्न करना होगी, इसके लिये ग्रन्थालय रीडिंग रूम को सुसज्जित करना चाहिए।
- पिछड़े महाविद्यालयों को संसाधन सम्पन्न बनाने हेतु विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि :-

उच्च शिक्षा में गुणवता बढाने के लिये उपरोक्त प्रयास प्राथमिकता के साथ करना चाहिए,साथ ही शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की पहचान कर उसका उचित प्रबन्ध करना चाहिए,यही गुणवता विस्तार का आधार है। महाविद्यालय परिसर में दबावपूर्ण परिस्थितियाँ, क्षेत्रवाद, सम्प्रदायवाद,नौकरशाहिता,गुटबाजी,असामाजिक तत्वों की भूमिका इत्यादि पर प्रतिबंध होना चाहिए।

संदर्भ:-

- 1. व्यक्तिगत प्राप्त जानकारी एवं अनुभव के आधार पर।
- 2. उच्च शिक्षा भोपाल द्धारा जारी पुस्तिका एवं पत्रों के आधार पर।



मोबाइल का समाज पर प्रभाव (शोध सारांश)

डॉ.पी.पी. पाण्डेय *डॉ. प्रभा पाण्डेय **

आज समाज एवं भारतीय समाज में कोई ऐसा पक्ष अछूता नहीं है जहाँ इस नवीन प्राद्योगिक अथवा वैज्ञानिक अविष्कार मोबाइल ने अपना प्रभाव न डाला हो। 21वीं सदी में संपूर्ण भारतीय समाज एवं संस्कृति विशेष रूप से भौतिक संस्कृति पर अपना प्रभाव डाला है। ज्ञान-विज्ञान ने मानव को चमत्कार के द्धारा अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रेरित किया है 21वीं सदी में रंगीन टेलीविजन में वैश्वीकरण एवं बाजार संस्कृति में क्रांतिकारी प्रभाव डाले जिसके परिणामस्वरूप नवीन उपभोक्ता संस्कृति के माध्यम से मानवीय समाज में दूरसंचार, क्रांति में तीव्रगामी परिवर्तनों की एकदम से बाढ सी ला दी है। इलेक्ट्रॉनिक का बाजार भरा पडा है जिसमें मानवीय संवेदनाओं एवं इधिकल वैल्यू का कोई भी स्थान नहीं है। मोबाइल फोन ने नवीन प्राद्योगिकी का आविष्कार द्धारा मानवीय समाज में क्षेत्रीय (भौगोलिक विषमताओं) एवं दूरिया समाप्त कर दी हैं। मोबाइल आज पद प्रतिष्ठा का प्रतीक बन चूका है। आज 500 से लेकर लाखों रूपये तक की कीमत के मोबाइल व्यक्ति उपयोग कर रहा है। यह प्रतिस्पर्धा संस्कृति को बढाती है उसके लिए टेलीविजन ने '' उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों है'' यह उपभोक्ता संस्कृति का जीता-जागता उदाहरण है मेरे घर में काम करने वाली बाई भी घर का काम अधूरा छोडकर रीचार्ज बाउचर डालने के लिए चली जाती है।

मोबाइल फोन सेवा भारत में वर्ष 1995 से शुरू की गई थी परन्तु मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग होने से भारत के लगभग 80 करोड उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। उपभोक्ताओं की सेहत को लगातार नुकसान होने से लोगों में बहरापन एवं जैविक एवं नर्वस सिस्टम को किस तरह से युवा पीढी को बर्बाढ़ कर रहा है। यह चिंता का विषय है। यह नहाने ,धोने से लेकर रात्रि सोते रहने में भी इसकी तरंगे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है। चूकि विश्व में लगातार मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ रही है नवम्बर 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 5911 विलियन है। मोबाइल फोन के नये मॉडल का उपयोग कर इसके कई लाभ ले सकते हैं:-

- ०१. संचार संवर्धन, इन्ट्रेक्शन , सलाहकार।
- 02. व्यापक लेन-देन क्षमता।
- ०३. ग्राहक शिक्षा।
- 04. नये ग्राहक सेगमेण्ट के साथ कनेक्ट।
- ०५. सामग्री मुद्रीकरण।
- 06. कार्यक्षेत्र की स्थिति का ज्ञान।
- 07. क्षेतिज स्थिति मोबाइल बैंकिंग पर सभी उद्योगों पर पोजिसनिंग।
- 08. कार्पोरेट बैंकिग सेवाओं के निजीकरण का ज्ञान।
- 09. मोबाइल फोन में इन्टरनेट कनेक्सन होने से हम संबंधित विषय के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- 10. हम एस.एम.एस. संदेश भेज सकते है।
- 11. वीडियो कैमरा और डिजिटल रिकॉर्डर का भी उपयोग कर सकते हैं।
- 12. नोट्स लिखने के लिए पेपर व पेंसिल की जगह कर सकते हैं।
- इसका उपयोग केल्कुलेटर अंग्रेजी शब्दकोष की तरह उपयोग में ला सकता है।
- 14. विदेशी भाषा की कक्षा में अनुवादक की तरह इस्तेमाल कर सकते है।
- 15. भारत में विभिन्न कृषि अनुसंधान केन्द्र है जहाँ से कृषक यह जानकारी मोबाइल फोन के द्धारा प्राप्त कर सकता है।
- सूचना का आदान-प्रदान संभव होने से व्यापार, व्यवसाय व सरकार में तेजी आई है।
- 17. सूचना का द्रूत :गति से सम्प्रेक्षण हुआ है।
- 18. मनोरंजन के अलावा ज्ञान बृद्धि में सहायक।
- 19. मोबाइल फोन द्धारा बिल भुगतान पेमेण्ट करना आदि।
- 20. ऑनलाइन एडमिशन को भी सुविधा जनक बताता है।

मोबाइल फोन के अंधाधुन्ध प्रयोग से होने वाली हानियाँ :-

- 01. मोबाइल रेडिऐशन का खतरा।
- 02. रहवासीय क्षेत्रों में लगे मोबाइल टावरों से उत्पन्न रेडिऐशन जन स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है।
- 03. मोबाइल रेडिऐशन से कैंसर होने का खतरा बढ जाता है यदि इसका अंधाधुंध उपयोग करते हैं।
- 04. सोते समय तकिये के नीचे मोबाइल रखना यह खतरनाक आदत है। इससे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पडता है।
- 05. मोबाइल हेण्डसेट के उपयोग से सिर की त्वचा में चुभन तथा जलन, थकान, नींद में व्यवधान, आलस एकाग्रता में कमीं, कानों का बजना, याददास्त में कमी, सिर दर्द, पाचन खराब होना, धड़कनों का बढना आदि लक्षण रिपोर्ट में दिये गए हैं।
- 06. प्रतिदिन एक घण्टे सेलफोन के उपयोग से दस साल या उसके बाद टियूमर रिस्क बद जाता है।
- 07. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग दुर्घटना को जन्म देता है।
- 08. माइक्रोवेव रेडिऐशन तरंगे कैंसर जैसी घातक बीमारियों को जन्म देती है।
- 09. समाज में बढ़ रहे अपराधिक प्रकरणों का श्रेय मोबाइल को देना अनुचित नहीं होगा। जो अपराधिक प्रक्रिया को सरलतम बनाता है।
- 10. बच्चों की एकाग्रता एवं संवेदनशीलता कमजोर पड जाती है साथ ही अधिक समय तक बच्चे गेम आदि खेलते रहने से नेत्र संबंधी विकार की संभावना बढ जाती है।
- 11. मोबाइल ने पर्यावर्णीय स्थानों में स्पीकर की आवाज बढाकर विभिन्न प्रकार के फूहड गाने सुनना एवं सुनाना कितनी असुविधा होती है यह कहना बडा मृश्किल है।
- 12. मोबाइल की पराधीनता के कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है।
- 13. मोबाइल फोन ने युवाओं में प्रजनन की क्षमता (D.NA System) के हास की समस्या, मानिसक समस्या तनाव की समस्या को जन्म देने के साथ-साथ इस वर्ग के चिंतन को भी कुलिषत कर सोंच को नकारात्मकता की ओर बढाया है।

सुझाव:-

- 01. हैण्डसेट या स्पीकर द्धारा।
- 02. फोन को शरीर से दूर रखकर।
- 03. टैक्सट ज्यादा, बात कम करनी चाहिये।
- 04. सिंगनल सही होने पर ही फोन सेट का उपयोग करें।
- 05. बच्चों को सीमित प्रयोग की सलाह।
- एण्टीना कैप्स तथा की पैड कवर का उपयोग न करें।
- 07. मोबाइल फोन का प्रयोग आवश्यकतानुसार संक्षिप्त वत्रलिप करें।
- 08. गर्भवती महिलाएँ मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
- 09. ऐसे मोबाइल फोन का चुनाव करें जिसका स्पेसिफिक एबजादर्शन रेट (एस.ए.आर.) कम हो।
- 10. हैण्डस फ्री किट का इस्तेमाल करें।

निष्कर्ष :-'' विज्ञान वरदान है परन्तु अभिषाप भी '' इस तरह हम कह सकते हैं कि मोबाइल दूरसंचार पद्धति एक वरदान है परन्तु अभिशाप भी । **संदर्भ सूची:-**

- 1. दैनिक म.प्र. दिनांक 16/12/12 (खतरे की घण्टी बजाता मोबाइल)
- 2. पत्रिका 16/12/12 (बहरा बना देगी चीनी कम्पनियां)
- 3. दैनिक भारकर (08/10/13) (दुनिया में मोबाइल का उपयोग)
- 4. संप्रेक्षण एवं संचार माध्यम (म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल)
- 5. अहा जिंदगी मार्च 2012 I

^{*} डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा ** प्राध्यापक अर्थशास्त्र शास. स्नात. महा., मैहर, जिला–सतना (म.प्र.)



निमाडी भाषा का स्वरूप एवं क्षेत्र (शोध सारांश)

डॉ. मनजीत अरोरा *

विंध्य और सतपुड़ा की गोढ़ में लेटे हुए जिस भू-भाग पर माँ नर्मढ़ा की लोल लहरे कल-कल नाढ़ की कल्लील करती हों। औंकार भगवान की जय-जयकार करती हों। चौपालों पर झाँझ और मृढंग की ताल पर संत सिंगाजी की अमरवाणी गूंजती हो, उस भूखण्ड अर्थात् निमाड़ की लोक भाषा निमाड़ी का म.प्र. की लोक भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह जाने की क्षमता हैं।

इसमें हमारी सभ्यता-संस्कृति और सामाजिक जीवन की इन्द्रधनुषीय छठा शोभायमान हैं। लोक भाषाएँ सहायक नदी की तरह होती हैं। लोक जीवन से आत्मसात् होने के कारण ही अपने साथ अपने मूल किनारों पर बसने वाली- जनता की सभ्यता-संस्कृति, गीत,कथा, कहावत और विपुल शब्द संपदा से राष्ट्रभाषा को समृद्ध करती आयी हैं। लोक जीवन के चितेरे को उपमा/ अलंकार कहीं से उधार नहीं लेने पड़ते हैं, वरन् वह तो अपने आस-पास की धरती, प्रकृति और जन-जीवन की उपमाएँ चुनकर अपनी कल्पना से सिंगार, सूझ और समझ के पंखों पर बैठकर नये लोक-जीवन की सृष्टि करता आया हैं। भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम होती हैं। भाषा मे व्यक्ति व्यक्त होता हैं और व्यक्ति मे भाषा की परवरिश होती हैं। यह स्पष्ट हैं कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में जितनी अच्छी तरह से व्यक्त हो सकता है, दीगर भाषा मे नहीं क्योंकि वह वातावरण, परिवेश, और स्थितिगत यथार्थ से जुड़ा होता है, वह उसमें रचता-बसता है।

निमाइी का क्षेत्र:— निमाड़ी भाषा प्रदेश अनेक भाषाओं से घिरा एक क्षेत्र हैं। इसके उत्तर मे मालवी भाषी क्षेत्र हैं जो इसकी लगभग 150 मील पूर्व पश्चिम परिधि से आरंभ होता हैं। दक्षिण मे इसकी पूर्व पश्चिम लगभग 160 मील लम्बी परिधि को छूता हुआ मराठी तथा उसकी एक बोली खानदेशी का क्षेत्र आरंभ होता है। लगभग 60 मील उत्तर—दक्षिण परिधि से संपर्कित निमाड़ी प्रभावित बुंदेली तथा पश्चिम में लगभग इतनी ही विस्तार परिधि में भीली भाषी क्षेत्र आरंभ होता हैं।

निमाड़ी - नामकरण: - इस भू-भाग का नाम ''निमाड़ी' फ़ारसी के ''नीम'' शब्द से निमाड़ी होना बताया गया हैं। फ़ारसी मे ''नीम'' का अर्थ ''आधा'' हैं। इस भू-भाग मे नर्मदा नदी का आधा भाग अपने आँचल मे छिपा रखा हैं। इसलिये इसे निमाड़ कहते हैं। यह नमर्दा के उदगम स्थान की अपेक्षा मुख से अधिक निकट हैं, लेकिन ''नीम'' शब्द के आगे ''आड़'' प्रत्यय लगा हैं। अत: उक्त मत स्पष्ट नहीं हैं। डॉ. फोर्सिथ ''निमाइ'' शब्द फ़ारसी के स्थान पर हिन्दू (हिन्दी) शब्द मानते है।(1)''-कुछ लोगों का मत हैं कि निमाड़ में प्रवेश करने वाला प्रथम मुसलमान शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जो सन् 1291 मे यहाँ आया था। यदि निमाड़ मुसलमानी नाम हो तो इस भू-भाग का यह नाम सन् 2191 के पश्चात् ही पड़ना चाहिए जबिक 11 वीं शताब्दी में आने वाले अरब यात्री अबलारूजी ने भी अपने यात्रा वर्णन मे इस प्रदेश का नाम ''निमाड प्रान्त'' लिखा है।(2) कुछ लोग इसका पूर्ण नाम ''निमवाड़' बतलाते हैं, जिसका अर्थ है-''नीम'' (एक वृक्ष) का प्रदेश।

इस प्रदेश में नीम के अधिक वृक्ष देखकर इसके नामकरण के संबंध में यह अनुमान लगाया जाता है। यद्यपि यह तर्क से अधिक पुष्ट है, लेकिन फिर भी संतोषजनक नहीं जान पड़ता है।⁽³⁾ इस संबंध में युवमुती कृत 'उत्तररामचित' की कुछ पंक्तियाँ विचारणीय हैं। विन्ध्या के समीप आने पर लक्ष्मण ने सीता से कहा- ''एश विन्ध्याखी मुखे विराधसरोध'' अर्थात् यह विन्ध्य की पत्यका हैं जहाँ हमें विराध ने अवरोध किया था। विराध का रमरण आते ही सीताजी के

कोमल हृदय पर आघात हुआ , जिसे देख कर राम ने कहा-

'' एतनि तनि गिरि निभीरिणी तरपु, वैखान साक्षित तरूचि तपोवनामि। ये एवतियेय परमा: यमिनो भजन्ते, नीवारमुपिरपचमा गृहिणी ग्रहणि।''

- प्रथमांक 25

उक्त श्लोक की अंतिम पंक्ति मे प्रयुक्त ''नीवार'' शब्द से तात्पर्य हैं जंगल मे उत्पन्न होने वाले एक प्रकार के चावल से, जिसे अरण्य में वास करने वाले

ऋषि-मुनि सेवन करते थे। इस भाग में उत्पन्न ''नीवार'' शब्द कुछ समय पश्चात् ''निमाइ'' कहलाने लगा हो, ऐसा माना जाता हैं। निमाइ मालवा का दक्षिण भाग हैं जिसे हम निम्न भाग ही कह सकते हैं। ''वाइ'' का अर्थ हैं- ''स्थान''। जैसे मारवाइ, मेवाइ, कठियावाइ, आदि नाम हैं। पूर्व मे ''निम्वाइ'' होना चाहिए। इस भाग से लगे भाग की मालवी भाषा में निम्न भाग को ''निमानी'' कहते हैं। अत: ''निम्वाइ'' से ही निमाइ नाम पड़ने की अधिक संभावना जान पड़ती है।

निमाइ की सीमावर्ती भाषाएँ: – उत्तर मे मालवी, पश्चिम मे गुजराती, दक्षिण मे खानदेशी और पूर्व मे होशंगाबाद शब्दों के आदान – प्रदान मे भी उसकी सीमावर्ती भाषाओं का प्रभाव रहा हैं।

निमाइी भाषी प्रदेश: – निमाड़ी में स्थित मुख्यतः दो जिलों की भाषा है। 21.4 और 22.5 उत्तर अक्षांश तथा 74.4 और 77.3 पूर्व देशान्तर के बीच स्थित हैं। इस भू-भाग के उत्तर में मध्यप्रदेश के धार, इन्दौर, देवास जिले, दिक्षण में खानदेश तथा विदर्भ के बुलढाना और अमरावती जिले, पूर्व में होशंगाबाद और बैतूल जिले और पिश्चम में मुम्बई प्रान्त हैं। विन्ध्याचल इस भू-भाग की उत्तरी सीमा पर सतपुड़ा, दिक्षणी सीमा पर इसके आंगन प्रहरी हैं। दोनों जिले पूर्वी निमाड़-खण्डवा तथा पिश्चमी निमाड़ -खरगोन, जिनकी भाषा के अतिरिक्त रहन-सहन, धार्मिक विश्वास, सामाजिकता, और भौगोलिक स्थित में कोई अन्तर नहीं हैं। इन दोनों जिलों में निवासरत् सभी निमाड़ी भाषी नहीं है किन्तु फिर भी अधिकांश लोगों की निमाड़ी ही बोली हैं। उत्तर में विशाल विन्ध्यालच और दिक्षण में अपनी सात शाखाओं वाला सतपुड़ा पर्वत के बीच बसा निमाड़ी भाषी भू-भाग हैं। दोनों पर्वतों के बीच इतना सकरा स्थान हैं कि जिसे हिरण भी छलांग मारकर पार कर सकता हैं। इसलिए यह स्थान ''हिरणफाल'' के नाम से जाना जाता हैं। डॉ आर.व्ही. रसेल ने इसे ''निमाड़ की पूर्वी सीमा बतलायी हैं। '' (4)

आज अत्यंत चिन्तनीय प्रश्न हैं कि आधुनिकता की बीहड़ में लोक भाषा, सभ्यता और संस्कृति की तलाश कहाँ की जाय और संस्कृति मूल्यगत अहसासों के निरन्तर सूखते वृक्ष के हरेपन को कैसे रोका जाय? बदलते परिवेश और मानसिकता के परिप्रेक्ष में लोकभाषा और संस्कृति की अन्तर्निहित मूल्यगत यात्रा चाहे संतोषजनक एवं सुखद नहीं है, लेकिन ये तमाम विसंगतियों का दुखभोग संवेदनिक अहसास जरूर हैं। अत: लोकभाषाएँ समाज की वे जड़े हैं जो सभ्यता के पेड़ को अपनी भूमि पर खड़ा रखती हैं और उसे हरापन भी देती हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ :-

- 1. डॉ. फोर्सिथ- निमाइ डिस्ट्रिक गजेटियर, पृ. 23-29
- 2. माउंट स्टुअर्स एलफिस्टोन हिस्टोरी ऑफ इण्डिया, (1889) पृ. 396
- 3. सेवयुस अबलारानी इण्डिया (1880) भाग, पृ.203
- 4. डॉ. आर.व्ही. रसेल-निमाड़ डिस्ट्रिक गजीटर भाग (1908), पृ. 20
- 5. डॉ. कृष्णलाल हंस**-** निमाड़ी और उसका साहित्य



महिलाओं की रक्षा के लिए उठाया गया कदम

डॉ. नरेंद्र कुमार जैन *

प्रस्तावना- लम्बी प्रतीक्षा के बाद घरेलू हिंसा निषेध कानून को 13 सितम्बर 2005 को राष्ट्रपति की संस्तुति से कानून का दर्जा मिला। घरेलू हिंसा महिलाओं के विरुद्ध ऐसी हिंसा है जो महिलाओं की आयु और गरिमा सम्बंधी सीमाओं को काट देती है। आए दिन होने वाली घरेलू हिंसा को यथार्थ के रूप में स्वीकारते हुए इस कानून के माध्यम से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के समाधान का अब कानून में पत्नि व बिना ब्याह साथ रही महिला के अलावा माँ, बहन तथा अन्य महिला रिश्तेदारों को भी इस अधिनियम द्धारा संरक्षण दिया गया है।

घरेलू हिंसा अपने सगे सम्बंधी पत्नि व पारिवारिक सदस्यों के प्रति शारीरिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दुर्ज्यवहार है किंतु बहुतायात में महिलाओं के पीड़ित होने के कारण इसे सामान्यत: महिलाओं के प्रति हिंसा ही कहा गया है। सदियों से घरों के अंदर बंद दरवाजों के पीछे होने वाले हिंसक बर्ताव को रोकने तथा ढोषियों को सजा दिलाने में सक्षम ऐसे विशेष कानून की मांग महिला संगठन और स्वयंसेवी संस्थाओं द्धारा लम्बे अर्से से की जा रही थी। इस अधिनियम से पहले वैवाहिक हिंसा से निपटने के लिए एकमात्र कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) था। परंतु यह कानून शारीरिक रूप से न होने वाली हिंसा के निपटारे में असमर्थ था।

महिलाओं को अबला, असहाय और बेबस जैसे खिताब देकर सदियों से पुरूषों के संरक्षण में रहने की सीख दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15-49 वर्ष की 70 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में हिंसा की शिकार है। भारत में प्रतिदिन हर 26 वें मिनिट में महिला का उत्पीडन, 34 वें मिनिट में बलात्कार, 42 वें मिनिट में यौन उत्पीडन, 43 वें मिनिट में महिला का अपहरण और हर 93 वें मिनिट में एक महिला जला दी जाती है। पति और रिश्तेदारों द्धारा हिंसा के 155439 मामले दर्ज हए जिनकी संख्या वर्ष 2010 में 150703 थी।

घरेलू हिंसा के कारण:-

घरेलू हिंसा को रोकने के लिए इसके कारणों का पता लगाना बहुत आवश्यक है, ये निम्न है-

- 1. वैवाहिक अंर्तविरोध
- नैतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण
- मादक व्यसन एवं महापान
- अज्ञानता
- सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियां
- 6. आर्थिक निर्भरता
- निर्धनता
- 8. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार

घरेलू हिंसा अधिनियम 05 के उपयोग एवं लागू होने की शर्तें – महिलाओं के खिलाफ जारी हिंसा को समाप्त करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारी परम्परागत सोच है जिसे बढ़लकर महिलाओं में जागरूकता कायम करने की नितांत आवश्यकता है।

अनेक महिलाएं अशिक्षित होते हुए भी घर के काम-काज के अलावा

फैक्ट्रीयों, घरों और भवन निर्माण क्षेत्र में जी-तोड़ काम करके परिवार को चलाती है तब भी पुरुष और शराबी पित इन्हीं मेहनती महिलाओं के साथ मारपीट करते है। क्या यह सब समाज को दिखाई नहीं देता? ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बड़े कानून बनाकर उन्हें सखती से लागू किए जाने की जरूरत थी और इनकी पूर्ति के लिए ही घरेलू हिंसा निषेध कानून बना है। 25 नवम्बर घरेलू हिंसा विरोधी दिवस के रूप में जाना जाता है।

कामकाजी और शिक्षित महिलाओं को इस कानून का लाभ उठाकर कम से कम उन महिलाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए जिन्हें इस कानून का ज्ञान नहीं है और जो शिक्षा व आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल से महिलाओं की मदद के लिए अलग पुलिस स्टेशन बनाया गया है। यहां महिलाओं को शिकायत करने के लिए विशेष प्रारूप में फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तरीके से यदि शिकायत जायज लगे तो वह स्वयं ही नोटिस भेजकर कार्यवाही शूरू करता है। यदि कोई महिला पुलिस को शामिल किए बिना ही केस की छानबीन कराना चाहे तो आयोग मदद देता है। आयोग की मुख्य रूप से यही कोशिश होती है कि उचित परामर्श के द्धारा शिकायती और प्रतिवादी के बीच समझौता हो सके।

मुंबई में लोकल पुलिस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्धारा स्थापित विशेष प्रकोष्ठ है। इसमें महिलाओं को भावनात्मक सहयोग, उचित सलाह और सहायता आदि अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। विशेष प्रकोष्ठ में अनुभवी सलाहकारों की सहायता से शिकायती एवं प्रतिवादी में समझौता कराने की कोशिश तथा साथ ही घरेलू हिंसा के कानूनी प्रावधान के प्रभावों की भी व्याख्या की जाती है। घरेलू हिंसा से बचने के लिए शार्ट स्टे होम शर्तें भी लाभदायक हो सकती है। ये महिलाओं और उनके शिशूओं को लगभग 6 माह तक भोजन एवं शरण देते है। इनमें महिलाएं यदि इच्छुक हो तो व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती है।

आवश्यकता पड़ने पर उचित परामर्श, वकील, पुलिस और डॉक्टर्स की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। अधिक सशक्तिकरण और स्वालंबन पर जोर देते हुए यह आवश्यक है कि महिलाएं स्वावलंबी बने और पुरुष प्रधान समाज में अपना अधिकार जाने।

नया कानून विभिन्न प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिला को संबल प्रदान करता है। इस कानून के तहत घर में रह रही किसी भी महिला के स्वस्थ जीवन या शरीर को कोई नुकसान पहुंचाना, शारीरिक या मानसिक कष्ट देना या उसके साथ ऐसा करने की मंशा करना, यौन उत्पीडन करना, गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, गाली-गलीच करना, शैब जमाना, बच्चों और खास तौर पर पुत्र न होने पर ताने मारना और अपमानित करना या पीड़ा पहंचाने की धमकी देना इत्यादि यही नहीं महिलाओं की आर्थिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाना भी घरेलू हिंसा के दायरे में है। यह कानून पीड़िता को उसी मकान में रहने का अधिकार देता है। जिसमे वह अत्याचार करने वाले व्यक्ति के साथ पहले से ही रह रही हो।

पीड़िता को मकान से हटाया या निकाला नहीं जा सकेगा। कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दंडनीय एवं गैरजमानती अपराध माना



गया है और अपराधी को 1 वर्ष की कैंद्र या 20000 का जुर्माना या दोनो हो सकते है।

अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा की परिभाषा-

इस कानून के दूसरे अध्याय में घरेलू हिंसा (धारा-3) की व्यापक परिभाषा दी गई है जिसमें सभी प्रकार की हिंसा और शारीरिक, मानसिक, यौन, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार जैसे सभी तरह के अत्याचार शामिल है। महिलाओं पर हो रही हिंसा में केवल पुरूष नही बल्कि कई बार महिलाएं भी सम्मिलित है। ऐसे कई उदाहरण है जिसमें महिला ने अपनी सास, जेठानी, ननद, बहन या अन्य किसी महिला द्धारा पीड़ित होने की शिकायत दर्ज कराई है।

महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम-

इस कानून से पीड़ित व्यक्ति (धारा-2ए) की परिभाषा उस महिला के रूप में की गई है जिसका प्रतिवादी के साथ पारिवारिक सम्बंध रहा हो जिसने प्रतिवादी द्धारा की गई किसी प्रकार की घरेलू हिंसा होने का आरोप लगाया हो। इस कानून में सुरक्षा अधिकारी और सेवा प्रदाता की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है जो घरेलू हिंसा से पीड़िता के लिए मुख्य सहायक के रूप में काम करते हैं।

इस कानून में सेवा प्रदाता (धारा-10) का भी प्रावधान किया गया है जो कोई भी स्वैच्छिक संस्था/एनजीओ/कम्पनी हो सकती है। जो कानूनी चिकित्सालय/वित्तीय सहायता जैसे कानूनी तरीकों से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित हो। संस्था राज्य सरकार के पास पंजीकृत होनी चाहिए। इस कानून के अध्याय-4 के तहत पीड़िता को आर्थिक राहत देने का आदेश दिया जा सकता है। कानून के तहत पीड़िता के लिए संरक्षण आदेश (धारा-18), आवास आदेश (धारा-19), आर्थिक सहायता (धारा-20) और मुआवजा आदेश (धारा-24) आदि समाधान उपलब्ध है।

सुप्रीम कोर्ट के जी.वी.एन. कामेश्वर बनाम जी जबीली (2002) 2 एस.सी.सी. 296 केस में ढूसरी पार्टी को कष्ट देने के उद्देश्य से किए गए कार्य को निर्दयता का दर्जा दिया गया है। कानून में कहा गया है कि अत्यधिक गुस्से के कारण घटित घटना को निर्दयता नहीं माना जाएगा। जबिक ए.जयचंद्र बनाम अनिल कौर (2005) 2 एस.सी.सी. 22 मामले में कोर्ट ने निर्दयता को निर्दयता माना है चाहे उसकी मनोदशा अत्याचार करने की हो या न हो। मुख्य रूप से अदालत इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करती है कि पित का चित्र निर्दयता से सम्बंधित है या नहीं जैसे-

- 1. पार्टी की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जिस समाज में वे रहते है, उसका सामाजिक व शैक्षिक स्तर।
- 2. पार्टी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य।
- 3. पार्टी का दिन व दिन के सम्बंध।
- पहले से ही अलग रहने वाली पार्टी में एक साथ रहने की संभावना।
- 5. शिकायत का ढूसरे पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ता है। अदालत इस बात पर भी विचार करती है क्योंकि यह कार्य जानबूझकर या गलती से किया गया भी हो सकता है।
- 6. यदि शिकायत झूठी और गैरकानूनी है तो दूसरे पक्ष पर इसके प्रभाव पर विचार नहीं किया जाता है।

यिष कोई महिला वकील करने में समर्थ नहीं है परंतु वह कोर्ट में किसी का प्रतिनिधित्व चाहती है तो वह सी.पी.सी. के आदेश 33 स्व. नियम 09 (क) के अंतर्गत वकील निर्धारित करने का प्रार्थना पत्र अदालत में पेश कर सकती है। इस कानून के अनुसार प्रत्येक महिला निशुल्क कानूनी सहायता की हकदार है। विभिन्न राज्यों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड है। सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी सहायता सेवा समिति है।

मेरा मानना है कि घरेलू हिंसा कानून अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि महिला को किसी भी हालात में घर छोड़ने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा जबकि पहले के कानून में महिलाओं को सबैव कहां रहेगी, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए अनिगनत बार न चाहते हुए भी उसी हिंसा के माहौल में रहकर समझौता करना पड़ता था। मेरे विचार से इस कानून में केवल मारपीट और लड़ाई-झगड़े ही नहीं, बल्कि महिलाओं की छोटी सी छोटी समस्या को बहुत बारीक से स्पष्ट किया है। लेकिन सुरक्षा अधिकारियों की अभी भी कमी है। प्रशासन को इस क्षेत्रमें नियुक्तियां बढ़ानी चाहिए। अदालत द्धारा दिए गए निर्देशों का पालन उचित तरीके से हो रहा है या नहीं इसकी जिम्मेदारी भी सुरक्षा अधिकारी की है। मेरा यह भी मानना है कि मुकदमे की बारिकियां समझने के लिए न्यायाधीशों के और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

उपसंहार- घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के मार्ग में अनेक बाधाएं है। जैसे-परम्परागत सोच, सामाजिक, लांछन, आर्थिक पराधीनता, अशिक्षित महिलाओं द्धारा कानून के प्रावधान की अनिभज्ञता तथा जटिल और लम्बी प्रक्रिया। कानून की प्रासंगिकता भी तभी है जब इसका उचित रूप से पालन किया जाए। कानून का उचित रूप से पालन हो इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

समाज में विस्तृत रूप से फैले इस हिंसा के दौर को मिटाने के लिए जागृति परम आवश्यक है। संगठनों को मिलकर हिंसा के प्रति आवाज को दृढ़ करना जरूरी है। जिससे महिलाओं की सुनवाई शीघ्र हो। अपराधी को ढूंढकर सजा का प्रावधान हो और बलात्कार जैसे मामलों पर कड़ी से कड़ी सजा मिले। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला को सामाजिक संस्थाओं द्धारा समर्थन एवं सुरक्षा मिले। मेहनत, मजदूरी करने वाली महिलाओं को बराबर का हक मिले। सब भेदभाव मिटाने के लिए और अधिक प्रयास हो। मीडिया का रवैया भी सकारात्मक होना चाहिए।

स्त्री अधिकार को लेकर संवेदनशील सामाजिक व्यवस्था बनाना महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन इसे व्यवस्थित ढंग से लागू करना और भी महत्वपूर्ण है। ऐसे कानून तभी कारगार सिद्ध हो सकते है जब पीड़ित पक्ष को भरोसा दिलाया जाए कि अन्याय उसकी किस्मत में नहीं है और उसे यातना से मुक्ति मिल सकती है। उसकी इस मानसिकता को बदलना होगा कि यदि वह अपने संरक्षण के लिए कानून का सहारा लेती है तो इसका अर्थ सामाजिक व पारिवारिक मर्यादा तोडना नहीं है।





मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का मानकीकरण एवं मूल्यांकन

डॉ. प्रभाकर मिश्र *

मानव विकास के लिए शिक्षा सर्वश्रेष्ठ उपादान है। इसके माध्यम से सामाजिक, राष्ट्रीय एवं वैष्विक समस्याओं का समाधान खोजने तथा मानव जीवन को समृद्ध बनाने की दृष्टि प्राप्त होती है। अत: वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब कि जन समस्याओं के अंबार और संसाधन क्षीणता में सतत् वृद्धि हो रही है, उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा से परिपूर्ण मनुष्य अपने तथा दूसरों के जीवन की राह को आसान बना सकता है क्योंकि उच्च शिक्षा ही समस्त सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी विकास की आधार शिला है।

अतः शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश के व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों को छोड़कर सामान्य उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों की गुणवत्ता के मानकीकरण की स्थिति का आंकलन करने का प्रयास किया गया है।

उच्च शिक्षा संस्थान के मानकीकरण की आवश्यकता :

वर्तमान समय में मानव विकास की प्रतिस्पर्धा ने उच्च शिक्षा के महत्व को और अधिक बढ़ा ढिया है। ढेश में श्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान, सक्षम फैकल्टी तथा विद्यार्थी उपलब्ध हैं परन्तु ज्ञान की वैश्विक स्पर्धा में प्राचीन काल में ज्ञानगुरू रहे भारत की स्थिति को अब संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है।

आज अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था है जिसे विश्व स्तरीय बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है ताकि भारतीय उच्च शिक्षा उत्पाद को विश्व बाजार की स्पर्धा में उतारा जा सके।

ऐसे में हमें अपनी उच्च शिक्षा व्यवस्था के दोषों को खोजकर उन्हें दूर करने के सामयिक प्रयास करने होंगे ताकि आगामी समय में भारतीय छात्र विश्व स्तरीय उत्कृष्टता का प्रदर्शन करके अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें।

उच्च शिक्षा की इस स्थिति के आलोक में केवल एक ही प्रयास किया जाना समीचीन है कि हम अपने संस्थानों का स्वच्छ मूल्यांकन करें। संस्था या व्यवस्था के मूल्यांकन से उसके सकारात्मक एवं प्रगति के अवरोधों का उद्घाटन होता है जिससे उसके सुधार की संभावनाओं तथा अनुकूलतम उपयोग की संभावनाओं का आंकलन करके वांछित सुधार किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा संस्थान के मूल्यांकन के आधार :

देश में उच्च शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्व स्तरीय बनाने के लिए 11 वीं योजना में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों की वास्तविक प्रगति ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् – 1994 (NAAC) जो कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है के माध्यम से संस्थानों का मूल्यांकन देश अन्य प्रगत संस्थानों की भांति किया जा रहा है।

शैक्षणिक मूल्यांकन के लिए परिषद् द्धारा उच्च शिक्षण संस्थानों को तीन वर्गों यथा – विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालय में विभक्त किया गया है। शैक्षणिक निष्पादन के आधार पर व्यवस्था के मूल्यांकन के लिए 07 मुख्य आधार (पाठ्यक्रम पक्ष, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन, शोध, अनुवीक्षण एवं विस्तार, अधोसंरचना एवं अधिगम संसाधन, छात्र सहायता प्रगति, प्रशासन, नेतृत्व एवं प्रबंधन तथा नवाचार एवं स्वस्थ परंपराएं) 36 उपविभाग तथा 196 प्रमापी संकेतक निधारित किये गये हैं। इन संकेतकों में से 25 संकेतक अति महत्वपूर्ण हैं जिनके संबंध में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। संस्थाओं के संचालन एवं संगठन की प्रकृति के आधार पर 07 मुख्य आधारों के 36 उपविभागों को निधारित रूप से अधिभारित करके प्रक्रियानुसार ग्रेडिंग (ए,बी,सी तथा डी) प्रदान करके संस्थान को मूल्यांकित किया जाता है।

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा :

म.प्र. शासन ने उच्चशिक्षा के सुदृढीकरण के लिए विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में संरचनात्मक सुधार एवं विस्तार के साथ – साथ उच्च शिक्षा की गुणात्मकता बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किये हैं। युवा पीढ़ी के समग्र विकास तथा ग्रामीण अंचल तक उच्च शिक्षा का व्यापक प्रसार करने हेतु सत्र 2010 – 11 में प्रदेश में 32 नवीन महाविद्यालय एवं 07 निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ किये गये हैं। उच्च शिक्षा के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सत्र 2010 – 11 के अनुसार प्रदेश में संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों का वितरण निम्नानुसार है –

壐.	उच्च शिक्षण संस्थान का प्रकार	संख्या
1.	प्रादेशिक विश्वविद्यालय	06
2.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	02
3.	विश्वविद्यालय स्तरीय अन्य संस्थान	08
4.	शासकीय महाविद्यालय	328
5.	शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय	77
6.	शासकीय अनुदान अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय	578

इन संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 0.54 लाख अनुसूचित जाति, 0.34 लाख अनुसूचित जन जाति तथा 01.31 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कूल 03.28 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थे।

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन :

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् – 1994 (NAAC) के प्रतिवेदन के अनुसार समस्त 07 विश्वविद्यालयों का मानकीकरण एवं मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश के 04 विश्वविद्यालयों को सितारा मूल्यांकन के अनुसार ए 4 सितारा ग्रेड प्रदान किया गया है वहीं शेष 03 विश्ववालयों अवधेष प्रताप विश्वविद्यालय, रीवा, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल तथा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर को नवीन मूल्यांकन पद्धति के अनुसार क्रमशः सी++,बी तथा बी++ ग्रेड दिया गया है।

सामान्य उच्च शिक्षा से संबंधित समस्त विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन कार्य शत प्रतिशत पूर्ण होने से संस्थानों की गुणवत्ता का स्तर ज्ञात हो जाने



से आगामी कार्य योजना बनाने में जहां सहायता मिल सकेगी वहीं ये संस्थान समय पर आवश्यक सुधार कर सकेंगे। इस प्रकार विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन कार्य सराहनीय है।

संबद्ध संस्थानों, महाविद्यालयों की स्थिति मूल्यांकन एवं प्रत्यायन के दृष्टिकोंण से उत्साहजनक नहीं कही जा सकती। प्रदेश के 790 में से केवल 42 महाविद्यालयों द्धारा मूल्यांकन कार्य करवाया गया है जो कुल का केवल 05.5 प्रतिशत ही है। जिनमें 64 प्रतिशत महाविद्यालय नगरीय क्षेत्र से तथा 36 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं।

42 महाविद्यालयों में से 08 महाविद्यालयों को ए श्रेणी, 28 को बी तथा शेष 06 महाविद्यालयों को सी श्रेणी प्राप्त हुई है। अब तक किये मूल्यांकन में प्रशासकीय दृष्टि से 69 प्रतिशत शासकीय महाविद्यालय तथा 31 प्रतिशत निजी महाविद्यालयों ने मूल्यांकन कार्य सम्पन्न कराया है जो महाराष्ट्र, हरियाणा तथा पंजाब जैसे राज्यों की तुलना में अधिक है।

समस्याएं :

विविध संस्थानों के मापन एवं मूल्यांकन से स्पष्ट है कि स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक वृद्धि प्रभूत मात्रा में प्रदर्षित हुई है जिसके कारण प्रबंधन एवं गुणात्मकता के आधार पर हास की प्रवृत्ति विचारणीय दिखायी देने लगी है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एवं प्रत्यायन से संबंधित समस्याएं निम्नानुसार हैं –

- पराम्परागत पाठ्यक्रम समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं
 हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना एवं शिक्षण संसाधनों का अभाव है।
- 3. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ का अभाव है। म.प्र. के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 769, सहायक प्राध्यापकों के 1032, ब्रन्थपाल के 123, क्रीड़ाधिकारी के 145 तथा रजिस्ट्रार के 17 पढ़ रिक्त हैं जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
- 4. वास्तविक एवं चुनौतीपूर्ण मौलिक शोध कार्य एवं इसके प्रसार एवं प्रकाशन का अभाव है।
- 5. परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य क्षेत्रों में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं जिससे छात्र असंतोष होता है और परिणाम घोषित करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।
- 6. मूल्यांकन संस्था की प्रवर्तन प्रक्रिया अनिवार्य नहीं होने से प्रदेश में मूल्यांकन का कार्य अत्यंत धीमा है जिससे विकास की प्रक्रिया में भी विलम्ब होना अवश्यंभावी है।

सुझाव :

- पराम्परागत पाठ्यक्रम में समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन एवं परिवर्धन करके उन्हें वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना एवं शिक्षण संसाधनों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्धारा संचालित पिछड़े क्षेत्र से संबंधित अनुदान योजना के माध्यम से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके अभाव को दूर करने के प्रयास किये जायें।
- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ के अभाव को यद्यपि अम्बेसडर प्राध्यापकों, प्रतिभावान प्राध्यापकों

- तथा अतिथि विद्धानों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की जाती है लेकिन यह उच्च गुणवत्ता के मानक को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। अत: पूर्णकालिक शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की व्यवस्था की जाना उचित है।
- 4. यह मूल्यांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्धारा आवश्यक क्षेत्रों में संस्थानों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए वांछित है।
- परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन में वांछित सुधार करके कार्योपरान्त परीक्षा परिणाम समय सीमा में घोषित होने चाहिए ताकि छात्रों को अन्य परीक्षा में बैठने /प्रवेश लेने का अवसर समय पर मिल सके।
- सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए मूल्यांकन अनिवार्य करके इसके लिए समय सीमा तय करनी चाहिए ताकि मूल्यांकन कार्य को शीघ्र पूरा किया जा सके।

निष्कर्ष :

उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। हमें अपनी शिक्षण व्यवस्था में विचारों की सामयिकता, प्रयोगधर्मिता, वैचारिक उदारता, नवीनता, कार्यकुशलता, मौलिकता तथा समर्पण एवं समन्वय को सिमलित करके लक्ष्य प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने होंगे। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने यद्यपि समसामयिक नवाचारों को स्थान देकर व्यवस्था को प्रगत करने का सराहनीय प्रयास किया है फिर भी विभिन्न शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन कार्य में अपेक्षित शीघ्रता की आवश्यकता है क्योंकि उच्च शिक्षा में व्यवस्था का सामयिक मूल्यांकन इसके परिशोधन एवं परिमार्जन की प्रगति एवं प्रकृति को जानने के लिए नितांत आवश्यक उपक्रम है जिसके अभाव में वांछित क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं तथा आवश्यकताओं को ज्ञात करके उनका समयोचित समाधान खोजना कठिन है।

संदर्भ :

- 1. उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन भोपाल, वार्षिक प्रतिवेदन, 2010–11
- परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, नव.
 2008
- 3. Higher Education in India: Issues related to expansion, inclusiveness, quality and finance, UGC pub. 2008.
- 4. Best practices series six curriculum aspect. NAAC pub. 2008.\
- Quality and excellence in higher education , State report MP NAAC pub. 2009



मानव विकास सूचकांक में भारत के राज्यों की स्थिति (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

डॉ. रिखबचन्द्र जैन *

अवधारणा -

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ जुडे हुए अर्थशास्त्री महबूब – उल – हक ने विकास के एक सर्वमान्य का विकसित करने की दिशा में सबसे पहले प्रयास शुरू किया और प्रो. अमर्त्य सेन तथा प्रो. सिगंर हंस के नेतृत्व में मानव विकास सूचकांक (HDI) विकसित किया।

मानव विकास सूचकांक में 2001 से 2013 तक जिसमें 2007 एवं 2008 को छोड कर पूरे विश्व में नार्वे प्रथम स्थान पर हैं। 14 मार्च 2013 को जारी HDI जो सन् 2012 के संमक पर आधारित हैं जिसमें प्रथम क्रम पर नार्वे जिसका HDI मुल्य 0.890 हैं भारत का स्थान 187 देशों में 136 वें क्रम पर हैं तथा HDI का मुल्य 0.554 है।

मानव विकास सूचकांक इस मान्यता पर आधारित हैं कि ''किसी राष्ट्र में रहने वाले लोग ही उस राष्ट्र की वास्तविक सम्पत्ति हैं आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिससे लोग लम्बे, स्वस्थ तथा सृजनात्मक जीवन का आनंब उठा सकें।मानव विकास सूचकांक तीन मानकों स्वास्थ्य, शिक्षा, आय एवं रहन-सहन के स्तर के आधार पर तैयार किया जाता हैं सूचकांक के लिए स्वास्थ्य स्तर का आकलन जीवन प्रत्याशा के द्धारा, शैक्षणिक स्तर का प्रोढ़ साक्षरता और प्राथमिक द्धितीयक एवं तृतीयक स्तर पर पंजीकरण के आधार पर तथा रहन-सहन स्तर का आकंलन आय के स्तर एवं क्रय शिक समता के आधार पर किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर ही भारत के राज्य भी अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने की ओर उन्मुख हुए है। राज्य स्तरिय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश है। जिसने 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

- 1. भारत में मानव विकास सूचकांक की स्थिति का अध्ययन करना।
- भारत के राज्यों में मानव विकास सूचकांक की स्थिति का अध्ययन करना।
- 3. मानव विकास सूचकांक के संकेतो का मूल्य ज्ञात करना।
- 4. मानव विकास सूचकांक के मुल्यों का उसके संकेतो से सहसम्बंध गुणांक ज्ञात करना।
- मानव विकास सूचकांक के स्तर को उच्च करने हेतु अन्य घटको का विश्लेषण करना।

शोध विधि:-

द्धितीयक संमको को ज्ञात करना तथा उन संमको से औसत, रैंक तथा सह सम्बंध गुणांक ज्ञात करना।

मानव विकास सूचकांक का विश्लेषण :- *(देखिए ग्राफ-* 1)

HDI का मापन :-

इसका माप दण्ड तीन आयाम एवं चार सूचको पर आधारित हैं जो निम्न है।

तीन आयाम

1. स्वास्थ्य 2. शिक्षा 3. जीवन स्तर

चार सूचक

- 1. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2. प्रोढ़ साक्षरता दर
- शिक्षा में संयुक्त संकल नामांकन 4. प्रति व्यक्ति संकल घरेलु उत्पाद

सन् 2010 सें पूर्व HDI के मापन की विधि -

 जीवन प्रत्याशा सूचकांक (LEI) = <u>LE-25</u> 85-25

2. शिक्षा में सूचकांक (EI) = <u>2</u> x ALI + <u>1</u> x GEI 3 3

2.1 प्रोढ़ साक्षरता सूचकांक (ALI) = <u>ALR - 0</u>

2.2 सकल नामांकन सूचकांक (GEI) = <u>CGER - 0</u> 100-0

3. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) = <u>Log (GDP_{PC}) - Log (100)</u> Log (40000) - Log (100)

100-0

इस प्रकार

HDI=<u>जीवन प्रत्याशा सूचकांक+शिक्षा में सूचकांक</u>+वास्तविक सकल घरेलु उत्पाद सूचकांक

मानव विकास सूचकांक के मापदण्ड की नई विधि :-

मापदण्ड का यह तरीका 4 नवम्बर 2010 को प्रकाशित हुआ जो HDI की 2010 की रिपोर्ट पर आधारित है। तथा यह 10 जून 2011 को लागू हो नारा है।

तीन संकेतो का उपयोग करते हुए

 जीवन प्रत्याशा सूचकांक LEI = <u>LE-20</u> 82.3 - 20

2. शैक्षणिक सूचकांक (EI) = **V**<u>MYSI.EYSI</u> 0.951

2.1 प्रोढ़ साक्षरता सूचकांक (MYSI) = <u>MYS</u> 13.2

2.2 शिक्षा में सकल नामांकन सूचकांक (EYSI) = <u>EYS</u>20.6

. आय सूचकांक (II) = <u>l. (GNIpc) - l. (100)</u>

l،(107721) - l، (100) अंतिम क्या से HDI का मागन गर्व के तीन संकेतो के गागीनर माध्य

अंतिम रूप से HDI का मापन पूर्व के तीन संकेतो के गुणोत्तर माध्य से ज्ञात करते हैं।

यहाँ LE

– जन्म के समय जीवन प्रत्याशा

MYS – 25 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का स्कूल नामांकन



EYS 👤 – 5 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का स्कूल में नामांकन

GNI_{PC} - प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू आय क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर

मानव विकास सूचक मूल्य -

मानव विकास का क्रम	HDI का मूल्य
विकसित देश	0.8 - 1.0
विकासशील देश	0.5 - 0.8

अल्पविकसित देश 0 - 0.5 (देखिये तालिका 1)

तालिका 1 से स्पष्ट है कि HDI में भारत का विश्व में स्थिति 1990 से लगभग बढ़ रहीं है। जो इस बात को परिलक्षित करता है कि आर्थिक सुधारों के पश्चात भारत ने उदारीकरण व वैश्वीकरण को अपनाते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं क्रयशक्ति में वृद्धि की है।

तालिका – 2 में केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडू एवं हरियाणा के मानव विकास सूचकांक अन्य राज्यों से उच्चतर है। सामान्यतया इन राज्यों का प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय भी ऊची है।

तालिका – 3 से स्पष्ट है कि HDI एवं जीवन प्रत्याशा में धनात्मक उच्च सहसंम्बंध गुणांक 0.934 है। जिससे स्पष्ट हैं कि HDI एवं जीवन प्रत्याशा में घनिष्ट धनात्मक सहसम्बंध है HDI एंव शैक्षणिक सूचकांक में सहसंम्बंध गुणाक +0.849 हैं तथा HDI एवं प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में सहसम्बंध गुणांक +0.836 हैं। अर्थात कभी –कभी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी HDI उच्च नहीं हैं क्योंकि वे राज्य आय का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं।

साथ ही स्पष्ट है कि केरल राज्य का प्रति व्यक्ति संकल घरेलु उत्पाद में देश में 5 वॉ क्रम हैं परन्तु आय का उचित उपयोग करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा पर व्यय करके HDI में प्रथम क्रम पर हैं, पंजाब का GDP में क्रम 9 वाँ होंने पर भी HDI में 3 वॉ क्रम हैं हरियाणा का GDP उच्च होने पर भी HDI नीचे हैं। हिमाचल प्रदेश का भी GDP कम होने पर भी HDI ऊंचा हैं गुजरात का GDP ऊंचा होने पर भी HDI नीचा हैं। अर्थात केरल, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश आय का उचित उपयोग करते हुए HDI को बढ़ा रहे हैं जबकी हरियाणा, महाराष्ट्र एवं गुजरात आय के सापेक्ष HDI को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अन्य राज्यों की कमोबेश स्थिति सामान्य हैं।

Source - HDRQ

निष्कर्ष एवं सुझाव :-

मानव विकास सूचकांक को 10 जून 2011 से नई विधि से माप रहे हैं जिसमें तीन आयाम तथा चार सूचक जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा प्रोढ़ साक्षरता ढर, शिक्षा में संयुक्त सकल नामांकन तथा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाढ़ हैं।

- 1. भारत का HDI का मूल्य आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के पश्चात लगभग बढ़ रहा हैं विश्व में भी भारत का स्थान लगभग स्थिर सा है।
- 2. भारत के प्रमुख राज्यों का HDI रेंक सन् 1981 से 2011 तक में केरल प्रथम क्रम पर हैं तमिलनाडु ने पूर्व के वर्षों से अपनी स्थिति मजबुत की है।
- 3. भारत के प्रमुख राज्यों का HDI का जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर तथा प्रति व्यक्ति संकल घरेलु उत्पाद से उच्च धनात्मक सहसंबंध हैं। HDI एवं जीवन प्रत्याशा में सहसम्बंध गुणांक, HDI एवं प्रति व्यक्ति आय में समसम्बंध गुणांक के सापेक्ष अधिक हैं।

सुझाव :-

- 1. HDI में शामिल तीन सूचक क मानव विकास का सूचक शिशु मृत्युदर पोषण आदि सामाजिक सूचको को भी शामिल करना चाहिए।
- 2. राज्यों एवं देश की आय की असमानता को कम करके HDI का मूल्य बढ़ा सकते हैं।
- 3. HDI का प्रमुख संकेतक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हैं जिसे बढ़ा कर HDI बढ़ा सकते हैं।
- 4. HDI का मूल्य बढ़ाने के लिए देश व राज्यों को आय का उचित उपयोग करते हुए मानवीय कल्याण को प्रमुखता देनी चाहिए।

संदर्भ :-

- 1. The Human development concept UNDP Retrieved 7 APR 2012.
- 2. www.undp.org
- 3. Economic Survey 2011-12 PP. 310 to 311
- 4. प्रतियोगिता दर्पण भारतीय अर्थव्यवस्था २०१०
- 5. आर्थिक संवृद्धि और विकास वी.सी. सिंहा मयूर पेपर बेक्स।

ग्राफ- 1

The HDI - three dimensions and four indicators Mote - The indicators presented in this figure follow the new methodology, as defined in box 1.2





भारत में मानव विकास सूचकांक (तालिका-1)

वर्ष	HDI	रेंक	वर्ष	HDI	रेंक
1990	.439	94	2000	.456	128
1991	.308	123	2001	.571	115
1992	.297	121	2006	.515	134
1993	.309	134	2007	.525	128
1994	.382	135	2008	.533	134
1995	.439	134	2009	.540	127
1996	.436	135	2010	.547	123
1997	.446	138	2011	.467	134
1998	.451	139	2012	.554	136
1999	.458	132			

मानव विकास सूचकांक में राज्य (तालिका-2)

राज्य	HDI आधारित रैंक						
(100)	1981	1991	2001	2011			
आन्ध्रप्रदेश	9	9	10	9			
असम	10	10	14	10			
विद्यार	15	15	15	14			
गुजरात	4	6	6	6			
हरियाणा	5	5	5	5			
कनार्टक	6	7	7	7			
केरल	1	1	1	1			
मध्यप्रदेश	14	13	12	13			
महाराष्ट्र	3	4	4	3			
उड़ीसा	11	12	11	15			
पंजाब	2	2	2	2			
राजस्थान	12	11	9	11			
तमिलनाडू	7	3	3	4			
उत्तर प्रदेश	13	14	13	12			
श्चित बंगाल	8	8	8	8			





भारत के राज्यों में मानव विकास सूचकांक वर्ष 2011 (तालिका-3)

		_						
राज्य	मानव विकास सूचकांक	मानव विकास सूचकां क का रेंक	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का रेंक	साक्षरता की दर	साक्षरता की दर का रेंक	प्रति व्यक्ति संकल घरेलू उत्पादन (करोंड् इ. में)	प्रति व्यक्ति संकल घरेलू उत्पादन का रेंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
केरल	.790	1	75.8	1	93.91	1	83725	5
हिमाचल प्रदेश	.652	2	69.4	4	83.8	2	74899	7
पंजाब	.605	3	72.6	2	79.9	5	74606	8
महाराष्ट्र	.572	4	69.5	3	80.1	4	101314	2
तमिलनाडू	.570	5	68.4	6	80.3	3	84496	4
हरियाणा	.552	6	68.9	5	76.6	9	108859	1
गुजरात	.527	7	66.4	11	79.3	7	89664	3
कर्नाटक	.519	8	67.9	7	75.6	10	68374	10
प. बंगाल	.492	9	67.2	8	77.1	8	55522	11
उत्तराखण्ड	.490	10	66.8	10	79.6	6	82193	6
आंधप्रदेश	.473	11	67.0	9	67.7	16	68970	9
असम	.467	12	61.9	16	73.2	12	33633	17
राजस्थान	.444	13	64.5	12	67.1	18	47506	12
उत्तरप्रदेश	.434	14	62.6	14	71.7	13	30051	18
झारखण्ड	.380	15	61.0	17	67.6	17	35652	16
मध्यप्रदेश	.376	16	61.0	18	70.6	15	38669	15
बिहार	.375	17	63.0	13	63.8	19	23435	19
उडिसा	.367	18	62.6	15	73.5	11	46150	14
छत्तीसगढ़	.362	19	61.0	19	71.0	14	46573	13
भारत	.467		65.5		74.04		61564	

सहसम्बंध गुणांक :-

 $r_{24} = + 0.934$

 $r_{26} = + 0.849$

 $r_{28} = +0.836$





दशपुर अंचल में भक्ति एवं शृंगार की रससिद्ध कवयित्रियाँ

(एक चिन्तन)

डॉ. कृष्णा पैन्सिया * डॉ. राजेन्द्र कुमार पैन्सिया **

मालवा जहां पग-पग रोटी डग-डग नीर के लिए प्रसिद्ध है वहीं भक्ति और शृंगार के लिये भी सिद्ध है। दशपुर जनपद के लिए लोक साहित्य विद् डॉ. पूरन सहगल ने लिखा है 'यदि मालवा, भारत का हृदय स्थल है तो दशपुर जनपद मालवा का हृदय स्थल है।' (1)

अपने इसी आलेख में वे लिखते हैं— 'यह दशपुर अंचल मालवा का राजदूत है। यह मालवा की गौरवशाली कीर्ति पताका है। यह दशौरी मालवी का क्षेत्र सितयों, साध्वियों और सतवंतियों की धरती है। यह पीरों, फकीरों, संतों, और समरथों की धरती है। यह वीरों और शहीदों की धरती है। यह अमीरों, दानवीरों, कवियों और साहित्यकारों की धरती है। यह गोपालों और किसानों की धरती है। यह चारणों और चराहगारों की धरती है। यह बालकिव बैरागी और स्वामी निर्भयरामजी की धरती है। यहाँ के फाग, यहाँ के राग, यहाँ की भुवाई, यहाँ के माच, यहाँ की छपाई, रंगाई, कताई, बुनाई का यश सात समुद्ध पार तक ख्यात रहा है। देवता .यहाँ मेहमान बनकर आते है। यह हरी—भरी, सुहाग—भाग की धरती है। यह देव भूमि है। यह सतरंगी छवियों वाली रलक—दलक सावगी—सुहानी धरती है। मालवा की यह चहेती है। अरावली की यह बेटी है। इसकी लोक संस्कृति मालवा की महान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की यह आधार भूमि है। इसका वंदन अभिनंदन !! (2)(मालवी से हिन्दी अनुवाद)

जब डॉ. पूरन सहगल को उन्हीं का लिखा यह अंश पढ़कर सुनाया तब उन्होंने कहा इसमें इतना और जोड़ लो-'' यह हुणारि हर्षवर्द्धन की धरती है। यह कृष्ण भक्त चन्द्रसखी, नवनिधि कुँवर और शृंगार की म्हाड मर्मज्ञ रस सिद्ध सुंदर की धरती है। रूपमती इस अंचल में आकर स्वयं को धन्य मानती थी। यह भक्ति और शृंगार के अदभुत संयोग की धरती है। यहाँ की प्रभात में भक्ति की तन्मयता है तो संध्या में शृंगार की मौज भरी उमंग।''

ऐसा है हमारा मालवा। इसी भाव को लेकर उन्होंने अपनी एक पुस्तक का नाम ''मालव देस सुवासणो' रखा है। उनके अनुसार भक्ति शृंगार को संयमित करती और शृंगार भक्ति को रसपूर्ण बना देता है। मीरा, सूरदास, तुलसीदास, रसखान और चन्द्रसखी नवनिधि कुंवर और सुदंर जैसी अनेक भक्त विभूतियाँ इसका उदाहरण है।''

बात चन्द्रसंखी की आती है तब आदिवासी लोककला एवं तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल व्हारा प्रकाशित ग्रंथ 'लोक की भक्ति' का अध्ययन करते हैं। यह ग्रंथ वर्ष 2009 में प्रकाशित हुआ। पृष्ठ 447 से 640 तक डॉ. पूरन व्हारा संकलित एवं अनुदित 219 चन्द्रसंखी के पद संग्रहित है। डॉ. सहगल के संग्रह में 140 पद अप्रकाशित भी सुरक्षित हैं। इस प्रकार चन्द्रसंखी के 359 पद डॉ. पूरन सहगल ने लोक कंठों से संग्रहित किए हैं। इस अँचल में भजन मंडलियों में मीरा से भी अधिक चन्द्रसंखी के भजन-पद गाए जाते हैं। उनके पढ़ों में 'चन्द्रसखी ब्रजबाल की शोभा', 'चन्द्रसखी ब्रज बाल कसन छवि', तथा केवल 'चन्द्रसखी' की छाप लगी दिखती है।

इस कृष्ण भक्त कवियत्री का मूल पारिवारिक नाम रुपकुँवर था। कृष्ण भक्ति के प्रति लगन इसे अपनी माता जसकुँवर के कारण लगी। जसकुँवर उस समय की जानी-मानी कृष्ण भक्त थीं। उनका स्व रचित कोई पढ़ नहीं मिलता किन्तु वे भजन मंडलियों में कृष्ण परक पढ़ गा-गाकर भक्ति रस का आनंढ़ पूरे अंचल को प्रदान करती थीं।

चन्द्रसखी चम्बल नदी के किनारे बर्रामा नाम के एक देवड़ा राजपूत ठिकाने की रहने वाली थी। कछे ला चारण गोत्र में इसका जन्म हुआ था। पारंपरिक रूप से गोचारण करना इसके परिवार का काम था। स्वयं चन्द्रसखी भी चम्बल के किनारे पर गोचारण करती थी। उसी दौरान वह खेजड़े वृक्ष के नीचे बैठकर अलगोजा बजाती थी और कृष्ण भक्ति के पदों का गान करती थी।

चन्द्रसखी की भक्ति न तो मीरा की तरह पित/स्वामी परक थी न सूरदास की भाँति सखा परक। वह कृष्ण की भक्ति रसखान की तरह ब्रह्म रूप में भी नहीं करती थीं और कृष्ण को ब्रह्म पुराणों, वेदों या कथा-भागवत में भी नहीं खोजती थीं। कृष्ण उसके भाई थे। इसी रूप-संबंध में चन्द्रसखी ने कृष्ण की आराधना की। अपने अंतिम दिनों में वे चम्बल, बर्रामा तथा सम्पूर्ण मालवा छोड़कर कृष्ण के देश चली गई। गोकुल में ही जाकर रही और वहीं उनका प्राण विसर्जन हुआ। अपने आत्म कथ्य में कहा है-

> ''चारण की जायी मुलक म्हारो मालवो। मुलक म्हारो मालवो, जी भ्रेस म्हारो मालवो॥ ⁽³⁾ ××× ××× ××× चम्बल कनारे म्हारो गाम सांवस्यो आ जा रे। ⁽⁴⁾

जब चन्द्रसखी मालवा छोड़कर कृष्ण के देश गोकुल में गई तब उसके पद में यह संदेश मिल जाता है।

'मुलक मालवा छोड़ कन्हैया, आई थारे देस।' ⁽⁵⁾ चन्द्रसखी का यह निम्नलिखित पद कृष्ण को भाई मानकर आराधने का करण-निवारण करता है-

''म्हारो हग्गो भाई लागे कुँवर कन्हाई ॥टेक॥
ढुपद सुता री लज्जा राखी, ज्युँ म्हारी लाज बचाई ।
जामण जाया रो वेश धरघो कान्हें लीला तुरत रचाई ॥
कारा भांग जुद्ध लड़यो, बण म्हारो हग्गो भाई ।
हेलो पाड़-पाड़ नैं थाकी, करो न क्युँ सुणवाई ।
चन्द्रसखी री वीणती, सुणलीजो नंद राई ।
थोड़ी और निभा लो कान्हा, अब तक घणी निभाई ॥ (6)



चन्द्रसखी का समय सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी विक्रमी के मध्य ठहरता है। बर्रामा में 'चन्द्रसखी की बारी' एक स्थान था। ऐसा स्थान पीहर वाले अपनी बहन-बेटी के मरणोपरान्त बहुधा बनवाते रहे हैं।

बर्रामा गांव गांधीसागर बाँध के जलविस्तार में डूब गया है। चन्द्रसखी उस गाँव की यश ध्वजा अपने भक्ति पढ़ों में पूरे मालवा में फहराती रही हैं। आज भी उनके पढ़, भजन मंडलियों में गाए जाते हैं। वे मालवा की मीरा के नाम से ख्यात हैं। ⁽⁷⁾

ऐसी ही एक और कृष्ण भक्त कवियत्री हुई हैं जिनका नाम नविनिध कुँवर 'खांगारोत'। वे मनासा के पास चन्द्रावत ठिकाना भाटखेड़ी की राजामाता थीं। उनका पीहर जयपुर राज्य के जोबनेर ठिकाने में था। उनका जन्म 1892 ईस्वी माना जाता है। (8) सन् 1908 ईस्वी में भाटखेड़ी ठिकाने में कुँवर सज्जन सिंह चन्द्रावत के साथ उनका विवाह हुआ था। विवाह के समय उनकी आयु 16 वर्ष थी। सज्जनसिंहजी की मृत्यु का वर्णन स्वयं खांगारोतजी ने भाटखेड़ी में उनके द्धारा अपने पति कुंवर सज्जनसिंह जी की स्मृति में बने शिलापट पर अंकित करवाया था जो आज भी पढ़ा जा सकता है। (9)

विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पित कुंवर सज्जनसिंहजी की मृत्यु इन्दौर के डेली कॉलेज के होस्टल में नागिन के डंसने से हो गई थी। इस दूसह दुख का वर्णन उन्होंने अपने एक गीत में किया है।

''बालपणे चुड़लो खण्डयो, रीति होई बाँट। जब री थारे आसरे, आई थारी छाँह।। नागण सौतण ने डस्यो, म्हारो भाग सुभाग। नागण जाया फुंफकारे, जब रा कारा नाग।। झट आओ रगसा करो, सांवलिया सिरकार। चन्द्रसखी रा वीरणा, मीरा रा भरतार।। रुकमणजी रा साहिबा, राधा रा सिणगार। नवनिधि री विपदा हरो, विपदा टारणहार।। विरथा ऊमर आ थगी, झट आओ करतार। हेला पाणू साँवरा, कद की ठाणी रार।। नवनिधि की झट सुण पुगो, कान्हा क्रसन मुरार। क्यों नी सुणो रे कानुड़ा, म्हारी अरज पुकार।। (10)

> ''विधवा प्रथम बणाय, फिर क्यों दुख देवण लगो । हिय पिगले नह हाय, रे जालिम जगनाथिया।।

नवनिधि कुँवर परम विदूषी महिला थीं। वे बहुपठ्य थी। (11) उनके समय में प्रकाशित होने वाली अनेक साहित्यिक पत्रिकाओं को वे मंगवाकर पढ़ती थी तथा उनमें उनके गीत आदि छपते थे। वे करुण रस की सिद्ध कवयित्री थीं। उनके देहान्त के पश्चात उनका प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य तथा पुस्तकालय उनके भाई नरेन्द्रसिंह ठिकाना जोबनेर अपने साथ ले गए आज उनके ठिकाने पर से भी सारी सामग्री गायब है। नवनिधि कुँवर जी की मृत्यु 23 मई 1947 को हो गई। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कृष्ण भक्ति के पद गाती थीं। उनका कंठ इतना मधुर था कि 'घट्टी' पीसने वाली महिलाएं अपने गीत भूलकर नवनिधि कुँवरजी के गीतों की धुन पर घट्टी पीसती थीं।

उनकी रचित अनेक पुस्तकों में से केवल आठ पुस्तकों के ही नाम उपलब्ध हैं। वे आठ भी उपलब्ध नहीं हैं। केवल 'छब चित्रावण क्रसन री' (अप्रकाशित) तथा 'आर्त आहें' (प्रकाशित) डॉ. पूरन सहगल जी के संग्रह में उपलब्ध हैं। कुछ फुटकर गीत भी डॉ. पूरन सहगल के संग्रह में हैं। (12) इसी प्रकार एक और संगीत साधना की सिद्ध कवियत्री रूपमती भी मालवी की रसिद्ध कवियत्री है। उनका रचित साहित्य अधिक उपलब्ध नहीं है। उनकी एक लोक गाथा 'धरती री हूर', 'रूपमती री गाथा' इस गाथा में 177 साखियाँ हैं। गाथा रूपमती के जन्म से मृत्यु पर्यंत की सम्पूर्ण घटनाओं का विवरण बखानती है। इसी प्रकार उनके स्वरचित 35 गीत तथा 75 साखियाँ डॉ. पूरन सहगलजी के संग्रह में (अप्रकाशित) उपलब्ध हैं। (13) रूपमती ने संगीत के अलवा कृष्ण भक्ति परक गीत रचे हैं। उनका एक पढ़ बहुत प्रचलित है–

'तारीके फरिश्ता' में रूपमती को 'लेडी आफ लोट्स' कहा है। सन् 1561 ई. में अहमद खां ने (अकबर का सेनापति) ने सारंगपुर और माण्डव पर विजय हासिल कर ली। 1561 में ही रूपमती का स्वर्गवास हो गया। 1593 में बाज बहादूर का देहान्त हो गया। सारंगपुर में दोनों का मकबरें है।

दोनों को आसपास दफनाया गया था। रूपमती मध्यकाल के संगीतकारों और कृष्ण भक्त कवियत्रियों में सर्वश्रेष्ठ विभूति थी। अकबर ने उनके मकबरे पर 'आशिके सादिक' लिखवाकर उनका सम्मान किया था। (14) रूपमती ने अनेक राग रागनियों की भी रचना की है। मांडव के सुल्तान से विवाह करने के उपरान्त भी वे नर्मदा मैया और कृष्ण की आराधना करती रहीं। उसे अपना धर्म निभाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।

मालवा की ही एक और कवयित्री का नाम दशपुर अंचल में माँड (एक राग) गायिका के रूप में अत्यंत सम्मानजनक रूप से जाना जाता है। दशपुर अंचल ठिकाना जीरन की यह राज गायिका थी। इसने अनेक माँड साखियों की रचना की तथा उन्हें खूब गाया भी।

डॉ. पूरन सहगल ने इसका समय सन् 1712-15 ईस्वी माना है। डॉ. पूरन सहगल ने अपने उपन्यास 'ढम्भ के विष' में 'सजना' नाम से इसे एक लोक गायिका के पात्र में प्रस्तुत किया है सुन्दर (सजना) जीरन की ही ढमामी कलवत जाति की गायिका थी। सुन्दर की साखियों और उसके सौंदर्य का वर्णन श्री समुद्धसिंहजी जोधा के सम्पादन में राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर से 1987 ई. एक राजस्थानी दोहों का संकलन प्रकाशित हुआ था। उसमें पृष्ठ क्रमांक 80-88 पर सुन्दर का उल्लेख किया गया है-(15)

सुन्दर सोहण सुन्दरी, अधर अलकता रंग। केहर तांकी क्षीण कटि, कोमल नेत्र कुरंग।। ××× ××× ××× सुन्दर घट घायल किया बहगी धार- दुधार। हारमनी प्रिय म्यानकर. नैणा री तरवार।। (16)



संवत् 1903 कि माघ बुदी पांचम बुधवार को लिखी गई (संग्रहित की गई) सुन्दर की साखियों की एक पाण्डुलिपि डॉ. सहगल को उपलब्ध हुई। उस पाण्डुलिपि के संग्रहक चेनराम गुजर गौड़ ब्राह्मण है। उन्होंने वाचिक परम्परा से सुन्दर की 328 साखियों का संग्रह किया था। जिसे डॉ. पूरन सहगल ने सतर्कतापूर्वक पुन: सुलेखित कर पुस्तकाकार में प्रकाशित किया। यह पुस्तक 10 फरवरी 2006 को श्री बालकिव बैरागीजी के जन्मिदन पर प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशक स्व. चन्द्रराजजी भण्डारी साहित्य अकादमी, भानपुरा है। इसकी भूमिका उज्जैन के डॉ. शिवकुमारजी चौरसिया और श्री बालकिव बैरागीजी ने लिखी है। (17)

यह पुस्तक मालवी में शृंगार साहित्य का चरम-परम उदाहरण है। दशपुर अंचल की इन काञ्य सिद्ध कवयित्रियों पर शीघ्र ही विक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर शोध की योजना प्रस्तावित है। तब डॉ. पूरन सहगल की वर्षों की तपस्या सार्थक होगी और मालवी की इन श्रेष्ठ सृजन धर्मी ऋषिकाओं की यशपताका पूरे साहित्याकाश में लहराएगी। आलेख को शृंगारित तथा रसमय करते हुए 'तक-तक करे सिकार' पुस्तक में से सुन्दर के ये दोहे प्रस्तुत हैं-

> रम-जम-रम-जम कामणी, आवे ईतर वास। पीलो पेर अटकाएको, आवी प्रीतम पास।। सुन्दर सेजां सांकरी, चुगली खोरा लोग। घुड़ले बागां आवजो, वठे मिलण का जोग।। चुड़लो हाथी दांत को, पाजप झणकदार। सुन्दर रखड़ी बीजरी, नैणा तेज कटार। (18)

सुन्दर के ये श्रृंगार दोहे बिहारी के उन दोहों की तरह छोटे किन्तु तीखे हैं जिनके लिए कहा है-

> 'सतसङ्ग्या के ढोहरे, ज्युँ नाविक के तीर। देखन में छोटे लगें, घाव करे गम्भीर।।

सुन्दर के इन दोहों को दरबारी लोक गायकों से (बारहटों से) लगाकर रनिवास डेहरी के सुरीले कंठों तक ने गाया है।

इस संग्रह के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार श्री बालकवि बैरागी ने कहा है-'डॉ. पूरन ने ऐसा किया है जैसे कोई किसी तीर्थ धाम से तीर्थ यात्रा करके हमारे घर आए और उस तीर्थ का प्रसाद, वहाँ की कंठीमाला, वहाँ का चंदन-गोपी चंदन पूरी श्रद्धा भावना से हमें दे-दे।' (19)

स्वयं डॉ. सहगल ने कहा है-'सुन्दर के इन दोहों का संकलन मेरा शोध नहीं है, शोध का गोखड़ा है, वातायन है, इन मनमीजी अल्हड़, उन्मुक्त और सदा युवा लोक रंजकों को इनके सर्जक का नाम बताकर बेनाम से सुनाम करने का एक सहज प्रयास है।' (20)

सचमुच दशपुर की इस 'जीरन-जेवड़ी' सुन्दर पर और अधिक गणेशणात्मक शोध की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह कार्य और कोई नहीं शोध संलब्ज स्वयं डॉ. पूरन सहगल को ही करना होगा। सुन्दर मालवा के 'सोलह श्रृंगार' की सौभाग्य बिंदी है। दशपुर अंचल ही नहीं समग्र मालवांचल भक्ति एवं श्रृंगार की इस सम्पदा एवं इनकी सृजक वाग्देवियों पर गर्व करता रहेगा।

संदर्भ

- 01. मालवी की उपबोलियाँ और उनका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य- पृ. 48, कॉवेरी शोध संस्थान का सेमिनार ग्रंथ- समन्वयक डॉ. श्याम सुन्दर निगम, प्रकाशक, म.प्र. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति-भोपाल म.प्र. वर्ष 2007 ईस्वी।
- 02,. वही- पृष्ठ 48, अंतिम अनुच्छेद।
- 03-4. लोक की भक्ति, पृ. 45।
- 05. लोक की भक्ति, पृ. 566 पढ़ 139 तथा पृ. 529 पढ़ 88 I
- 06. वहीं पृ. 540, पद 102।
- देखें मधुमती–राजस्थान साहित्य अकादमी, जून 2006।
 जॉ. पूरन सहगल का आलेख 'मालवा की मीरा' पृ. 20–28।
- 08. डॉ. पूरनसहगल के संग्रह में संकलित तथ्यों के आधार पर।
- 09. भाटखेड़ी पाठशाला पर लगे शिलापट के आधार पर।
- 10. डॉ. पूरन सहगल के संग्रह के उपलब्ध गीत।
- नवनिधि कुंवर की प्रकाशित कृति 'आर्त आहें' संवत् 1991।
 प्रकाशक सौ. देवी धर्मपत्नी ठा. शक्तिसिंहजी ठिकाना झालरा मेवाड़, पृ. 2, पद 17।
- 12. मालव लोक संस्कृति अनुष्ठान मनासा का ग्रंथालय।
- 13. मालवा लोक संस्कृति अनुष्ठान मनासा के संग्रह (ग्रंथालय) में उपलब्ध ।
- 14. धरती की हूर-रूपमती री गाथा- डॉ. सहगल के ग्रंथालय में संग्रहित।
- 15.. दम्भ का विष– लेखक डॉ. पूरन सहगल।
- 16. देखे उपरोक्त ग्रंथ- राजस्थानी दोहावली पृष्ठ 80-88।
- 17. तक-तक करे सिकार सुन्दर- डॉ. पूरन सहगल।
- 18. तक-तक करे सिकार सुन्दर- डॉ. पूरन सहगल दोहा 6, 8, 13
- 19. तक-तक करे सिकार सुन्दर- डॉ. पूरन सहगल, पृष्ठ 5, अनुच्छेद २ ।
- 20. तक-तक करे सिकार सुन्दर- डॉ. पूरन सहगल, पृष्ठ ९, अनुच्छेद ४।





नीमच जिले में जनांकिकीय परिवर्तन (१९७१ से २०११ तक)

एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. एल.एन. शर्मा * आशीष शर्मा **

प्रस्तावना :-

जनसंख्या राष्ट्र की सम्पित होती है, देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम होती है तो देश का विकास धीमी गित से होता है तथा प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का आकार सन्तुलित होता है तो देश का विकास तीव्र गित से होता है तथा प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का आकार अधिक होता है तो वह जनसंख्या प्रमुख समस्या बन जाती है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, शोषण, आपराधिक प्रवृत्तियाँ, निम्न जीवन स्तर आदि अनेक समस्याएं भयावह रूप ले लेती है। नीमच जिले में हो रहे जनांकिकीय परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन इस शोध पत्र का उद्देश्य है। सीआरपीएफ की जन्म स्थली नीमच जिला म.प्र. राज्य के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में स्थित है तथा इसके तीनों ओर राजस्थान राज्य की सीमाएँ लगी हुई है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं खदान है तथा अफीम का उत्पादन देश में विशेष स्थान रखता है। जनांकिकीय अध्ययन में जनसंख्या तथा उसको प्रभावित करने वाले तत्वों का समावेश किया जाता है, जिसमें समुदाय का आकार, जन्मदर, विवाह, मृत्युदर, आयु संरचना, लिंग संरचना, प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है।

शोध का उद्देश्य :-

म.प्र. राज्य एवं भारत वर्ष की तुलना में नीमच जिले में हो रहे जनांकिकीय परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन कर उन कारकों की खोज करना है जो इस परिवर्तन के लिये जिम्मेदार है साथ ही जिले की सभी तहसीलों में भी हो रहे जनांकिकीय परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन करना है, कि वे कारक सर्वाधिक किन तहसीलों को प्रभावित कर रहे हैं।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र :-

प्रस्तुत शोध पत्र में सम्पूर्ण द्धितीयक समंकों का प्रयोग किया गया है। जनगणना के प्रकाशित आंकड़े शोध पत्र के अध्ययन का आधार है। वर्ष 1971 से 2011 तक की जनगणना में जनसंख्या का आकार, लिंग संरचना व साक्षरता का ही तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जनांकिकीय परिवर्तनों को मुख्य रूप से चार घटक प्रभावित करते हैं –

- प्रजननता, जिसमें -(अ) जैविकीय तत्व (ब) परोक्ष सामाजिक तत्व (स)प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व, जो सीधे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं।
- 2. मृत्यु क्रम भी जनसंख्या वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
- 3. प्रवास
- अन्य घटक जो अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि या कमी को प्रभावित करते हैं।

शोध पत्र की तालिका क्रमांक 01 के अध्ययन से स्पष्ट है कि 1971 से 1981 के मध्य नीमच जिले की जनसंख्या वृद्धि दर म.प्र. व भारत की तुलना में अधिक है तथा तालिका क्रमांक 02 के अध्ययन से भी स्पष्ट हो रहा है कि जिले की तीनों तहसीलों में भी जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक है विशेषकर नीमच तहसील में 35.58 प्रतिशत है, जिसके निम्न कारण हैं-

अ. जिले में प्रजनन दर ऊंची रही है।(3)

- ब. जिले में जनसंख्या का आव्रजन हुआ है विशेषकर नीमच तहसील में सर्वाधिक है।⁽⁴⁾
- स. जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम में उदासीनता रही है।⁽⁵⁾ परन्तु 1981 से 1991 के दशक में नीमच जिले में जनसंख्या वृद्धि पर म.प्र. व भारत की तुलना में कम रही है तथा जिले की तहसीलों का भी तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर में भारी कमी हुई है जिसके निम्न कारण रहे हैं –
- 1. जिले में प्रजनन दर में कमी आयी है। ⁽³⁾
- 2. जिले में विशेषकर नीमच तहसील में आव्रजन स्थिर रहा है। (4)
- तथा जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम को आशातीत सफलता प्राप्त हई है। ⁽⁵⁾

इसी प्रकार 2011 की जनगणना में भी नीमच जिले की जनसंख्या वृद्धि दर म.प्र. व भारत की तुलना में कम है, हाँलािक जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट जिले के साथ-साथ प्रदेश व देश में भी है, परन्तु जिले में सर्वाधिक गिरावट 7.69 है जो एक नये संकेत की ओर है, जिसका प्रमुख कारण जनता द्धारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्राथमिकता से अपनाना है साथ ही शिक्षा एवं रोजगार के कारण जनसंख्या का प्रवास भी है।

जनांकिकीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण घटक लिंग संरचना है जिसे लिंग अनुपात भी कहा जाता है। लिंग अनुपात किसी क्षेत्र के स्त्रियों की कूल जनसंख्या में पुरुषों की कुल जनसंख्या का भाग देकर 1000 के गुणांक में ज्ञात किया जाता है।⁽⁶⁾ सामान्यतया जन्म के समय लिंगानुपात 105 होता है।⁽⁷⁾ नवजात लड़कों की तुलना में लड़कियों की देखभाल कम होने के कारण चार वर्ष के अन्तराल में यह अनुपात बराबर हो जाता है और 95 वर्ष की आयु में यह अनुपात आधा रह जाता है। सामाजिक रीति रिवाज, परम्पराएँ, मान्यताएँ एवं पुरुष प्रधान व्यवस्था ने भी लिंग अनुपात को सर्वाधिक प्रभावित किया है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, गरीबी, अशिक्षा, पुत्रमोह आदि अनेक कारणों ने भी लिंग अनुपात को प्रभावित किया है। परन्तु शोध पत्र की तालिका क्रं.03 से यह निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि 1971 की जनगणना को छोड़कर शेष सभी जनगणनाओं में नीमच जिले में लिंग अनुपात मप्र व भारत से अधिक है, यह एक सुखद स्थिति है कि विगत 50 वर्षों में जो लिंग अनुपात जिले के साथ-साथ प्रदेश व देश में बढ़ा है, उसमें नीमच जिला अग्रणी रहा है। प्रदेश में बेटी बचाओ आन्दोलन एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं जननी सुरक्षा योजना आदि का प्रभाव प्रदेश व जिले के लिंगानुपात पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है जिले में लिंग अनुपात बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान मनासा तहसील का है। तालिका क्रमांक 04 में जिले की विभिन्न तहसीलों का तुलनात्मक अध्ययन करने यह निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि नीमच तहसील में 1971, 1981, 1991 एवं 2001 के मध्य लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है परन्तु 2011 में जावद व मनासा तहसीलों में लिंग अनुपात तेजी से बड़ा है 2001 की तुलना में 2011 में मनासा तहसील में लिंग अनुपात 18 वृद्धि के साथ 975 हो गया जो सर्वाधिक है, एवं अपने आप में एक रिकार्ड है।



साक्षरता के अध्ययन से किसी देश के लोगों की शिक्षा, संस्कृति एवं वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। शिक्षा से नैतिक विकास, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण, बुद्धि का विकास, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आविष्कार करने, सामाजिक कल्याण करने तथा मातृभूमि की प्राचीन संस्कृति का परिरक्षण होता है। (*) विज्ञान एवं प्राविधिकी पर आश्रित एक विश्व में शिक्षा ही एक ऐसा तत्व है जो लोगों की समृद्धि, कल्याण तथा सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करता है। (*) शोध पत्र की तालिका क्रं. 05 के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पिछले 5 दशक में नीमच जिले में पुरुषों के साक्षरता का प्रतिशत म.प्र. व भारत से अधिक है जबिक महिला शिक्षा में यह जिला प्रदेश व देश से लगातार पीछे रहा है।

स्कूल चले हम, गाँव की बेटी, प्रतिभा किरण, एवं अन्य छात्रवृत्तियों स्कूल जाने हेतू निःशुल्क साईकिल, यूनिफार्म, पुस्तकें आदि के प्रोत्साहनों ने महिला शिक्षा के प्रतिशत में काफी हद तक वृद्धि तो की है परन्तु आज भी इस क्षेत्र में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। गरीबी, रूढ़ीवादिता एवं सामाजिक परम्पराएँ बेटियों को आगे बढ़ने में एवं पढ़ने में बाधक बन रही है। जिले में जहाँ पुरूषों की साक्षरता देश की तुलना में शिखर पर है, वहाँ महिला साक्षरता के प्रतिशत में कमी तथा प्रदेश व देश की तुलना में कम, एक चिन्तनीय पहलू है। तालिका 05 में यह स्पष्ट हो रहा है कि 1991 से 2001 के दशक में पुरूष साक्षरता में सर्वाधिक 13.2 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता में 19.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है परन्तु 2001 से 2011 में यह प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

शोध के निष्कर्ष :-

- नीमच जिला, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रदेश व देश से आगे हैं। जिसमें जिले की जावद तहसील का विशेष योगदान हैं।
- शिक्षा एवं रोजगार के कारण जिले के युवाओं का प्रवास देश के अन्य स्थानों के साथ-साथ विदेशों में भी हो रहा है।
- 3. नीमच जिले का लिंगानुपात विगत चार दशकों में म.प्र. व भारत की तुलना में अधिक है। इसमें जिले की मनासा तहसील का सर्वाधिक योगदान है। बेटी बचाओ अभियान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि का प्रभाव जिले में स्पष्ट दिखाई देता है। विगत तीन दशकों में जिले की तीनों तहसीलों का भी लिंग अनुपात देश व प्रदेश की तूलना में अधिक है जो एक शुभ संकेत है।
- 4. नीमच जिला पुरुष साक्षरता में विगत तीन दशकों से म.प्र. व भारत की तुलना में आगे है परन्तु विगत पाँच दशकों से महिला साक्षरता में जिला प्रदेश व देश से पीछे है जो एक चिन्तनीय पहलू है शोध के निष्कर्ष से यह ज्ञात हुआ है- (अ) जिले में शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में, महिला साक्षरता का प्रतिशत कम है (ब) जिले में कार्यशील जनसंख्या की तुलना में अकार्यशील जनसंख्या की तुलना में अकार्यशील जनसंख्या में महिला साक्षारता का प्रतिशत

कम है। (स) युवाओं की तुलना में प्रौढ़ महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत कम है। (द) आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों की तुलना में गरीब परिवारों में महिला साक्षरता का प्रतिशत कम है।

सुझाव :-

- 1. जनसंख्या नियंत्रण हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, परिवार कल्याण कार्यक्रम को और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है।
- 2. जो गरीब बच्चे धन अभाव के कारण पढ़ाई छोड़कर होटलों में कार्य कर रहे हैं एवं बच्चियां बर्तन, झाडू-पौछा आदि का कार्य कर रही है, उनके लिये विशेष प्रयास की आवश्यकता है एवं युवाओं को उच्च शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु जावद तहसील में, डीकेन व जीरन तहसील में, महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने की अति आवश्यकता है एवं रोजगार मूलक उद्योग लगाने हेतु विशेष प्रयास की भी आवश्यकता है। नीमच तहसील में तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु इन्जिनियरिंग व मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जानी चाहिए।
- जिले के गरीब परिवारों को चिन्हित करके उनके बच्चों को शिक्षा दिलाने हेतु सरकार द्धारा विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- 4. जिले में साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु प्रौढ़ शिक्षा अभियान को सघन करना चाहिए ताकि किसी भी परिवार में प्रौढ़ अनपढ़ न रहे। इसे जन आन्दोलन का रूप देने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची :-

- 01. Spenglar and Duncan: Demographic Analysis 1963 P.-53
- A. Sinha, V.C. & Dwivedi, R.S.: Principal of Demography, 1989, P-21 B.
- 03. * अ.) मन्दसौर जिले में प्रजनन दर आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल के सर्वे के आधार पर * ब.) सेम्पल रजिस्ट्रीकरण बुलेटीन: भारत के महारजिस्ट्रार, गृह मंत्रालय, नई बिल्ली, 1991, पृष्ठ-2, 3, एवं 14 * स.) सेम्पल सर्वे - आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय. भोपाल
- भारत की जनगणना आव्रजन तालिका * 1971 पृष्ठ 43-46
 * 1981 पृष्ठ 127-130 * 1991 पृष्ठ 132-134
- 05. अ.) मन्दसीर जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम : जिला चिकित्सालय, मन्दसीर से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर अब.) ईयर बुक 1987-88 एवं 1990-1991 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अस.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म0प्र0 शासन, भोपाल
- 06. Kumar, V.: Demography, 1993, P.- 41
- 07. पेत्रोव विक्तर : भारत का जनसंख्या मूलक अध्ययन, 1987, P.- 91
- 08. Mukarji, S.N.:Education in India Today's & Tomorrow, 1964, P.-2
- 09. Report of Education commission, 1964-66, P.-2
- 10. भारत की जनगणना 1971, 1981, 1991, 2001, 2011
- 11. मन्दसौर जिला जनांकिकीय अध्ययन 1971 से 1991 पीएच.डी. थीसिस 1995
- 12. www.censusindia.gov.in

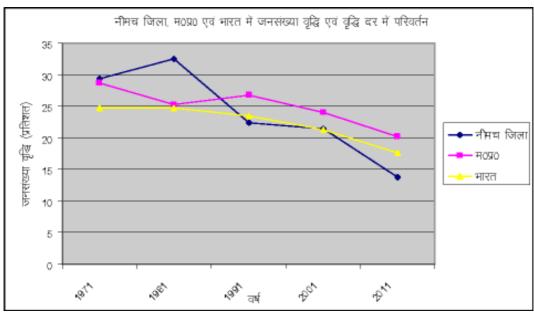
नीमच जिला, म.प्र. एवं भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वृद्धि दर में परिवर्तन तालिका क्रं. 01

वर्ष	कुल जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत)			जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन		
чч	नीमच जिला	म040	भारत	नीमच जिला	म040	भारत
1971	29.41	28.67	24.80			
1981	32.50	25.27	24.75	+3.09	-3.40	-0.05
1991	22.48	26.75	23.56	-10.02	+1.48	-1.19
2001	21.44	24.03	21.34	-1.04	-2.62	-1.78
2011	13.75	20.30	17.64	-7.69	-3.73	-3.70



nss

तालिका क्र. 01 का चार्ट

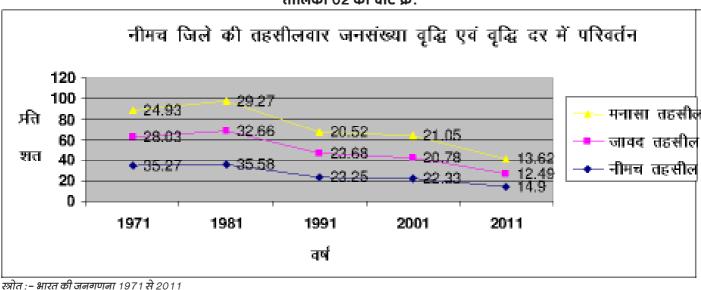


स्त्रोत :- भारत की जनगणना 1971 से 2011

नीमच जिले की तहसीलवार जनसंख्या वृद्धि एवं वृद्धि वर में परिवर्तन तालिका क्रं. 02

	कुल जनसंख्या वृद्धि (प्रतिशत)			जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन			
वर्ष	नीमच	जावद	मनासा	नीमच	जावद	मनासा	
	तहसील	तहसील	तहसील	तहसील	तहसील	तहसील	
1971	35.27	28.03	24.93				
1981	35.58	32.66	29.27	+0.31	+4.63	+4.34	
1991	23.25	23.68	20.52	-12.33	-8.98	-8.75	
2001	22.33	20.78	21.05	-0.92	-2.90	+0.53	
2011	14.90	12.49	13.62	-7.43	-8.29	-7.43	

तालिका ०२ का चार्ट क्र.



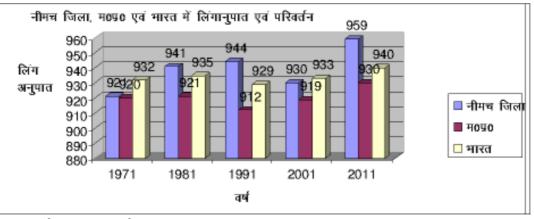




नीमच जिला, म.प्र. एवं भारत में लिंगानुपात एवं लिंगानुपात में परिवर्तन तालिका क्रं. 03

वर्ष	लिंग अनुपात			लिंग अनुपात में परिवर्तन			
44	नीमच जिला	म0प्र0	भारत	नीमच जिला	म0प्र0	भारत	
1971	921	920	932				
1981	941	921	935	+20	00	+03	
1991	944	912	929	+03	-09	-06	
2001	930	919	933	+06	+07	+04	
2011	959	930	940	+09	+11	+07	

चार्ट क्रं. 03

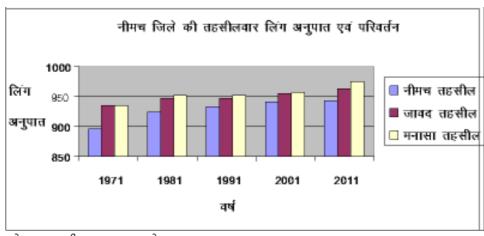


स्त्रोत :- भारत की जनगणना 1971 से 2011

नीमच जिले की तहसीलों में लिंग अनुपात एवं लिंग अनुपात में परिवर्तन तालिका क्रं. 04

	लिंग अनुपात			लिंग अनुपात में परिवर्तन			
वर्ष	नीमच	जावद	मनासा	नीमच	जावद	मनासा	
	तहसील	तहसील	तहसील	तहसील	तहसील	तहसील	
1971	896	935	934				
1981	923	947	952	+27	+12	+18	
1991	933	947	952	+10	00	00	
2001	940	954	957	+07	+07	+05	
2011	942	963	975	+02	+09	+18	

चार्ट क्रं. 04

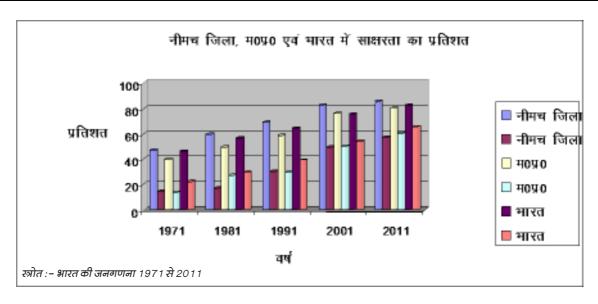


स्त्रोत :**- भा**रत की जनगणना 1971 से 2011



नीमच जिला, म.प्र. एवं भारत में साक्षरता एवं साक्षरता में परिवर्तन चार्ट कं. 05

वर्ष		साक्षरता का प्रतिशत						साक्षरता के प्रतिशत में परिवर्तन					
44	नीमच जिला		म040		भारत		नीमच जिला		4040		भारत		
	цо	편0	ч о	편0	цо	편0	чо	편0	цо	편0	ч0	편0	
1971	47.05	14.30	39.40	13.90	45.96	21.97	_						
1981	59.21	16.40	49.30	26.90	56.38	29.76	12.16	2.10	9.9	13.0	10.42	7.79	
1991	69.30	30.00	58.50	29.40	64.13	39.29	9.91	13.6	9.2	2.5	7.75	9.53	
2001	82.5	49.0	76.10	50.30	75.26	53.67	13.2	19.0	17.6	20.9	11.13	14.38	
2011	85.90	57.30	80.50	60.00	82.14	65.46	3.4	8.3	4.4	9.7	6.88	12.00	



जनहित में जारी

बेटी है तो कल है – बेटी बचाओ जल है तो जीवन है – जल बचाओ ऊर्जा है तो हम है – ऊर्जा बचाओ रक्तदान – जीवनदान नेत्रदान – महादान



Effect of Duration of Marriage on Marital Adjustment

श्रीमती कमलेश उपाध्याय *

Abstract -

अध्ययन का उद्देश्य 5 वर्ष से कम तथा 5 से 10 वर्ष तक के विवाहित दम्पत्तियों के वैवाहिक समायोजन का मापन करना था। इस हेतू 2×2 कारक अभिकल्प का उपयोग किया गया। श्री प्रमोद कुमार एवं क्र.कंचन रोहतगी द्धारा निर्मित 'वैवाहिक समायोजन प्रश्नावली' की सहायता से 5 वर्ष से कम विवाहित 20 दम्पत्तियों एवं 5 से 10 वर्ष की वैवाहिक अवधि वाले 20 दम्पत्तियों को यादच्छिक रीति से प्रयोज्यों के रूप में चयनित कर प्रदत्तों का संकलन किया गया। अध्ययन के परिणाम इस प्रकार रहे- (1) 5 वर्ष से कम की अवधि के विवाहित दम्पतियों में महिला प्रयोज्यों का लैंगिक, सामाजिक तथा भावनात्मक समायोजन अपने पुरुष साथियों से अधिक पाया गया है। (2) 5 से 10 वर्ष की अवधि के मध्य विवाहित दम्पत्तियों में महिला प्रयोज्यों की तुलना में पुरूष प्रयोज्यों के लैंगिक, सामाजिक तथा भावनात्मक समायोजन का स्तर अधिक पाया गया है। (3) सम्पूर्ण परीक्षण पर 5 वर्ष से कम विवाहित महिला प्रयोज्यों का वैवाहिक समायोजन पुरूष प्रयोज्यों की तुलना में अधिक पाया गया। (4) इसी प्रकार 5 से 10 वर्ष की विवाह अवधि के पुरुष प्रयोज्यों में सम्पूर्ण परीक्षण पर वैवाहिक समायोजन उनके तुल्य समूहों (महिला प्रयोज्यों) से अधिक पाया गया। (5) परीक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र के वैवाहिक समायोजन के स्तर में अध्ययन समूहों में सांख्यिकीय दृष्टिकोण से कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

Introduction-

विवाह स्त्री-पुरुष के बीच अत्यधिक महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है। मनोवैज्ञानिकों ने विवाह को छह विभिन्न क्षेत्रों यथा-धर्म, सामाजिक जीवन, पारस्परिक मित्र, सास-ससुर, अर्थ एवं काम में परिभाषित किया है।¹ वास्तव में विवाह जीवन यात्रा का वह चरण है, जिसमें साथी का सही रूप में चयन, जिंदगी में खुशियों की बौछार ला सकता है, वहीं दूसरी ओर गलत चयन तकलीफों की तलवार लटका सकता है। परिपक्व उम्र में हो रही शादियाँ चयन के आधार पर सफल है परंतु समायोजन के अभाव में वैवाहिक जीवन के मोती अनेक अवसरों पर बिखरते नजर आते हैं। भग्न परिवार, विखंडित परिवार, अकेला (माता या पिता) अभिभावक या फिर तलाक ऐसी अनेक समस्याओं की जड़ वैवाहिक समायोजन में कमी ही है।² संतुष्टि और वैवाहिक समायोजन में ऊतर है। वैवाहिक समायोजन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जबिक वैवाहिक संतुष्टि इस समायोजन प्रक्रिया से प्राप्त प्रतिफलों में से एक है। स्पेनियर तथा कूले (1976)³

वैवाहिक समायोजन को परिभाषित करते हुए थॉमस ने लिखा है कि ''वैवाहिक समायोजन वह अवस्था है, जिसमें पित-पत्नी में अपने विवाह तथा एक ढूजे से खुशी एवं संतुष्टि की सम्पूर्ण भावना निहित होती है।'' समान प्रजाति, धर्म अथवा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले जीवन साथी के साथ आमतौर पर बेहतर वैवाहिक समायोजन स्थापित हो पाता है। अरनेस्ट, बुगेस एण्ड लिओनार्ड कोटरेल (1939) वैवाहिक समायोजन

ताउम्र चलने वाली प्रक्रिया है। अधिकांश वैवाहिक संबंधों में लैंगिक क्षमताएं एवं आपस की आनंद वैवाहिक जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण कारक हैं। Methodology

Objective- वैवाहिक समायोजन के स्तर पर विवाह की अवधि (0 से 5 वर्ष तथा 5 से 10 वर्ष) एवं लिंग (महिला तथा पुरूष) के प्रभाव का अध्ययन करना।

Hypothesis- यह परिकल्पना की जाती है कि निम्नांकित समूहों के वैवाहिक समायोजन संबंधी मध्यमान प्राप्तांकों के मध्य सांख्यिकीय हिकोण से कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा-

- 1. महिला तथा पुरुष प्रयोज्यों के मध्य।
- 2. 0 से 5 वर्ष तथा 5 से 10 वर्ष की वैवााहिक अविध वाले प्रयोज्यों के मध्य।

Sampling – वर्तमान अध्ययन का प्रतिदर्श म.प्र. के नीमच जिले से लिया गया है। 5 वर्ष से कम तथा 5 से 10 वर्ष की विवाह अविध वाले 20 – 20 दम्पत्तियों को प्रयोज्यों के रूप में लिया गया। सभी प्रयोज्यों की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक थी।

Used Test- प्रमोद कुमार एवं कु.कंचन रोहतगी द्धारा निर्मित ''वैवाहिक समायोजन प्रश्नावली'' प्रपत्र का उपयोग प्रयोज्यों के वैवाहिक समायोजन के स्तर का मापन करने के लिये किया गया। यह परीक्षण तीन विभिन्न क्षेत्रों –लैंगिक, सामाजिक तथा भावुकता में वैवाहिक समायोजन के स्तर का मापन करना है। परीक्षण में हाँ/नहीं के दो विकल्पों के साथ कुल 25 पद सम्मिलित है। परीक्षण की विश्वसनीयता अर्द्ध-विच्छेद विधि से .70 तथा परीक्षण-पुनर्परीक्षण विधि से .84 पाई गई है। परीक्षण की वैधता .71 से .84 पाई गई है। परीक्षण में शतांशीय मानक दिए गए हैं।

Design -

उपरोक्तानुसार परिकल्पनाओं का परीक्षण करने हेतु 2× 2 कारक अभिकल्प का उपयोग किया गया है। अध्ययन में चर लिंग के दो मूल्य महिला तथा पुरुष एवं विवाह की अविध के दो मूल्य 0 से 5 वर्ष तथा 5 से 10 वर्ष लिए गए हैं।

Discussions & Conclusions-

Table-1

वैवाहिक समायोजन प्रश्नावली के विभिन्न क्षेत्रों के मध्यमानों, मानक विचलनों तथा t मूल्यों को दर्शाती (5 वर्ष से कम अविध वाले विवाहित दम्पत्तियों के संदर्भ में)

A maga	Fen	nale	Male					
Areas	Mean's	SD's	Means	SD's	t			
लैंगिक	2.85	1.53	2.65	1.01	0.66			
सानाजिक	7.80	1.53	7.40	1.51	0.71			
भावनात्नक	9.70	1.99	9.55	2.00	0.08			
सन्यूर्ण परीक्षण	20.30	4.48	19.65	6.83	1.95			



तालिका क्रमांक— 1 जो कि 5 वर्ष से कम वैवाहिक जीवन वाले दम्पत्तियों के वैवाहिक समायोजन संबंधी मध्यमानों, मानक विचलनों एवं t मूल्यों को प्रदर्शित करती है। स्त्री एवं पुरूष प्रयोज्यों के लैंगिक, सामाजिक, भावनात्मक समायोजन एवं कुल प्राप्तांकों संबंधी मध्यमान प्राप्तांकों में कोई सार्थक अंतर सांख्यिकीय दृष्टिकोण से नहीं पाया गया है।

5 वर्ष से कम विवाह अवधि के बम्पत्तियों के वैवाहिक समायोजन को दर्शाता तुलनात्मक दण्ड आरेख

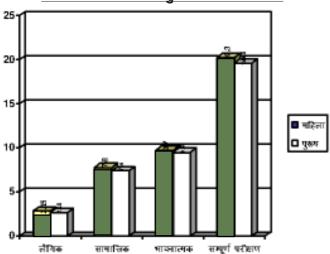
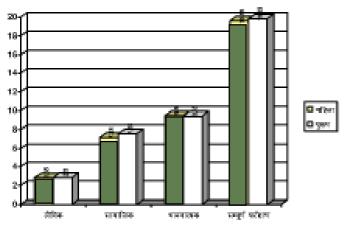


Table-2
वैवाहिक समायोजन प्रश्नावली के विभिन्न क्षेत्रों के मध्यमानों, मानक विचलनों
तथा t मूल्यों को दर्शाती है (5 से 10 वर्ष की अविध वाले विवाहित दम्पत्तियों
के संदर्भ में)

	Fer	male		Male				
	Mean's	SD's	Means	SD's	t			
लैंगिक	2.85	0.79	2.90	0.81	0.19			
सामाजिक	7.15	1.51	7.55	1.56	0.60			
भावनात्मक	9.50	2.86	9.45	1.97	0.50			
सम्पूर्ण परीक्षण	19.55	4.60	19.85	3.34	0.65			

5 से 10 वर्ष की विवाह अविध के बम्पत्तियों के वैवाहिक समायोजन को दर्शाता तुलनात्मक दण्ड आरेख



इसी प्रकार तालिका क्रमांक 2 जो कि 5 से 10 वर्ष की वैवाहिक अविध साथ गुजारने वाले बम्पतियों के वैवाहिक समायोजन के क्षेत्रवार प्राप्तांकों को दर्शाती है। तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वैवाहिक जीवन की अविध के बढ़ने से महिला/पुरूष प्रयोज्यों के समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है।

 Table-3

 वैवाहिक समायोजन प्रश्नावली के क्षेत्रवार F मृल्यों को दर्शाती तालिका

Areas of the Test	N	df	F	Significence
लैंगिक	80	3/76	0.297	NS
सामाजिक	80	3/76	2.38	NS
भावनात्मक	80	3/76	0.170	NS
सम्पूर्ण परीक्षण	80	3/76	0.669	NS

इसी प्रकार तालिका क्रमांक 3 के अध्ययन में सम्मिलित किए गए चारों समूहों के मध्यमानों की सार्थकता के अंतर की सांख्यिकीय विवेचना को प्रदर्शित करती है। लैंगिक समायोजन का F= 0.297 (NS) सामाजिक समायोजन का F= 2.38 (NS)] भावनात्मक समायोजन का F=0.170 (NS) तथा सम्पूर्ण प्रश्नावली पर कुल वैवाहिक समायोजन का F=0.669 (NS) पाया गया है। अत: निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अध्ययन में उल्लेखित उपरोक्त दोनों परिकल्पनाएं सत्य सिद्ध होती है।

Refrences-

- Lazarus R.S.Delingis; A pshychological stress and coping in aging, Americal Psychologist 1983; 38: 245-254
- 2- Patidar Sangeeta, " A Comparative study of Marital Adjustment." A undergraduate Research Project, 2007-08 Page-3
- 3- International Journal of Sociology of the Family, 6(1), 127-128
- 4- Thomas E.J. Marital Communication and Decision Making. New York, Free Press (1977)
- 5- Earnest Burgess and Leonard Cottrell, Success or failure on marital Adjustment (1939)
- 6- Dr. Shikha Goel, Dr.Darshan Kaur Narang, Dr. Kavita Karodiya, Marital Adjustment and Mental Health among Bank employees and Doctors during Middle age (40-45)





Rotationally Inelastic Collisions in N₂ - Ne System

and Validity of Two Parameter Power-Gap Law.

Dr. N.K.Dabkara * Dr. V.K.Ojha**

Abstract - The maximum amount of rotational energy transfer I∆EI* given by the power-gap law has been investigated over a wide range of energies for N_a-Ne system. Further the variation of cross -sections with energy are discussed. Also we compared the predicted and computed cross- sections for the N2-Ne system. We found that they are in a very good agreement. However the variation is about 4 %.

Keywords: Rotational energy transfer, inelastic crosssections, power-gap law.

1. Intorduction

The study of rotationally inelastic collisions in molecular systems has been a subject of considerable interest. In molecular system, the rotational transitions usually accompany vibration and/or electronic transitions .But at low collision energy rotational transitions occurs even without vibration and electronic transitions. Thus the study of rotational inelastic scattering between molecules and neutral atoms at low collision energies is a fast developing field in collision dynamics1-10.

The experimental and theoretical framework on rotationally inelastic collisions can be divided into two concepts, the dynamically and statistically based scaling laws¹¹⁻¹². The infinite order sudden approximation (IOSA)13-14 and the energy corrected sudden approximation (ECSA)¹⁵⁻¹⁶ are the common representatives of dynamically based scaling laws. On the other hand statistically based scaling laws are the powergap(PG) law17, the exponential-gap (EG) law18-19 and the power exponential-gap(PEG) law20 which are typically depend on the rotational energy spacing.

One of the important outcomes regarding the rotational energy transfer (RET) in atom-diatom collisions has been the evolution of the empirical scaling and fitting laws which attempts to fit the entire matrix of integral inelastic crosssections (IICS) and rate constants in terms of a few parameters. Considerable attention has been focused on the power-gap (PG) law21-22.

For the computation of cross-sections for rotational transitions in the molecular collisions by the approximate quantum mechanical methods, it is now possible to study the dependence of cross-sections on different terms and parameters of the intermolecular potential. Thus, it is possible to examine the validity of different scaling and fitting laws over a wide range of potential functions and collision parameters. Such a study of fitting laws is also expected to lead to various interesting features such as the correlation between the parameters of the colliding system and potential with the parameters of the fitting laws. A systemic study of such a correlation may also lead to some fundamentally important information regarding the mechanism of the rotational energy transfer. In view of the above mentioned importance of the mechanism of RET, we have planned our investigations as follows:-

- (i) The integral inelastic cross-sections (IICS) have been computed using the modified infinite order sudden approximation (IOSAM)23-24 for rotational transitions in a simple system like N₂-Ne over a wide range of collision energy.
- (ii) To analyze the cross-sections so obtained by using the well known two parameter power-gap law.
- (iii) The validity of the power-gap law has been examined and the correlation between the parameters of the power gap law and the collision parameters has been studied.

The computational details and the procedure for determination of the classical limit of rotational energy transfer IΔEI* are given in Section 2. The numerical results are presented and discussed in Section 3. Finally the conclusions are summarized in Section 4.

2. Computational Details

2.1. Computation of cross-sections

The integral inelastic cross-sections (IICS) were computed by using Agrawal and Raff's modified version of the infinite order sudden approximation (IOSAM)23-24.

IOSAM cross sections $\sigma_{\mbox{\scriptsize IOSAM}}$ are related to those calculated by the well known infinite order sudden approximation (IOSA) by the following relation:-

$$\mathbf{\sigma}_{\text{IOSAM}} = (\mathbf{k}_{f} / \mathbf{k}_{i}) \mathbf{\sigma}_{\text{IOSA}}, \tag{1}$$

where k, and k, represents the wave vectors corresponding to final and initial translational energies respectively. Such a

^{*} Department of Physics, Govt. Girls College, Neemuch (M.P.)

^{**} Department of Physics, Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)



modification closes those channels which are not allowed by the energy conservation constraints.

2.2. Potential energy surface

For the computation of IICS the homo nuclear diatomic molecule, N_2 , is treated as a rigid rotator and the atom, Ne, is taken as a pair wise sum of the potential terms, i.e,

$$V = V(r_1) + V(r_2) \tag{2}$$

where r_1 and r_2 are the N¹-Ne and N²-Ne distances, respectively, as shown in Fig.1

The following forms of Lennard - Jones (L-J) potentials are taken:

$$V(9-6) = \mathbf{E}[2(r_0/r_1)^9 - 3(r_0/r_1)^6] + \mathbf{E}[2(r_0/r_2)^9 - 3(r_0/r_2)^6],$$

and

$$V(12-6) = \mathbf{\varepsilon} [(r_0/r_1)^{12} - 2 (r_0/r_1)^6] + \mathbf{\varepsilon} [(r_0/r_2)^{12} - 2 (r_0/r_2)^6],$$
(4)

where r_0 and ϵ are taken as 3.232 Å and 5.352 meV respectively.

In addition to the above potential functions, only repulsive terms of the potential functions have also been investigated. Such potentials were denoted by the notation VR(9) and VR(12). Thus the following expressions can be written for the repulsive potentials:

$$V_{R}(9) = 2 \, \mathbf{\varepsilon} \, [\, (r_{0} / r_{1})^{9} + (r_{0} / r_{2})^{9} \,], \tag{5}$$

$$V_{R}(12) = \mathbf{E} \left[(r_{0}/r_{1})^{12} + (r_{0}/r_{2})^{12} \right], \tag{6}$$

2.3. Computation of I∆EI*

The parameter $I\Delta EI^*$ is determined with the help of cross-sections obtained from scattering calculations and the power-gap law.

According to the power-gap law, the cross-sections $\sigma(j_i \rightarrow j_f)$ can be expressed as:

$$\sigma(j_i \to j_f) = a \left(T_f / T_i \right)^{1/2} I \Delta E I^{-r}, \qquad (7)$$

where a and Υ are the fitting parameters, j_i and j_f are the initial and final rotational quantum numbers, T_f and T_i are the final and the initial translational energies and $I\Delta EI$ is the energy gap between initial and final rotational levels.

In the power-gap law the dependence of two parameters a and Υ on I Δ E I was pointed out by different research group²⁷⁻³⁰. They found that two straight lines are required to fit the cross-sections. Schinke³⁰ pointed out that the transitions with I Δ EI \leq I Δ EI* correspond to the classically allowed region and those with I Δ EI > I Δ EI* correspond to the classically forbidden region. Thus it is reasonable to identify I Δ EI* as the maximum limit of rotational energy transfer.

The power-gap law given by Eq. (7) gives the following equation that can be used to separate the two regions:

$$Y = -X + \ln a , (8)$$

where
$$Y = In[\sigma(j_i \rightarrow j_f) (T_i / T_f)^{1/2} / (2j_f + 1)],$$
 (9)

and
$$X = \ln I\Delta EI$$
. (10)

Fig.2 gives a typical X-Y plot for N_2 -Ne system at initial translational energy E=0.1 eV for the potential $V_R(9)$. This plot shows the existence of two straight lines signifying the two regions. The location of the critical point has been marked as $|\Delta E|^*$ in the figure. For all sets of computed cross sections $|\Delta E|^*$ has been obtained by such plots.

3. Results and Discussions

3.1 Variation of cross-sections

Table1 gives the variation of cross-sections with energy and comparison of cross sections so obtained by IOSAM with the cross sections predicted by the power-gap law for the system $\rm N_2$ -Ne using potential V(12-6) are also listed in the table.

We see that with the increase in energy the cross sections are decreased. Also a comparison of predicted and computed cross sections for N $_2$ -Ne system in the energy range 0.15 \leq E \leq 0.5 eV shows that they are in very good agreement .The variation is about 4%.

3.2 Effect of energy

The effect of varying energy on Υ_{low} , Υ_{high} , a_{low} and a_{high} given by the scattering calculations and power gap law for V(9-6) and $V_R(9)$ potentials is shown in Table 2. In all the calculations, the molecule N_2 , has been taken initially in the rotational ground state. We see that the value of $I\Delta EI^*$ is found to increase with the increase in E for all the potentials studied. The dependence of $I\Delta EI^*$ on E is also exhibited by the plots shown in Fig. 3.

It is to look at the variation in the parameters Υ_{low} , Υ^{high} $ln(a_{low})$ and $ln(a_{high})$ with energy as given in Table 2. For a given potential we see that Υ_{low} , and $ln(a_{low})$ are insensitive to the change in the collision energy E. The variation exhibited in the table is within the accuracy of the results. However, the values of Υ_{high} and $ln(a_{high})$ shows a different trend.

The data reported in Table 2 also reveal that all four parameters increases with removal of attractive term in the potential. However, the physical explanation of the four parameters of the power-gap law is a matter of further research.

4. Conclusions-

The two parameter power-gap law has been used to compute the maximum amount of rotational energy transfer $I\Delta EI^*$ from the cross sections computed by scattering calculations for N_2 - Ne system over a wide range of energies. Further the variation of cross sections with energy are also discussed and predicted and computed cross sections are compared for N_2 - Ne system.



The important feature of this study is the understanding of the two regions of rotational energy transfer. For $I\Delta EI \leq I\Delta EI^*$, the cross- sections satisfy the power gap law given by Eq.(7) with constant $a=a_{low}$, $\Upsilon=\Upsilon_{low}$, and for $I\Delta EI>I\Delta EI^*$ the power-gap law holds good with constant $a=a_{high}$, $\Upsilon=\Upsilon_{high}$.

It is also found that the value of $I\Delta EI^*$ increases with the increase in initial translational energy E for V(9-6) and $V_R(9)$ potentials. Further, we found that the predicted and computed cross sections are in very good agreement.

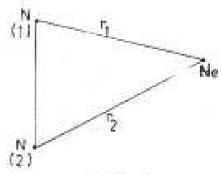
Acknowledgements-

One of the authors N.K.Dabkara gratefully acknowledges Dr. Meena Harit, Principal of the Govt. Girls College, Neemuch for her inspiration and cooperation during the course of this work.

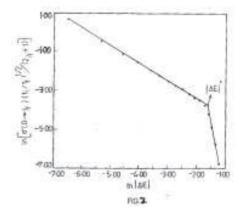
References-

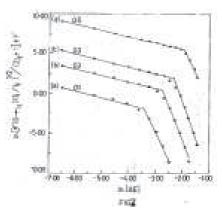
- 1. F.A. Gainturcu , J.P.Toennies and M.Bernardi. J.Chem. Soc. Faraday Tran, **87**,31 (1991).
- 2. X.Yang and A.M.Wodke, J.Chem. Phys., **96**,5123,(1992).
- 3. L.S.Bontuyan, A.G. Suits, P.L. Hutson and B.J. Whittaker, J.Phys. Chem. **97**, 6342,(1993).
- B.Kumar, N.Chandra and G.P.Singh, Phys. Lett. A , 262, 174(1999).
- 5. D.Bruno, M. Cacciatore, S. Lonap and M.Rutigliano, Chem. Phys. Lett., **320**, 245,(2000).
- 6. Keith Burnett, Paul S. Julienne, Paul D. Lett, Eite Tiesinga And Carl J. Williams, Nature, **416**,225,(2002).
- 7. Dieter Gerlich, J.Anal.At. Spectrom, 19, 581,(2004).
- 8. L.Paramonov and S.N. Yaliraki, J.Chem.Phys. **123**, 1941119(2005).
- R.Wambier and R. Schneider, Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 10285, (2011).
- J.Perez-Rios, G.Tejeda, J.M.Fernandez, M.I. Hernandez and S.Montero, J. Chem. Phys. 134, 174307(2011).
- 11. P.M. Agrawal and S. Tilwanker, Acta Phys. Pol. A, **93**, 453, (1998).
- 12. P.Beaud, T. Gerber, P.P.Radi, M.Tules and G.Knopp, Chem. Phys. Lett. **373**,251,(2003).
- 13. R.Goldflam, S. Green and D.J.Kouri, J.Chem. Phys. **67**, 4149,(1977).
- 14. A.E. De Pristo, ,and H.Rabitz, J. Chem. Phys. Lett. **24**, 201(1977).
- 15. A.E. De Pristo, S.D. Augustin, R. Ramaswami \$ H. Rabitz, J.Chem. Phys., **71**, 850(1979).
- 16. M.H. Alexander, J. Chem. Phys. 71, 1683 (1979).
- 17. N.K. Dabkara & P.M. Agrawal, Chem. Phys., Lett., **299**,125(1999)
- 18. D.F. Heller, Chem. Phys. Lett. 45,64(1977).
- J.M. Hartmann, C. Boulet & D. Robert, Cellisional Effects on Molecular Spectra, Elsevier (2008).
- 20. W.F. Wang, J.M. Sirota & D.C. Reuter, J. Mol. Spectro Sc.,

- 198,201(1999).
- 21. J.M. Hutson, Annu. Rev. Chem. Phys. 41,123 (1990).
- 22. Xia Zhang, Chris Eyles, Csiag A. Tatjes, Dajun Ding & Steren Stolte, Chem. Phys., **15**,5620(2013).
- 23. P.M. Agrawal & L.M. Raff., J. Chem. Phys., **74**,3292(1981).
- P.M. Agrawal, S. Tilwankar & N.K. Dabkara, J. Chem. Phys., 108,4854(1998).
- 25. D.E. Gray(Ed.), American Institute of Physics, Handbook, McGraw Hill, New York, 1957,P. 4.**129**.
- 26. R.A. Svehla, NASA Tech. Rep. TR R-132,1962.
- 27. I. Noor Batcha, N. Sathyamurthy, Chem. Phys. Lett., **79**, 264(1981).
- 28. N.K. Dabkara, Acta Phys.Pol. A 100, 41(2001).
- P.M. Agrawal & N.C. Agrawal Chem. Phys. Lett., 117,451(1985).
- 30. R. Schinke, J. Chem. Phys., **75**,5205,(1981).



F1G. 1







Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013

Table-1 Variation of cross sections in (Å)² with energy and composition of predicted ^(a) and computed ^(b) cross sections for the system N_2 -Ne using potential V(12-6). Parameters are r_0 =3.232Å and ϵ =5.351947 meV

	E=0	.15 eV	E=0).3 eV	E=0).5 eV
_	Predicted		Predicted		Predicted	
J	(a)	Computed (b)	(4)	Computed (b)	(4)	Computed (b)
2	6.53	6.63	5.19	5.47	4.58	4.90
4	4.80	4.58	3.80	3.63	3.27	3.17
6	3.95	3.84	3.13	3.03	2.67	2.58
8	3.38	3.48	2.71	2.66	2.29	2.21
10	2.95	3.04	2.40	2.38	2.03	1.98
12	2.58	2.67	2.16	2.19	1.83	1.80
14	2.26	2.41	1.96	1.97	1.66	1.66
16	1.95	1.45	1.78	1.81	1.53	1.56
18	1.64	1.54	1.62	1.67	1.41	1.43
20	1.31	1.27	1.47	1.45	1.30	1.35
22	0.91	0.82	1.32	1.32	1.20	1.24
24	0.07	0.07	1.18	1.18	1.12	1.13
26			0.98	0.94	1.03	1.07
28			0.77	0.76	0.95	0.96
30			0.58	0.62	0.84	0.84
32			0.10	0.09	0.74	0.78
34					0.64	0.69
36					0.55	0.56
38					0.46	0.44
40					0.36	0.37

⁽a) Predicted by the Power - Gap Law.

Table-2 Effect of energy on the slopes and IEI* for the system $\mathrm{N_2}\text{-Ne}$ at different potential energy surfaces

Potential	Energy (eV)	Ylow	Yhigh	In (a _{low})	In (a _{high})	IEI*
	0.10	0.76	1.78	4.446	7.197	0.067
wa ex	0.15	0.78	3.47	4.700	10.493	0.116
V(9-6)	0.20	0.79	2.21	4.845	7.629	0.141
	0.30	0.81	4.08	5.064	9.740	0.243
	0.10	0.90	4.54	4.824	15.881	0.048
	0.15	0.94	6.74	5.176	19.087	0.091
L v /0v	0.20	0.92	5.59	5.125	15.197	0.116
V _R (9)	0.30	0.92	6.90	5.265	15.105	0.193
	0.40	0.93	7.05	5.385	13.327	0.273
	0.50	0.92	4.44	5.411	9.406	0.322

⁽b) Computed by IOSAM



X-ray absorption studies of some copper (II) mononuclear and binuclear complexes

Dr. R.D.Gupta * Dr. S.K.Joshi ** Shashank Dubey ***

Abstract - The X-ray K-absorption spectra of copper (II) mixed mononuclear and binuclear complexes have been studied using a 40 cm bent crystal spectrograph. The complexes included in the present studies are: (I) [(glygly) Cu(H2O)], (II)[(glygly)Cu(ImH)], (III)[(glygly)Cu-Im-Cu(glygly)]Na, (IV)[(glygly)Cu-Im-Zn (glygly)]Na and (V)[(glygly)Cu-Im-Ni(glygly)]Na, where glygly = glycylglycine and ImH = imidazole. X-ray absorption chemical shifts have been determined using the K-edge positions in the spectra of the complexes. Our studies support the tetrahedral geometry for the complexes.

Keywords: X-ray absorption spectra, XANES, Chemical shift. **1. Introduction:**

Mixed ligand complexes play an important role in biological process as exemplified by many instances in which enzymes are known to be activated by metal ions¹. Copper (II) complexes have found possible medical uses in the treatment of many diseases including cancer²

The copper complexes included in the present studies are:

- (l) [(glygly) Cu(H2O)]
- (II) [(glygly) Cu(ImH)]
- (III) [(glygly)Cu-Im-Cu(glygly)] Na
- (IV) [(glygly)Cu-Im-Zn(glygly)]Na
- (V) [(glygly)Cu-Im-Ni(glygly)]Na

All these samples are important from the biological point of view as imidazolate bridged binuclear copper(II) complexes have been used as models for the study of copper-zinc superoxide dismustase. Samples I and II mentioned above are mononuclear complexes viz., aquaglycylglycinato copper (II) and imidazole glycinato copper(II). Samples III, IV and V are binuclear copper(II) complexes and these also serve as model compounds for type-3 copper in cuproproteins³. X-ray K-absorption spectral studies of such complexes are known to provide useful structural information for metals and their complexes⁴⁻⁷.

2. Experimental Details:

A Chirana X-ray tube with a tungsten target having two beryllium windows was used as the source of continuous radiation. The tube was operated at 20 kV and 10 mA. A bent crystal spectrograph of diameter 0.4m was used in this work to record the spectra using (100) reflection planes of mica on Agfa/Konica X-ray films. Tungsten WL $\alpha_{\!_{1}}$ nd $K\beta_{\!_{1,3}}$ emission lines were used as reference lines. The data acquisition system adopted in the present work* consists of interfacing a microdensitometer with personal computer (P.C.) using a stepper motor controller unit. A proper software

programme involving the data port and status port of the LPT (printer port) have been used in the present work.

3. Results & Discussion:

Chemical Shift:

The shift of the X-ray absorption edge ΔE_i (i=K,M,L.....) of an element in a compound/ complex with respect to that of the pure element is written as : ΔE_i = E_i (compound) - $E_{i(metal)}$

Extensive studies have been reported⁹⁻¹¹ on chemical shift of X-ray absorption edges. Two main factors contribute to the observed high energy shifts of X-ray absorption edges, i.e., (i) The tighter binding of the core level because of the change of the effective charge (or screening) of the nucleus caused by the participation of the valence electrons in the chemical bond formation. (ii) Appearance of the energy gap E_g when we go from a metal to a compound or complex. In general, the chemical shift is towards the high energy side of the metal edge¹² increasing progressively with increase of the valence of the cation. Of course the shift may also be suppressed by the covalent character of the bond or enhanced by the formation of metal - metal bonding. In the present work, the K-absorption edges of all the copper complexes are found to be on the high energy side.

Earlier workers¹³-¹⁵ have reported the chemical shift values of various copper (II) complexes between 6.8 - 12.9eV. For the presently studied complexes, the shift values lie in the range 7.6 to 10.4 eV and hence on the basis of this comparison all our complexes under present investigations possess oxidation state 2⁺.A perusal of Table 1 shows that the chemical shift values for the mononuclear complexes are I(10.0eV)≈II (9.9eV). Central metal copper ion is surrounded by three nitrogen and one oxygen in complex II, whereas two oxygen and two nitrogen in case of complex I. The electro negativity values of oxygen and nitrogen are 3.5 and 3 respectively. Contribution of two oxygen - copper bonds in case of complex I slightly increase the effective charge

and hence the chemical shift value in case of complex I For the binary complexes the shift values vary in the sequence IV>III>V. However, the values for III and V samples are less than those for the mononuclear complexes. This may be interpreted as follows:

The contribution of surrounding ligands in a mononuclear complex is for one copper centre only whereas in a binuclear complex the contribution of the bonding ligands towards effective nuclear charge on the copper metal ion is for two copper centers and hence on any one centre it is reduced as compared to the case of mononuclear complex. This is the reason for the lower chemical shift values in case of samples III and V. However for the complex IV i.e. Cu-Zn- hetero metallic binuclear complex the higher value of chemical shift at first sight seems to be surprising. Patel and Pandeya¹⁶ have reported the EPR spectral studies of an imidazolate bridged Cu-Zn complex of glycylglycine. Their studies suggest that the imidazolate bridged complex is stable in the pH range 7-10. At lower pH (<7) the imidazolate bridge breaks on the copper side. At higher pH (>10) the EPR changes suggest either hydroxylation of the copper centre or breaking of the imidazolate bridge on the zinc side. According to Patel and Pandeya¹⁶ only four such complexes have been reported so far, and the imidazolate bridge has been found to behave differently from compound to compound. X-band EPR spectral studies at room temperature of the polycrystalline Cu-Zn complex are suggestive of weak dipole-dipole interaction arising from spin-exchange interaction which is confirmed by the presence of a strong half-field signal. That the nature of this interaction is intermolecular is confirmed by the EPR observations in solutions where the interaction is lost. Further Patel and Pandeya¹⁶ have reported the A₁₁ and g₁₁ parameters vis-a-vis geometry of copper (II) in this complex. Their studies support the distorted tetrahedral geometry for this complex. Further the higher value of chemical shift as obtained from present X-ray absorption studies for the Cu-Zn complex also supports the hydroxylation of the copper centre. This implies that due to hydroxylation the effective charge on the central metal copper ion has increased resulting in the higher value of chemical shift. (See Table No.1)

4. Conclusion:

The X-ray K-absorption spectra of copper in the mononuclear and binuclear complexes with mixed ligands have been studied. These studies establish the oxidation state of 2* for all the complexes. The values of chemical shifts obtained have been explained for the different complexes. Our X-ray absorption studies confirm the tetrahedral geometry for the complexes.

References:

- [1] B.L. 'Valle and J.E. Coleman, Compr. Biochem. **8** (1968) 1458.
- [2] J.R.J. Sorenson, Chem. Br. 16 (1984) 1110.
- [3] H. Sigel, Metal Ions in Biological Systems, (Marcel Dekker, New York) 13 (1981).
- [4] R.K. Vyas, S.K. Joshi, B.D. Shrivastava, M.C. Shah and J. Prasad, Ind. J. of Pure & Appl. Phys. 43(2005) 509.
- [5] R.D. Gupta, S.K. Joshi, B.D. Shrivastava, M.C. Shah and J. Prasad, Natl. Acad. Sci. Lett. 28 (1 & 2) (2005) 39.
- [6] R.J. Iwanowski, K. Lawniczak-Jablonska, Z. Golacki & A. Traverse, Chem. Phys. Lett.,283(1998)313.
- [7] F. d Acapito, S. Mobilio, G. Battaglim, E. Cattarnzza, etal., J Appl. Phys., 87(2000)1819.
- [8] U.A. Palikundwar, V.B. Sapre and S.V. Moharil, Proc. of the NSI **30** (2006) 580.
- [9] S.K. Joshi, B.D. Shrivastava and A.P. Deshpande (Eds) X-ray Spectroscopy and Allied Areas (Narosa Publishing House, New Delhi) 1998.
- [10] C. Bonnelle and C. Mande, (Eds) Advances in X-ray Spectroscopy (Pergamon Press, New York) (1983).
- [11] S.K. Joshi, B.D. Shrivastava, Bhakta Darshan Shrivastava and A. Mishra, X-ray Spectrom. **33** (2004) 466.
- [12] B.K. Agrawal and L.P. Verma, J. Phys. C 3 (1970) 535.
- [13] R.C. Kumavat, S.K. Joshi and B.D. Shrivastava, Jpn. J. Appl. Phys.32 (1993)567.
- [14] P.N. Koul and B.D. Padalia, X-ray Spectrom. **12** (1983) 128.
- [15] A.N. Nigam, O.P. Rajput and B.D. Shrivastava, X-ray Spectrom. **15**(1986)111.
- [16] R.N. Patel and K.B. Pandeya, J. Inorg. Biochem. **72** (1998) 109.

Table 1: Chemical shifts* and other X-ray K-absorption parameters for copper (II) complexes

Complex	Complex	Wave-length	Edge	Chemical
No.		of K-edge λ _K (m Å)	Position E _K	Shift*
			(eV)	$\Delta E_K(\pm 0.3 \text{eV})$
I	[(glygly)Cu(H ₂ O)]	1379.14	8990.0	10.0
П	[(glygly)Cu(ImH)]	1379.16	8989.9	9.9
Ш	[(glygly)Cu-Im-Cu(glygly)]Na	1379.34	8988.7	8.7
IV	[(glygly)Cu-Im-Zn(glygly)]Na	1379.09	8990.4	10.4
V	[(glygly)Cu-Im-Ni(glygly)]Na	1379.51	8987.6	7.6

^{*}With respect to copper metal K_1 Edge (E_E =8980.0 eV)



Importance of Computational Chemistry and Fields of application

Sunil Kumar Sikarwar *

Abstract - Computational chemistry is a branch of chemistry that uses principles of computer science to assist in solving chemical problems. It uses the results of theoretical chemistry, incorporated into efficient computer programs, to calculate the structures and properties of molecules and solids. Its necessity arises from the well-known fact that apart from relatively recent results concerning the hydrogen molecular ion, the quantum n-body problem cannot be solved analytically, much less in closed form. While its results normally complement the information obtained by chemical experiments, it can in some cases predict hitherto unobserved chemical phenomena.

It is widely used in the design of new drugs and materials. Examples of such properties are structure (i.e. the expected positions of the constituent atoms), absolute and relative (interaction) energies, electronic charge distributions, dipoles and higher multipole moments, vibrational frequencies, reactivity or other spectroscopic quantities, and cross sections for collision with other particles.

The methods employed cover both static and dynamic situations. In all cases the computer time and other resources (such as memory and disk space) increase rapidly with the size of the system being studied. That system can be a single molecule, a group of molecules, or a solid. Computational chemistry methods range from highly accurate to very approximate; highly accurate methods are typically feasible only for small systems. Ab initio methods are based entirely on theory from first principles. Other (typically less accurate) methods are called empirical or semi-empirical because they employ experimental results, often from acceptable models of atoms or related molecules, to approximate some elements of the underlying theory.

In some cases, the details of electronic structure are less important than the long-time phase space behavior of molecules. This is the case in conformational studies of proteins and protein-ligand binding thermodynamics. Classical approximations to the potential energy surface are employed, as they are computationally less intensive than electronic calculations, to enable longer simulations of molecular dynamics. Furthermore, cheminformatics uses even more empirical (and computationally cheaper) methods like machine learning based on physicochemical properties. One typical problem in cheminformatics is to predict the binding affinity of drug molecules to a given target.

Key Words: Computational chemistry, methods and applications.

Introduction

Building on the founding discoveries and theories in the history of quantum mechanics, the first theoretical calculations in chemistry were those of Walter Heitler and Fritz London in 1927. The books that were influential in the early development of computational quantum chemistry include Linus Pauling and E. Bright Wilson's 1935 Introduction to Quantum Mechanics - with Applications to Chemistry, Eyring, Walter and Kimball's 1944 Quantum Chemistry, Heitler's 1945 Elementary Wave Mechanics - with Applications to Quantum Chemistry, and later Coulson's 1952 textbook Valence, each of which served as primary references for chemists in the decades to follow.

With the development of efficient computer technology in the 1940s, the solutions of elaborate wave equations for complex atomic systems began to be a realizable objective. In the early 1950s, the first semi-empirical atomic orbital calculations were carried out. Theoretical chemists became extensive users of the early digital computers. A very detailed account of such use in the United Kingdom is given by Smith and Sutcliffe.[1] The first ab initio Hartree-Fock calculations on diatomic molecules were carried out in 1956 at MIT, using a basis set of Slater orbitals.

For diatomic molecules, a systematic study using a minimum basis set and the first calculation with a larger basis set were published by Ransil and Nesbet respectively in 1960.[2] The first polyatomic calculations using Gaussian orbitals were carried out in the late 1950s. The first configuration interaction calculations were carried out in Cambridge on the EDSAC computer in the 1950s using Gaussian orbitals by Boys and coworkers.[3] in 1971, when a bibliography of ab initio calculations was published,[4] the

largest molecules included were naphthalene and azulene.[5][6] Abstracts of many earlier developments in ab initio theory have been published by Schaefer.[7]

In 1964, Hückel method calculations (using a simple linear combination of atomic orbitals (LCAO) method for the determination of electron energies of molecular orbitals of? electrons in conjugated hydrocarbon systems) of molecules ranging in complexity from butadiene and benzene to ovalene, were generated on computers at Berkeley and Oxford.[8] These empirical methods were replaced in the 1960s by semi-empirical methods such as CNDO.[9]

In the early 1970s, efficient ab initio computer programs such as ATMOL, Gaussian, IBMOL, and POLYAYTOM, began to be used to speed up ab initio calculations of molecular orbitals. Of these four programs, only GAUSSIAN, now massively expanded, is still in use, but many other programs are now in use. At the same time, the methods of molecular mechanics, such as MM2, were developed, primarily by Norman Allinger.[10]

One of the first mentions of the term "computational chemistry" can be found in the 1970 book Computers and Their Role in the Physical Sciences by Sidney Fernbach and Abraham Haskell Taub, where they state "It seems, therefore, that 'computational chemistry' can finally be more and more of a reality."[11] During the 1970s, widely different methods began to be seen as part of a new emerging discipline of computational chemistry.[12] The *Journal of Computational Chemistry was first published in 1980*.

Accuracy - The words exact and perfect do not appear here, as very few aspects of chemistry can be computed exactly. However, almost every aspect of chemistry can be described in a qualitative or approximate quantitative computational scheme.

Molecules consist of nuclei and electrons, so the methods of quantum mechanics apply. Computational chemists often attempt to solve the non-relativistic Schrödinger equation, with relativistic corrections added, although some progress has been made in solving the fully relativistic Dirac equation. In principle, it is possible to solve the Schrödinger equation in either its time-dependent or time-independent form, as appropriate for the problem in hand; in practice, this is not possible except for very small systems. Therefore, a great number of approximate methods strive to achieve the best trade-off between accuracy and computational cost.

Accuracy can always be improved with greater computational cost. Significant errors can present themselves in ab initio models comprising many electrons, due to the computational expense of full relativistic-inclusive methods. This complicates the study of molecules interacting with high

atomic mass unit atoms, such as transitional metals and their catalytic properties. Present algorithms in computational chemistry can routinely calculate the properties of molecules that contain up to about 40 electrons with sufficient accuracy. Errors for energies can be less than a few kJ/mol. For geometries, bond lengths can be predicted within a few picometres and bond angles within 0.5 degrees. The treatment of larger molecules that contain a few dozen electrons is computationally tractable by approximate methods such as density functional theory (DFT).

There is some dispute within the field whether or not the latter methods are sufficient to describe complex chemical reactions, such as those in biochemistry. Large molecules can be studied by semi-empirical approximate methods. Even larger molecules are treated by classical mechanics methods that employ what are called molecular mechanics. In QM/ MM methods, small portions of large complexes are treated quantum mechanically (QM), and the remainder is treated approximately (MM).

Methods- A single molecular formula can represent a number of molecular isomers. Each isomer is a local minimum on the energy surface (called the potential energy surface) created from the total energy (i.e., the electronic energy, plus the repulsion energy between the nuclei) as a function of the coordinates of all the nuclei. A stationary point is a geometry such that the derivative of the energy with respect to all displacements of the nuclei is zero. A local (energy) minimum is a stationary point where all such displacements lead to an increase in energy. The local minimum that is lowest is called the global minimum and corresponds to the most stable isomer. If there is one particular coordinate change that leads to a decrease in the total energy in both directions, the stationary point is a transition structure and the coordinate is the reaction coordinate. This process of determining stationary points is called geometry optimization.

The determination of molecular structure by geometry optimization became routine only after efficient methods for calculating the first derivatives of the energy with respect to all atomic coordinates became available. Evaluation of the related second derivatives allows the prediction of vibrational frequencies if harmonic motion is estimated. More importantly, it allows for the characterization of stationary points. The frequencies are related to the eigenvalues of the Hessian matrix, which contains second derivatives. If the eigenvalues are all positive, then the frequencies are all real and the stationary point is a local minimum. If one eigenvalue is negative (i.e., an imaginary frequency), then the stationary point is a transition structure. If more than one eigenvalue is



negative, then the stationary point is a more complex one, and is usually of little interest. When one of these is found, it is necessary to move the search away from it if the experimenter is looking solely for local minima and transition structures.

The total energy is determined by approximate solutions of the time-dependent Schrödinger equation, usually with no relativistic terms included, and by making use of the Born-Oppenheimer approximation, which allows for the separation of electronic and nuclear motions, thereby simplifying the Schrödinger equation. This leads to the evaluation of the total energy as a sum of the electronic energy at fixed nuclei positions and the repulsion energy of the nuclei. A notable exception are certain approaches called direct quantum chemistry, which treat electrons and nuclei on a common footing. Density functional methods and semi-empirical methods are variants on the major theme. For very large systems, the relative total energies can be compared using molecular mechanics. The ways of determining the total energy to predict molecular structures are:

Ab initio methods

The programs used in computational chemistry are based on many different quantum-chemical methods that solve the molecular Schrödinger equation associated with the molecular Hamiltonian. Methods that do not include any empirical or semi-empirical parameters in their equations - being derived directly from theoretical principles, with no inclusion of experimental data - are called ab initio methods. This does not imply that the solution is an exact one; they are all approximate quantum mechanical calculations. It means that a particular approximation is rigorously defined on first principles (quantum theory) and then solved within an error margin that is qualitatively known beforehand. If numerical iterative methods have to be employed, the aim is to iterate until full machine accuracy is obtained (the best that is possible with a finite word length on the computer, and within the mathematical and/or physical approximations made).

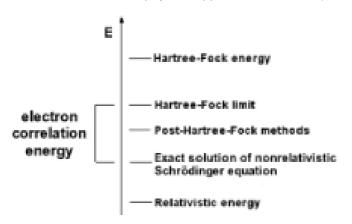


Diagram illustrating various ab initio electronic structure methods in terms of energy. Spacings are not to scale.

The simplest type of ab initio electronic structure calculation is the Hartree-Fock (HF) scheme, an extension of molecular orbital theory, in which the correlated electronelectron repulsion is not specifically taken into account; only its average effect is included in the calculation. As the basis set size is increased, the energy and wave function tend towards a limit called the Hartree-Fock limit. Many types of calculations (known as post-Hartree-Fock methods) begin with a Hartree-Fock calculation and subsequently correct for electron-electron repulsion, referred to also as electronic correlation. As these methods are pushed to the limit, they approach the exact solution of the non-relativistic Schrödinger equation. In order to obtain exact agreement with experiment, it is necessary to include relativistic and spin orbit terms. both of which are only really important for heavy atoms. In all of these approaches, in addition to the choice of method, it is necessary to choose a basis set. This is a set of functions, usually centered on the different atoms in the molecule, which are used to expand the molecular orbitals with the LCAO ansatz. Ab initio methods need to define a level of theory (the method) and a basis set.

The Hartree-Fock wave function is a single configuration or determinant. In some cases, particularly for bond breaking processes, this is quite inadequate, and several configurations need to be used. Here, the coefficients of the configurations and the coefficients of the basis functions are optimized together.

The total molecular energy can be evaluated as a function of the molecular geometry; in other words, the potential energy surface. Such a surface can be used for reaction dynamics. The stationary points of the surface lead to predictions of different isomers and the transition structures for conversion between isomers, but these can be determined without a full knowledge of the complete surface.

A particularly important objective, called computational thermochemistry, is to calculate thermochemical quantities such as the enthalpy of formation to chemical accuracy. Chemical accuracy is the accuracy required to make realistic chemical predictions and is generally considered to be 1 kcal/mol or 4 kJ/mol. To reach that accuracy in an economic way it is necessary to use a series of post-Hartree-Fock methods and combine the results. These methods are called quantum chemistry composite methods.

Density functional methods

Density functional theory (DFT) methods are often considered to be ab initio methods for determining the

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013



molecular electronic structure, even though many of the most common functionals use parameters derived from empirical data, or from more complex calculations. In DFT, the total energy is expressed in terms of the total one-electron density rather than the wave function. In this type of calculation, there is an approximate Hamiltonian and an approximate expression for the total electron density. DFT methods can be very accurate for little computational cost. Some methods combine the density functional exchange functional with the Hartree-Fock exchange term and are known as hybrid functional methods.

Semi-empirical and empirical methods

Semi-empirical quantum chemistry methods are based on the Hartree-Fock formalism, but make many approximations and obtain some parameters from empirical data. They are very important in computational chemistry for treating large molecules where the full Hartree-Fock method without the approximations is too expensive. The use of empirical parameters appears to allow some inclusion of correlation effects into the methods. Semi-empirical methods follow what are often called empirical methods, where the two-electron part of the Hamiltonian is not explicitly included. For ?-electron systems, this was the Hückel method proposed by Erich Hückel, and for all valence electron systems, the extended Hückel method proposed by Roald Hoffmann.

Molecular mechanics

In many cases, large molecular systems can be modeled successfully while avoiding quantum mechanical calculations entirely. Molecular mechanics simulations, for example, use a single classical expression for the energy of a compound, for instance the harmonic oscillator. All constants appearing in the equations must be obtained beforehand from experimental data or ab initio calculations. The database of compounds used for parameterization, i.e., the resulting set of parameters and functions is called the force field, is crucial to the success of molecular mechanics calculations. A force field parameterized against a specific class of molecules, for instance proteins, would be expected to only have any relevance when describing other molecules of the same class. These methods can be applied to proteins and other large biological molecules, and allow studies of the approach and interaction (docking) of potential drug molecules (e.g. [1] and

Methods for solids

Computational chemical methods can be applied to solid state physics problems. The electronic structure of a crystal is in general described by a band structure, which defines the energies of electron orbitals for each point in the Brillouin zone. Ab initio and semi-empirical calculations yield orbital energies; therefore, they can be applied to band structure calculations. Since it is time-consuming to calculate the energy for a molecule, it is even more time-consuming to calculate them for the entire list of points in the Brillouin zone.

Chemical dynamics

Once the electronic and nuclear variables are separated (within the Born-Oppenheimer representation), in the timedependent approach, the wave packet corresponding to the nuclear degrees of freedom is propagated via the time evolution operator (physics) associated to the time-dependent Schrödinger equation In the complementary energydependent approach, the time-independent Schrödinger equation is solved using the scattering theory formalism. The potential representing the interatomic interaction is given by the potential energy surfaces. In general, the potential energy surfaces are coupled via the vibronic coupling terms.

The most popular methods for propagating the wave packet associated to the molecular geometry are:

- the split operator technique,
- the Chebyshev (real) polynomial,
- the multi-configuration time-dependent Hartree method (MCTDH).
- the semiclassical method.

Molecular dynamics

Molecular dynamics (MD) use either quantum mechanics, Newton's laws of motion or a mixed model to examine the time-dependent behavior of systems, including vibrations or Brownian motion and reactions. MD combined with density functional theory leads to hybrid models.

Interpreting molecular wave functions

The Atoms in molecules or QTAIM model of Richard Bader was developed in order to effectively link the quantum mechanical picture of a molecule, as an electronic wavefunction, to chemically useful concepts such as atoms in molecules, functional groups, bonding, the theory of Lewis pairs and the valence bond model. Bader has demonstrated that these empirically useful chemistry concepts can be related to the topology of the observable charge density distribution, whether measured or calculated from a quantum mechanical wavefunction. QTAIM analysis of molecular wavefunctions is implemented, for example, in the AIMAII software package.

Fields of application

The term theoretical chemistry may be defined as a mathematical description of chemistry, whereas computational chemistry is usually used when a mathematical method is sufficiently well developed that it can be automated





for implementation on a computer. In theoretical chemistry, chemists, physicists and mathematicians develop algorithms and computer programs to predict atomic and molecular properties and reaction paths for chemical reactions. Computational chemists, in contrast, may simply apply existing computer programs and methodologies to specific chemical questions.

There are two different aspects of computational chemistry:

- Computational studies can be carried out to find a starting point for a laboratory synthesis, or to assist in understanding experimental data, such as the position and source of spectroscopic peaks.
- Computational studies can be used to predict the possibility of so far entirely unknown molecules or to explore reaction mechanisms that are not readily studied by experimental means.

Thus, computational chemistry can assist the experimental chemist or it can challenge the experimental chemist to find entirely new chemical objects.

Several major areas may be distinguished within computational chemistry:

- The prediction of the molecular structure of molecules by the use of the simulation of forces, or more accurate quantum chemical methods, to find stationary points on the energy surface as the position of the nuclei is varied.
- Storing and searching for data on chemical entities (see chemical databases).
- Identifying correlations between chemical structures and properties (see QSPR and QSAR).
- Computational approaches to help in the efficient synthesis of compounds.
- Computational approaches to design molecules that interact in specific ways with other molecules (e.g. drug design and catalysis).

Software packages

There are many self-sufficient software packages used by computational chemists. Some include many methods covering a wide range, while others concentrating on a very specific range or even a single method. Details of most of them can be found in:

- Biomolecular modelling programs: proteins, nucleic acid.
- Molecular mechanics programs.
- Quantum chemistry and solid state physics software supporting several methods.
- Molecular design software
- Semi-empirical programs.
- Valence bond programs.
- Bioinformatics
- Computational Chemistry List

- Efficient code generation by computer algebra
- Force field implementation
- Important publications in computational chemistry
- International Academy of Quantum Molecular Science
- Mathematical chemistry
- Molecular graphics
- Molecular modelling
- Molecular modelling on GPU
- Monte Carlo molecular modeling
- Protein dynamics
- Computational Science
- Statistical mechanics

References:

- Smith, S. J.; Sutcliffe B. T., (1997). "The development of Computational Chemistry in the United Kingdom". Reviews in Computational Chemistry 70: 271-316.
- Schaefer, Henry F. III (1972). The electronic structure of atoms and molecules. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co. p. 146.
- Boys, S. F.; Cook G. B., Reeves C. M., Shavitt, I. (1956).
 "Automatic fundamental calculations of molecular structure". Nature 178(2): 1207. Bibcode: 1956
 Natur.178.1207B. doi: 10.1038/1781207a0.
- Richards, W. G.; Walker T. E. H and Hinkley R. K. (1971).
 A bibliography of ab initio molecular wave functions.
 Oxford: Clarendon Press.
- 5. Preuss, H. (1968). International Journal of Quantum Chemistry 2: 651. Bibcode:1968IJQC....2..651P. doi:10.1002/qua.560020506.
- Buenker, R. J.; Peyerimhoff S. D. (1969). "Ab initio SCF calculations for azulene and naphthalene". Chemical Physics Letters 3: 37. Bibcode:1969CPL.....3...37B. doi:10.1016/0009-2614 (69) 80014-X.
- 7. Schaefer, Henry F. III (1984). Quantum Chemistry. Oxford: Clarendon Press.
- 8. Streitwieser, A.; Brauman J. I. and Coulson C. A. (1965). Supplementary Tables of Molecular Orbital Calculations. Oxford: Pergamon Press.
- 9. Pople, John A.; David L. Beveridge (1970). Approximate Molecular Orbital Theory. New York: McGraw Hill.
- Allinger, Norman (1977). "Conformational analysis. 130. MM2. A hydrocarbon force field utilizing V1 and V2 torsional terms". Journal of the American Chemical Society 99 (25): 8127-8134. doi:10.1021/ja00467a001.
- Fernbach, Sidney; Taub, Abraham Haskell (1970).
 Computers and Their Role in the Physical Sciences.
 Routledge. ISBN 0-677-14030-4.
- 12. "vol 1, preface". Reviews in Computational Chemistry. doi:10.1002/9780470125786.





Socio-Economic Status of Fishermen in Western Nimar (M.P.)

Dr. Sunita Bakawale * Dr. R. Kanhere **

Abstract - The present study was conducted to assess the socioeconomic status of fishermen Sep.2005 to Aug. 2006. The results reveal that the data of fishermen population and total population of villagers in the Districts of Barwani ranges from 1-55kms as in the Case of population distribution the total fisher folk 415 and the number of fisher folk households highest in Piplud 64 and lowest in Eklara 15. The total Population of villagers 15239. The literacy rate among the fishermen in the village was poor. Untill now fishermen were doing fishing by traditional methods i.e. riverine fishing but now the flowing river water is changed to a reservoir of stagnant water. The fishermen generally belong to a very low stratum of society, and fishing is invariable regarded as one of the meanest of all trades of professions. Fishermen normally lack any formal fisheries education. They need to be trained through vocational courses in scientific innovations and techniques for better utilization and conservation of aquatic resources & also to create awareness of the fisheries potential in terms of resource conservation and utilization, farming system, processing and product development.

Key Words : Fishermen, Livelihood status, Education, Annual Income

Introduction:

Madhya Pradesh state of India, as its name implies-madhya means "central" and pradesh means "region" or "state"- is situated in the heart of India. Madhya Pradesh is the 2nd biggest and totally a land-locked state of India, surrounded by five other states, it possesses one of the oldest mountain ranges-The Vindhyas (1400 million Years old) & the Satpuras (1000 million years old) older than the Himalayas. The Vindhyas extend from Gujarat in the West up to Amarkantak in the East covering, a very large area in Madhya Pradesh. The Satpuras is situated just southwards and extends parallel to Vindhyas.

Narmada River has been a vital source of livelihood for people residing along its bank. Besides it has been a shelter for a large number of aquatic organisms. Narmada is unique, as it is the only river, which flows through West.

A fishermen household is defined as a unit of residence where primary source of income is fishing and allied activities and living under the same roof. However, when the term fisher folk are used, it refers to everybody living in the fishermen households irrespective of their occupation.

Sharma (1984) in his paper on the Tilisha fishery discussed the importance of the fishery of this fish and its relationship with the a major rational for fishery socio- economic analysis is realization the development of economic policies in fisheries requires understandings of suppositional problems faced by the fishermen. Suppositional problems are those related to the social and economic structure of communities in which

fishermen work, the nature of resource base and the likely effect of development projects and programmes (Sherry Joseph 2003).

Ninety percent of the traditional fisher folk live below poverty line. Most of them have huge debts and live in huts and do not own property (Kocherry 1993).

Aryaetal. (2001) has reported fish catch in the river Narmada using the cast net and the gill net and its socio-economic effect on the local fishermen community. Experimental netting was performed in the selected stretch at selected sampling stations. The netting was done using gill nets of mesh size ranging from 10 mm to 50 mm and cast nets.

Fishermen are the back bone of the fisheries industry. The economic problems of fishermen, their methods of production, purchase of domestic and production requisites provision of credit and the sale of their produce must be visualised. Fishermen are largely illiterate and are very poor community. They have always been exploited by middlemen through whom their catch is sold. They are forced to sell their catch to the middlemen to whom they owe the money, Fishermen get very poor return of their catch and therefore, they are invariably under debt. Forced by the circumstances of their trade, they are economically poor, socially backward. Considering the above fact, the present study was carried out to assess the livelihood status and constraint faced by the fishermen of western nimar (M.P.).

Materials & Methods:

For the present study 14th stations were selected at the bank of river Narmada, Satmatra, Eklera, Kasrawad, Bagud,



Piplud, Bhilkheda, Pendra, Nangaon, Phichodi, Kathora, Sondul, Jangarwa, Chikhalda & Koteshwar in the stretch of 15 Km. The period of investigation were one year from Sept. 2005 to Aug. 2006.

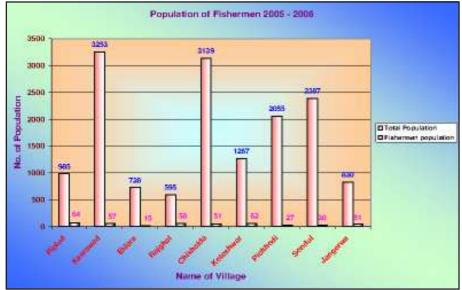
In the present study the survey of fisherman was conducted on the basis of questionaire and the data was analyzed to find out the level of education and economic status of the fishermen, it was compared with the data of other areas.

Keeping the objectives of the study in view, data were collected employing different tools like direct observations, structured interviews, and group discussions.

The occupational characteristic feature classified into fishing, fishing related and other activities was made. Analysis was also carried out to determine the differences in the fishing income and returns etc.

Results & Discussion:

In the present study the data of fishermen population and total population of villagers was studied within the stretch of the river Narmada in a total length of 15 km. As in the case of population distribution the total fisher folk 415 and the number of fisher folk households highest in Piplud 64 and lowest in Eklara 15. The total Population of villagers 15239. The total number of Fishermen surveyed is given in (Chart-1)



Formal education through schools is also a part of the fishermen. Primary School & Aganwadi education is very old phenomena for the village. 39% of the population 5 year are enrolled in the primary school with regard to the education infrastructure accessible to the villagers, there are 7 primary schools (Table-1).

In the year of 2005-2006 an attempt was made to study the pattern of income distribution among the fishermen households by ascertaining their household incomes. About 97% of the fishermen had annual income of Rs. 12,444 or less. Taking the poverty line at an annual income of 15,000 per annum set for six plans at 1978-79 prices, we find that almost all the fishermen in the village were below the poverty line **(Table-2).**

In Comparison to the above the CIFRI Unit, Hoshangabad during their survey (1958-66) covered 945 kms. Of the river; 800 kms. in M.P. and 145 Kms. in Gujarat. Nearly 712 villages were covered in their survey in both the states. Out of 69, 152 fishermen reside in 349 Villages (285 in M.P. and 64 in Gujarat fishing villages) only 3082 fishermen (2600 in M.P. and 482 in Gujarat) were reported to be actively engaged in fishing throughout the year.

According CIFRI the population of active fishermen is 3.2 fishermen / Km. in 1958-66 whereas according to the Fisheries Department report it is 6.1/km. in 1967-71 periods.

According to the IIMA (1983) the fisherman in general, belong to the weaker section of the society. They are socially, economically and educationally backward. In view of the fishing intensity and population per kilometer, where in they hardly get 2 to 3 kg. fish per day per head, their income is fairly low and they live much below the poverty line. The community as a whole is still under the clutches of money-

lenders and fishing contractors. The Indian Institute of Management, Ahmedabad during their survey (1983 Vol. I) has observed that the average income of fishermen from fish business was found to be Rs. 1008 /- and over all income is Rs. 1302/- per year. Both of them were found to be lowest in the country.

Sarangi et al. (1987) reported net profit to the sum of Rs. 64,461 by fish farmers of village Nussasan (Puri district in Orissa).

Murthy et al. (1987) reported that majority of fisherman of Mandya district (Karnataka) fall in the annual income group of Rs. 2,000 to 5,000.

Agarwal (1990) and Piska (2000) stated

that the fish production increased with increase of number of fishermen engaged in fishing. They conclude that the fish production from the natural water bodies could be increased by proper utilization of manpower and material for fishing.

It is apparent from the above discussion that the fishermen generally belong to a very low stratum of society and fishing is invariable regarded as one of the meanest of all trades of professions. Fishermen normally lack any formal fisheries education. They need to be trained through vocational courses

in scientific innovations and techniques for better utilization and conservation of aquatic resources. They should be motivated to know how to supervise and manage them so that they remain as a healthy self - generating replensihable resource of their livelihood.

There is a crying need for improvement in the Fresh water fishing craft and tackle. Much improvement has not been done due to (a) the conservation of the old fashioned ideas (b) the inland waters are mostly located in remote regions where the influence of civilization and education is waters are mostly located in remote regions where the influence of civilization and education is generally lacking.

(Table-1)

	Edu	ed			
Age Group					Total
rage Gristage	Illiterate	Primary	Middle	High	
	Juniteriate:	School	School	School	
Below Syear	22				22
5	10	39	-	-	49
6 to 13	28	59	10		97
14-20	35	40	9	2	86
21-30	17	22	9	5	53
3145	31	4			35
46-55	46				46
56+	27	-	-	-	27
		Total		•	415

References

- * Agarwal S. C. 1990. Fishery Management. Ashish Publishing House, New Delhi.
- Ary S. C., K. S. Rao & S. Shrivastava 2001. Biodiversity & Fishery Potential of Narmada basin western zone (M.P.) India with special References to fish conservation in environment & Agriculture108-112 pp.
- * CIFRI 158-66. Present Hydro biological and Fishery status of Narmada Valley. Directorate of Fisheries Madhya Pradesh, Research Report Project Reports (1967-71)
- * IIMA Report 1983. Economic status of fishermen, IIMA Report, Vol. I, 29 pp.
- * Murthy H. S., M. C. Nandeesha 1987. Hydrobiologia 36(1):320pp.
- * Piska R.S. 2000. Impact of stocking densities of major can seed on fish production in a minor reservoir, Fishing Chimes, 20 (9):39-41.
- * Sarangi N., S. K. Sarkar, B. K. Sharma & N. K. Thakur 1987. Tans. Amer. Microsc. 83(2): 324.
- * Sharma I. A. S. 1984. Hilsa fishery reach of perish National workshop on fish seed production fishery Deptt. Govt. of West Bengal Calcutta 4 pp.
- * Sherry J. 2003 Fishermen: Their social & economic development. Pub. By Praveen Jain for Saloni Publishing House New Delhi. 1- 150 pp.

(Table-2)

NO.	Name of Village	Populat ion	Fishermen Population		No. of Boa t	No of Net	Production per day		Annual Producti on in Kg.	Annual income of fisherme n	Annual income of per fisherme n	
			Men	Women	Children			Weig ht wise in Kg.	Cost wise 40- 50Rate			
1	Piplud	985	15	13	36	9	16	20	800	7200	288000	19200 Rs
2	Kasrawad	3253	11	9	37	9	11	10	400	3600	144000	13090 Rs
3	Eklara	728	3	4	8	0	2	2	80	720	28800	9660 Rs
4	Rajghat	595	11	12	35	9	9	3	120	1080	43200	3927Rs
5	Chikhalda	3139	10	9	32	10	12	12	480	4320	172800	17280Rs
6	Koteshwar	1267	12	13	37	5	6	8	320	2880	115200	9600 Rs
7	Pichhodi	2055	5	4	18	8	8	4	160	1440	57600	11520 Rs
8	Sondul	2387	5	7	18	1	3	4	160	1440	57600	11520 Rs
9	Jangerwa	830	9	9	33	9	8	7	280	2520	100800	11200Rs





A Comparative Study Of Organizational Learning Among Public, Deemed And Private Universities Of Rajasthan

Dr. A.k. Chaudhary * N. Jain **

ABSTRACT- The purpose of the present research work is to compare the level of organizational learning among public, private and deemed universities. Respondents were directly contacted for filling up the standard questionnaire of Organizational Learning Diagnostics, developed by Dr. Udai Pareek. Three phases and 5 mechanisms were measured through OLD Tool. The statistical techniques used for the study were F-test and T-test. Results conclude that there is significant difference among organizational learning of Private, Public and Deemed universities. The significance of the study is based on the challenges facing higher education and to improve their academic standard through organizational learning by the Public, Private and Deemed universities.

Key words: Organizational learning, Private University, Public University, Deemed University **Introduction**

Organizational learning is the process by which an organization gains new knowledge about its environment, goals, and processes. Herbert Simon (1997) posits three ways in which organizations learn: (1) individuals within the organization learn some new fact or procedure, (2) the organization ingests outsiders with knowledge not already in the organization, and (3) the organization incorporates new knowledge into its files and computer systems. As broader organizations, publics and policy-making communities also learn. (Smith) The word "university" is derived from the Latin universitas magistrorum et scholarium, which roughly means "community of teachers and scholars." The University Grants Commission (UGC) of India is a statutory organisation set up by Union public in 1956, for the coordination, determination and maintenance of standards of university education. The status of Deemed University is granted only after fulfilling certain criteria laid down by the UGC. The Deemed University status allows the institutions to develop their own syllabus and course work. They also get the autonomy to set their own guidelines regarding admission and fees. Private Universities established by Entrepreneur with self-finance. The Public Universities established by public.

Review of Literature Georgia L. Bauman (2005) "Promoting Organizational Learning in Higher Education to Achieve Equity in Educational Outcomes" disagreeing with Garvin's view (1993) that higher education institutions do not engage in learning, I agree with his observation that colleges and universities do not learn as effectively as they could. Institutional actors are capable of applying their practices as communities of researchers to studies of the institution itself. Therefore, faculty who conduct research in economics,

sociology, business, the study of organizations, and many other fields can use their research methods for the assessment and improvement of their own institutions. Teams composed of such researchers ought to examine data that are relevant to the charge just as they would examine data for a funded research project. The study and improvement of our own institutions should be as rigorous as our study of other types of institutions and social structures. In this study, the high learning groups experienced the highest levels of group learning about inequities in educational outcomes among students of different ethnic groups because of their attention to and thorough experimentation of data. Albert (2005) found that top management support and involvement of consultant's also facilitated organizational learning and change.

Objective of the Study: The significance of the study is based on the challenges facing higher education and to improve their academic standard through organizational learning by the public, private and deemed universities.

- 1) To study the organizational learning in the Public, Deemed and Private Universities,
- To study the various dimensions like Innovation, Implementation, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and Competency Building among employees
- 3) To compare the various dimensions among Public, Deemed and Private Universities.

Participant: The sample consisted of a total number of 90 academic and non academic staff 30 employees from Public universities namely Mohan Lal Sukhadia University, University of Rajasthan, 30 employees from Private universities namely Pacific University, Mewar university, and 30 employees from Deemed universities namely Rajasthan Vidyapeeth, Bansthathali Vidhyapeeth.

^{*} Senior Lecturer, Department of Psychology, Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.)

^{**} Research Scholar, Faculty of Management, Pacific University, Udaipur (Raj.)



Methodology: First of all the head of the institutions were contacted and after taking permission for data collection respondents were contacted at their comfort zone of time. Then the OLD questionnaires were distributed and collected after 45 minutes. Thereafter scoring was done manually and interpretation was done. For final result we use Analysis of variance at significance of level and applied F-test and T-test for the comparison of groups in the context of various phases and mechanism.

Tool: OLD (Organizational Learning Diagnostics) by Udai Pareek was used. The scale consists of 3 phases like Innovation, Implementation and Stabilization & 5 Mechanics like Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary Systems, and Competency Building. It has reliability 0.98 and validity is not available.

Tools Used for Data Collection

Questionnaire method was used to collect data from the respondents. The questionnaire was developed to measure organizational learning practices followed in different Universities. An OLD index was computed by adding the score of all the twenty three statement. Each Statement is rated with a five point scale i.e. very highly valued (4), highly valued (3), valued (2), low value (1) and no value (0)

Research Design

Data were collected from 90 employees drawn from Public, Private and Deemed Universities. For testing the differences on present organizational learning practices among Public, Private and Deemed Universities, the distribution of sample is as follows: Public Universities = 30; Private Universities = 30; Deemed Universities = 30

ANALYSIS AND DATA INTERPRETATION

H1: There will be no significant difference among Public, Deemed and Private Universities regarding dimensions of organizational learning (Innovation, Implementation, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and Competency Building)

Table - 1 : Comparison of Public , Deemed and Private University regarding organizational learning Diagnostics (See Table No. 1)

The F-ratio for Innovation dimension of Organizational Learning was 47.627 which is significant at 0.01 level on Innovation dimension of Organizational Learning. It infers that there is significant difference among Public, Private and Deemed universities on Innovation dimension of Organizational Learning. The F-ratio for Implementation dimension of Organizational Learning was 29.970 which is significant at 0.01 level on Implementation dimension of Organizational Learning. It infers that there is significant difference among Public, Private and Deemed Universities on Implementation dimension of Organizational Learning. The F-ratio for Stabilization dimension of Organizational Learning was 55.708

which is significant at 0.01 level on Stabilization dimension of Organizational Learning. It infers that there is significant difference among Public, Private and Deemed Universities on Stabilization dimension of Organizational Learning. The F-ratio for Experimentation dimension of Organizational Learning was 51.289 which is significant at 0.01 level on Experimentation dimension of Organizational Learning. It infers that there is significant difference among Public, Private and Deemed Universities on Experimentation dimension of Organizational Learning. The F-ratio for Mutuality dimension of Organizational Learning was 47.550 which is significant at 0.01 level on Mutuality dimension of Organizational Learning. It infers that there is significant difference among Public, Private and Deemed Universities on Mutuality dimension of Organizational Learning. The F-ratio for Planning dimension of Organizational Learning was 47.627 which is significant at 0.01 level on Planning dimension of Organizational Learning. It infers that there is significant difference among Public, Private and Deemed Universities on Planning dimension of Organizational Learning. The F-ratio for Temporary Systems dimension of Organizational Learning was 32.712 which is significant at 0.01 level on Temporary Systems dimension of Organizational Learning. It infers that there is significant difference among Public, Private and Deemed Universities on Temporary Systems dimension of Organizational Learning. The F-ratio for Competency Building dimension of Organizational Learning was 40.336 which is significant at 0.01 level on Competency building dimension of Organizational Learning. It infers that there is significant difference among Public, Private and Deemed Universities on Competency Building dimension of Organizational Learning.

H2: There will be no significant difference in the mean score between Public, and Deemed Universities regarding Organizational Learning like Innovation, Implementation, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and Competency Building among employees

Table - 2: Comparison of dimensions of Organizational Learning Diagnostics between Public and Deemed University (See Table No. 2)

The mean score for Public Universities on Innovation dimension of Organizational Learning was found to be 71.7740 and the mean score for Deemed Universities on Innovation dimension of Organizational Learning was found to be 62.5040. The mean difference was 9.27 and, the 'T' value was 2.945 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Innovation dimension of Organizational Learning of Public and Deemed University. The mean scores represents that Public University have more new method, idea, product, and technological innovations in comparison to Deemed University. The mean score for Public Universities on Implementation dimension of Organizational



Learning was found to be 70.5957 and the mean score for Deemed Universities on Implementation dimension of Organizational Learning was found to be 62.1433. The mean difference was 8.45233 and the 'T' value was 2.211 which is significant at 0.05 level. It infers that there is significant difference in Implementation dimension of Organizational Learning of Public and Deemed University. The mean scores represents that Public University have more tendency to promptly execute organizational learning program in comparison to Deemed University. The mean score for Public Universities on Stabilization dimension of Organizational Learning was found to be 70.5237 and the mean score for Deemed Universities on Stabilization dimension of Organizational Learning was found to be 60.7320. The mean difference was 9.79167 and the 'T' value was 3.076 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Stabilization dimension of Organizational Learning of Public and Deemed University. The mean scores represents that Public university have more stablity to implement organizational learning program in comparison to Deemed University. The mean score for Public Universities on Experimentation dimension of Organizational Learning was found to be 64.7727 and the mean score for Deemed Universities on Experimentation dimension of Organizational Learning was found to be 56.2123. The mean difference was 8.56033 and the 'T' value was 2.869 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Experimentation dimension of Organizational Learning of Public and Deemed University. The mean scores represents that Public University are more prompt to experiment an idea in comparison to Deemed University. The mean score for Public Universities on Mutuality dimension of Organizational Learning was found to be 71.0407 and the mean score for Deemed Universities on Mutuality dimension of Organizational Learning was found to be 61.7367. The mean difference was 9.30400 and the 'T' value was 2.861 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Mutuality dimension of Organizational Learning of Public and Deemed University. The mean scores represents that Public University have more Mutual understanding among employees in comparison to Deemed University. The mean score for Public Universities on planning dimension of Organizational Learning was found to be 70.3333 and the mean score for Deemed Universities on Planning dimension of Organizational Learning was found to be 61.5000. The mean difference was 8.83333 and the 'T' value was 3.080 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in planning dimension of Organizational Learning of Public and Deemed University. The mean scores represents that Public University have more systematic work in comparison to Deemed University. The mean score for Public Universities on Temporary System dimension of

Organizational Learning was found to be 70.4177 and the mean score for Deemed Universities on Temporary Systems dimension of Organizational Learning was found to be 61.3887. The mean difference was 9.02900 and the 'T' value was 2.368 which is significant at 0.05 level. It infers that there is significant difference in Temporary Systems dimension of Organizational Learning of Public and Deemed University. The mean scores represents that Public University have more Temporary System in comparisons to Deemed University. The mean score for Public Universities on Competency Building dimension of Organizational Learning was found to be 71.5287 and the mean score for Deemed Universities on Competency Building dimension of Organizational Learning was found to be 61.5277. The mean difference was 10.00100 and the 'T' value was 2.744 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Competency Building dimension of Organizational Learning of Public and Deemed University. The mean scores represents that Public University have more demonstrates ability to operate effectively in comparisons to Deemed University.

H3: There will be no significant difference in the mean score between Public, and Private Universities regarding Organizational Learning like Innovation, Implementation, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and **Competency Building among employees**

Table - 3 Comparison of dimensions of Organizational Learning Diagnostics between Public and Private University (See Table No. 3)

The mean score for Public Universities on Innovation dimension of Organizational Learning was found to be 71.7740 and the mean score for Private Universities on Innovation dimension of Organizational Learning was found to be 44.6893. The mean difference was 27.08467 and the 'T' value was 11.351 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Innovation dimension of Organizational Learning of Public and Private University. The mean scores represents that Public Universities have more new method, idea, product, and technological innovations in comparison to Private University. The mean score for Public Universities on Implementation dimension of Organizational Learning was found to be 70.5957 and the mean score for Private Universities on Implementation dimension of Organizational Learning was found to be 45.12. The mean difference was 25.47567 and the 't' value was 9.002 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Implementation dimension of Organizational Learning of Public and Private Universities. The mean scores represents that Public Universities have more promptly execute organizational learning program in comparison to Private University. The mean score for Public Universities on

ทรร

Stabilization dimension of Organizational Learning was found to be 70.5237 and the mean score for Private Universities on Stabilization dimension of Organizational Learning was found to be 40.2103. The mean difference was 30.31333 and the 'T' value was 12.635 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Stabilization dimension of Organizational Learning of Public and Private Universities. The mean scores represents that Public Universities have more stable to implement organizational learning program in comparison to Private University. The mean score for Public Universities on Experimentation dimension of Organizational Learning was found to be 64.7727 and the mean score for Private Universities on Experimentation dimension of Organizational Learning was found to be 38.4093. The mean difference was 26.36333 and the 'T' value was 11.455 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Experimentation dimension of Organizational Learning of Public and Private University. The mean scores represents that Public University have more prompt to experiment an idea in comparison to Private University. The mean score for Public Universities on Mutuality dimension of Organizational Learning was found to be 71.0407 and the mean score for Private Universities on Mutuality dimension of Organizational Learning was found to be 43.1947. The mean difference was 27.846 and the 'T' value was 11.746 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Mutuality dimension of Organizational Learning of Public and Private University. The mean scores represents that Public University have more Mutual understanding among employees in comparison to Private University. The mean score for Public Universities on planning dimension of Organizational Learning was found to be 70.3333 and the mean score for Private Universities on Planning dimension of Organizational Learning was found to be 42.5833. The mean difference was 27.75 and the 'T' value was 13.040 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Planning dimension of Organizational Learning of Public and Private University. The mean scores represents that Public University have more systematic work in comparison to Private University. The mean score for Public Universities on Temporary System dimension of Organizational Learning was found to be 70.4177 and the mean score for Private Universities on Temporary System dimension of Organizational Learning was found to be 43.056. The mean difference was 27.36167 and the 'T' value was 9.097 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Temporary System dimension of Organizational Learning of Public and Private University. The mean scores represents that Public University have more Temporary System in comparison to Private University. The mean score for Public Universities on Competency Building dimension of

Organizational Learning was found to be 71.5287 and the mean score for Private Universities on Competency Building dimension of Organizational Learning was found to be 42.917. The mean difference was 28.61167 and the 'T' value was 10.224 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Competency Building dimension of Organizational Learning of Public and Private University. The mean scores represents that Public University have more demonstrates ability to operate effectively in comparison to Private University.

H4: There will be no significant difference in the mean score between Deemed and Private Universities regarding Organizational Learning like Innovation, Implementation, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and Competency Building among employees

Table - 4: comparison of dimensions of Organizational Learning Diagnostics between Deemed and Private University (See Table No. 4)

The mean score for Deemed Universities on Innovation dimension of Organizational Learning was found to be 62.5040 and the mean score for Private Universities on Innovation dimension of Organizational Learning was found to be 44.6893. The mean difference was 17.81467 and the 'T' value was 6.196 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Innovation dimension of Organizational Learning of Deemed and Private University. The mean scores represents that Deemed University has more new method, idea, product, and technological innovations in comparison to Private University. The mean score for Deemed Universities on Implementation dimension of Organizational Learning was found to be 62.1433 and the mean score for Private Universities on Implementation dimension of Organizational Learning was found to be 45.12. The mean difference was 17.02333 and the 'T' value was 5.112 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Implementation dimension of Organizational Learning of Deemed and Private University. The mean scores represents that Deemed University have more promptly execute organizational learning program in comparison to Private University. The mean score for Deemed Universities on Stabilization dimension of Organizational Learning was found to be 60.732 and the mean score for Private Universities on Stabilization dimension of Organizational Learning was found to be 40.2103. The mean difference was 20.52167 and the 'T' value was 6.527 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Stabilization dimension of Organizational Learning of Deemed and Private University. The mean scores represents that Deemed University have more stable to implement organizational learning program in comparison to Private University. The mean score for Deemed Universities on Experimentation



dimension of Organizational Learning was found to be 56.2123 and the mean score for Private Universities on Experimentation dimension of Organizational Learning was found to be 38.4093. The mean difference was 17.803 and the 'T' value was 6.748 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Experimentation dimension of Organizational Learning of Deemed and Private University.

The mean scores represents that Deemed University have more prompt to experiment an idea in comparison to Private University. The mean score for Deemed Universities on Mutuality dimension of Organizational Learning was found to be 61.7367 and the mean score for Private Universities on Mutuality dimension of Organizational Learning was found to be 43.1947. The mean difference was 18.542 and the 'T' value was 6.125 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Mutuality dimension of Organizational Learning of Deemed and Private University.

The mean scores represents that Deemed University have more Mutual understanding among employees in comparison to Private University. The mean score for Deemed Universities on Planning dimension of Organizational Learning was found to be 61.500 and the mean score for Private Universities on Planning dimension of Organizational Learning was found to be 42.5833. The mean difference was 18.91667 and the 'T' value was 6.587 which is significant at 0.01 level.

It infers that there is significant difference in planning dimension of Organizational Learning of Deemed and Private University. The mean scores represents that Deemed University have more systematic work in comparison to Private University. The mean score for Deemed Universities on Temporary System dimension of Organizational Learning was found to be 61.3887 and the mean score for Private Universities on Temporary System dimension of Organizational Learning was found to be 43.056. The mean difference was 18.33267 and the 'T' value was 5.278 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Temporary System dimension of Organizational Learning of Deemed and Private University. The mean scores represents that Deemed University have more Temporary System in comparison to Private University.

The mean score for Deemed Universities on Competency Building dimension of Organizational Learning was found to be 61.5277 and the mean score for Private Universities on Competency Building dimension of Organizational Learning was found to be 42.917.

The mean difference was 18.61067 and the 'T' value was 5.813 which is significant at 0.01 level. It infers that there is significant difference in Competency Building dimension of Organizational Learning of Deemed and Private University. The mean scores represents that Deemed University have more demonstrates ability to operate effectively in comparison

to Private University.

Findings

The Public University used more learning practices in comparison of Deemed and Private Universities. It infers that there is significant difference among Public, Private and Deemed universities on Innovation, Implementation, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and Competency Building dimension of Organizational Learning. The mean scores represents that Public University have more Innovation, Implementation, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and Competency Building in comparisons to Deemed University. It infers that there is significant difference in Innovation, Implementation, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and Competency Building dimension of Organizational Learning of Public and Deemed University.

The mean scores represents that Public Universities have more Innovative, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and Competency Building in comparison to Private University. It infers that there is significant difference in Innovation, Implementation, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and Competency Building dimension of Organizational Learning of Deemed and Private University. The mean scores represents that Deemed University has more Innovative, Implementation, Stabilization, Experimentation, Mutuality, Planning, Temporary System and Competency Building in comparison to Private University.

Recommendations

- Public University maintained all three main subsystems of Organizational Learning such as Innovation, Implementation and Stabilization. While Private and Deemed Universities required all three subsystem.
- 2. The Organizational Learning Program organized in the Deemed and Private University also. So that employee can perform better.
- Private and Deemed University enhance environment of Flexibility and Positive attitude, Mutuality support, Mutuality respect, collaborative work and effective teams to solve problems.
- Public University maintained environment of flexibility and positive attitude, Mutuality support, Mutuality respect, collaborative work and effective teams to solve problems.
- Public University maintained Temporary system in his organization and Private and Deemed Universities increase task group or task forces, project groups etc.
- 6. For Competency Building Private and Deemed University held seminar, external training programme, Implementation of change.

Limitation of the Study: This research is limited to the educational sector of Rajasthan. This study relied on self



Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013

report and surveyed data.

References

- Albert, M. (2005). Managing change: Creating a learning organization focused on quality. Problems and Perspectives in Management 1.
- Garvin, D.A. (1993) "Building a learning organization" Harvard Business Review, July - August.
- Georgia L. Bauman (2005) "Promoting Organizational

Table - 1: Comparison of Public, Deemed and Private University regarding organizational learning Diagnostics

Dimensions of	Source of	Sum of	df	Mean.	F	Significance
OLD	Vaciation	Squares		Square		
Innovation	Between Groups	11368.774	2	5684,372	47.627	0.01
	Within Group	10383,599	87	119.352		
	Total	21752,373	89		1	
Implementation	Between Groups	10102.454	2	5051.227	29,970	0.01
	Within Group	14663,369	87	168.544		
	Total	24765.823	89		1	
Stabilization	Between Groups	14359.137	2	7179.569	55,708	0.01
	Within Group	11212.379	87	128.878		
	Total	25571.516	89			
Experimentation	Groups	10852.515	2	5426.257	51.289	0.01
	Within Group	9204.369	87	105.797		
	Total	20056.884	89			
Mutuality	Between Groups	12057,699	2	6028.849	47,550	0.01
	Within Group	11030,743	87	126.79		
	Total	23988.442	89			
Planning	Between Groups	12059.306	2	6029.653	57.424	0.01
	Within Group	9135.208	87	105,002		
	Total	21194.514	89			
Temporary System	Between Groups	11662.703	2	5831.352	32.712	0.01
	Within Group	15508,741	87	178.261		
	Total	27171.444	89			
Competency Building	Between Groups	12650,044	2	6325.022	40.336	0.01
	Within Group	13642,372	87	156.809		
	Total	26292,416	89			

Table - 2 : Comparison of dimensions of Organizational Learning Diagnostics between Public and Deemed University

Dimensions of OLD	Туре	N	Mean.	Std. Deviation	Mean Difference	ŧ	Significance
Innevation	Public Private	30 30	71.7740 44.6893	19.49218 7.79198	27.08467	11.351	0.01
Implementation	Public Private	30 30	70.5957 45.1200	13.15322 8.20136	25,47567	9.002	0.01
Stablization	Public Private	30 30	70.5237 40.2103	9,48828 9,69172	30.31333	12.635	0.01
Experimentation	Public Private	30 30	64.7727 38.4093	19.41917 7.0955	26.36333	11.455	0.01
Mutuality	Public Private	30 30	71.0407 43.1947	10.27059 7.94497	27.84600	11.746	0.01
Planning	Public Private	30 30	70.3333 42.5833	8,21934 8,26509	27.75000	13.04	0.01
Temporary Systems	Public Private	30 30	70.4177 43.0560	13.14410 9.92854	27.36167	9.097	0.01
Competency Building	Public Private	30 30	71.5287 42.9170	12.76448 8.48498	28.61167	10.224	0.01

Learning in Higher Education to Achieve Equity in Educational Outcomes" New Directions For Higher Education, No. 131, Fall 2005: Wiley Periodicals, Inc. pp.23-

- Senge, Peter M., Charlotte Roberts, Richard B. Ross, Bryan J. Smith, and Art Kleiner. 1994. The Fifth Discipline Fieldbook. New York: Doubleday.
- Simon, Herbert (1997), Administrative Behavior (3rd ed.) . New York: The Free Press
- Pareek Udai "Training Instruments for Human Resource Development" Tata Mc Graw Hills, New Delhi

Table - 3 Comparison of dimensions of Organizational Learning Diagnostics between Public and Private University

Dimensions of	Туре	N	Mean	Standard	Mean	t	Significance
OLD				Deviation	Different		
					e		
Innovation	Public	30	71,7740	10.49218	9.27000	2.945	0.01
	Deemed	30	62.5040	13.68409			
Implementation	Public	30	70,5957	13.15322	8.45233	2.211	0.05
	Deemed	30	62.1433	16.28999			
Stabilization	Public	30	70.5237	9.48828	9.79167	3.076	0.01
	Deemed	30	60.7320	14.62692			
Experimentatio n	Public	30	64.7727	10.41917	8.56033	2.869	0.01
	Deemed	30	56,2123	12.58916	1		
Mutuality	Public	30	71,0407	10.27059		2.861	0.01
	Deemed	30	61.7367	14.55208			
Planning	Public	30	70.3333	8.21934	8.83333	3.08	0.01
	Deemed	30	61.5000	13.38424			
Типрогату	Public	30	79.4177	13.14410	9.02900	2.368	0.05
Systems	Deemed	30	61.3887	16.22844			
Capacity	Public	30	71.5287	12.76448	10.00100	2.744	0.01
Building	Deemed	30	61.5277	15.34601			

Table - 4: comparison of dimensions of Organizational Learning Diagnostics between Deemed and Private University

Dimensions of OLD	Type	N	Mean	Std. Deviation	Mean Differenc e	t	Significance
Innovation	Deemed	30	62.5940	13.68409	17.81467	6.196	0.01
	Private	30	44.6893	7.79198			
Implementation	Deemed	30	62.1433	16.28999	17.02333	5.112	0.01
	Private	30	45.1200	8.20136			
Stabilization.	Deemed	30	60.7320	14.62692	20.52167	6.527	0.01
	Private	30	40.2103	9.09172			
Experimentation	Deemed	30	56.2123	12.58916	17.89300	6.748	0.01
	Private	30	38,4093	7,0955			
Mutuality	Devmed	30	61.7367	14.55208	18.54200	6.125	0.01
	Private	30	43.1947	7.94497			
Planning	Deemed	30	61.5000	13.38424	18.91667	6.587	0.01
	Private	30	42.5833	8.26509			
Temporary	Deemed	30	61.3587	16.22844	18.33267	5.278	0.01
Systems	Private	30	43,0560	9.92854			
Capacity	Devmed	30	61.5277	15.34691	18.61967	5.813	0.01
Building	Private	30	42.9170	8.48498			



A Comparative of Succidal Ideation Among HIV Negative, Positive and AIDS Cases

Saroj Verma * Ravindra Prajapati ** Manik Samvatsar ***

Abstract - The aim of present paper is to analysis a comparative study of suicidal ideation among HIV negative, positive and AIDS cases. It is found that our present study reveal that consistent and systematic difference exist among HIV negative, positive and AIDS.

Introduction-

AIDS stands for Acquired immune deficiency syndrome or acquired immunodeficiency syndrome that refers to collection of syndromes and infections resulting from the specific damage to the immune system caused by the human immunodeficiency virus (HIV), in humans (U.S. National Institute of Health. 2007).

AIDS is a chronic, lifethreating condition. HIV the causing virus is different from most other viruses because it attacks the immune system. Immune system gives the ability to fight infections in a body. HIV interferes with this body ability to effectively 5th off viruses, bacteria and fungi that cause disease, HIV destroys a type of white blood cell (T cells or CD4 cells) that the immune system must have to fight disease and when the immune system gets infected some other infections occurs. These types of infections are opportunistic infections.

A blood test can determine if the person is infected with HIV. but if person's test is positive for HIV, it does not necessarily mean that the person has AIDS. A person with HIV may receive an AIDS diagnosis after developing one of the CDC defined AIDS indicator illness or on the basis of certain blood rests (CD4 count) and may not have experiences any serious illness. CD4 level lower than 200 means the person has developed AIDS. So HIV/AIDS occur in two stages. First is the entry and detection of HIV in body that slowly reduces the strength of the immune system and leads to the second stage of AIDS that is more severe a problem.

In the Unites States, as of Dec. 31, 2001 a total of 8047.075 adults and adolescents have been reported having AIDS. With current estimate suggested around one million of the 462,653 (57%) have die. As of the end of 2002, 42 million people were estimated to be living with HIV/AIDS

worldwide. with an estimated 5 million people acquiring the infection in 2002 (Centres for Disease control and Prevention 2001). An estimated 20 million individuals have die from HIV worldwide. This shows the pace of increase in sufferery every year. In 2005, more than 4 million people will be newly infected wity HIV, 25 million have died of AIDS since the epidemic began. AIDS has replaced malaria and tuberculosis as the world's deadliest infectious disease among adults and that's why it is clamied to be the fourth leading cause of death worldwide. Over 13 million children have been orphaned by the epidemic.

As of January 2006, joint United Nation Programme on HIV / AIDS (UNAIDS) and the world Health Organization (WHO) estimated that AIDS has killed more than 25 million people since it was first recognized on June 5, 1981, making it one of the most destructive epidemics in recorded history. In 2005 alone, AIDS claimed an estimated 2.4-3.3 million lives, of which more than 570,000 were children (UNAIDS (2006). The picture in India is equally worse. The first case of HIV was detected in 1984. And till now it is gradually increasing. The rate of HIV infection are 21 per thousand and the total number of AIDS cases reported upto August 31st 1997 was 4846 (NACO, 19777) whereas now total no. of AIDS cases are 24 lacks and 70 thousand (NACO, July, 2006).

Methodology-

The topic is highly sensitive one because its highly personalized and stigmatizing nature. For conducting the study both the qualitative and quantitative methods were employed. The most important task was to reach the HIV patients, this however was made possible by selecting the patients who were attending the NACOICTC centers. As the patients were already in contact with the investigator it was easy to develop rappot and confidence with the patients. For



data collection standardized questionnaire and personal interviews were used. The subjects fot the study were chosen partly from Haryana and partly from Delhi. It is pertinent to mention here that the cultural values, socio economic conditions and the living standards of the people living the area are almost same. The most important criteria for the inclusion in the study was the CD4 level. The interviews for the study were conducted after the confidentiality was ensured and rapport was established. The inital visits therefore were to build confidence and rapport with the patients. As suggested by Ficher. (1983) for design the coding scheme, sequence of questionnaire, sensitive questions, mixing of open ended and dichotomus questions and pilot study etc were taken into consideration by using the standardized questionnaires. The subjects were not only informed but informed consent was obtained from each and every participant in writing. As the investigator worked as counsellor and therefor had sufficient training and experince in interviewing the HIV patients and their caregivers and the experience was a great help in working for this study. During the pilot study investigator obtained sufficent training to adminisrer various questionnaires.

Design-

As the study aimed to explore the psychosocial problems in the HIV/AIDS patients and also attempted to see the impact of counselling on these variables. The study was conducted in two phases, in the first phase a multi group design was used in examine/asses, suicidal ideation, in HIV negative, HIV postive and AIDS cases and their care given. There were three groups of HIV/AIDS and three groups of their care givers. There were 250 participants in each group. As shown in Table- 1

Table: 1 showing the design of the study- distribution of subjets in different groups

GROUP-1	GROUP-2	GROUP-3	GROUP-4	GROUP-5	GROUP-6
HIV	Care Givers	HIV	Care Givers	AIDS	Care Givers
negative	of HIV	positive	of HIV	Patients	ofAIDS
	negative		Positive		Patients
n=50	n=50	n=50	n=50	n=50	n=50

For the second phase of the study i.e. for examining the impact of counselling on depression, suicidal ideation, family burden and health and quality of life in HIV positive and AIDS cases and their caregivers a per-post desing was use.

SAMPLE-

The samples of the study consisted of HIV negative, HIV positive and AIDS cases and their care givers. In all a total number of 300 participants were included in the study. There

were 50 participants in each group i.e. 50 HIV negative. 50 HIV positive and 50 AIND cases and their care givers (50 in each groups).

The HIV negative, HIV positive and AIDS cases and their care givers were selected on the basis of non random purposive sampling bases from ICTCs of Delhi, Haryana (India).

In the first group 50 HIV negative participants were selected and their age range was 24 years to 48 years out of this total number of males were 25 and females were also 25. The second group i.e. caregivers of HIV negative participants were in the age range of 28 yeara to 46 years, out of the total number of males were 25 and famale were also 25. In the third group there were 50 HIV positive perticipants (as tested and identified by ICTC Center the age range was 30 years to 48 years. There were equal number of males and females. Majority of cases were labours/drivers and many of them were multiple drug users (more than 50%). The fourth group represented care givers of HIV positive participants. Total numbers of caregivers were 50. The age range was 28 years to 49 years. with an equal number of males and females. In the fifth group there were 50 AIDS cases in the range of 32-48 yearas with an equal number of males and females cases. Majority of participants were labours/drivers and multiple drug users (more than 50%). In the sixth group there were 50 caregivers of AIDS cases. There age range was 28 years to 49 uears.

Tools Uses -

The following tool. were administered uniformly and individually to each subject by investigator himself.

Suicidal Ideation Questionnaive (SIQ)- The suicidal ideation questionnaire is a self reported measure designed to assess thought about suicide ideation in andolescents and young adults. The SIQ is developed by Reynolds. (1988). The SIQ consist of 30 items and the respondents need to rand each of the items on a 7 point scale, which assess the frequency with which the cognition occurs. For comming purpose, items are scored from 6 to 0. Items are scored in a pathological direction, so that a high score is indicative of number of suicidal congintions occuring with significant regularity. The maximum possible score on the 30 itmes SIQ is 180, and lowest possible score is zero which indicates that none of thoughts indicated by the itmes have ever occurred.

The internal consistency reliability of the SIQ and SIQ-JR across development samples and for various sub samples by age and sex was completed using Cornbach (1951) co-

efficient alpha (rd) Reliability co-efficent by grade were uniformly high and ranged from 969 to 974, with a total sample reliability coefficient of 971 for ths SIQ. In the study reported by Klastemen-Fields, (1985) with 156 femals college students (primarily 18 and 19 years old) a reliability coefficient of 964 was found. The test re-test reliability of the SIQ was examined in a large sample of adolescent from a high school in the mid-west. Subjcts were 80% youngsters from research sample B who were represented on the SIQ on the SIQ approximately 9 week after the initial assessment. On the inital assessment a mean of 17.79 (SD=20.76) was obtained and 4 week later a mean SIQ score of 17.49 (SD=23.82) was found. The test retest reliability based on these two assessments was. 72 which is moderate and consistent with the status of the SIQ. The scale is given in appendix-B.

Procedure- Each participant was administered measures of suicidal ideation after building rapport everyone was biefed about the purpose of the study and informed conesent was obtained. Those who volunteered for the study were included for the final testing. The testing was done under uniform and standardized conditions and all the measure were administered individually to each participant by the investigator himself. For the second phase of the study before and after design was used to examine the impact of the counselling on psychosocial problems of HIV/AIDS patients and their care givers. The base line scores were taken from the first testing in the first phase and all the subjects in all groups were taken up for the second phase of the study. For this study the counselling module for HIV positive and AIDS cases and for their care givers were taken of as such for the counselling. the counselors training modules develop by National. AIDS Control Organization, Department of AIDS. Ministry of healthy, Government of India. New Delhi.

The HIV positive. AIDS cases as well as their care givers were given counselling individually by the investigator every week for three month. Every case were called in ICTC Center onces a week and it continued for three months, after the completion of three months, measure of suicidal ideation, were administered again to each subject under standered test condition uniformly by the investigation.

The sorted format of standard counselling module for HIV positive, HIV nagative, AIDS cases and their care givers are given in the Appendix-F.

Administration and Scoring - All the participants were interviewed at the intake after developing rapport and building

confidence. Informed consent was obtatined from the each participant after explaining the purpose of the study and the procedure. It was followed up by standardized AIDS counselling in the groups. The counselling was done by the investigator hinmself. For the second part of the study a post counselling assessment was done after three months of intake.

Results and Discussion-

Present study was conducted with the aim of assessing the psychosocial problems of HIV/AIDS patients and their caregivers. It was also intended to examine the effect of counselling on psychosocial problems of HIV/AIDS patients and their caregivers. The study was counducted on 150 cases, out of these, there were 50 HIV negative, 50 HIV positive and 50 AIDS cases and 150 caregivers (50 each in HIV negative, HIV positive and AIDS cases group).

The data were analyzed by using statistice i.e. mean, SD and test and simple analysis of variance. Duncan's Post hoc test was done for checking the statistical significance of the difference between groups. The results are detailed in tables below, are described and discussed.

Suicidal Ideation-The first objective of the study was to assessand compare HIV negative, HIV positive and AIDS cases on and sucidal ideation. The obtained results were analyzed by using analysis of variance, followed by Duncan's test for Post-hoc comparison and the results are given in Table2 and 3 below

Table:2 means and SD's of HIV negative, HIV positive and AIDS cases on depression and suicidal ideation.

Variables	Categories							
	HIV negative HIV Positive			AIDS negative				
	Mean	SD	Mean SD		Mean	SD		
Suicidal ideation	0.40*	0.63	6.60°	1.32	6.46°	1.09		

a b c alphaher indicare Duncan's post hoc comparospm Similar same alphaher indicate non signifcant whereas differecnt alphaber indicate significant difference.

Variables	Sources of Variance	Sum of	Mean	F
		Squares	Squares	
Suitidal	Between Groups	1244.65	622.30	
ideation	Within groups	164.74	1.12	555.30"

#= Significant at 0.05 level

ns=non significant

^{**=} Significant at 0.01 level



Table 3 Summary of ANOVA of HIV ositive and AIDS cases on and suicidal ideation (df=2.147)

The mean suicidal ideation score of HIV group was 0.40 and it was 6.60 and 6.46 respectively of HIV positive and AIDS group (Table 2) ANOVA was done and it was found (Table 3) that the mean suicidal ideation scores of three groups differed significantly (F=555.30 df=2.147 p<01). Post hoc comperision by using Duncan's lest revealed (Table 2) that the HIV negative cases have significantly less suicidal ideation than both the HIV positive and AIDS cases.

The HIV positive and AIDS cases scored almost equal on suicidal ideation therefore the results confirm the first hypothesis. that the HIV negative, HIV positive and AIDS cases will score differently on measures of depression and suicidal ideation.

The second hypothesis was that the caregivers of HIV negative, positive and AIDS case would differ in terms of suicidal ideation. The results are given Table 4 and 5 below

Table: 4 Means and SD's of caregivers of HIV negative, HIV positve and AIDS eases on suicidal ideation.

Variables	Categories							
	HIV no	egative	HIV Positive		AIDS negative			
	Mean	Mean SD Mean SD I		Mean	SD			
Suicidal ideation	0.184	0.38	4.58 ^b	2.76	6.341	1.09		

a b c alphaher indicare Duncan's post hoc comparospm Similar same alphaher indicate non significant whereas different alphaber indicate significant difference.

Table 5 Summary of ANOVA of HIV ositive and AIDS cases on and sjuicidal ideation (df=2.147)

Variables	Sources of Variance	Sum of	Mean	F
		Squares	Squares	
Suicidal	Between Groups	1006.72	503.36	
ideation	Within groups	440.78	2.99	167.87**

#= Significant at 0.05 level

ns=non significant

The caregivers of HIV negative cases obtained a mean scores of 0.18 (SD=0.38) on suicidal ideation where as the mean suicidal ideation scores of caregivers of HIV positive (Mean=4.58, SD=2.76) and AIDS cases (Mean=6.34, SD=1.09) was higher. ANOVA (Table 5) revealed that the

suicidal ideation scores of all the three groups differed significantly (F=167.87, df=2.147) at .01 level of confidence. Duncan's test revealed that the caregivers of HIV negative cases had significantly less suicidal ideation than the HIV positive and AIDS cases (Table-4) AIDS cases scored significantly higher on suicidal ideation than the HIV positive group (Table-4). Thus second hypothesis of the study is also confimed. The objective of the study were relating to the suicidal ideation to the HIV negatvie, HIV positive and AIDS cases and their cargivers.

Findings of the study revealed (Table 2 to 5) that the HIV positive and AIDS cases have had significantly high suicidal ideation than HIV negative cases and their caregivers. Sucidal ideation is one of the critical features of the depression and therefore keeping the higher level of depression in HIV positive and AIDS cases and their caregivers in mind in seemed to be justified. Thus the finding are in a way indicated the reported higher level of depression in HIV positive and AIDS cases and their caregivers.

The finding of the studies are in line with the results of Catatan (1999), Counor and Fostrein (2000), Turina (2001), Green and Smith (2004) reporting higher level of depression and suicidal ideation in HIV positve and AIDS cases.

Though there are scattered evidence in research literature about the higher areas of suicide in HIV positive and AIDS cases, yet bill date evidence is lacking that the national AIDS control society and the state AIDS control societies are keeping track of the actual suicides committed by the HIV positive and AIDS cases.

The fidings of the study in tems of higher level of their cargivers have implications for the family members as well as for the government orgaization. They should focus more on this issue to prevent the suicides by directing there efforts to the critical issue also.

Refenceres-

- NACO (1997), HIV/AIDS
 Serosurveillance Update, New Delhi NACO
- 2. (2006) UNGASS, India report : Progress report on the declaration of commitment of HIV/AIDS.
- 3. UNAIDS (2006), "Overview of the Globel Aids, Epidemic, "2006 report on the Globle, AIDS, Epidemie (PIDF)
- 4. Leserman, J. Role of Depresion, stress and trauma in HIV diseass progression 2008 Apr. 28 (2) 203-7.
- Masliah, E. and Achim. C.L. (1992) Gandre spetrum of HIV Assoeiated Neocortical Damge, Annual, Neusology 32, 321, 329

^{**=} Significant at 0.01 level

E- Mart: A Necessity Not A Boon

Dr. Devendra Singh Rathore*

Concept -

The importance of the topic with which this paper deals has been well established. This paper deals with E-marketing, giving a brief overview of the entire E-marketing concept. The main focus of this paper is to address the various mediums through which a potential business can implement E marketing for itself. This paper has been made with the aim of the paper:

The India is the second-most populous country with over 1.22 billion people. more than 50% population of India is below the age of 25 years and over 65% below the age of 35 years India will reach somewhere in the vicinity of 250-350 million Internet users by 2015. I took a liberal interpolation of those estimates to arrive at a number of 30 million new users that we will add in the coming year. That's a staggering number and larger than the entire population of Australia if you like those kinds of comparisons. However, to truly deconstruct this number and get a sense for what the potential impact this will have for a business looking to leverage this user base, we need to look carefully not just at the users but also at the following 'inverted iceberg'- where there is more than that meets the eye below the surface. It means India has a very big market of youth customer. to reach this group of population we need to develop the *E-marketing* for the country as the youth of India has also become techno-savvy which is the prime reason behind me doing this paper.

Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the Organization and its stakeholders. Therefore we can see that E -Marketing by its very nature is one aspect of an organizational function and a set of processes for Creating, communicating and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the Organization and its stakeholders

Since the start of 21st century, the Internet has had a revolutionary impact on culture and commerce, including the rise of near-instant communication e mail, sms, blogs, social networking , Face book.twitter ,video calls ,4g,Telyshoping and different search engine. The Internet takeover over the global communication landscape was almost instant in historical terms. Today the Internet continues to grow, driven by ever greater amounts of online commerce, entertainment, Culture and networking. Internet has expanded at an astonishing rate across the world; Most of the world has embraced this new age technology with lot of gusto Popularity of social networking (face book/twitter) on internet can be judged by the fact that 'Twitter' and 'Face book' are making news and receiving coverage from print as well as visual media.

Today's more than 6000 companies like KFC, Samsung, Dell, and Apple in world are spending as much as 34 % of their marketing budgets on Internet ads. According to a web world report, consumers showed a 31 % greater Ability to recall a brand after seeing an Internet ad than earlier -Compared with a 29 % increase with magazines, 26 per cent with newspapers, and 28 % with television. Online advertising has an advantage over the TV and Paper ad campaigns. While the good TV ad arouses curiosity, and the effective print press ad offers a little more information, the impact gets dissipated over the days. When people are actually ready to buy, your campaign may be off and a rival's campaign may be on, and your potential customers have no way of retrieving your earlier ads In India internet is growing. It's defiantly not the largest medium for advertising but without doubt it can give you better ROI (return on investment) as compared to any other conventional medium. Having given a fair idea of the growing popularity of e mart

As such an aspect, *E-Marketing* has its own approaches and tools that contribute to the achievement of marketing goals and objectives. E- Marketing ties together creative and technical aspects of the Internet including design, development, advertising, and sales. E Marketing does not simply entail building or promoting a website, nor does it mean placing a banner ad on another website. Effective E marketing requires a comprehensive strategy that synergizes a given Company's business model and sales goals with its website function and appearance, focusing on its target market through proper choice of advertising type, media, and design. E Marketing is a tool that nearly everyone uses today,



and it continues to grow and be more prevalent in the lives of people around the world. Meanwhile, on-line marketing was once seen as a risky Endeavour for most businesses, but the gap between it and off-line marketing has rapidly narrowed: E-marketing involves using the internet and other emerging technology to research the market and carry out promotional activities. E marketing process and explores some of the benefits that it can provide to business.

E-Marketing, also referred to as *E-mail marketing, web* marketing, Online marketing, electronic / digital marketing or Internet Marketing, is the marketing of products or services over the Internet. E-Marketing is essentially part of marketing. So let's try to understand where it fits within the subject of marketing. E-marketing involves using the internet and other emerging technology to research the market and carry out promotional activities. E-marketing process and explores many benefits that it can provide to business. *E-Marketing is a broader term that describes* any marketing activity performed via electronic medium. Characteristics of E-Marketing

1. One-to-one approach-

The targeted user is typically browsing the Internet alone, so the marketing messages can reach them personally. This approach is used in search marketing, where the advertisements are based on Search engine keywords entered by the user. And now with the advent of Web 2.0 tools, many users can interconnect as "peers"

2. Appeal to specific interests-

E- Marketing places an emphasis on marketing those appeals to a specific behavior or interest, rather than reaching out to a broadly defined demographic. "On- and Off-line" marketers typically segment their markets according to age group, gender, geography, and other general factors. Marketers have the luxury of targeting by activity and geo location. Internet marketing differs from magazine advertisements, where them goal is to appeal to the projected demographic of the periodical. Because the advertiser has knowledge of the target audience-people who engage in certain activities (e.g., uploading pictures, contributing to blogs) - the company does not rely on the expectation that a certain group of people will be interested in its new product or service.

3. Geo targeting-

Geo targeting (in internet marketing) and geo marketing are the methods of determining the geo location (the physical location) of a website visitor with geo location software, and delivering different content to that visitor based on his or her

location, such as country, region/state, city, metro code/zip code, organization, Internet Protocol (IP) address, ISP or other criteria.

4. Different content by choice-

A typical example for different content by choice in geo targeting is the FedEx website at FedEx.com where users have the choice to select their country location first and are then presented with different site or article content depending on their selection.

5. Automated different content-

With automated different content in internet marketing and geo marketing the delivery of different content based on the geographical geo location and other personal information is automated.

Difference between E-Marketing v/s Traditional marketing

- E- Marketing is very economical and fast way to promote product.
 - Traditional Marketing is very expensive and takes more time to promote product.
- 2. E-Marketing is very useful for promoting product globally [without any additional cost].
 - It is very expensive and time consuming process for traditional marketing.
- In E- Marketing, you can also work with less employee [you can take more work with less man power]. In Traditional Marketing, you need more employment with more man power which in terms requires spending more money.
- 4. In E marketing you can sell or buy product 24 X 7, round the year without employing any person. That is not possible in traditional marketing.
- 5. Paying Professional and Experienced E- Marketing Company is very economical. Paying renowned Advertising and Marketing Company is very costly.

E- Marketing in Indian scenario -

E-marketing has had a large impact on several previously retail oriented industries including music, film, pharmaceuticals, banking, flea markets, as well as the advertising industry itself. Across the world E-marketing is now overtaking radio marketing in terms of market share. In the music industry, many consumers have been purchasing and downloading music (e.g., MP3 files) over the Internet for several years in addition to purchasing compact discs. it is surprising but truth in 2012 *You tube / airtel* (ring tone "why this kolaveri di" and "Gangnam Style") became

largest music vendor in Asia.

The number of banks offering the ability to perform banking tasks online has also increased. Online banking is believed to appeal to customers because it is more convenient than visiting bank branches. Internet auctions have gained popularity. Unique items that could only previously be found at flea markets are being sold on eBay. As the premier online reselling platform, eBay is often used as a price-basis for specialized items. The effect on the advertising industry itself has been profound. In just a few months, online advertising has grown to be worth tens of E-marketing has had a growing impact on the electoral process. We all knows just few month before *In Gujrat Assembly election Narendra modi heavily utilized E marketing (3d image projection/sms/blogs & twitter)* strategies to reach constituents.

Today all the companies and corporate in India have products or services to sell and they are advertising them via T.V, newspapers, brochures, magazines, radio etc. But it's time to take the promotions Online. Online advertising is an effective way of advertising that uses the power of Internet and World Wide Web in order to deliver marketing messages and attract customers. Online marketing business is galloping at a higher rate in India. Keeping pace with the international market, Indian search engines are undergoing a phenomenal growth. According to a study by Internet and Mobile Association of India (IAMAI) in association with Pin storm, India alone produces more than half-a-million searches a month. The study puts light to the evolution and growth of search engine marketing in India. Even the Indian websites like **Shaadi.com**, **Bharat matrimony** are burgeoning rapidly and are being used too. The concepts of e-ticketing, sms ticketing, e-banking, e learning are getting popular and widely used in India. The prime reason is that they Film Producer Kamal Hassan consume less time and are more productive as well as economic. Recently, the very popular released his movie "Vishwaroopam" on D2h which has happened first time in India. This is best example of e marketing. There have been many singers nowadays who prefer to show their talents on you tube and other talent hunt websites to save money and at the same time reach the masses. For example the teenage heartthrob Justin Bibber was discovered through you tube when he uploaded his song. People are becoming aware of the internet and are using it to the maximum. People are trying online shopping on sites such as Yebhi.com, Jabbong.com, Qukr, Olex, Home **Shopee** and many International brands are available online.

Websites are developed for trading also like quickr.com which are getting very popular. Thus making, trading,. Selling and purchasing easier. Other websites such as justdial.com are acting as global phone directories making it easy for people to find out emergency contact numbers.

The web search data show in year 2012 over 60,000 marketers is using this platform to capture the market share. That's not all; the number is growing at a higher pace as people research choices, product details and prices for every sort of buying decision - from travel to banking to insurance to education to even a film career. 22 of the top 50 and 37 of the top 100 search advertisers by keyword volume are firms with Indian operations. The number of net surfers in India is increasing at a rapid rate and studies have shown that people are spending more and more time on the web. Buying products online is convenient, hassle-free and easy. Online market places allow buyers to see the best deals available without moving from their desks and choose the products they want which they could not find at the local supermarket. For a company putting an advertisement online gives a benefit of being present right next to your competition when people are looking for products or services.

E marketers such as shopping for books, apparel, electronics, and such have really exploded this past year. However, consider that these 'applications' currently comprise not only of just 14% of the total online ecommerce spends (travel comprises the remainder) but also a similar percentage in terms of the Internet users who have actually ever used them. Snap deal, a popular deal shopping site has only recently grown to over 10 million users. Not to undermine those numbers, but what are all the other users doing then? In my opinion, it still represents a gap from a business opportunity standpoint - email, reading news, social networking, checking cricket scores, browsing music and videos. Rise in news consumption, NRI visit local websites, retail boom, Travel and Tour, e commerce, e learning.

The E market provides a wide range of opportunities for small businesses that are prepared to get involved. This chapter features information about researching your online market and making informed Regardless of the size and type of your business, understanding your customers is fundamental to successful marketing. Understanding online customers is even more vital due to the wider geographic and cultural spread, as well as diverse characteristics and attitudes to both obtaining information and buying online.

Online customers are empowered like never before - they now have more information and many product and price options. They are also less tolerant of poor products and

services and with the rise of latest technologies like social media, they can communicate instantly and raise their voices through blogs and forums in areas that interests and concerns them. To build a better understanding of your online customers, you need to find out about their mindset,

attitudes, aspirations and fears and plan e-marketing campaigns accordingly to get better results out of your online efforts. You need to consider several factors including:

Today Indian e-marketer's facing big problem for expand their business. e-market growth rate is slow Those Indian e-commerce companies are facing: "Indians do not interested to purchase on the internet". While people have access to online shops and e-commerce nobody wants to buy anything online. So most Indians are looking more towards social networking, entertainment and communicating over the internet rather than purchasing and spending online. While apparel and online retail are the fastest growing sectors in India, the absolute numbers of searches and conversions are still very small and growing at a slow rate.

This is largely due to the cultural mistrust of banks, credit cards and of *buying things one cannot touch and examine*. Surprised? We all thought that we were finally getting past that mindset and people were opening up to purchasing online, but such is not the case. While more people do buy online than they used to, its still an insignificant number. The growth trend is starting to flatten and the online purchases beginning to cap. *Cash on Delivery (COD) (old VPP)* is the choice mode of payment for Indian customers as credit card adoption is low and online transaction security is still not trusted. COD becomes a problem for suppliers due to additional cost and management overhead of managing lost in transition and customer returns.

E-marketing has had a large impact on several previously retail oriented Industries including *music*, *film*, *pharmaceuticals*, *banking*, *Flea markets as well as the advertising industry itself*. Across the world E-marketing is now overtaking shop showroom marketing in terms of

market share. In the music industry, many consumers have been purchasing and downloading music (e.g., MP3 files) from internet sites. The number of banks offering the ability to perform banking tasks online has also increased. Online banking is believed to appeal to customers because it is more convenient than visiting bank branches. Internet auctions have gained popularity.

Unique items that could only previously be found at flea markets are being sold on eBay. As the premier online reselling platform, eBay is often used as a price-basis for specialized items. It is absolutely right that E-marketing is the greatest change in business history which is happening right now. How to Lead Your Business through e marketing, it gives business leaders the tools to detect trends that cut across not just industries but also countries, rethink the economic and business principles they rely on, and adapt to the speed of innovation and unprecedented needs of the new global economy. This change is good not just for the businessman but also for customer and society. My dear friends please adopt it, promote it and encourage it because

E marketing is a necessity not a boon.

References:

- 01. Times life
- 02. Wikipedia
- 03. web service
- 04. Face book website
- 05. US Interactive Marketing Forecast, 2011 To 2016
- 06. Transactional Emails: Make your first e marketing
- 07. Pew Internet & American Life Project
- 08. Media Week: UK e-mail marketing predicted
- 09. O'Brian J. & Montezuma,
- 10. Shashank Mehrotra is the business head of BigRock
- 11. IBN Tech.
- 12. The economic times
- 13. Indian Digital Review
- 14. assocham study 2012
- 15. Junglee.com



A study of Green Shoe Options in India

Dr. Sanjay Agrawal *

Abstract

A green shoe option (GSO) provides the option of allotting equity shares in excess of the equity shares offered in the public issue as a post-listing price stabilising mechanism. This study examines whether companies need to include GSOs in their initial public offerings (IPOs), and explores the reasons for the indifference on the part of issuer companies and merchant banks in India towards GSOs. The aftermarket price performance of companies that included GSOs in their IPOs is analysed; however, the results of this analysis do not lead to any generalization due to the small number of companies that opted for GSO.

I-Introduction

The primary market for securities plays an important role in the economic development of a country, by enabling companies to mobilise financial resources from the public for undertaking various projects. The primary market also enables members of the public to invest their savings in gainful investment; it allows them to participate directly in the profits of the corporate sector. The fact that 91 companies raised capital to the tune of INR 67,609 crore in 2010-2011 is proof of this role of the primary markets. In 2009-2010, a total of INR 57,555 crores was mobilised by 76 companies.

Green Shoe Options (GSOs), or over-allotment options, were introduced by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the Indian market regulator, in 2003 to stabilise the aftermarket price of shares issued in IPOs. A GSO provides the option of allotting equity shares in excess of the equity shares offered in the public issue as a post-listing price stabilising mechanism.

The objective of this mechanism is to reassure investors, especially small investors who are known as retail individual investors (RIIs), that they would have an exit route during the first 30 days after the listing of shares (called the GSO window period) at a price close to the issue price, due to the price stabilising activity of the merchant banks. The issuer company also benefits from this mechanism, as enhanced investor confidence will result in more bids from investors at better prices.

The objective of this paper is to examine the GSO mechanism that was included by some companies in their IPO programmes since the introduction of GSOs, and to explore the reasons for the indifference to GSOs on the part of issuer companies and merchant banks. The paper will explore whether companies need to include GSOs in their IPOs.

II-IPO Process

To understand the Green Shoe Option (GSO) mechanism, one first needs to understand the initial public offering (IPO) process. When a company decides to launch an IPO, it hires a merchant bank to help it assess the number of shares that it can offer and at what price. Based on this advice, the company fixes a price band (or a floor price) within which (or above which) the investors bid for the shares.

An IPO can be made through the fixed price method, the book building method, or a combination of both. When the issuer decides the issue price at the outset and mentions it in the offer document, it is commonly known as a fixed price issue. When the price of an issue is discovered based on the demand received from the prospective investors at various price levels, it is called a book built issue.

In a book built issue, the issuer company and the merchant bank solicit indications of interest from institutional investors in order to construct a demand curve. Book building is a process of price discovery. The issuer discloses a price band or floor price before the opening of the issue of the securities offered. It is at this stage that the issuer company and the merchant bank decide whether to avail of the GSO. This decision is taken after considering various factors such as the level of confidence of the issuer company and the merchant bank about the price band determined by them, the expectation regarding investors' response, the market sentiment, and so on.

As the issue price is determined based on the bids received from the investors, it is fair to expect that the after market price of the shares will hover around this price, at least in the short run. In practice, it is observed that the aftermarket price is often significantly higher (underpricing) or significantly lower than the issue price (overpricing). This indicates a miscalculation in the pricing of the issue. However, research supports the claim that book building helps companies to reduce underpricing.

III- Rationale for including GSOs in IPO programmes Investors in an IPO could be anxious about various things:



before the allotment of shares, they are generally anxious whether they will get the shares; after they get the shares, they worry about how the secondary market will react in the period immediately following the day of listing. Will the market open above the issue price or will it open below? If the market price immediately following the listing day is higher than the issue price, it implies that the issue price was underestimated, a phenomenon known as underpricing. On the other hand, if the market price immediately following the listing day is lower than the issue price, it implies that the issue price was overestimated, a phenomenon known as overpricing.

The inclusion of GSOs in the IPO programme of an issuer company can be justified on five grounds: avoiding panic among RIIs, signalling confidence in the IPO price, protecting the reputation of merchant banks, enhancing liquidity in the aftermarket, and favouring preferred clients.

A. Avoiding panic among small investors

Small investors anywhere are likely to panic if the price of the shares they received in an IPO were to fall immediately after listing. In their panic, they may try to sell their shares at low prices, and may exit the capital markets altogether in some cases.

B.Signalling confidence

Many investors, especially small investors, are usually unable to make up their minds whether to bid or not to bid for the shares at the stated price band, as they stand to lose if the price turns out to be unsustainable.

In this context, the issuer company and the merchant bank can signal confidence in the issue by availing of the GSO mechanism. By so doing, the merchant banks back up their claims of the price being fair by proposing to buy shares from the secondary market if their claims were to be disproved and the aftermarket price were to fall below the issue price.

C.Merchant bank reputation

Merchant banks may prevail upon the issuers to avail of GSOs in their IPO programmes to retain or enhance their reputation. Given that the merchant bank plays an important role in arriving at the price band or the floor price; they risk facing the ire of the investors if the share trades at a price below the issue price in the immediate aftermarket. Thus, the reputation of a merchant bank may be affected if an issue managed by them has a bad opening.

D.Liquidity

Investors expect the market to stay liquid and transparent when trading begins in the secondary market.. Green shoe options help improve the liquidity of markets in two ways.

Firstly, due to the over-allotment of shares, more shares would go to the investors than it would have if GSOs were

not present. The larger the number of shares in the hands of the investors, the greater the possibility there these shares will be traded in the secondary market.

Secondly, if the aftermarket prices of the shares were to go below the issue price during the GSO window period, the stabilising agent would buy shares from the market, thereby enhancing liquidity.

E. Favoring preferred investors

During the planning phase of IPOs, merchant banks go on a road show, meeting institutional investors and other sophisticated investors, in order to gauge the potential demand for the IPO and the price at which the shares could be sold. The merchant bank then makes a favourable allotment to such institutional investors.

IV- GSOs in India

The GSO facility was introduced in India by the SEBI on August 14, 2003. This facility was expected to be a major policy initiative to reassure investors, especially the RIIs. The rationale for the introduction of GSOs was stated as follows:

Unexpected developments may have an adverse impact on price of newly listed securities. The facility of green shoe option introduced by SEBI facilitates the investment bankers to stabilize the post listing price of the security. This measure is expected to mitigate volatility and enhance investor confidence.

The GSO process involves the appointment of a merchant bank as a stabilising agent (SA) by the issuer company; the SA enters into an agreement with promoters or other preissue shareholders to 'borrow' a certain number of shares from them. Pre-issue shareholders are usually the promoters or other individuals who were already holding shares in the company at the time of the IPO. The issuer company needs to pass a shareholder resolution for availing the GSO, for appointing a stabilising agent, and for carrying out the market stabilising activity in the aftermarket.

A notable feature of the regulation of GSOs in India is the invocation of the doctrine of unjust enrichment; according to this, neither the issuer company nor the promoters or preissue shareholders can derive any profit from the stabilising activity. The profits, if any, would be used for protecting and educating investors. Another notable feature of the regulation of GSOs in India is that it is optional; it is left to the discretion of the issuer-company.

Apart from GSOs, the SEBI Regulations also contain an enabling provision for issuer companies to provide for a safety-net arrangement. The idea of a safety net is as follows: if the shares trade at a price below the issue price in the period immediately following the listing date, a specially designated entity would buy the shares from the investors. The issuer

company and the merchant bank are required to ascertain the financial capacity of the designated entity, and make requisite disclosures in the offer document.

V- Data and methodology

The current study focuses on the IPOs made in India from the time the first IPO was made on March 26, 2004 after the GSO mechanism was introduced by SEBI, up to and including the IPOs made until December 2011. This period saw 304 IPOs being made. The data relating to these IPOs was gathered from the commercial database Prime Database, the prospectus issued by the respective companies, and the SEBI bulletins and press releases. The information relating to whether or not the issuer company had opted for the GSO was gathered from the offer documents filed by the companies with the SEBI. The price data was obtained from the Website of the National Stock Exchange of India Limited (NSE). Of the 365 companies that made an IPO from August 2003 (when GSOs were introduced in India) to December 31, 2011, only 18 companies availed of the GSO facility in their IPO programmes.

This data is summarised in Table 1. (See Table No. 1)

The evaluation of the aftermarket performance of companies that included GSOs is presented in the next section.

VI- Analysis

From August 24, 2003 (the day GSOs were introduced in India) to December 31, 2011, 365 companies made IPOs in India. Of these companies, only 18 companies (4.93%) had included GSOs in their IPO programme (see Table 1). If we consider a more recent time period, we see that only two out of 122 companies (1.64%) included GSOs in their IPO programmes from January 1, 2009 to December 31, 2011.

A list of companies that included GSOs in their IPO programmes is given in Table 2. (See Table No. 2)

Table 3 shows the GSO window period (i.e., 30 days from the listing date) performance of the companies that included GSOs in their IPO programmes. Of the 18 companies that did included GSOs, the aftermarket closing price of six companies never went below the issue price during the GSO window period. As such, the SAs of these companies did not buy any shares from the market. At the close of the GSO window period, the SAs handed over the amount received by them on over-allotment of shares to the issuer company; the issuer company then made a further issue of shares at the cut-off price to the preissue shareholders who had lent their shares to the SA; finally, the SA closed the GSO bank account and the GSO, without any profit or loss. (See Table No. 3)

However, the number of companies that included GSOs in their IPO programmes in India was so small in comparison to the IPOs during the period that was studied (4.93%) that it was not possible to make any meaningful generalizations.

VII- Reasons for indifference towards GSOs

The data reveals that there is a case for issuer companies and merchant banks to avail the facility of GSOs to reassure investors, especially RIIs, and to discourage them from exiting the capital markets. What then is the reason for this indifference to GSOs on the part of issuer companies and merchant banks? From our interaction with market participants and merchant banks, various reasons emerged, such as the uncertainty about the effects of GSOs, the interference with market forces, the unfair advantage to merchant banks, the merchant banks' unwillingness to bear additional responsibility, the lack of incentives, the absence of market discipline, and so on. These reasons are discussed in some detail in the rest of this section.

A.Uncertainty about impact of GSOs

Our interviews with merchant bankers revealed that many issuer companies and quite a few merchant banks were unsure of the effects of GSOs. There was a feeling that the GSOs facility was highly constrained by the limit of 15% over-allotment and the 30-day stabilisation period. The general opinion was that there was no guarantee that the stabilisation programme would in fact be successful. In this scenario, these issuer companies and merchant banks felt that the panic and fear of the retail individual investors (RIIs) would only increase.

B.Interference with free play of market forces

Some investors felt that the practice of GSOs was questionable as it artificially propped up share prices, thereby interfering with the free play of market forces. It was suggested that starting from the pre-SEBI days, RIIs were led to believe that investing in an IPO would guarantee them positive initial returns. The GSO would merely reinforce these attitudes. Further, any aftermarket price stabilisation would deprive "value investors" from purchasing shares from naïve investors when the price falls in the immediate aftermarket.

C.Unfair advantage for merchant banks

Merchant banks that are designated as stabilising agents get high fees for availing of the GSOs. Such high fees for merchant banks were felt to be unjust as they face limited risk in implementing GSOs

D.Unwillingness of merchant banks to accept additional responsibility

The issuer companies and merchant banks that we interacted with felt that the legal and regulatory compliances were cumbersome, and that the consequent risks had increased manifold. In this scenario, they were not prepared to take any additional responsibility for a facility that was optional to begin with.



E. Lack of incentives

According to the GSO regulations, merchant bankers are not allowed to earn a profit from the aftermarket price stabilising activity. SEBI does not permit merchant bankers to make money in trading. They will have to buy the stock if the price falls below the offer price, but they are not allowed to sell even if the stock value goes up. We are required to stabilise the price around the offer price for which we get a fixed fee" Any profits arising from the price stabilisation activity need to be transferred to the Investor Protection and Education Fund (IPEF) established by the SEBI. In this scenario, issuer companies, promoters and pre-listing shareholders, and merchant banks did not see any incentive to opt for GSOs.

F. Absence of market discipline

In a mature market, if the aftermarket price of the shares falls significantly, the investors would hold the merchant banks responsible for the same. In such an event, the credibility of the merchant banks would take a hit. This would adversely affect their chances of getting further business because investors would keep away from the issues managed by them.

However, investors in India, especially the RIIs, appear to be indifferent to ascribing responsibility. In the face of this lack of market discipline, merchant banks in India have no reason to shirk the additional responsibilities associated with GSOs and talk about the lack of incentives.

VIII- Suggestions

The GSOs provision was introduced by the SEBI in 2003 as a mechanism for reassuring RIIs that the aftermarket price of the shares they were allotted in an IPO would be maintained at least in the first month of listing. However, we found that most issuer companies and merchant banks were indifferent to GSOs, and such options were rarely availed. Various reasons for this indifference emerged, such as the uncertainty about the effects of GSOs, the unwillingness to bear additional responsibility, the lack of incentives, the absence of market discipline, and so on.

Based on our findings, we propose the following suggestions: make GSOs mandatory; control flipping by qualified institutional buyers (QIBs); disclose the track record of merchant banks; and tighten IPO norms, especially for small IPOs.

A.Make green shoe options mandatory

On the face of it, the suggestion to make GSOs mandatory may sound preposterous to many people. Currently, GSOs are not mandatory in any country. However, given the SEBI's objective of increasing the participation of RIIs, and the peculiar nature of the capital markets in India, we feel that the suggestion to make GSOs mandatory is reasonable.

B.Control QIB flips

When an issuer company is unable to satisfy the eligibility criteria related to past track records, they are allowed to make an IPO if they are able to get qualified institutional buyers (QIBs) to make a significant investment. The implicit assumption is that the QIBs are sophisticated investors who would take a long-term investment view of the investment.

C.Disclose track record of merchant banks

Merchant banks seemed to be indifferent to the aftermarket price movement. They claimed this indifference was justified because the compliance work of IPOs was already voluminous, and they were not in any position to assume additional responsibilities and risks. Merchant banks in India are able to get away with this attitude because the investors do not show any interest in disciplining them, for instance, by boycotting the issues managed by them. In order to facilitate such market discipline, the regulator may need to mandate an additional disclosures requirement regarding the aftermarket returns for each merchant bank.

D. Tighten norms for small IPOs

The performance of small IPOs (with an issue size less than INR 100 crore) has been dismal. There is a definite need to re-examine the IPO norms for such small issues. The implicit assumptions and expectations from QIBs and project appraisal agencies in such small issues also need to be re-examined. Further, this issue needs to be studied in detail by independent researchers.

IX-Conclusion

Based on the analysis of the aftermarket price performance of the companies that availed of the GSO facility in their IPO programmes, it could be concluded that GSOs were not effective in stabilising the prices in the period immediately following the listing date. However, broad generalizations cannot be made due to the small size of the companies, both in absolute terms and as a proportion of the companies making IPOs. of the companies that did not include the GSO facility in their IPO programmes, a disproportionately large number of companies performed poorly. This led us to propose that GSOs be made mandatory; some penalties would need to be imposed on QIBs who sell in the immediate aftermarket; merchant bankers would need to disclose their track record; and the IPO norms would have to be tightened, especially for small issues.

References:

- 1. Website of Security Exchange board of India
- 2. Website of National Stock Exchange of India
- 3. News paper Economic Times
- 4. News Paper Financial Express
- 5. Website of Bombay Stock Exchange





Table 1: Number of Companies that Opted for GSOs in their IPOs in India from Aug. 14, 2003 to Dec. 31, 2011

Year	No. of Compines of IPOs	Opted for GSOs		
		of companies opting for GSOs	Percentage of companies opting for GSOs	
2003	3	0	0%	
2004	21	2	9.52%	
2005	43	3	6.98%	
2006	60	6	10%	
2007	86	5	5.81%	
2008	30	0	0%	
2009	17	1	5.88%	
2010	66	1	1.51%	
2011	39	0	0%	
Total	365	18	4.93%	

Table 2: List of Companies that Opted for GSOs in their IPOs in India from Aug.14, 2003 to Dec. 31, 2011

No.	Issuer COMPANY	Opening Date	Listing Date
01	Tata Consultancy Services Ltd.	29 Jul 2004	25 Aug 2004
02	Deccan Chronicle Holdings Ltd.	25 Nov 2004	22 Dec 2004
03	3I Infotech Ltd.	30 Mar 2005	22 Apr 2005
04	HT Media Ltd.	04 Aug 2005	01 Sep 2005
05	Shree Renuka Sugars Ltd.	07 Oct 2005	01 Sep 2005
06	Entertainment Network (India) Ltd.	23 Jan 2006	15 Feb 2006
07	Jagran Prakashan Ltd.	25 Jan 2006	22 Feb 2006
08	B. L. Kashyap & Sons Ltd.	20 Feb 2006	17 Mar 2006
09	Prime Focus Ltd.	25 May 2006	20 Jun 2006
10	Parsvnath Developers Ltd.	06 Nov 2006	30 Nov 2006
11	Cairn India Ltd.	11 Dec 2006	09 Jan 2007
12	House of Pearl Fashions Ltd.	16 Jan 2007	19 Feb 2007
13	Idea Cellular Ltd.	12 Feb 2007	09 Mar 2007
14	Housing Development & Infrastructure Ltd.	28 Jun 2007	24 Jul 2007
15	Omaxe Ltd.	17 Jul 2007	09 Aug 2007
16	Brigade Enterprises Ltd.	10 Dec 2007	31 Dec 2007
17	Indiabulls Power Ltd.	12 Oct 2009	30 Oct 2009
18	Electrosteel Steels Ltd.	21 Sep 2010	08 Oct 2010

Table 3: Performance of Companies that Opted for GSOs in India from Aug. 14, 2003 to Dec. 31, 2011

No.	Issuer COMPANY					
01	Tata Consultancy Services Ltd.	25 Aug 04	850	00	23	0
02	Deccan Chronicle Holdings Ltd.	22 Dec 04	162	17	22	77.27
03	3l Infotech Ltd.	22 Apr 05	100	20	21	95.24
04	HT Media Ltd.	01 Sep 05	530	19	21	90.48
05	Shree Renuka Sugars Ltd.	01 Sep 05	285	00	21	0
06	Entertainment Network (India) Ltd.	15 Feb 06	162	00	20	0
07	Jagran Prakashan Ltd.	22 Feb 06	320	19	19	100.00
08	B. L. Kashyap & Sons Ltd.	17 Mar 06	685	00	18	0
09	Prime Focus Ltd.	20 Jun 06	417	23	23	100.00
10	Parsvnath Developers Ltd.	29 Dec 06	300	00	21	0
11	Cairn India Ltd.	09 Jan 07	160	21	21	100.00
12	House of Pearl Fashions Ltd.	19 Feb 07	550	20	20	100.00
13	Idea Cellular Ltd.	09 Mar 07	075	00	19	0
14	Housing Development & Infrastructure Ltd.	24 Jul 07	500	04	22	18.18
15	Omaxe Ltd.	09 Aug 07	310	04	21	19.05
16	Brigade Enterprises Ltd.	31 Dec 07	390	21	23	91.30
17	Indiabulls Power Ltd.	30 Oct 09	045	20	20	100.00
18	Electrosteel Steels Ltd.	08 Oct 10	011	18	21	85.71



Perception Of Unorganised Retailers Towards FDI In Multibrand Retailing In India

Dr. Pradeep Kumar Sharma * Vishwas Sharma ** Rishi Mishra***

Abstract - FDI in multi brand retail remained a most discussed topic in the last few years. Almost all unions of the unorganized retailers across the nation opposed it. This resistance of unorganized retailers gave a clear indication that all of them understand the impact of the FDI in multi brand retailing. This research is conducted to know whether unorganized retailers have clear understanding about FDI or not. This research work aims at giving a fair idea of the understanding of the local unorganized player in this particular matter. The study is exploratory in nature and was conducted in Indore city which is popularly referred as the business capital of Madhya Pradesh. The study is based on both primary and secondary data and structured questionnaire has been used to collect the primary data from respondents. Random and judgmental sampling has been used to conduct the research work. Data has been analyzed using pivoting methods in excel. The study concludes with the suggestions and recommendations for addressing the queries of the unorganized retailers and gaining their good faith in any further decision.

Keywords: - FDI, Multi brand Retailing, Unorganized Retailer. **Introduction-**

In 2004, The High Court of Delhi defined the term 'retail' as a sale for final consumption in contrast to a sale for further sale or processing (i.e. Wholesale). In other words retail can be defined as a sale to the ultimate consumer.

Thus, retailing can be said to be the interface between the producer and the individual consumer buying for personal consumption. India is a signatory to World Trade Organization's General Agreement on Trade in Services, which include wholesale and retail services, had to open up the retail trade sector to foreign investment. The government made a proposal to allow 51% FDI in multi brand retailing and raise the bar to 100%. The UPA government announced on 24 November 2011 the following:

- 51 % FDI in Multi- Brand retailing.
- Single brand foreign retailers, such as Apple and IKEA, can own 100 percent.
- Both multi-brand and single brand stores in India will have to source nearly a third of their goods from MSME.
- Multi-brand retailers must have a minimum investment of US\$100 million with at least half of the amount invested in the back end.

Almost all unions of the unorganized retailers across the nation opposed it which ultimately led to the rollback of FDI decision in multi brand retailing. Finally in December 2012, the UPA Govt. passed the FDI bill in parliament.

This research work has been conducted to understand the level of understanding of the local unorganized retailers with respect to FDI, more particularly towards multi-brand FDI, its effects, and to gauge their perception towards the Government's decision.

This study will help to identify the level of authenticity of the fact that all unorganized retail players, were against its FDI decision. It will help in adopting measures to increase the level of awareness and reduce inflated concerns of the affected.

Objectives -

- To study the awareness level of unorganized retailers towards FDI.
- To analyze the respondent's knowledge of Multi-Brand FDI and its effects.
- 3. To analyze source of information regarding FDI and its impacts.
- 4. To suggest positive measures to build consensus among unorganized retailers.

Literature Review-

Tomu Francis (2006) concluded that organized retailing refers to trading activities undertaken by licensed retailers, that is, those who are registered for sales tax, income tax, etc mainly involving the corporate-backed hypermarkets and retail chains, and also the privately owned large retail businesses.

Unorganized retailing, on the other hand, refers to the traditional formats of the retail industry involving example, the local kirana shops the corner stores, owner manned general stores, paan/beedi shops, convenience stores, hand cart and pavement vendors, etc. The latter involves a large majority of the Indian population that is involved in the retail industry.

^{*} Prof. of Com.Govt. Hamidia College, Bhopal ** Asst. Prof. SAIM&S, Indore *** Visiting Faculty, B Schools, Indore



According to Deepak Joshi (2012) majority of the unorganized retailers were having an opinion that FDI will have negative effect. Minority of them actually knew what FDI (Multi / Single Brand) is all about.

Surabhi Pareek (2011) Concluded in her research paper that the investment may lead to an interruption in the smooth flow of the economy and would lead to external dominance.

Tripathi, Salil (2011), suggests that critics of retail policy had five points; One, India doesn't need foreign retailers, since homegrown companies and traditional markets are doing the job well. Two, independent stores will close, leading to job losses. Three, profits will go to foreigners. Four, there will be sterile homogeneity and Indian cities will look like cities anywhere else. And five, the government hasn't built consensus.

Indian Brand Equity Foundation (2011), Reports, "India has been ranked as the fourth most attractive nation for retail investment among 30 emerging markets by the US-based global management consulting firm, A.T. Kearney, in its Global Retail Development Index (GRDI) 2011, and Indian retail sector accounts for 22 per cent of the country's gross domestic product (GDP) and contributes to 8 per cent of the total employment".

Research Methodology-

The study is based on both primary and secondary data. The required information was collected through the following sources:

Primary Data-

A non-probability, convenience sampling technique was used to administer the questionnaire. A structured questionnaire has been used by the researcher to identify awareness level of unorganized retailers about FDI, Multi brand and Single Brand FDI, their response towards government decision and the source of information of FDI.

Sample Size -

The initial data was collected from 200 unorganized retail players from Indore City. However for getting the meaningful and reliable insights the aware of FDI (172) were evaluated on other parameters.

Tools and Techniques-

The data collected through questionnaire were tabulated and analyzed by using pivoting methods in excel.

Data Analysis And Interpretation-

Awareness Level of FDI (See Graph No. 1)

The data analysis showed that 86% of the respondents had heard of FDI previously, while 14% had not heard of the FDI before. Based on this response, the questionnaire of the responds that were aware of FDI in India were analyzed further to gain deeper insights.

Perceived Effect of FDI Vis a Vis Education Level

(See Table No. 1.1)

52% of the respondents had an opinion that FDI will have negative effect while 15% said that it will impact positively, while 22% were unable to analyze what will happen. 38% of the total (Including Big and Small Shop owners) had a graduate and above degree while 20% were uneducated. 19% were below 10th and 23% were up to 12th. However it was interesting to note that overall 46% of uneducated said that FDI will impact negatively while only 61% of respondents with graduation and higher degree said it will impact negatively.

Knowledge Of Single And Multibrand FDI (See Table No. 1.2)

The respondents were asked whether they were aware of single and multi brand FDI concerns. Almost 44% of total respondents were aware of Multi/Single Brand and FDI. 38% respondents answered irrelevant.

Reaction Towards Governments Decision On Multibrand FDI (See Table No. 1.3)

55% of the Respondents were against The Multi Brand FDI, though only 44% as discussed earlier actually knew what multi brand FDI was. Only very few 8% of total supported Government saying it will benefit them.

Reaction Towards Governments Decision On Multibrand Fdi Vs Source Of Info (See Table No. 1.4)

38% of the Respondents got information on FDI from TV and Newspapers while 29% got from fellow Business Man and union leaders. 13% Got information from their family members and rest 20% from other sources. The co-relation of source of information and views of respondents for FDI gave an interesting outcome that almost 98% of the respondents who got information about FDI from Fellow Businessman and Union Leaders, voted against FDI. Almost 69% of the Respondents who got the info about the FDI through TV/Newspaper had almost a neutral view.

Perception Of Future Vs Reaction Towards Government's Decision (See Table No. 1.5)

Majority (50%) of the respondents had a view that Big will grow and smaller will perish, while others were almost divided equally in their perception i.e. Both Big & Small Players will benefit, Don't Know, and nothing will happen. When this perception was further analysed vis a vis their reaction towards Government's decision of allowing multi brand FDI, 77% of Respondents who were against FDI had a view that Big will grow and smaller will perish, while rest either Didn't had an idea or said nothing will happen and even both Big and Small will grow (The point to be considered here is though they had answered previously that they were against Government's Decision, however either they didn't knew the future scenario or had a conflicting view).



nss

Annual Turnover And Education Level (See Table No. 1.6)

54% of the Respondents were having annual turnover below 2 lakhs, 22% Respondents had turnover between 5 - 10 lakhs, 17% were having 10 lakhs and above while 7% were having 2-5 lakhs annual turnover. From education point of view 38% were having qualification above graduation, 23% upto 12th, 19% below 10th.

Action Against Declining Business Vs Source Of Information (See Table No. 1.7)

52% Did not had any idea what they shall do if business declines, 34% had a view that ultimately they will have to switch their present business and 10% hoped that reducing cost will help them to stay in the business. While 4% were adamant saying it won't happen (FDI cannot impact them). The Co-relation of the responses for the actions that respondents were willing to opt in case their business is affected negatively with the source of information gave very meaningful insights. The 67% of respondents who had a view of Reducing Costs had Newspapers/TV as their source.

Action Against Declining Business Vs Annual Turnover (See Table No. 1.8)

35% of the respondents who said that they will switch their occupation were having turnover below 2lakhs. It is important to note that as per table 1.7, the source of Information for 62% of such respondents (switch occupation) was other than TV and Newspapers.

Findings Of The Research

- The research shows that only 86% of the initial respondents were aware of FDI and 14% did not had any idea of FDI.
- 52% of the respondents (out of 172) were having an opinion that FDI will have negative effect and 15% said that it will impact positively.
- The study reveals that 46% of uneducated respondents said that FDI will impact negatively while only 61% of respondents with graduation and higher degree said it will impact negatively.
- 44% of respondents actually knew what FDI (Multi / Single Brand) is all about, though 55% of them were against The Multi Brand FDI.
- 38% of the Respondents got information on FDI from TV and Newspapers while 29% got from fellow Businessmen and union leaders. 13% got information from their family members and rest 20% from other sources.
- The study reveals that almost 98% of the respondents who got information about FDI from Fellow Businessman and Union Leaders, voted against FDI, while around 69% of the respondents who got the info about the FDI through

- TV/Newspaper had almost a neutral view.
- 50% of the respondents had a view that Big will grow and smaller, while others were almost divided equally in their perception.
- The survey revealed that 78% of respondents who were against FDI had a view that Big will grow and smaller will perish, while others, who were actually against FDI, either didn't knew what will be the future scenario or their future perception posed a conflicting view.
- 52% of the respondents did not had any idea what they shall do if business declines, 34% had a view that ultimately they will have to switch their present business and 10% hoped that reducing cost will help them to stay in the business.
- The 67 % of respondents who were having a view of reducing costs had Newspapers/TV as their source of information of FDI.
- The study reveals that all those who were against FDI and had said to Switch their Occupation, got the updated information about FDI from sources other than TV/ Newspapers. Further 35% of them were having turnover below 2 lakhs.

In a nutshell, all the respondents were not against FDI, the most of the respondents who were against FDI(multibrand) and tout their negative impacts were not having their own understanding of the scenario, they were responding based on what they are being made to visualize by others (mostly fellow businessmen and union leaders). In this case, Newspaper and TV have been most authentic source of information. Newspaper and TV have played an important role in shaping the understanding the views of the respondents in a positive manner.

Recommendations/suggestions

- There is an urgent need of increasing the level of understanding of FDI and implications.
- Alternative means such as local newspapers, regional TV channels, Community radios should be used to increase the level of awareness about FDI.
- Panchayati Raj institutions can play an important role in disseminating positive information and creating awareness in this regard.
- Programmes organized by MSME, specially focused on small unorganized retailers should be made; so as to help the local retailers increase efficiency and build competitive advantage.
- Government should permit FDI in multibrand retailing in a phased manner; phased opening of the sector for FDI will facilitate the fellow unorganized player to gauge the impact, if any and adjust accordingly.



Conclusion

Everything has its pros and cons; the same is the case of permitting multi brand FDI in India. however the merits and demerits of permitting FDI has not been analysed properly, and voices which are deemed to be of the affected ones are actually of the mediators or politicians, who are known for voicing such concerns for their own benefits. The allowing FDI in multibrand retail is going to have a positive impact for consumers and medium and small suppliers. It may control inflation, increase jobs, reduce wastages, and improve supply chain. Unorganized retailers have lots of confusions about FDI. There is an urgent need to make them aware of FDI in multibrand retail.

200

150

100

50

O

References-

- Deepak Joshi (2012), IJRCM- FDI in Multibrand Retailing in India: Perception of the Unorganised Retailers in Business capital Of Uttarakhand.
- DIPP. (2010). Discussion Paper On Foreign Direct Investment (FDI) In Multi-Brand Retail Trading. New Delhi: Department of Industrial Policy and Investment Promotion
- 3. Tomu Francis (2006): Single Brand Retail. Viewed on March, 25, 2012 http://www.businessgyan.com/node/
- 4. Tripathi, Salil (2011): India needs Super markets, London: The Guardian, Viewed on March 21, 2012 http:/ /www.guardian.co.uk/globaldevelopment/povertymatters/2011/nov/29/india-needs-foreign-owned-super markets.

172 Aware of FDI Not Aware of FDI 28

Awareness Level of FDI (Graph No. 1)

Awarenee level of FDI Source: Primary Data Table 1.1: Perceived Effect of FDI Vis a Vis Education Level

Will FDI in Retail Affect you	Uneducated	Below X	Up to XII	Graduation & Above	Grand Total	% of Respondents
Don't Know	9	6	1.2	11	38	22%
No	7	3	6	2	18	11%
Yes, in a +ve way	3	5	6	12	26	15%
Yes, in a -se way	16	19	1.5	40	90	52%
Total No. Respondents	35	33	39	65	172	
% of Respondents	20%	19%	23 %	38 %	100%	100%

TABLE 1.2: Knowledge Of Single And Multibrand FDI

Do you Know Multi/Single Brand FDI	Blank	No	Yes (Irrelevant Answer)	Yes (Relevant Answer)	Grand Total
Uneducated	3	9	17	6	35
Below X	3	5	11	14	33
up to XII	1	6	8	24	39
Graduation & Above	2	3	29	31	65
Total No. Respondents	9	23	65	75	172
% of Respondents	5%	13%	38%	44%	100%

Table1.3: Reaction Towards Governments Decision On Multibrand FDI

Do you Favor the Govt's decision to allow FDI in Multi brand Retail	Uneducated	Below X	Up to XII	Graduation & Above	Grand Total	% of Respondents
Against it	25	25	18	26	94	55%
can't say	2	1		2	5	3%
Neutral	8	3	17	32	60	35%
Yes, it will benefit us		4	4	5	13	7%
Total No. Respondents	35	33	39	65	172	
% of Respondents	20%	19%	23%	38%	100%	100%

Table 1.4: Reaction Towards Govt. Decision On Multibrand FDI Vs Source Of Info

Response For:	Governmen	nt Decision fo				
Source of FDI Info	Against it	can't say	Neutral	Yes, it will benefit us	Grand Total	% of Respondents
Family Members	12		9	1	22	13%
Fellow Businessmen & Union Leaders	49			1	50	29%
Newspaper / TV	14		45	6	65	38%
Other Sources	19	5	6	5	35	20%
Total No. Respondents	94	5	60	13	172	
% of Respondents	55%	3%	35%	7%	-	100%

Table 1.5: Perception Of Future Vs Reaction Towards Government's Decision

Response For:	Governmen	Government Decision for Allowing Multi Brand FDI				
Future Scenario	Against it	can't say	Neutral	Yes	Grand Total	% of Respondents
Big will grow and smaller will Perish	67		16	3	86	50%
Both Big & Small players will benefit	2		18	8	28	16%
Don't Know	13		19	2	34	20%
Nothing will happen	12	5	7		24	14%
Total No. Respondents	94	5	60	13	172	
% of Respondents	55%	3%	35%	7%		100%





Table 16:	Annual	Turnovor	And E	ducation	Lovol
Table 1 b.	Annuai	IIIrnover	And Ed	nucation	i evei

Annual turnover & Education	Uneducated	Below X	Up to XII	Graduation & Above	Grand Total	% of Respondents
10 Lkhs and above	4	7	9	9	29	17%
5 – 10 Lkhs	2	1	6	29	38	22%
2 - 5 Lkhs	4	6		2	12	7%
Below 2 Lkhs	25	19	24	25	93	54%
Total No.Respondents	35	33	39	65	172	-
% of Respondents	20%	19%	23%	38%	100%	100%

Table 1.7: Action Against Declining Business Vs Source Of Information

Response For:	Govern	ment Decision for A	Allowing Multi	Brand FDI		
Source of FDI Info	Family Members	Fellow Businessmen & Union Leaders	Newspaper / TV	Other Sources	Grand Total	% of Respondents
Don't Know	10	29	31	19	89	52%
It won't Happen		5		2	7	4%
Reduce Costs	1	2	12	3	18	10%
Switch my occupation	11	14	22	11	58	34%
Total No. Respondents	22	50	65	35	172	
S% of Respondents	13%	29%	38 %	20%		100%

Table 1.8: Action Against Declining Business Vs Annual Turnover

Response For:		Annual To	urn Over			
What will be the action if Business Declines	10 Lkhs and above	5-10 Lkhs	2 - 5 Lkhs	Below 2 Lkhs	Grand Total	% of Respondents
Don't Know	17	11	8	53	89	52%
It won't Happen	3	4			7	4%
Reduce Costs		4	2	12	18	10%
Switch my occupation		21	2	35	58	34%
Total No. Respondents	20	40	12	100	172	
S% of Respondents	12%	23%	7%	58%		100%



Rural Women Enterprenership Development in India

Dr. Ravi Prakash Pandey *

Introduction -

The Government of India (1984) has defined women entrepreneur as "an enterprise owned and controlled by a women having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to women".

This definition does not suit to rural women entrepreneurs in India. Any rural women or a group of rural women which innovates, limitates or adapts an economic activity may be referred as a rural women entrepreneur. The educated women do not want to limit their lives in the four walls of the house. They demand equal respect from their partners. However, Indian women have to go a long way to achieve equal rights and position because traditions are deep rooted in Indian society where the sociological set up has been a male dominated one. Women are considered as weaker sex and are always made to depend on men folk in their family and outside, throughout their life. The Indian culture made them only subordinates and executors of the decisions made by other male members, in the basic family structure. While at least half the brainpower on earth belongs to women, women remain perhaps the world's most underutilized resource. Despite all the social hurdles, India is brimming with the success stories of women. They stand tall from the rest of the crowd and are applauded for their achievements in their respective field. The transformation of social fabric of the Indian society, in terms of increased educational status of women and varied aspirations for better living, necessitated a change in the life style of Indian women. She has competed with man and successfully stood up with him in every walk of life and business is no exception for this. These women leaders are assertive, persuasive and willing to take risks. They managed to survive and succeed in this cut throat competition with their hard work, diligence and perseverance. Ability to learn quickly from her abilities, her persuasiveness, open style of problem solving, willingness to take risks and chances, ability to motivate people, knowing how to win and lose gracefully are the strengths of the Indian Women Entrepreneurs.

Concept Of Women Entrepreneurs-

Men & Women both are two wheels of society and contribution of both is very essential for building healthy nation. There are around seven lakh villages in India and more than 70% of our population lives in villages. In rural sector 56% of the male and 33% of the female were in the labor force. About 66% of the female population in the rural sector is idle & unutilized. Even after 56 years of the independence women in India are struggling for entrepreneurial freedom. They have to face various socio-economic problems. Women entrepreneurs may be defined as the women or a group of women who initiate, organize and operate a business enterprise. The Government of India has defined women entrepreneurs as an enterprise owned and controlled by women having a minimum financial interest of 51 per cent of the capital and giving at least 51 per cent of the employment generated in the enterprise to women. Women entrepreneurs engaged in business due to push and pull factors which encourage women to have an independent occupation and stands on their on legs.

A sense towards independent decision-making on their life and career is the motivational factor behind this urge. Saddled with household chores and domestic responsibilities women want to get independence. Under the influence of these factors the women entrepreneurs choose a profession as a challenge and an urge to do something new. Such a situation is described as pull factors. While in push factors women engaged in business activities due to family compulsion and the responsibility thrust upon them.

Objectives And Research Methodology Of The Study-

The study is based on secondary data which is collected from the published reports of RBI, NABARD, Census Surveys, SSI Reports, newspapers, journals, websites, etc.

The study was planned with the following objectives:

- To evaluate the factors responsible for encouraging women to become entrepreneurs
- To study the impact of assistance by the government on women's entrepreneurship.
- To study the policies, programmes, institutional networks and the involvement of support agencies in promoting women's entrepreneurship.
- To critically examine the problems faced by women entrepreneurs.

Reasons For Women Becoming Entrepreneurs -

- Self identify and social status.
- 2. Education and qualification.
- Support of family members.
- 4. Role model to others
- 5. Success stories of friends and relatives.
- 6. Bright future of their wards.
- 7. Need for additional income.
- 8. Family occupation.
- Government policies and procedures.



- 10. Freedom to take own decision and be independent.
- 11. Employment generation.
- 12. New challenges and opportunities for self fulfillment.
- 13. Innovative thinking.

Growth in women Entrepreneurship-

In recent years the entrepreneurship has gained wide popularity on the whole globe. The rate of becoming entrepreneurs in women is more compared to men. (Renzulliet a1 2000)In North America 38 percent & small businesses are owned by women (Brush & Hierarch, 1999) the growth rate in women enterprises in some of the developing countries are higher as compared to the developed countries. According to ILO Statistics the growth rate is 24% in Malaysia, 30% in Thailand & 36% in Philippines & 42% in Indonesia. The growth rate was highest in the Tamil Nadu state of India. It was 18% in 2001.

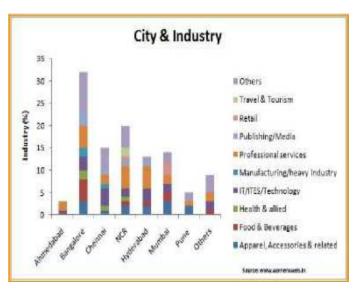
Challenges Faced by Rural Women Entrepreneurs

The main challenges faced by rural women in business are educational & work background. They have to balance their time between work & family. Some of the challenges faced by rural entrepreneurs are as

- 1. Growth of Mall culture- The greatest deterrent to rural women entrepreneurs is that they are women. India is a kind of patriarchal male dominant society. Male members think it is a big risk financing the ventures run by women.
- 2. Illiteracy- The literacy rate of women in India is found at low level compared to male population. The rural women are ignorant of new technology or unskilled. They are often unable to do research & gain the necessary training (UNIDO, 1995, p1). According to the economist, women are treated as second-class citizens which keeps them in a" Pervasive cycle of poverty". The uneducated Rural Women do not have the knowledge of measurement and basic accounting.
- 3. Low Ability to Bear Risk-Women in India lives protected life. She is taught to depend on male members from birth. She is not allowed to take any type of risk even if she is willing to take and has ability to bear. Economically they are not self dependent.
- 4. Lack of Infrastructure and Rampant Corruption These are also the other problems for the rural women entrepreneurs. They have to depend on office staffs and intermediaries to get the things done, especially the marketing and sales side of business. Here is the more probability for business fallacies like the intermediaries take major part of the surplus or profit. 5. Lack of Finance- The financial institutions discourage women entrepreneurs on the belief that they can at any time leave their business. Therefore, they are forced to rely on their own savings, loan from their relatives and family friends. Women are developing city wise and industrywise due to some limitations.

Schemes of the Government

At present, the Government of India has over 27 schemes



for women operated by different departments and ministries. Some of these are: -

- Integrated Rural Development Program (IRDP)
- Khadi And Village Industries Commission (KVIC)
- Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM)
- Prime Minister's Rojgar Yojana (PMRY)
- Entrepreneurial Development program (EDPs)
- Management Development programmes
- Women's Development Corporations (WDCs)
- Marketing of Non-Farm Products of Rural Women (MAHIMA)
- Assistance to Rural Women in Non-Farm Development (ARWIND) schemes
- Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD)
- Working Women's Forum
- Indira Mahila Yojana
- Indira Mahila Kendra
- Mahila Samiti Yojana
- Mahila Vikas Nidhi
- Micro Credit Scheme
- Rashtriya Mahila Kosh
- SIDBI's Mahila Udyam Nidhi
- Mahila Vikas Nidhi
- SBI's Stree Shakti Scheme
- NGO's Credit Schemes
- Micro & Small Enterprises Cluster Development Programmes (MSE-CDP).
- National Banks for Agriculture and Rural Development's Schemes
- Rajiv Gandhi Mahila Vikas Pariyojana (RGMVP)
- Priyadarshini Project- A programme for Rural Women Empowerment And Livelihood in Mid Gangetic Plains' NABARD - KFW- Seva Bank project"

Her mantra of success, Just remember that work is worship - whatever you do, be it at home or outside, treat it respectfully.



Conclusion

It can be said that today we are in a better position wherein women participation in the field of entrepreneurship is increasing at a considerable rate. Efforts are being taken at the economy as brought promise of equality of opportunity in all spheres to the Indian women and laws guaranteed equal rights of participation in political process and equal opportunities and rights in education and employment were enacted. But unfortunately, the government sponsored development activities have benefited only a small section of women i.e. the urban middle class women. Women sector occupies nearly 45% of the Indian population. At this juncture, effective steps are needed to provide entrepreneurial awareness, orientation and skill development programs to women. The role of Women entrepreneur in economic development is also being recognized and steps are being taken to promote women entrepreneurship.

Resurgence of entrepreneurship is the need of the hour emphasizing on educating women strata of population, spreading awareness and consciousness amongst women to outshine in the enterprise field, making them realize their strengths, and important position in the society and the great contribution they can make for their industry as well as the entire economy. Women entrepreneurship must be moulded properly with entrepreneurial traits and skills to meet the changes in trends, challenges global markets and also be competent enough to sustain and strive for excellence in the entrepreneurial arena.

If every citizen works with such an attitude towards respecting the important position occupied by women in society and understanding their vital role in the modern business field too, then very soon we can pre-estimate our chances of out beating our own conservative and rigid thought process which is the biggest barrier in our country's development process. We always viewed that a smart woman can pick up a job any day, but if she becomes an entrepreneur she can provide a livelihood to 10 more women at least..!! Highly educated, technically sound and professionally qualified women should be encouraged for managing their own business, rather than dependent on wage employment outlets. The unexplored talents of young women can be identified, trained and used for various types of industries to increase the productivity in the industrial sector.

In this time women are progressing every area then why we give a chance lead some business unit. So many women are leading like Indira Noori, chanda Kocher, in business and give a highest return to that business unit. In this time so many area where women are dominated and give extraordinary result to the society because in nature he is having patience, good logical thinking, work done in a perfection manner, sincerity, follow the command, this the qualities which is given by a nature. In my view must be give

a chance for the rural development in India because women power can be utilized at a optimum level. Women are so good for her work, science, politics, economics, medical science, space research work, military operation, etc. In other words Rural area development then India become a developed country.

Refernces-

Arora, R.;and Sood, S.K.(2005), Fundamentals of Enterpreneurship and Small Business Baporikar, N. (2007) Entrepreneurship Development & Project Management-Himalaya Publication House Brush, C. (1997). Taori ,Dr. Kamal - Entrepreneurship in the Decentralised Sector Women-Owned Businesses: Obstacles and Opportunities, Journal of Developmental Entrepreneurship.

Desai, V: (1996) Dynamics of Entrepreneurial & Development & Management Himalaya publishing House - Fourth Edition, Reprint Dhameja S K (2002), Women Entrepreneurs: Opportunities, Performance and Problems, Deep Publisher (P) Ltd., New Delhi. Gordon E. & Natarajan K.: (2007) Entrepreneurship Development - Himalaya Publication House, Second Revised edition. Hattangadi Dr. Vidya: (2007) Entrepreneurship - Need of the hour, Himalaya Publication House, First edition. Schemes and Programmes of Ministry of Small Scale Industries and Ministry of Agro & Rural Industries, Govt. of India Kalyani Publishers. Kumar, A (2004), "Financing Pattern of Enterprises Owned by Women Entrep reneurs". The Indian Journal of Commerce, Vol. 57, No

Websites

- * info@ijrcm.org.in accessed on 19 April 2011
- * www. Smallindustryindia.com accessed on 4 April 2011
- * www.dcmsme.gov.in/schemes/Schemes for the development and promotion of women entrepreneurs. PDF accessed on 4 April 2011
- * www.ghallabhansali.com accessed on 4 April 2011
- www.icfaijournals.com accessed on 4 April 2011
- * www.imer.com accessed on 7 April 2011
- www.ludhianadistrict.com/articles/article1184678891.html accessed on 20 April 2011
- * www.ludhianadistrict.com/personality/rajni-bector.php accessed on 20 April 2011
- www.nawbo.org. "About NAWBO" National Association of Women Business Owners accessed on 2 April 2011
- * www.newsweek.com/2010/07/06/women-will-rule-theworld. accessed on 20 April 2011
- * www.referenceforbusiness.com/small/Sm-Z/Women-Entrepreneurs.html accessed on 20 April 2011
- * www.udyogini.org accessed on 2 April 2011

{Approved by Dr. P.P.Pandey(Dean/professor) Awadesh Pratap Singh University Rewa(M.P) Govt.P.G.College Maihar Distic Satna (M.P)}

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013



Indian Agriculture Sector: After Economic Reforms

Dr. Vinod Kumar Sharma*

Although agriculture now accounts for only14 per cent of Gross Domestic Product (GDP), it is still the main source of livelihood for the majority of the rural population. It is accounted for about 58 per cent employment in the country according to Census 2001. As such rapid growth of agriculture is critical for inclusiveness. There are several ways to assess performance of agriculture sector.

The most common indicator is at what rate the sector is growing and whether growth rate is decelerating, stagnant or accelerating. The average of annual growth rates of GDP in agriculture and allied sectors during the XI Five Year Plan is now placed at 3.3%. This is short of the target of 4 per cent but is significantly better than the achievement of 2.4 % in the X Plan. Growth rates and average growth of five years since the beginning of XI Plan have been higher than long run growth rate in Indian agriculture, which is 2.86. Indian agriculture faced serious slowdown during 1996-97 to 2005-06. There is an unambiguous recovery from 2006-7 onward.

The First Five-Year Plan accorded highest priority to agriculture and allocated substantial part of the plan outlay to this sub-sector. The importance and priority given to agriculture was diluted in the Second and Third Five Year Plans, and as a consequence, the sub-sector witnessed a deceleration during sixties (1.7%). This led to severe shortage of food grains, and the country was compelled to import huge quantities of food grains.

The food aid from the USA came with conditionality, which influenced economic and foreign policies of the country, and forced the country to put greater efforts to increase food grain production. In mid-sixties, a new agricultural strategy was adopted which emphasized on spreading dwarf and highyielding varieties (HYVs) of wheat and rice.

The new strategy paid dividends and resulted in wellacclaimed 'green revolution'. The crop sub-sector, which was growing at an annual rate of 1.8 per cent in the seventies, grew at the rate of 2.2 per cent in 1980s and 3.0 per cent in the nineties. Though the same growth in the crops was maintained, it fell short of the targeted growth rate of 4 per cent in the eleventh five year plans. The policy support, adoption of improved production technologies and public

investment in infrastructure, research and extension contributed to growth in the agricultural sector. However, investment on agriculture declined throughout the nineties, leading to a slowdown in the agricultural growth especially in the late nineties. The magnitude of secular decline in growth variability over the last 30 years is also important.

This is now less than a third of its peak. A major role must have been played by the increase in irrigation from about 20 per cent of arable area in 1981 to 35 per cent today, based mainly on groundwater.

However, since water tables have fallen and temperatures risen, the extent of variability decline is surprisingly large. Even assuming zero variability on irrigated land, this implies that variability on rain-fed land must have reduced very substantially.

Crop Sector More than half of cropped area in India is rain fed. As was seen in the case of GDP agriculture, crop sector output also followed sharp deceleration in growth after 1996-97.

There is some increase in the rate of growth of crop output during 11th Plan. Another notable change in growth pattern is that the effect of severe drought of 2009-10 was moderate compared to the previous droughts of similar magnitude.

This indicates increased resilience of agriculture to weather shock. Crop Productivity Performance of crop sector has also been quite variable across crops. Also, area under some crops is rising while some crops show decline. Thus growth in production of various crops shows much higher variation than the variation in growth in productivity.

Trend growth rate in productivity of major crops was estimated by fitting log linear trend to two years moving average of productivity beginning with 1999-00. Still, it is pertinent to mention that, despite this smoothening, growth rates can turn out to be totally different with small change in the period. Cotton topped the list with more than 10 per cent annual growth in its productivity, a Bt driven phenomenon which now occupies more than 90 percent area under cotton. Bajra comes second with more than 4 per cent annual growth

Productivity of groundnut, soyabean and jowar is increased

nss

by more than 3 per cent during 2001 to 2008-9. Maize and sunflower maintained per cent growth in productivity during the last decade. Among the two major cereals, productivity of rice show annual growth of 1.69 percent but wheat productivity experienced less than half a percent growth. The increase in productivity of pulses remained unimpressive. Productivity of sugar cane remained stagnant.

Factors Affecting Agriculture Growth

An examination of various factors affecting agriculture at national level shows that following factors have contributed in a big way to the recovery of growth rate in recent years:

Terms of trade

Terms of trade for agriculture witnessed a sharp decline during late 1990s to 2004-05. There has been a turnaround in TOT after this. This is evident from terms of trade for agriculture sector relative to non-agriculture and from ratio of food price index relative to prices of non-food items. Share of agriculture in total GDP at 2004-05 prices was 18.9 during 2004-05. During 2010-11 it declined to 14.3 per cent at constant prices but rose to 19.0 per cent at current prices. The difference in share of GDP in agriculture at current and constant prices show that farm gate prices received by farmers have turned 30 percent higher than non-agriculture prices during six years after 2004-5.

Public and private investments-

Indian agriculture had suffered a stagnation and even decline in public investment in agriculture for more than two decades beginning with 1980-81). As a result share of public investments in agriculture dropped from more than 5 per cent to 1.6 percent during 1980-81 and 2000-01. Private sector investment also showed phases of stagnation during this period.

This long stagnation and decline in public investment was reversed during 2004-05 when public investments in real terms (1999-00 prices) were raised by almost 30 per cent in one shot. Both public as well as private investments witnessed sharp increase after 2003-04. However, public investments showed decline again in year 2008-09.

Quality Seed and Hybrid-

Seed is carrier of technology. During last six years strong emphasis and support has been provided to seed sector. This has resulted in success in two fronts. One, production of quality seed doubled in four years after 2004-5). Two, public sector has taken on private sector to compete in seed market.

As a result share of private sector in seed production has

gone down in the last five years. Still ratio of quality seed to total seed is much lower than norm and there is a tremendous scope to raise productivity and production by raising share of quality seed in total seed used by farmers.

The data for the seven years i.e., after 2001-02 show that the gap between private sector and public sector in development of hybrid considerably narrowed down compared to the earlier period even though private sector continued their dominance in cross pollinated crops like cotton, maize, pearl millet and sorghum.

Recommendations-

- There is also a need for policies and strategies to adjust to the new types of technologies, changing demand patterns, upcoming value chains and supermarkets, revolution in communication technology, institutional innovations and globalization and other evolving changes in the system surrounding agriculture.
- It is essential for sustainable production activity in long run that India focus on farmers and natural resource system, comprising land, water, vegetation, which form the production base of agriculture. Unless growth and development of farming leads to improvement in welfare of farmers, it cannot be sustained.
- Agriculture diversification towards high value agricultural commodities like fruit, vegetables and dairy products hold vast potential to accelerate growth and improve farm income in the country.
- Growth in output and farm income depends upon a large number of factors viz. prices of output and inputs, technology and other non-price factors. Raising growth requires remunerative and assured pricing environment for output, access to improved technology, application of quality inputs and machinery because growth comes primarily from the increase in productivity.
- Terms of trade for agriculture during 1997 to 2005 remained adverse and are identified as one of the factors for poor performance of agriculture during this period. Till some big breakthrough in technology takes place, agriculture growth will be led by price incentives. Therefore, in order to maintain the tempo of growth, agricultural prices should not be suppressed.
- India would need to raise public investment to 4% of GDP agriculture. Public investments are falling short of this target which needs to be met at the earliest.
- Technology is the prime mover for growth. Considering



- the costs and constraints of resources such as water, nutrients and energy, the genetic enhancement of productivity should be coupled with input use efficiency. This can be made possible only by creation and utilization of new and improved technology.
- There is need to raise supply of power to rural areas and agriculture sector and to check erratic supply, unscheduled cut and low voltage. This restricts exploitation of irrigation potential in several areas and adoption of efficient technologies like drip and sprinkler. Free or highly subsidised fixed tariff for electric power results in inefficient use of power and also results in indiscriminate use of scarce water resources which has serious implications for future availability of water
- Seed is the basic input to raise productivity. In most of the crops use of quality/certified seed in total seed use is awfully low. Inadequate availability at or near to villages, high prices and spurious or low quality seed are the major constraints in promoting use of seed.
- In Central and Eastern states having a large potential

- like Bihar, East Uttar Pradesh, Orissa, Assam, Chattisgarh and West Bengal, marketing infrastructure is very underdeveloped and private trade is exploitative. As such, the incentives for the adoption of new technology in such areas are very weak. In order to usher in green revolution in these states farmers need to be assured of incentive structure.
- Evidence from field observations in various parts of the country shows that at peak times either adequate labour is not available or it is available at very high wage rate.. Thus, despite, labour abundance and poverty in the countryside, farmers face difficulties in getting hired labour. Policies that reduce availability of labour for agriculture and hurt production prospects need to be reoriented.

References-

- 1. Economic survey 2011-12
- 2. Draft of 12th Five year plan
- Working papers



A Correlational Study Of Stress And Adjustment Of Nursing College Students

Dr. Ajay Kumar Chaudhary* Nisha Mod**

Abstrat - The present study was undertaken to analyze the correlation between stress and adjustment in Nursing College students. The study was purposively conducted on 30 students of Balaji Nursing College of Udaipur city. The data was collected randomly on nursing college students using Bist Battery of Stress Scale constructed by Dr Abha Rani Bist and the Adjustment Inventory by Dr A.K.P. Sinha and Dr R.P. Singh. The data was analyzed using Mean, S.D. and t-test. The analysis of data showed that the nursing college students are experiencing high level of academic stress and maladjustment in various areas of adjustment. Result shows that there is significant correlation between high level of stress and maladjustment.

Introduction

Nursing school an exciting and challenging adventure that will devote much of nursing student in terms of time and energy because nursing in a discipline comprising knowledge from many related fields students nurse will be asked to learn to think critically, synthesize information and then apply it to situations involving like people. (Dewet, 2003). Nursing field is most crucial that nursing students have some stress in their student life. Stress affects human life at all stages of development but especially it affects student life. Stress affects the academic achievement because this can harm child physically, socially, intellectually and emotionally.

Stress means the tension, pressures, affecting physically, emotionally and mentally. Stress is a normal reaction for people of all ages but students life is a period of stress. They experience emotional instability from time to time which is a logical consequences of the necessity of making adjustments to new patterns of behaviour and to new social expectations. Students life lead a period of stress a time when a number of major adjustments must be made in the home, college and social aspects of their lives.

Lazarus and Folkman (1984) define psychological stress as "a relationship between the person and the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endangering his or her well being" (p. 21). They add that the person uses cognitive appraisal to judge whether the person-environment relationship is stressful. Varcarolis, Benner- Carson and Shoemaker (2006) define stress as a state which is created by "a change in the environment that is perceived as challenging, threatening or damaging to a person's well being" (p. 212). Sullivan, an American psychiatrist who developed the Interpersonal Theory, defined anxiety as an emotion or painful feeling "arising from social insecurity or blocks to getting biological 8 needs satisfied" (Varcarolis et al., 2006, p. 17).

Elsevier et al. (2006) reported that nursing student have stress in many ways. First stress is an experience a person is exposed to through a stimulus or a stressors are disruptive forces operating within or on any systems (Human 1995) stress is also the appraisal or perception of stressors. Appraisal is how people interpret the impact of the stressors on themselves of what is happening and what they can do about it, finally stress is a general term that line environmental demands the student capacity to meet those demands (kasl, 1992) stress in this concept refers to the consequences of stressors as well as to the person's appraisal of the stressors.

The word "Adjustment" came into popular use in psychology during the 1930's. Adjustment may be defined as the activities which an individual attempts to meet the demands made upon him by biological, social and academic need with the resources in his environments. It can be seen in different dimensions such as home, emotional, social, and educational adjustment.

Students who are poorly adjusted especially those who have been making poor adjustments in educational field tend to be most unhappy the more persistently throughout the whole academic life. Their unhappiness increases the stress which affects their psychological, emotional and educational life.

As students often change their clinical settings, many find that the unfamiliarity of clinical setting is stressful (Beck & Srivasteva, 1991; Kim, 2003; Shipton, 2002). Nursing students in Melia's study (1982) stressed the importance of fitting in and learning the rules of the wards. They identified the transient nature of their experiences as a source of stress.

Several studies reported that relationships with teachers were a big source of stress, particularly during interpersonal conflict with the instructor and when students were being observed or evaluated (Beck & Srivasteva, 1991; Garret, Manuel & Vincent, 1976; Mahat, 1998; Parkes, 1985;



Kleehammer et al., 1990; Mahat, 1998; Kim, 2003; Sellek, 1980). Other studies show that students were stressed or anxious when their teacher was inexperienced (Melincavage, 2008), incompetent (Pagana, 1988; Shipton, 2002), anxious (Windsor, 1987) or had ineffective teaching skills (Kleehammer et al., 14 1990; MacMaster, 1979; Melincavage, 2008; Oermann, 1998; Shipton, 2002). Many nursing students identify non supportive (Brophy, 2000), threatening, derogatory (Windsor, 1987), and demeaning (Mahat, 1998; Pagana, 1988) teachers as a source of anxiety.

Objectives:- 1. To study the level of Stress in nursing students.

- 2. To study the level of Adjustment in nursing students.
- 3. To study the correlation between stress and adjustment in nursing college students.

Hypothesis :- There will be no correlation between stress and adjustment in nursing college students.

Method- Sample- The sample for the study consisted of 30 nursing college students from Balaji Nursing of Udaipur city.

Tools:- The Bist Battery of Stress Scale was used to assess the academic stress of nursinng college students which is constructed by Dr Abha Rani Bist and the Adjustment Inventory by Dr A.K.P. Sinha and Dr R.P. Singh was used to study the adjustment of nursing college students.

Result and Discussin:-

The collected data was tabulated and the results obtained are present under the following; **Table-1** (**Distribution of**

Stress	Mean	S. D.
Academic	95.20	13.54
Frustration		
Academic Conflict	46.50	10.79
Academic Pressure	48.50	12.83
Academic Anxiety	78.60	12.04
Total Stress	268.80	49.20

The data was obtained among nursing students on the Bist Battery of Stress Scale. Academic stress had four components such as academic frustration, academic conflict, academic pressure and academic anxiety.

The above table1 shows that distribution of academic stress in nursing college students. The data reveals on the academic stress on nursing college students are respectively; (95.2with±13.54), (46.5with±10.79), (48.5with±12.83) and (78.6with±12.04). This shows that nursing college students are experiencing high academic frustration and academic anxiety in their academic life.

Adjustment	Mean	S. D.
Emotional adjustment	2.28	1.60
Social adjustment	3.40	2.35
Educational adjustment	6.80	2.25
Total Adjustment	12.48	6.20

Table -2 (Distribution of Adjustment in Nursing students)

The above table2 shows that distribution of adjustment in nursing college students. The inventory consists of three type of adjustment as; Emotional, Social and Educational adjustment. The result indicates that the mean and standard deviation on adjustment of nursing college students are respectively;(2.28with±1.60), (3.40with±2.35) and (6.80with±2.25). This shows that nursing students are more educationally maladjusted than that of emotional and social adjustment. **Table -3 (Correlation between Stress and**

Variables	N	Mean	S.D.	ľ	Remark
Stress	30	268.68	49.20	0.75	*significant
Adjustment	30	12.48	6.20		

^{*} significant at 0.01 level

The above table3 illustrate that the mean value of stress and adjustment in nursing college students are (268.80with±49.20 SD) and (12.48with±6.20 SD).

The result shows that the nursing college students are experiencing high academic stress which affects their adjustment and it is significant at 0.01 level.

The coefficient of co-relation is 0.75 which shows high correlation between stress and maladjustment.

Conclusion-

- 1. Nursing students are experiencing high academic stress.
- Nursing college students are more academically maladjusted than that of emotional and social adjustment.
- 3. There is high correlation between stress and maladjustment of nursing college students.

References-

- * Abidin, R. R. EBD (1995). Parenting stress Index (3rd), New York: Psychological Assessment Resources.
- * Bell (2001) Transforming the National's Health: Next Step in Mental Health Promotion. American Journal of Public Health 100 (12).
- * Bethesda (2002) Stress among Male and Female Nursing students for job. Journal of Advanced Nursing, Vol 2 (1) pg 12. Chrostal Bech Nurse (2002) Adjustment about job in Nursing Students. The Journal of Psychaitric and Mental Health Nursing. Vol 3 (1) pg 73.
- * Dewit & Elsevier et al. (2003): Health of Nursing Person at Work Place. Dissertation Abstract International, 65 (9), 3078-83.
- * Elsevier et al. (2006) "Source of stress among Nursing students," Journal of Applied Psychology, Vol 23, 32.
- Human (1995) "Stress and Stressors" Guinea Publications, Gueina. Pg 234-244.
- * Kaplan (1993) Adjustment about job in Nursing Students. Journal of Psychaitric and Mental Health Nursing. Vol. 3 (1) pg 74.
- * Kasal, (1992) " Environmental Demands booster for Stress Management, Vol 12(1) pg 25.
- Lawrence (2002) Stress in Nursing Faculty. A Case Study of Nursing School.



Impact Of Cotpa Act 2003 On The University And Colleges Of Indore

Yakshita Malhotra * Dr. Sharda Trivedi**

Abstract - Tobacco is the only lethal product that has no safe limit and that is legally marketed to consumers (especially near educational institutes) around the world. So, in order to find out the ground reality, whether the tobacco laws, as envisaged in the COTPA Act 2003 being enforced and followed. The study was conducted in the university and colleges of west Indore. 120 samples for the study (Staff and students) were selected by the random sampling method. Self constructed questionnaire was used to collect the information through survey method. For analyzing the results percentage was used and revealed the level of awareness among the respondents towards COTPA Act 2003.

Introduction:-

Tobacco smoking is the act of smoking tobacco products, especially cigarettes and cigars. Tobacco smoking is considered a significant cause of human health problems, especially cancer and other disorders affecting the lungs. The practice of smoking tobacco originated as a ritual practice among American Indians in North America, where tobacco is native. Today it is widespread throughout the world; according to WHO, it is most common in East Asia, where as many as 2/3rd of all adult males smoke tobacco.

Smoking represents a serious global health issue given that it has been unequivocally established that exposure to tobacco smoke causes significant mortality and morbidity. Use of tobacco currently accounts for 3 million deaths each year worldwide, and nearly a third of these deaths occur in India. Effective tobacco control needs multipronged strategies focusing on reducing the demand for tobacco products.

The Government of India has launched a new National Tobacco Control programme to implement the anti tobacco laws. The Indian parliament enacted the COTPA Act 2003 cigarettes and other tobacco products (Prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production, supply and distribution) Act2003 on May 18.

The Act is a result of decades of consultations and development and has undergone many changes to assume a final form. Beginning with the cigarettes (Regulation of production, supply and distribution) act which specified statutory health warnings on cigarettes in 1975, over the years, it has evolved and gradually developed into a complete, comprehensive act encompassing key aspects of tobacco control, regulation and enforcement. Tobacco use is on rise among the youngsters.

People including smokers and cigarette sellers are seemingly obvious of a law that bans smoking in public places. If we walk into any college canteen we will find ourselves enveloped in a haze of smoke. No one would have heard of the COTPA Act 2003, which bans smoking in places such as education institutions, hospitals, auditoriums, restaurants, and publictransport. And those who have heard of it couldn't care to hoot about the law. A global youth tobacco survey has found that percentage of teenage smokers in eastern India increased from 7.7% in 2003 to 12.7% in 2006. COTPA has been framed specifically to discourage the young from taking up smoking.

The cigarettes and other tobacco products act 2003 in India is a comprehensive legislation which prohibits the advertisement of and production, supply and distribution of cigarettes and other tobacco products. However, this act is not being strictly enforced in different part of the country due to various reason and is mostly limited to papers only.

Objectives:-

- 1. To assess the awareness among the students towards COTPA Act 2003 of the university and colleges.
- To find out the awareness among the staff (teaching and non teaching) towards COTPA Act 2003 of the university and colleges of Indore.

Methodology:

The study was conducted to study the awareness among the students and staff(N=120) towards COTPA Act 2003 of the university and college campus, Indore. Random selection method was used to select the sample unit. Out of 120 samples 40 each were selected randomly from the University(Journalism & Mass Communication DAVV, Indore), colleges (Holkar science and Arts & Commerce). For eliciting



the awareness of the study subjects, self structured questionnaire was developed under the guidance of subject experts.

Before administering the tool the pilot study was conduted in order to finalize the tool. Two different questionnaires were used, one for students and other for staff(teaching &non teaching) to obtain information regarding issues related to COTPA Act 2003. The type and number of questions were framed in such a way so as to find out the information towards issues related to COTPA Act 2003 among the respondents.

For each correct answer respondents were given 1 mark and 0 to those having wrong or partial information. Survey method was used for the data collection.

Analysis of Data:

Percentage was used for data analysis.

Scoring

0-3(not aware)

3-8(aware)

The awareness towards COTPA Act 2003 was analysed in the form of percentages as given below:

Table 01: Awareness among students towards issues related to COTPA Act 2003

Level of	Journalism	Holkar	Arts
awareness	&mass	Science(&comm
	communication	%)	erce(%)
	(%)		
0-3(not	80	45	70
aware)			
3-8(aware)	20	55	30
Total	100	100	100

The data in the above table shows that among the students of Journalism & Mass communication maximum 80% were not aware and only 20% were aware, 55% were aware and rest 45% were not aware in Holkar Science and again in Arts & Commerce college maximum 70% students were not aware only 30%were aware about the issues towards COTPA Act2003.

Table 02: Awareness among staff towards issues related to COTPA Act 2003

Level of awareness	Journalism & mass commun ication(%)	Holkar college(%)	Arts &com merce
0-2(not	45	40	40
aware)			
2-6(aware)	55	60	60
Total	100	100	100

The data above reveals that among the staff members, among both Holkar Sciences, Arts and Commerce colleges. 60% staff and 55% staff of Journalism and Mass Communication were aware towards the issues related to COTPA Act 2003. Rest 45% staff of Journalism, 40% each from both the colleges were not aware about the related topic. Table 3 Distribution of respondents (N=120) on the basis of their responses towards impact of COTPA Act 2003 (See Table 3)

The data in the above table describes the their responses towards the impact of COTPA Act 2003. Among Journalism and Mass communication maximum 80% said that there is a ban on smoking tobacco in their department, 655 said that these laws are effective and being implemented in India, 60% reported that they have seen people consuming tobacco in the department, 355 of them said that there is a punishment in their department for violating these laws and the same percent of them said that they consume tobacco.

In Holkar science, 55%said that they consume tobacco. According to these laws are effective and there is a ban on smoking in their department. In Arts and Commerce maximum 70% said that there is ban on tobacco in India but they had seen people being punished for violating these laws. 40% accepted that these laws are effective and they themselves consume it.

Conclusions:-

The responses of the subjects were thoroughly studied and analysed .It was found that awareness towards the issues related to COTPA Act 2003 was not satisfactory among the respondents. Very few percent of them were aware about the name of the COTPA Act 2003, many of them both the students as well as staff even had not heard about it.

Again the information related to the penalty for violating the law, distance upto which the sale of tobacco is banned near educational institutes, age limit for buying tobacco and other such issues were not answered correctly by maximum of them. Although most of them (89%) had the positive attitude toward these laws and its implementation but maximum of them were not eager to take some steps on their own to help government and other agencies to eradicate this scourge from the society especially the male members.

The condition was almost similar in all the three study areas. Very few of them (52%) said that they usually like to take initiative in order to stop any person if consuming tobacco infront of them.

The implementation was although effectively being followed by the authorities related to COTPA Act 2003. As there was

nss

ban on the consumption of tobacco in the campus, each of the educational area had rules like 500 fine on violating the laws. In Arts and Commerce college punishment like suspension from class for week etc.effective and appealing, motivating posters, hoardings have been used within these areas. In media department they use to conduct time to time GD's on these type of current issues among students, also their staff take active participation.

Suggestions:

For further study-

- The sample size could be increase for further study.
- For further study the impact of COTPA Act 2003 could be seen on other groups like-from rickshaw pullers to executives, etc.
- The same study could be made comparative by comparing the prevalence of tobacco consumption different groups like, according to age group, different socioeconomic status, family background, geographical area etc.
- The study could have been done to search for the factors that result in the failure of implementation of these laws.

For general public-

- More smoke free public and workplaces should be created across the country as mandated under section 4 of COTPA.
- Key stakeholders as well as the general public should be made aware of the public health significance of the smoke-free law.

Refernces:

- 1. Ahuja Ram, Research Methods: Rawat Publications, 2008.
- Braverman and Aaro's,2003: Tobacco marketing awareness on youth smoking suspectibility and perceived prevalence before and after an advertising ban.
- Kumara Achala, 2010: Prevalence of chewing form of tobacco and existing quitting patterns in urban population of Jamnagar, Gujarat, V35(1),105-108.
- 4. Indian Journal of community medicine, 2007:V32
- Malhotra C, Malhotra R, MM Singh, S Garg GK Ingle, 2007:A study of tobacco use among street children of Delhi; V32(1),58-59
- Nayak NS, Annigeri VB, Revankar DR, 2010: The efficacy of cigarettes and other tobacco products act 2003; V47(5)24-29
- 7. Peter D, 2010:Enforcement of youth access laws reduces tobacco sales to minors:V75(14)

Table 3 Distribution of respondents (N=120) on the basis of their responses towards impact of COTPA Act 2003

Issues related to COTPA Act 2003	Journalism &	Holkar	Arts &
	mass	Science (%)	Commerce
	communication		(%)
Ban on adds of tobacco in India	65 %	50%	70%
Consumption of tobacco products	35%	55%	40%
Tobacco laws are effective	65%	55%	40%
Ever seen anyone being punished for	20%	30%	60%
violating the law			
Ban on smoking tobacco consumption in	80%	55%	55%
the department			
Ever noticed anyone having tobacco in the	60%	25%	70%
department			
Is there punishment for violating the	35 %	-	45%
tobacco prohibition laws in the department			

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013



Ecological conciousness in Kamla Markandaya's Nectar in a sieve

Mrs. Asha Jain*

Abstract- Nature nurtures human socities and it has played a very important role in the human development. Kamala markandaya's first novel 'Nectar in a sieve' deals with the impact of environmental degradation, cultural and Social economic strands and uprootedness caused by industrialization and agrarian bankruptcy. The bitter experience of hunger, starvation, and disintegration in Rukmani's life dealt realistically. The heroin Rukmani encounters not only the consequences of changing times but other problems like destitution, deprivation, death, loss of tradition that are experienced by many people for many reasons in contemporary India. The novel is a sharp protest against the demoralizing impact of industrialization and urbanization. Kamla Markandaya is a very sensitive novelist who conveys very sharply how people became insensitive to the aesthetics of nature. She brilliantly demonstrates that the survival of humanity depends on the sensitive treatment of nature. Any disrespect shown against nature will inevitably results in lamentation.

This research paper will focus on the introduction of Ecocriticism and symbiotic relationship between man and nature. It would explore the environmental problems created by man due to rapid industrialization and the consequent exploitation of nature .lt would suggest the solutions at the moral level as suggested by Kamla Markandaya's 'Nectar in a Sieve'.

Key words- Nature, Nectar in a sieve, Environment, symbiosis

Intorduction -

Man's relation with nature is an exciting theme. In the present context this has become absolutely important because human beings survival depends on the nature. 'Nectar in a sieve' is the first novel of Kamala Markandaya that deals in terms of present and future relations between human communities and the environment. It is a powerful, depressing, but ultimately hopeful novel of a life with love, faith and inner strength. It is also about the destruction of the traditional way of life in an Indian village by a tannery. It deals with the growing industrial capitalism that destroy the traditional rural values. It was written in 1954 and has effectively communicated the concept of symbiotic relationship. It deals with the continuous struggle of Rukmani, a peasant from a village in India. This paper is an attempt to explore environmental consciousness and symbiotic relationship between human and his environment.

1. Definition of Ecocriticism

Ecocriticism is a vast and complex field that has a broad scope of inquiry. Literary texts create a multidimensional world which is not distinct from environment, but an integral part of it. It is a mixture of all interconnections and interrelatedness of all organisms. There are diverse views of ecocritics about the growth and necessity of eco-criticism that challenges readers to understand the subject properly. Various definitions will help us to comprehend the subject and its scope properly-

Cheryll Glotfelty says: "Eco-criticism is the study of the

relationship between literature and physical environment. Just as feminist criticism examines language and literature from a gender-conscious perspective, and Marxist criticism brings an awareness of modes of production and economic class to its reading of texts, eco-criticism takes an earth centered approach to literary studies (Cheryll, 1996 xviii)

Greg Garrard defines, " Eco-criticism is the study of the relationship of the human and the non human, throughout human cultural history and entailing critical analysis of the term "human" itself (Garrard, 2007: 5.)

Glen a love in his book, "Practical Eco-Criticism" defined Ecocriticism as a literary enquiry that encompasses nonhumans as well as human contexts and consideration.

(Glen a love ,2003:1)

1.2 Historical Background

The term "Ecocritisim" was coined firstly by William Ruckert in 1978 in his essay "Literature and Ecology an experiment in Ecocriticism". (cheryll. 1996: 105-123). By Ecocriticism he meant "the application of and ecological concepts to the student of literature". Mainly he was concerned with the science of Ecology. Cheryll, writes "Some scholars like the term, ecocriticism because it is short and can easily be made into other forms like ecocriticism and ecocritic. Additionally, they favor eco-criticism to show relationships between things, in this case, between human culture and the physical world. Further more, in conotations, enviro-is anthropocentric and dualistic, implying that we humans are at the centre surrounded by everything that is not us, the environment. Eco, in contrast, implies interdependent communities and integrated system, and strong connections



among constituent part!

(Cheryll, 1996:x

X)

2. Nectar in a sieve: An Ecocritical Analysis

Kamala Markandaya has presented nature with its vivid manifestations. She believes that nature is an inseparable part of human societies. She voices her sharp protest against the demoralizing impact of industrialization and its ugly effects on environment. It has marginalized the subalterns and dislocated the poor and innocent villagers. The damage done to the purity of nature is incalculable. It is the first novel of Kamala Markandaya published in 1954 less than a decade after India's independence. It is translated in seventeen languages. It is not dealing with any specific time or place yet it has the universal appeal.

The living conditions, life struggles, poverty, fragility and abasement of life depicted are beyond imaginations for those who are never able to stretch a single meal. Everyday was a life and death situation. Starvation was a certainty that Markandaya knew firsthand. In 1943 a starvation in Bengal of epidemic proportions claimed the lives of over three million people.

She describes hunger in the novel with reference to starving people, who are sometime willing to do anything in order to feed themselves. People's attitude towards the new spectrum of economic opportunities is tempered by the cruelty of the natural environment on which they rely. The other consequences of changing times such as destitution, deprivation, death, loss of tradition, tension between Hindu and Muslims, creation of Pakistan and other political issues are experienced by many people for many reasons, in contemporary India.

However the central connection is Rukmani's respect for nature's inherent energy and a belief in pristine nature as a necessity for human life. She believes that man must respect nature's sacred energy and so must reverse the present trends towards progress at any cost, and have an unwavering passion for what is nature .(Mcclintock 1989:41)The novel deals with the post -colonial conditions of India. It depicts a south Indian family, which had met many tragic experiences like poverty, unemployment, deprivation of land, population growth, malnutrition, failure of crops and famine conditions make their life more miserable. Their two sons leave the house in search of work and their other two sons die due to poverty and malnutrition. Deprivation of land by the heartless landlord, that they were cultivating for decades and deeply attached to it increases their hardships.

This love and symbiotic relationship with the land becomes the cause of Nathan's death .Rukmani narrates the centrality of the natural environment as the essential part of human life. After her marriage, while on her journey towards her husband's abode she catches the landscape and narrates: "For six hours we rode on and on along the dusty road, passing several villages on the way to ours, which was a good distance away. Halfway there we stopped and ate a meal: boiled rice, dhal, vegetables and curds......my husband......unyoked the bullocks and led them each a handful of hay. Poor beasts, they seemed glad of water, for already their hides were dusty.......The animals, refreshed, began stepping jauntily again, tossing their heads and jangling the bells that hung from their red-painted horns. The air was full of the sound of bells, and of birds, sparrows and bulbuls mainly ,and sometimes the cry of an eagle, but when we passed a grove ,green and leafy, I could hear mynahs and parrots .It was very warm, and unused to so long a jolting, I fell asleep." (12)

Throughout the novel nature is presented in its various manifestations. Sometimes in the form of blue skies, tender trees and the brook and Sometimes in the form of seeds and vegetables. "....the beans, the brinjals, the chillies and the pumpkin vine which had been the first to grow under my hand. And their growth to me was constant wonder from the time the seed split and the first green shoots broke through, to the time when the young buds and fruit began to form. I was young and fanciful then, and it seemed to me not that they grew as I did .unconsciously, but that each of the dry, hard pellets I held in my palm had within it the very secret of life itself, curled tightly within, under leaf after protective leaf for safekeeping, fragile, vanishing with first touch or sight. With each tender seedling that unfurled its small green leaf to my eager gaze, my excitment would rise and mount: winged, wondrous......There have been many sowings and harvestings, but the wonder has not been departed". (23-24)

3. Symbiotic relationship between human and environment

Every object of nature seems to posses the secrets of life. Earth is portrayed as a regenerative force that supports human life through its fertility. It is personified in feminine form and observed as the symbol of life and its growth.

"The soil here was rich, never having yielded before and loose so that it did not require much digging. The seeds sprouted quickly, sending up delicate green shoots that I carefully watered, going several times to the well nearby for the purpose. Soon they were not delicate but sprawling vigorously over the earth, and pumpkins began to form, which fattening on soil and sun and water, swelled daily larger and larger and ripened to yellow and red, until at last they were ready to eat, and I cut one took it in. (9)"

Kamala Markandaya believed that nature is like a trained 'wild animal', if treated sensitively than human beings can



get immense beneficial result, but disregard towards the call of nature will only bring calamities. The environmental scientists are giving warning repeatedly that the disturbance in the ecological system is the great hazard of life on this earth. She talks more about the fury of nature through incessant rains, dislocating the lives of the peasants, washing out paddy in the corn fields, devastation of uprooted trees, dead dogs, cats and rats cluttering the roadside. Ecocritism is concerned with ecological literacy and environmental issues along with the causes of ecological degradation. Threat to natural resources and rapidly increasing natural disasters have impelled us to think that spiritual quality of life and loving and living relationship with diversity are more important than material possessions. The answers to ecological problems are found in Nectar in a sieve', Hunger, disappointment, failure of rains, severe famine aggravates their struggle and bewailing of Rukmani:

"Each day the level of the water dropped and the heads of the paddy hung lower. The river had shrunk to a trickle; the well was dry as a bone." (101) She is pointing towards water crisis which we are facing in the present context. She complains that "the earth is parched and dust and all that I grew is dead."(104) Feeling of the respect for other living things in the universe is developed. Nathan tells to his wife Rukmani; "yet you have lived long enough to learn to disregard them,' he said. Are they not found everywhere-tree snakes, water snakes and land snakes? You only need to be careful and they pass you by."(25)

4. Lack of Empathy for biodiversity

At one side the novelist has shown care and regards towards the animals, but on the other side the dialogues between Rukmani and carter shows the disregard and insensitivity towards animals. Lack of empathy for the suffering of animals 'need for survival and attraction towards materialism suggest disturbed relationship between human and animals, The comparison between the various objects of nature and divergent human qualities are shown here as-

"Pumpkins round and fleshed like young women," "a maiden like a flower"," bend like the grass, that you don't break," (160) Human life without nature is unimaginable. Sunlight and fresh air are the essential sources of human life. The bond of deep attachment between the land and humans is eternal. Land and nature is portrayed as the eternal repository of their emotions. "Look at our land-is it not beautiful? The fields are green and the grain is ripening. It will be a good harvest year, there will be plenty." (39)

5. Personification of nature

Nature is personified into a living being and dislocation

from their land is the result of the beginning of industry on the lives of the villagers. Growth of industry means marginalization of subalterns and dislocation of the villagers. It is an inestimable damage done to the purity of nature. Man's evolution is nothing but a series of encounters with nature. His greed and selfishness prompts him to dislike nature. The ill effects of urbanization, the insensitive attitude of human beings towards nature became a great danger to the aesthetics of nature.

6. Conclusion

Markandaya's focus is on the rapid degradation of environment. She protest sharply against the demoralizing and disorganizing effects of industrialization, unhygienic conditions in the towns and incalculable damage done to nature. At the same time she communicates her ideas about symbiotic relationship between man and nature and sensitive treatment of nature for the survival of humanity.

She investigates the possibility of rational arguments for assigning intrinsic value to the natural environment and its nonhuman contents. Narrator deals with dynamic balance of nature, with the interdependence of living and nonliving things. Any disregard to the dynamics of nature and its functioning will bring unimaginable consequence to the human mind. Nectar in a sieve can rightly be considered a critical text in terms of present and future relations between communities and environment. Markandaya's environmental ethics affirm the sacredness of mother earth, ecological unity and the interdependence of all species and the right to be free from ecological destruction.

References:

- * Christopher,Hitt. (1999), "Toward an Ecological sublime", new literary
- * History,30.3p.612.
- * Curry, Patrick. Ecological Ethics: An Introduction. Cambridge: Polity . D. Balasubramanian, (2006), "We borrow the earth from our children: protection of the biosphere and biodiversity is relevant to all of humankind."
- * 7 September The Hindu.
- * Garrard, Greg.(2004). Ecocriticism. First Indian reprint. Newyork: Routledge, Glotfelty,cheryll and Harold Fromm. (1996).The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology.Georgia:The university of Georgia Press. James, I.Mcclintock,' (1989),Edward Abbey's "Antidotes to despair", Critique,vol. 31.1p.41.
- Markandaya Kamala. (1954), Nectar in a Sieve New York: John Day,; rpt. New York: Signet, n.d. Subsequent references to this edition appear in the text. Peter Reed, (1989), "Man Apart: An Alternative to the Self-Realization Approach", Environmental To Whom It May Concern:rr Ethics, 11.153-69.
- * Valentine T.Bill, (1974).Nature in Chekhov's fiction', Russian review, vol.33.no.2.



Potential of Visual Culture in Voicing Women as Subaltern: Deepa Mehta's Water

Veena Singh*

In India we often associate subalternity with the lowest socioeconomic classes and social castes but social expectations of women allow for the presence of subalternity is very complex and we find Indian cinema as an active carrier of the complex nature of gendered subalternity. This paper focuses on Deepa Mehta's Water to express the ways that how a particular social position is enforced through oppression and humiliation. The class which enjoys a social power does not let women enjoy their own status in society. Deepa Mehta's Water presents before us different aspects of subalternity. And also show how essential are they in South Asian Cultural production. The movie effectively demonstrates how subalternity is constructed and enforced across social contexts and how a woman's social worth is derived from her husband. We see her subjectification being enforced through social ridicule and panoptic discipline. Kalyani, a widow is restricted to a secluded life in an ashram of Varanasi. She is constantly punished for being without a husband. The movie opens with a quote from the Manusmiriti which outlines the expected behaviour of widows. The juxtaposition of this sacred Hindu scripture suggests that what type of behaviour is demanded by a lady without husband. The film here gives an accurate description of the way that the existence of women cannot be imagined without the institution of marriage.

The head widow of the ashram, Madhumati, prostitutes Kalyani to pay for rent. Kalyani accepts her fate as she considers her womanhood as a punishment. Her body is used as a product, a commodity. Her physical abuse preserves her subaltern status when she is approached by a young Gandhian idealist for marriage, she accepts his proposal but her plans are abondoned by Madhumati by physical restraints and shearing her hair. As this scene almost invokes a sense of female castration as Kalyani is forced in compliance through the violent. Madhumati locks Kalyani in her room and thus limits her mobility. Kalyani is transformed into a docile subject. A fellow widow eventually frees Kalyani. She soon discovers that her fiance's father has sexually exploited her in the past. Thus her escape from the legacy of her subalternity becomes impossible. In the end we find Kalyani drowns herself in Ganga, a violent act that turns her body into a physical testament to her plight. Her suicide turns her body into a text that can be read, viewed and understood. Gayatri Chakraborti Spivak gives a same example in "Can the Sulbaltern Speak" Bhubaneswari Bhaduri, a woman who committed suicide for her failure to commit an act of anti-colonial violence. She waited until she was menstruating to end her life to demonstrate that the suicide was not the result of a doomed love affair. Despite her intentions, this is the way her suicide was read (Spivak, 1985: 120-130). Kalyani's suicide is her way of resistance though Madhumati considers it a lesson for all widows who live in ashram. But it is her way of speaking against the systematic oppression, she faces as a widow. Her action is unable to change her fate. She can never reduce the burden of her status, which shows her inability as a subaltern to change her fate and makes the audience shamed into acknowledging their plight.

Water does not allow the happy closure of a widow's marriage but like the early novels on the subject, probes the reasons for Kalyani's action. It succeeds in making apparent the helplessness of a woman trapped within the social grid when she has neither the means nor the opportunities of standing by herself in defiance of society. Without the protection of a male, she is merely an object for exploitation, whether inside or outside a home or a bidhva-ashram, by men and colluding women.

Water points not only to the suffering of widows in colonial India but to the widow-house that still exists in Varanasi and houses poor widows in seclusion and disgrace, away from the community. The film opens the lens to the prostitution and privation experienced by many widows, as well as Gandhi's efforts to change the laws that affected "widow remarriage." The question of 'widow remarriage', along with dowry and Sati, became popular issues at various times in the last hundred years when the nation wished to champion the uprightness of Indian masculine morality, and its ability

nss

to protect its women. Water points to the inequality between men and women, remarking on the traditional practice of an arranged match between a man in his forties or fifties with a young pre-pubescent girl. It looks closely at the custom of sending widows to live in isolation, lifelong chastity, and renunciation of 'worldly desires',

Even if Water (Canada, 2005, Deepa Mehta) had not been nominated for an Oscar for Best Foreign Language Film, which constitutes peer approbation of its cinematic distinction, it would have been marked as a singular achievement for the director's determination to complete the film.

Though the plight of the Hindu widows has captured the attention of the people in India and abroad, and the Indian National Commission for Women presented its Report on widows living in Mathura, Vrindavan and Varanasi in 1996, their lot remains unchanged. Three images in particular-the child widow, the ascetic widow, and the widow who burns on her husband's pyrehave never failed to evoke pity and consternation. The current work of social reformers and women's rights activists focuses on the financial well-being and the customary rights of widows to property as both daughters and daughters-in-law.6 The urgent need is to highlight the widow's rights in principle and the reality of their denial. However, these matters are yet to be satisfactorily resolved, given the patrilineal laws and customs in India as well as the existing social norms in patrilineal communities Deepa Mehta's film Water contributes to this filmic discourse on widowhood and makes commendable attempts to embed the cinematic images in the dialectical force-field of social practice and the urgent need for change. In all the three films of the trilogy-Earth, Fire and Water -Mehta's treatment is informed by a strong feminist stance. This means that she is sensitive to the gendered way of seeing the world and therefore consciously creates a frame of reference and a standpoint in each film to critically examine the issues that each film brings into discussion.

Deepa Mehta's cinematic aesthetics is pleasing and thedetails of every frame are handled with care. But the film is intended to disturb the mind and shake the complacency of the postmodern world by attending to the traces of the past which continue in the present. It speaks of issues long neglected by the Indian society so that the widows of Mathura, Vrindavan and Varanasi seem to be the forgotten inhabitants of an oppressive and archaic world. As a women Deepa Mehta could easily feel the pain of the subalternity of women in

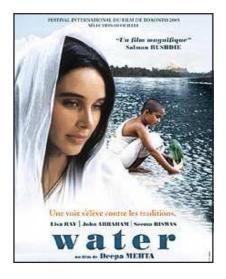
Indian society and has tried a craft a beautiful visual painting giving voice to the same. As Jasbir Jain argues, "Water critiques Brahminical values but it also goes beyond this to bring in a host of other issues related to value-structures, colonial stupor and social change" (Jain 66)

References

- * Bhabha, Homi. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.
- * Chatterjee, Partha. The Partha Chatterjee Omnibus. New Delhi: Oxford University Press, 1999.
- * Corbridge, Stuart, and John Harriss. Reinventing India. Cambridge: Polity Press, 2000.
- Jasbir, Jain. "The Diasporic Eye and the Evolving I Deepa Mehta's Element Trilogy." Films, Literature and Culture Deepa Mehta's Elements Trilogy. Ed. Jasbir Jain. Jaipur: Rawat
- * Publications, 2007. 54-74. Print.
- * Levy, Emanuel. "Mehta Water". May 2006 http://www.emanuellevy.com/article.php?articleID=2300.
- * Narayan, Uma. "Contesting Cultures." In The Second Wave: A Reader in Feminist Theory. Ed. Linda Nicholson. New York: Routledge, 1997.
- * Nijhawan, Amita. "Damning the Flow: Deepa Mehta's Water." M/C Journal 9.4 (2006). 02 Jun. 2013 http://journal.media-culture.org.au/0609/3-nijhawan.
- * Said, Edward. Orientalism. Revised ed. New York: Vintage Books, 1994.
- * Spivak, Gayatri. "Can the Subaltern Speak?". In Marxism and the Interpretation of Culture. Eds. Carl Nelson and Lawrence Grossberg. Urbana: University of Illinois Press, 1988.

Films

Water. Directed by Deepa Mehta. David Hamilton. 2005.







Alternative Dispute Resolution (ADR) System in India: Problems and Prospects

Pardeep Singh *

Introduction

The 'Welfare State' demands more and more socio-welfare legislations, transparency in governance, Rule of Law and above them all 'Justice'-Social, economic and political. A country performing well in these parameters may rightly be said an 'egalitarian society'. Disputes (takrar) are very basic tendency of human behaviour, but devil resides in the resolution (karar) of disputes. The WJP Rule of law Index, 2012-2013, having surveyed 97 countries with 2500 experts and 97,000 other individuals from around the world seems to be a rear view mirror for all the countries surveyed. Total 48 specific indicators taken into consideration which consisted of civil justice is not subject to unreasonable delay, civil justice is free of discrimination, of corruption, of improper government influence, criminal adjudication system is timely and effective. ADR are accessible, impartial and effective etc.

In this report, Indian Civil Court system ranked poorly (ranking 78th out of 97 countries), mainly because of deficiencies in the areas of court congestion, enforcement and delay in processing cases. Order and security-including crime, civil conflict, and political violence-is also a serious concern in India as it is ranked second lowest in the World. It adds to the skepticism of the legal academics and researchers in general. It is the high time to deconstruct the actual position of our country and to build a constructive paradigm for the active global participation in near future.

Skewed Access to Justice

A Concern Access to justice is the top most priority of any democratic country. That is why Constitution of India explicitly use the word 'Justice-Social, Economic and Political' in the 'Preamble' which is known as a key to open the mind of makers of the Constitution. For administration of justice, the right to remedy is one of the rights which is of paramount importance and the same has got a place in Part III of Constitution of India under Article 32. In India there is well structured modus operandi for knocking the doors of the Court in both types of cases i.e. civil or criminal. For civil matters the Code of Civil Procedure, 1908 under section 26 makes the provision for the initiation of the proceeding by filing a Plaint or otherwise, whereas in criminal cases, there are provisions for lodging FIR, Complaint or Information to the

concerned authorities. But, unfortunately the prevailing corruption and redtapism at every walk of the court proceedings makes the way very cumbersome for the justice seekers. If someone succeeds in approaching the Court then the agony of persons seeking justice gets aggravated when the case prolongs year after year. 'Justice delayed is justice denied', this saying perhaps suitable for Indian adversarial judicial system. In India the very idea of providing easy access to justice for all seem to be under threat in the prevalent circumstances, which certainly needs a respite in the form of some additional mechanism.

In our country, the ratio between the population and the judges is unrealistic. India has 15.5 judges per million people, a figure that compares very poorly with other countries. Supreme Court of India had directed the Union Government that the judge-population ratio be raised to 50 per Million in a phased manner. The proposal could not be acted upon till date. The deliberations to double the strength of existing judges in the next five years in a Joint Conference of Chief-Ministers and Chief-Justices of High Courts, held on 7-04-2013, once again generated a ray of hope.

Further, the problem of mounting arrear of cases on the judiciary aggravates the issue. Dr. Manmohan Singh, hon'ble Prime Minister of India himself has shown his concern to it while highlighting the problem of backlog of more than 3 crore cases in India. On an average, approximately 18 million cases are being filed every year and the average disposal is somehow more or less equivalent to the filing and does not contribute in decreasing the arrear. Number of cases has increased so fast that the entire adjudicative system is overburdened. On the financial front also, the Union Government's allocation of funds to judiciary under the five year plans is less than one per cent of the total plan outlay. which cannot be justified. Judiciary being a watchdog of our constitutional values is supposed to be financially strong. However, Prime Minister patted the government's initiatives for having provisions especially for judiciary under 14th Finance Commission.

Experiment with Gram Nyayalaya under Gram Nyayalaya Act, 2008 has not taken up as expected. There was a target to establish 5,000 gram nayalayas, but till date only 172



have been established. Out of these, only 152 are operational, though Government is hoping that up to year 2014, 616 gram nayalayas will be established. Obviously, it questions our political will.

ADR Strengthen the Access to Justice

The above stated problems are the consequences of blindly following the Adversarial Court System which has been borrowed from the Colonial regime in India. However, a large number of disputes can be settled outside the courtroom with the help of ADR mechanism which will be less expensive for the parties. ADR mechanism seems to be a right approach for addressing the problems caused by the adversarial court system. With the potential of providing a speedy, inexpensive and fair justice, ADR system can be better utilized in India. **Meaning of ADR**

According to Black's Law Dictionary the word 'Alternative' means 'giving an option'. Similarly the word 'Dispute' means a 'conflict' or 'controversy'. In the same manner the word 'resolution' means 'a formal expression of an opinion'. In totality an inference may be drawn that ADR is a mechanism for resolving a justifiable controversy through an unconventional method. Primary object of ADR system is always being avoidance of vexation, expenses and delay and promotion of the idea of 'access to justice'.

Recently a difference of opinion towards the importance of ADR mechanism between two legal luminaries viz. Sh. Gopal Subramanium and Sh. Sriram Panchu was published in the editorial pages of 'The Hindu' dated May 1, 2013 and May 6, 2013 respectively. Wherein the former was of opinion that: "the court-mandated resort to ADR as one of the factors that limits the effectiveness of the judicial system... it is improper for the courts to shy away from adjudicating, and look at ADR," the later one came with a strong backing of ADR when he said that: "...we need not negate or decry any method as second hand but take comfort from knowing that with a panoply of ways to address dispute, we have a good chance to control conflict between individuals, companies, other organizations and communities." This dichotomy of opinions can be given a solution by citing the words of Sir Laurence Street:

ADR is not in truth alternative. It is not in competition with the established judicial system. It is an additional rage of mechanism within the overall aggregated mechanisms for the resolution of disputes. Nothing can be alternative to the sovereign authority of court system. We can, however, accommodate mechanisms which operate as additional or subsidiary processes in the discharge of the sovereign's responsibility. Theses enable

the court system to devote its precious time and resources to the more solemn task of administrating justice in the name of sovereign.

Various Modes of ADR

There are well over sixteen distinct ADR processes currently in use. Many of these processes have been developed as hybrid from three basic models: processes involving only the disputing parties (negotiation), process involving a neutral, non-decision-maker (mediation), and processes involving a decision-maker (arbitration). All methods of ADR, including arbitration are consensual in nature- the parties must consent to the procedure before being compelled to participate in the procedure and before public courts deter to the procedure and outcome. ADR techniques are extra-judicial in character. They can be used in almost all contentious matters which are capable of being resolved, under law, by agreement between the parties. They have been employed with very encouraging results in several categories of disputes, especially civil, commercial, industrial and family disputes.

Lok Adalat or 'people's courts' in India have been proved to be an example before the World for imparting access to justice outside the Courts. In India, till date more than 11 lacs Lok Adalats have been organized which resulted into the resolving of 3.76 crore cases outside the adversarial court system. In 2011 alone, as many as 41,35,411 cases were settled through Lok Adalats.

ADR processes were not being resorted to with the desired frequency, Parliament thought it fit to introduce section 89 and Rules 1-A to 1-C in Order X in the Indian Code of Civil Procedure, 1908 in year 2002 to ensure that ADR process to be resorted before the commencement of trial in suits. Section 89 of the Code of Civil Procedure,1908 provides for settlement of disputes outside the court. Sub-section (1) of section 89 of the Code empowers the courts, when it appears that there exist elements of settlement which may be acceptable to the parties, the court shall formulate the terms of settlement and give them to the parties for their observations and after receiving the observations of the parties, the court may reformulate the terms of a possible settlement and refer the same for:

- Arbitration
- Conciliation
- Judicial Settlement including settlement through Lok Adalat; or
- Mediation

However, taking notice of various lacunae in the drafting of section 89, Mr. Justice R.V. Raveendran has observed:

Conclusion



Section 89 apparently was drafted in a hurry. It is not very happily worded. It is not very practical. But the object behind section 89 is sound.

The objects behind the insertion of section 89 in C.P.C. was to thrive the ADR system in India. While interpreting section 89 in consonence with this objective and after pointing out various anomalies in it's drafting the Supreme Court of India in the case of M/S Afcons Infra. Ltd. & Anr. v. M/S Cherian Varkey Const. directed that clause (c) and (d) of sub-section (2) of section 89 deserves to be interchanged. The sum and substance of what the Court discussed elaborately is that:

Know the dispute; exclude unfit cases; ascertain consent for arbitration or conciliation; if there is no consent, select Lok Adalat for simple cases and mediation for all other cases, reserving reference to Judge-assisted settlement only in exceptional or special cases.

Consequently, the Law Commission of India (238th Report) recommended a number of changes to be made in the section 89 of Code of Civil Procedure, 1908. Now the ball is in the court of Policy Makers to alter the Code in consonence with the directions given by the Supreme Court for removing the ambiguity present therein and for promoting ADR for amicable settlement of disputes outside the courts.

In India, Justice-Social, Economic, Political, as goal of Constitution of India, can only be realized by recognizing ADR and by giving ADR its due. Legal Services Institutions like: National Legal services Authority (NALSA), various State Legal Services Authorities etc. are contributing a remarkable role by promoting the concept of ADR particularly through

Lok Adalats which need to be appreciated. The Adversarial Court system will definitely be benefitted by the promotion of ADR as it will give enough time to the courts for applying its judicial mind in the cases for which adjudication is must. The wording of John F. Kennedy is best suited in the Indian context when he said that: "Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate."

References:

- * Mark David Agrast, Juan Carlos Botero, et. al., World Justice Project- Rule of Law Index (2012-13).
- Pardeep Singh, "Amicable Settlement of Disputes: A Journey from takrar to karar via Indian Judicial System" Legal Aid & Inclusive Judicial Process, CUH, 2012
- * All India Judges Association v. Union of India, AIR 1992 SC 165.
- * Speech of Prime Minister of India in an inaugural ceremony of joint Conference of CM's and CJ's held on 7-04-2013 at Vigyan Bhawan, New Delhi.
- * Speech delivered by Sh. Ashwani Kumar, the then Union Minister of Law and Justice at the inaugural ceremony of Joint Conference of CMs and CJs on 7-04-2013 held at New Delhi.
- * Sir Laurence Street, "The language of Alternative Dispute Resolution" Alt. L J, 194(1992). Supra note 5.
- * Justice R.V. Raveendran, "Section 89 CPC: Need For an Urgent Relook" (2007) 4 SCC J 23.
- * M/S Afcons Infra.Ltd. & Anr. v. M/S Cherian Varkey Const., Civil Appeal No. 6000 of 2010.
- * Law Commission of India, 238th Report on Amendment of Sec. 89 of the Code of Civil Procedure, 1908 and Allied Provisions (2011).



A Comparative study of job satisfaction & health between female teachers of Government and Private schools.

Dr. Rashmi Singh*

Abstract - The objective of the study was to compare the level of job satisfaction and health between the female teachers of government and private schools. The sample constituted of 60 female teachers divided in two (30 female teachers from government schools and 30 female teachers from private schools) of Udaipur City. Job satisfaction scale by Dr. Amar Singh& Dr. T. R. Sharma and P.G.I.H.Q. by S. K. Verma, N. N. Wig and D. Prashad were used. The result indicated that there was significant difference between the Govt. School teachers and private school teachers. Govt. school teachers were found to be more job satisfied than private school teachers. There is high level of job satisfaction in Govt. school teachers than private school teachers. The higher level of health was experienced by Govt. school teachers than private school teachers.

Intorduction -

The public sector, sometimes referred to as the state sector is a part of the state that deals with either the production, delivery and allocation of goods and services by and for the government or its citizens, whether national, regional or local/municipal.

The public sector is usually composed of organizations that are owned and operated by the government. This includes federal, provincial, state or municipal govt., depending on where we live. Privacy legislation usually calls organizations in the public sector a public body or a public authority.

The Private sector is that part of the economy which is both run for private profit and is not controlled by the state. These usually include cooperation's (both profit and non profit), partnerships and charities. Job satisfaction describes how content an individual is with his or her job. The happier people are within their job, the more satisfied they are said to be.

Job design aims to enhance job satisfaction and performance; methods include job rotation, job enlargement and job enrichment. Other influences on satisfaction include the management style and culture, employee involvement, empowerment and autonomous work groups. Job satisfaction reflects an employees overall assessment of their job particularly their emotions, behaviors and attitudes about their work experience. Health is metabolic efficiency.

The English word health comes from the old English world Hale, meaning wholeness, a being whole, sound or well. "Health is a state of a complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity." (WHO 1948) health is resource for everyday life, not the objective of living.

Health is positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities. (WHO 1986) Lancet states that "health is not a state of complete physical, mental and social well being." Neither is it "merely the absence of disease or infirmity." There are two broad aspects of healthphysical health and mental health. Physical health means a good body health, which is healthy because of regular physical activity, good nutrition and adequate rest. Mental health refers to people cognitive and emotional wellbeing. A person who enjoys good mental health does not have a mental disorder. According to WHO, mental health is " a state of well being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community."

Objective- 1) To study the significant difference of job satisfaction among female teachers of Govt. and private schools.

To study the significant difference of health among female teachers of government and private schools.

Hypothesis-

- There is no significant difference between job satisfaction of female teachers in government and private school.
- There is no significant difference between health of female teachers in Government and private school.

Method: - Sample - In accordance with the aim of the present research 30 female teachers from government school and 30 female teachers from private schools were taken from Udaipur city by random sampling.

Tools- 1) Job Satisfaction scale by Dr. Amar Singh and Dr. T.R. Sharma was used. It constitute of 30 items which cover different areas like job intrinsic, job extrinsic, economic and community/ national growth. Reliability of the scale by testretest method is 0.978 and validity is 0.743.

P.G.I.H.Q.N-1 by S. k. Verma, N. N. Wig, D. Pershad was used to measure the health of the teachers. It is divided in two Area A constitute of 16 items and Area B constitute of 22 items respectively.



Procedure- Each of the two tests was administered individually while collecting data for the study. Prior to administration of each test or scale appropriate rapport was formed and following the instructions and procedure suggested by the authors of the scales and tests the instruments were administered.

Rssult- Table1-The t score between Govt. female teachers and private female teachers on job satisfaction

Groups	Mean	SD	SE	CV	t
Govt. female teachers	60.8	7.18	1.33	12	6.76**
Private female teachers	49.03	6.34	1.17	13	

Table-2- The t score between Govt. female teachers and private female teachers on health

Groups	Mean	SD	SE	CV	t
Govt. female teachers	2.53	1.40	0.26	55	13.60**
Private female teachers	7.97	1.64	0.30	21	

After data collection statistical analysis was done to test the hypotheses. Firstly t was calculated to find difference on job satisfaction between female teachers of Govt. and private school. The mean of job satisfaction among govt. teacher is 60.8 and of private teacher are 49.03. The t value is 6.76 that is significant at 0.05 and 0.01 level.

For the second variable Health, mean of Govt. teachers is 2.53 and mean of private teachers is 7.97. After evaluation the t value is 13.60, which is significant.

Discussion- Govt. school teachers were more job satisfied than private school teachers. It is because Govt. job is likely to have fixed working hours, reasonable wages, and fair benefits, have to go by the law. Whereas private school had irregular working hours, lots of unpaid work, more stress from upper authorities, risk of having demotion or fired out from work.

UM Flint professor Mark J. Perry recently cited data showing that government employees make 45% more on average than private employees. Govt. jobs are considered for stability and job security. Govt. jobs are more difficult to get but when it is in our hand then we can be sure that we will have the job unless otherwise we decide to leave.

They also come with good retirement benefits unlike jobs in the private sector. Private school come more with work and there is no luxury or paid for overtime. Private teachers were found to more in stress because of work pressure and it was found that stress had a negative influence on job satisfaction (Rosalie,2002). Brief (1998) wrote " if a person's work is interesting, her pay is fair, her promotional opportunities are good, her supervisor is supportive, and her coworkers are friendly, then a situational approach leads one to predict she is satisfied with her job." Joshi G. (2001) studied that job satisfaction is not found significantly higher in the private organization as compared to public organization. Govt. teachers were found healthier than private school teachers. Because of fixed working, work and less pressure they can easily keep attention to their families and do not have anxiety of their work in home or school. They easily manage their responsibilities.

They can easily make balance between the personal, professional life, whereas in private schools because of overwork or less salary they are stressed more and are unable to attend their families. There are more holidays in Govt. school so they get the time to rest. Job satisfaction and health are correlated with each other. We find a positive link between job satisfaction and subjective health measures; that is employees with higher or improved job satisfaction levels feel healthier and are more satisfied with their health. (Alfonso Sousa- Poza, Justina A. V. Fisher 2009).

References-

- * www.google.com
- * WHO int. "preamble to the constitution of the world health organization as adopted by the international health conference", New York, 19-22; June 1946; signed on 22 July 1947 by the representative of 61 states (official records of the World health organization, no.2, p.100); and entered into force on 7 April 1948.
- * WHO "Ottawa charter for health promotion" 1986. The harward professional group. Three hallmarks of a career position. http://www.harvardpro.com/careerjobs5a.htm.1998.
- * Justina A.V. Fischer & Alfonso Sousa- Poza, 2009. "does job satisfaction improve the health of workers? New evidence using panel data and objective measures of health," health economics, John Wiley and sons, Itd, vol.18 (1), pages 71-89
- * Rosalie, B. Lopopolo (2002). The relationship of role related variables took satisfaction and commitment to the orgabization in a restructured hospital environment. Physical therapy, 82 (10), 72- 78 Joshi G. (2001) "occupational level and job satisfaction: a comparative study of public and private sector organization"; journal of the Indian academy of applied psychology, 2001 jan-jul; 27 (1-2): 157-61
- * Brief, Arthur P. (1998). Attitudes in and around organizations. Thousands oaks, CA: Sage, p-91 Perry, Mark J, (2010); "flint economist proves growing salary gap between public and private sectors"; Flint journal.Dr. Singh Amar & Dr. Sharma T. R.(1999); manual of job satisfaction scale; national psychological corporation, Agra. Verma ,S.K.; Wig N.N.; Preshad, D.;(1998); manual of P. G. I. H. Q. N-1; national psychological corporation, Agra.

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013



A Correlation Study of Self Concept and **Adjustment of Adolescents**

Dr. A.K. Chaudhary * Deepika Jain**

Abstract - The present investigation was undertaken to study the self-concept & adjustment in adolescent for this purpose a random sample of 30 adolescent. Self-concept scale (SCQ) by R.K. Saraswat and adjustment scale by V.K. Mittal were conducted on sample. Correlation was tasted. Result indicated that correlation between self concept and adjustment is 0.69. It indicates that the strong positive relationship between adjustment and self-concept. Research Scholar Dept. of Psychology, Mewar University, Chittorgarh

Key Words: Correlation, Self Concept, Adjustment, Adolescents, Self-concept scale (SCQ)

Introduction:

Adolescents have been described as phase of life, beginning, in biology and ending in society. Adolescent may be defined as the period within the life span when most of person biological, cognitive psychological and social characteristics are changing from what is typically considered child like to what is considered adult like (learner and span 2000).

For the adolescent, this period is a dramatise challenge, one requiring adjustment to change in the self, in the family and in the peer group. In contemporary society, adolescents and their parents, adolescent is a time of excitement and anxiety, of happiness and trouble of linked with the future.

The self concept is associated with mental health. It is fact that health is an indispensable quality in human being. It is indispensable as soil from which the finest flowers grow. Health indicates psychosomatic well being. The world health organization's chapter defined health as a state of complete physical, mental and social well being not merely the absence of disease (Monopoles, 2007).

Regulation settlement of claims on equitable arrangement of conflicting claims as in set-off contribution, subrogation and marshalling. The apportion of brining all the parts of an adjustment, as a microscope or telescope, into their proper relative position for use; the condition of baling thus adjusting or condition of binge adjusted act, of bringing into proper relations, regulation settlement of claims an equitable arrangement of conflicting claims, as in set-off, contribution exoneration, subrogation, and marshalling the operation of bring all the parts of an adjustment, as a microscope or telescope into their proper relative position for use the condition of being thus adjusted, as to get good adjustment table in or out of adjustment.

Review of Literature:

Gage and Berliner (2006) States that self-concept is the affective or emotional aspect of self and generally refers to how we feel about or how we value ourselves (one's selfworth).

Charles, Descries M. (2004) examined in their study that anti-social behaviour are significant factor in adolescences' self-concept.

According to crow (1967) adjustment is a term much used both by the psychologist and the people. The latter now ever, tend to use the term in properly. They seem to assume that adjustment is desirable term that connotes either good or successful adjustment or poor adjustment.

Gardner, et al. (2004) the self-concept is also implicated in work assessing self-esteem (the evaluative component of self-concept), in relation to adjustment. Performance at a high level is one manner in which they can maintain behaviour that is consistent with their self-concept.

Good fellow and Nowak (2009) in the study on "Social Adjustment, Academic Adjustment and the Ability to Identify Emotion in Facial Expressions of 7 -Year-Old Children".

Marsh (2002) studied the structural equation model and demonstrated that actual effect on self-concept factors were positive and ideal effects were negative thus supporting the discrepancy models' predictions.

Objective:

- To study the self concept of adolescents.
- To study the adjustment of adolescents.
- To study the correlation between self concept and adjustment of adolescents.

Hypothesis:

There is no correlation between self concept and adjustment in adolescents

137

Method:

Sample: The present study was conducted on 30 students (15 were boys and 15 were girls) of Govt. High Secondary School in Udaipur.

Tools: The following tools were used, Self concept questionnaire by Dr. Rajkumar Saraswat and Adjustment Inventory by V.K Mittal were used for data collection.

Procedure: The self concept & adjustment scale was administered individually on 'Subjects' brief instructions. Score given to them the answered questionnaires are collected and scored as per manual. The score are statically analyzed by using correlation analysis.

Results and Discussion:

Results are shown below:

Table: 1 self-concept

Area	Mean score	S.D.	Category
Physical	31.47	2.34	Above average
Social	31.20	2.99	Above average
Temperament	32.00	2.38	Above average
Education	39.97	3.81	High self concept
Moral	35.10	2.09	High self concept
Intellectual	27.23	3.05	Above average

Table: 2 Adjustments

Area	Mean	S.D.	Category
Home	51.03	3.56	Average
Social	49.47	2.83	Average
Health	44.27	7.61	Average
College	50.47	3.22	Average

Table: 3 Correlation = Significance of difference between two groups Self Concept & Adjustment

Correlation between Self	R	Significance
concept and Adjustment	0.69	0.01

Discussion:

The above table shows that the mean score of dimension physical self concept of adolescence was found to be 31.47 with S.D 2.34 of which first that they are having above average of physical dimension of self concept. Social self concept of adolescent was found that to be mean score 31.20 with S.D 2.99 which is in second that they are having above average social dimension of self concept. The mean score found to be 32.00 with S.D of 2.38 above average of temperament dimension of self concept. The mean score 39.97 with S.D of 3.81 which is found that high educational self concept and moral self concept of adolescence was found to be mean score 35.10 with S.D 2.09 high score.

The mean score of home dimension to adjustment of adolescence was found to be 51.03 with S.D of 3.56 which is in first that they are having average adjustment of home dimension. And the social mean score 49.47 with S.D of 2.83 they are having average adjustment and the mean score of health dimension to be 44.27 with S.D of 7.61 they are having average adjustment. And the mean score of college adjustment of adolescence was found to be 50.47 with S.D of 3.22 that they are having average adjustment.

The correlation between self concept & adjustment is 0.69 and it is significant at 0.01 levels. From above results it is found that if self concept is good than adjustment is also good. We can say that self concept is directly proportional to adjustment.

References:

- * Charles, R.E and Deserie, M. (2004): Changing self-concept: Outward Bound school programme impact. Unpublished thesis, Brisbane College of advanced Education, Brisbane.
- * Crow, L.D. (1967): psychology of human adjustment, Alford A. Knof, New York.
- * Gardner, D.G., Dyne, L.V. & Pierce, J.L. (2004): "The effects of pay level on organization based self-esteem and performance: A field study". Journal of Occupational and Organizational Psychology 77: Page 311.
- * Good Fellow, Nowak (2009): Social Adjustment Academic Adjustment and the ability to identify Emotion in Facial Expressions of 7-years old children. Journal of Genetic Psychology, V. 170: N 3, pp. 234-243.
- * Marsh, (2002): Integrating of self-concept theory and research: A lonely cry of protest from the dust bowl of empiricism. Contemporary psychology, 37, 1321-2.
- * **Monopoles (2007):** Adolescents time perspective and mental American journal of psychiatry, 154.



Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013



A Comparative Study Of Depression Among HIV **Negative, Positive And AIDS Cases**

Ravindra Prajapati * Saroj Verma**

Abstract:- The purpose of this paper is investigated a comparative study of depression among HIV negative positive and AIDS cases. The finding of the present study reveals that consistent and systematic difference exists among HIV negative, positive and AIDS cases.

Introduction: Depression is a mood dis-order, characterized by sadness and dejection, decresed motivation and interest in life, negative thoughts physical symptom as sleep disturbances, loss of appetite and fatigue [Atkinsm and Atkinson 1998, Smith, Beon and Hookes, 2000]. Excessions depression contributes to a sense of a negative view of self, a negative view of the world, and a negative view of future. It is observed that the irrational structures of selfblame, self-pity and other pity become major causes of depression. In view of the negative influence of long standing depression, the present study to find an answer regarding to possible differences between the prevalence and impact of depression in HIV negative positive and AIDS cases. It is observed that HIV seropositive persons are more affected by depression than seronegative person. This is so because it is probably one of the factors responsible for the quite progression of their HIV seropositive status to AIDS.

Ramachandran, Sarada and Arunagire have been pointed out that depression is associated with disturbances in family, sex, low social class, windowed state, unemployed condition, low educational level, nuclear family, living alone, and high incidence of physical illness stigma is the most important factor which producing and extending the negative psychosocial impact of HIV and AID. Stigma can be difined as "an act of identifying, labelling or attributing undesirable qualities targreted towards those who are perclined as being shamefully different and deriant from the social ideal" and as an attribute that is significantly discrediting (and is) used to set the affected person or groups apart from the normalized social order (Morgan-2002). Stigma prevents people from taking about and acknowledging HIV as a major cause of illness and death. Stigma prevents HIV-infected people from seeking counselling, obtaining medical and psychosocial care and taking preventive measures to avoid infecting others.

There are several authors Havens 2005, Bing 2001, Brown and Harris (1979) Sethi 2001, and Goldbort 2006, who have been defined the various stages of dipression and their mental health and substance absuse issuses among people with HIV. In the light of above study it is found that a comparative study of Depression and suicidal ideation among HIV negative, positive and AIDS is the topics is highly sensitive one because of its highly personalized and stimatizing nature.

Methodology:-

The present study aimed to explore the psychosocial problems in the HIV/AIDS patients and attempted to see the impact of counselling on these variables. The study was conducted in two phases, in the first phase a multi group design was used to examine/asses, suicidal ideation, depression, family burden, health and quality of life in HIV negative, HIV positive and AIDS cases and their caregivers. There were three groups of HIV/AIDS patients and three groups of their care gives. There were 50 participants in each group. As shown in Table 1

For the second of the study a pre-post design was used in which we examine the impact of counselling on depression, suicidal ideation, family burden and health and quality of life in HIV positive and AIDS cases and their caregivers.

The samples of the study consisted of HIV negative, HIV positive and AIDS cases and their givers. In all a total number of 300 participants were included in the study. There were 50 participants in each group i.e., 50 HIV negative, 50 HIV positive and 50 AIDS cases and their care givers (50 in each groups).

The HIV negative, HIV positive and AIDS cases and their care givers were selected on the basis of non random purposive bases from ICTCs of Delhi, Haryana and (India).

In the first group 50 HIV negative participants were selected and their age range was 24 years to 48 years out of this total number of males were 25 and females were also 25. The second group i.e care givers of HIV negative participants were in the age range of 28 years to 46 years, out of this total number of males were 25 and female were also 25. In the third group there were 50 HIV positive participants (as tested and certified by ICTC Centers) the

nss

age range was 30 years to 48 years. There were equal number of males and females. Majority of cases were laborers/drivers and many? of them were multiple drug users (more than 50%). The fourth group represented care givers of HIV positive participants. Total numbers of care givers were 50. The age range was 28 years to 49 years, with an equal number of males and females. In the fifth group there were 50 AIDS cases in the range of 32-48 years with an equal number of males and females cases. Majority of participants were laborer/drivers and multiple drug users (more than 50%). In the sixth group there were 50 care givers of AIDS cases. There age range was 28 years to 49 years.

Tools Used-

The following tool, were administered uniformly and individually to each subject by investigator himself.

Hamilton Depression Rating Scale (HDI):-

Hamilton developed it. (1967). this scale has 23 questions in MCQ format that clinician may use to rate the severity of a patients depression. The Questionnaire rates the severity of symptoms observed in depression such as low mood, insomnia, anxiety and weight loss. HDI is presently one of the most commonly used scale for rating depression in medical research and is a self report measure of the severity of depressive symptomatology in adults. The MDI may be administered individually or in a group formats it requires approximately 10 minutes to completes. although greater time may he required by elderly persons or persons who are slow readers. There are 3 versions of the paper and pencil form of the HDI, including the full scale HDI which consists of 23 items, the HDI 17 i.e. compressed of the first 17 items of the HDI and is designed to be equivalent in content and scoring to the 17 items, clinicians administered HDRS and HDI-SF, a 9 items short forms of the HDI. The HDI does not include reverse scored items, although it does include several sets of items that are directly opposite in their symptom expression. The response formats for individuals items varies in scoring from 0-2 or 0-4. Internal consistency reliability estimates for the HDI, HDI-17 and HDI-SF based on total HDI development samples. The reliability for the psychiatric sample was high, with a co-efficient alpha reliability of .89 for the HDI with the total psychiatric sample all forms of the HDI demonstrated very high levels of test re- test reliability. The re-test reliability co-efficient for the HDI total was 95 where as it was .93, respectively for HDI-17, HDI-SF and HDI-MEL.

Scoring procedure for the HDI is simple. The form HS answer sheets are located in the inside sheet of the two page carbon less answer sheets. Tear the perforating at the top of the answer sheet and peel away the top page. The

responses to each of the 40 questions transfer through to the bottom page. The number that corresponds to a respondents answer to an individual question is the score for that question. Each individual HDI items measure a circumscribed depressive symptom domain. Some symptom domains are adequately measured by only one question while others required multiple questions for adequate sensitivity of measurement. Therefore, several HDI items comprise only one question. Item 2,3,8,9,12,14,16 and 19 through 23 each comprise a single question. All other items (i.e, 1,4,5,6,7,10,11,13,15,17 and 18) comprise multiple questions and therefore require special weighted scoring procedures. Although based on a single question item 16 also requires special scoring procedures.

The HDI is scored in a pathological direction such that higher item scores indicate higher levels of depressive symtomatology, Scores on items that comprise multiple questions are rounded to one decimal place (i.e. a score of 2.2857 on item 1 is rounded to 2.3). Raw scores for all summary indexes are rounded to the nearest half point (i.e. 5). The possible range of raw scores is 0 to 73 for the HDI, 0 to 52 the HDI 17, and 0-33 for the HDI-SF sometimes, an adult skip or otherwise leave one or more HDI items blank. In case where five or more of the items are left blank, the HDI result should be considered invalid. In order to consider of HDI protocol as valid at least 19 of the items on the 23 items HDI must be completed. An item in considered incomplete if any question that should have been answered was left blank, thereby making the calculation of the item score impossible. The scales items are appended in appendix-A.

Procedure-

Each participant was administered measures of depression, after building rapport Everyone was briefed about the purpose of the study and informed consent was obtained. Those who volunteered for the study were included for the final testing. The testing was done under uniform and standardized conditions and all the measure were administered individually to each participant by the investigator himself. For the second phase of the study before and after design was used to examine the impact of the counselling on psychosocial problems of HIV/AIDS patients and their care givers. The base line scores were taken from the first testing in the first phase and all the subjects in all groups were taken up for the second phase of the study. For this study the counselling module for HIV positive and AIDS cases and for their care givers were taken of as such for the counselling, the counselors training modules develop by National AIDS Control Organization, Department of AIDS



Ministry of health Government of India, New Delhi.

The HIV positive. AIDS cases as well as their care givers were given counselling individually by the investigator every week the three month. Every case were called in ICTC Center once a week and it continued for three months, after the completion of three months, measure of depression, suicidal ideation, family burden health and quality of life were administered again to each subject under standard test condition uniformly by the investigator. The sorted format of standard counselling module for HIV positive. HIV negative. AIDS cases and their cars givers are given in the Appendix -F. Administration And Scoring:

All the participants were interviewed at the intake after developing rapport and building confidence, Informed consent was obtained from the each participant after explaining the purpose of the study and the procedure. It was followed up by standardized AIDS counselling in the groups. The counselling was done by the investigator himself. For the second part of the study a post counselling assessment was done after three months of intake.

Results And Discussion:-

Present study was conducted with the aim of assessing the psychosocial problems of HI V/AIDS patients and their caregivers. It was also intended to examine the effect of counselling on psychosocial problems of HIV/AIDS patients and their caregivers. The study was conducted on 150 cases, out of these, there were 50 HIV negative, 50 HP positive and 50 AIDS cases and 150 caregivers (50 each in HIV negative, HIV positive and AIDS cases group). The data were analyzed by using statistics i.e. mean, SD and test and simple analysis of variance. Duncan's post hoc test was done for checking the statistical significance of the difference between groups. The results are detailed in tables below, and are described and discussed in this paper, keeping the objectives of the study in mind.

Section1: Psychosocial problems Depression and Suicidal Ideation:-

The first objective of the study was to assess and compare HIV negative, HIV positive and AIDS cases on depression and suicidal ideation. The obtained results were analyzed by using analysis of variance, followed by Duncan's test for Post - hoc comparison and the results are given in **Table 2 and 3**

Results (Table 2 and 3) revealed that the HIV negative cases obtained low score on depression scale than both HIV positive and AIDS cases. The mean depression score of HIV negative cases was 2.94 (SD2.07) and the i-IW positive group scored a mean of 29.54 (SD=5.36) where as AIDS group scored mean of 262.10 (SD=4.22). Analysis of variance revealed that all the three groups i.e. HIV negative, HIV positive

and AIDS differed significantly (F=616.90, df = 2, 147, p < .01). Post hoc comparison was done by Duncan's post hoc test and it was found (Table 4.1) that the HIV positive group scored significantly higher than the AIDS and HIV negative group. The mean depression and scores of HIV positive and AIDS cases however did not differ. The AIDS cases had significantly higher level of depression than the HIV negative cases (Table 01).

The second hypothesis was that the caregivers of HIV negative, positive and AIDS cases would differ in terms of depression. The results are given in **Table 4 and 5**

The caregivers of HIV negative cases obtained a mean scores of 3.86 (SD=2.02) and the HIV positive cases obtained mean score of 32.50 (SD=4.02) where as the AIDS cases obtained a mean score of 31.74 (SD=2.99). ANOVA was done and it was found (Table 4.4) that the mean depression scores of three groups differed significantly (F=1365.10. df2, 147) at .01 level of confidence. Duncan's post hoc test revealed that the caregivers of HIV negative cases scored significantly less than both the caregivers of HIV positive as well as AIDS cases. The caregivers of HIV positive and AIDS cases however did not differ (Table 4)

Reference:-

- Atkinson.R.L., Atkinson, R.C.(1998), Smith E.E..Bem, D.T., Hokes, S.N. (2000), Hilgard's introduction to psychology. 13 Ed, Glossary. New York: Wlley.
- Ramchandran, V., Sarada, Mand Arunagiri, S. (1982). Social cultural factorin late onset depression. Indian journal of psychaiatry, 24,268-273.
- Morgan, D., Mahe, c., Mayanja, B., Okonge, J.M., Lubega, R., & Whitworth, and J.A.(2002). "HIV-I infection in rural Africa: Is there a difference in median time to AIDS survival compared with that in industrialized countries"? AIDS 16:597-632.
- Havens JF, Mellins CA, Ryan S. Child Psychiatry: Psychiatry Sequelae of HIV and AIDS. In: sadock B, Sadock V, eds. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005:3434.
- Bing E, Burnham M, Longshoire D, Fleishman JA, Sherbourne CD, Turner LAS, BJ EF, Beckman R, Vitiello B, Morton SC, Orlando M, Bozzette SA, Ortiz-Barron L, Shapiro (2001). Psychiatric disorders and drug use among human immunodeficiency virusinfected adults in the United States. Archaeology General Psychiatry 58:721-728.
- 6. Brown, G.W. Harris. T.O. (1978). Social origins of depression. London. Tavistokk.
- Goldbort, .Joanne (2006) Transcultural analysis of postpartum depression. MCN
- 8. Sethi, (2008). Texbook of psychiatry. Elsevier: New Delhi .



	_	-		-	
Group -1	Group -2	Group -3	Group -4	Group -5	Group -6
HIV	care givers	HIV positive	Care-givers	AIDS	Care givers
negative	of HIV		of HIV	patients	of AIDS
	negative		positive		patients
n=50	n=50	n=50	n=50	n=50	n=50

Table 2 : Means and SD's of HIV negative, HIV positive and AIDS cases on depression and suicidal ideation.

			Categ	gories		
Variables	HIV n	egative	HIV positive		AIDS Cases	
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD
Depression	2.94 ⁿ	2.07	29.54 ^b	5.36	26.10 ^b	4.22

a b c alphabet indicate Duncan's post hoc comparison. Similar/ same alphabet indicate non significant, whereas different alphabet indicate significant difference

Table 3 : Summary of ANOVA of HIV negative, HIV positive and AIDS cases on depression and (df=2,147)

Variables	Sources of Variance	Sum of Squares	Mean Squares	F
Depression	Between Groups	20929.70	10465	616.90**
Depression	Within Groups	2493.474	16.96	010.50

Table 4 : Means and SD's of caregivers of HIV negative, HIV positive and AIDS cases on depression

Variables	Categories							
	HIV negative		HIV positive		AIDS Cases			
	Mean	SD	Mean	SD	Mean	SD		
Depression	3.86 ^a	2.02	32.50 ^b	4.02	31.74 ^b	2.99		

abc alphabet indicate Duncan's post hoc comparison. Similar/same alphabet indicates non-significant, whereas different alphabet indicate significant difference.

Table 5 : Summary of ANOVA for depression and caregivers of HIV negative, HIV positive and AIDS cases (df =2,147)

Variables	Sources of Variance	Sum of Squares	Mean Squares	F	
Depression	Between Groups	26635.36	13318	1365.10**	
	Within Groups	1434.14	9.75	1505110	

^{*=} Significant at 0.05 level

^{**=} Significant at 0.01 level



Awareness Among Adolescent Girls (10-12yrs) Towards Secondary Sexual Changes And Menarche

Yakshita Malhotra * Mrs. Parul Tripathi **

Abstract- The present study aims to know the Awareness among adolescent girls (10-12years) towards secondary sexual changes and menarche. The sample consists of 160 girls in the age group of 10-12 years from both rural as well as semi urban areas of banasthali(Rajasthan). Purposive sampling technique was used to select the sample. The major objectives of the research was to assess the awareness of girls towards secondary sexual changes and menarche, to make comparison of the level of awareness of girls from both the settings rural and semi urban areas towards secondary sexual changes and menarche.

The tool used for the study was a self structured questionnaire and checklist based on Pubertal Development Scale, Tanner Drawings. The data was analyzed on the percentage and chi-square basis. The main findings showed the significant difference in the awareness of rural and semi urban girls towards secondary sexual changes and menarche.

Introduction:

Of all the studied areas of Human Development, the stage of preadolescence has been the most neglected. This age range typically described as 9 to 10 or 10 to 13 is uniquely an awkward range that somehow bridges the gap between childhood and adolescence. It has been expressed as the period of time when the nicest children begin behaving in most awful way. Children of this age are difficult. Their unconventional mannerism and their unpredictable behaviours make them a very difficult group to research. Teachers find them uncooperative and parents find them annoying. In general it is easier to deal with youth that are either younger or older than with the preadolescents. Yet this should not make us fail to recognize the need for more knowledge about children within this age range (Hershel Thornburg, 1990).

Preadolescence is a period of anticipation- a transition period since the pubic changes that begin during these ages and mature later are essential to full adult sexual functioning. Parents as well as the major institutions in society are aware and apprehensive about these changes.

Some aspects of sexual changes appear earlier than others, and some come on at different individuals. The time and rate of development is not the same for boys and girls either. Biological puberty, announced by the menarche in girls and by the capacity for ejaculation in boys and with the development of secondary sex characteristics in both, begins between the ages of eight and fifteen.

During this transitory period, several bodily changes occur in girls. Some of these changes are external such as breasts development, growth of pubic and axillary hair, while the others are internal pertaining to the reproductive process. To really understand what is or is not happening when a young child exhibits signs of puberty, a basic understanding of the physical and hormonal events of puberty is very helpful.

Adolescents confront a number of problems, because of lack of authentic knowledge, attitude and practice regarding their growing up, particularly the issues relating to pubertal health due to lack of proper source of information which leads to inaccurate information with jumbled and often contradictory messages regarding issues related to pubertal changes. Pubertal changes awareness is required for girls (right from the preadolescent age) to provide them positive direction and information which would avoid unnecessary worries and tensions.

Objectives:

- To assess the awareness and practices of girls (10 to 12 year) towards secondary sexual changes and menarche.
- To compare the awareness of girls (10 to 12year) towards secondary sexual changes and menarche from two different settings i.e., one group from semi urban and other from rural setting.
- To find out the sources of information for menarche among the girls from both the settings.

Hyposthesis:

There is no significant difference in the awareness among girls related to secondary sexual changes and menarche in girls from semi urban and rural settings.

Methodology:

The study was conducted among 160 girls of 10, 11 and 12 years from rural and semi urban settings of Banasthali(Rajasthan). The survey method was used for the



data collection through self constructed tool .keeping in mind the purpose of study and objectives the researcher made contacts with the selected samples to get the relevant information.

Analysis:

Percentage Chi square

Scoring:

The checklist contains 32 statement and was 2 point scale in which, option 'yes' carried one mark and option 'no' carried zero marks. And the questionnaire contains 21 open ended questions and was 3 point scale in which 'yes' means that girls have correct information about secondary sexual changes and menarche and was allocated 3 marks, likewise 'can't say' means girls have no information regarding the subject and allocated 2 marks whereas 'no' means they have wrong information and was allocated one marks. (see table 1)

The data in the above table shows that the semi urban girls had comparatively more correct knowledge of the general facts related to secondary sexual changes and menarche than rural girls. Among the 10 year girls from rural area not a single girl had the correct information that pubertal changes occur due to biological causes and starts in girls earlier than boys. They said yes to the questions like menstruation cleans the body of dirty blood, girls become weak during periods. They did not know that heavy exercises are dangerous during periods and showed incorrect information about the complications during puberty. Among the girls of age 11 and 12 year not a single girl gave correct response to the question on whether the girls become weak during periods. From the semi urban girls of all the three age groups, although the percentage of girls responding correctly to all the questions was more than the rural girls but were not satisfactory.

(Distribution of respondents on "sources of information about menarche") (See Table 2)

The data in the above table shows that among the 10 year girls mother and teachers were the highest sources of information for the rural girls whereas maximum of the semi urban girls reported peers (close friends)as their sources of information about menarche. None of the semi urban girl reported warden and teachers as their sources. From the girls of 11 years of age, mother and peers were the highest sources among rural and semi urban settings respectively and no one from the semi urban settings respectively and no one reported books as their source of information about menarche. And among the 12 years of age, mother was the highest source of information for both the rural and semi urban girls. Books, teachers were reported as the sources of

menarcheal information only by the rural girls.

Table 3.

Different settings (Semi Urban and Rural settings) and awareness towards secondary sexual changes and menarche among girls (10-12years

Ho: There is no significant difference in the awareness towards secondary sexual changes and menarche among girls (10-12years) of different settings.

Age(in years)	Calculated value of chi square
10	18.62*
11	22.63*
12	37.85*

(*) Value of chi square at 0.05 level of significance Df =10

Obtained value of chi-square for all the 3 age groups (10, 11 and 12) is greater than the tabulated value (14.1) thus, rejecting the hypothesis. This concludes that there is a significant difference in the attitude towards secondary sexual changes and menarche among girls belonging to semi urban and rural settings.

Discussion

Study emphasizes that there is a significant difference in the source of information about menarche in the rural and semi urban girls. The data reveals that the highest source of menstrual information were peers for the semi urban girls followed by mother, relatives, teachers, wardens, books whereas mothers were the main source of information for rural girls followed by teachers, books, relatives, peer and television, in the decreasing order.

There is a significant difference in the awareness towards secondary sexual changes and menarche in girls (10-12years) from rural and semi urban areas. Semi urban girls were having comparatively more correct knowledge than rural girls.

Conclusion:

The result and study reveals that it is important to educate preadolescents about issues related to menstruation and other pubertal changes, so that they can further safeguard themselves against various infections and diseases. This could further help them to lead a healthy life.

It is evident from the study that none of the respondents possess sufficient and correct knowledge regarding pubertal changes. Only 17.24% girls of semi urban and 38.75% rural girls reported teachers as their source of information and also the schools of both the settings are inadequately equipped to meet the challenge.

So they should be provided with unbiased, unmoralistic information so that they are better informed and adjusted to their changing physical, biological and emotional needs.





Mostly these age group girls are very shy to express their problems in front of others. They themselves think it as a matter to shame if disclosed to anyone. In order to increase the awareness among preadolescent girls regarding their pubertal health, there must be a proper source and channel of knowledge provided to them.

The role of teacher and family members especially mother and wardens must rise up. By getting right knowledge through right channel and of right time will automatically make them confidant and upraise their reproductive health status.

Suggestions:

For parents:

- Parents should preinform their adolescents about pubertal changes.
- Parents must keep positive attitude towards their child's puberty.
- Parents should ensure that everyone goes through puberty, they are not alone.

For teachers:

 Teachers must introduce the adolescents about the pubertal changes under their subjects.

For wardens:

- Wardens must keep friendly attitude towards them.
- Wardens should organize periodical meetings their pubertal changes.

For further study:

- Further research can be worked on other sectors of adolescent girls such as lower socio economic, illiterate and disabled girls.
- The comparison of the awareness about pubertal changes can be done among the boys and girls.
- The same study can be done on girls belonging to different groups on the basis of mother's education and working status, type of family.
- The study can be used for planning programmes, making new policies for improving the level of information of adolescent girls.

References:

- * Adentokunbo, Tayo O.;Oluwarotimi, Akinola, I.;Lukeman;Shittu A.J.and Osinusi,B.O:Appraisal of Menstrual Awareness and pattern among female secondary school students in Logos.journal of Obstetrics and Gynecologny,2009.
- * Bista,M.B.(2004)A review of research literature on girls education in Nepal. For UNESCO Bangkok.
- * Bhatt, Nirojini;Mahajan, Payal and Sondhi, Minal: Awareness regarding sex knowledge among Adolescent Girls. Vikas publishing House, 2004, 6(2):101-103.
- * Brooks-Gunn, J. and Petersen, A.C.:Girls at puberty:

- Biological and psychosocial perspectives, plenum. Press, New York. 1984.
- * Dhingra, Rajni;Kumar ,Anil and Kaur Manreet:Knowledge and Practices related to Menstruation among Triabl(Guijar)Adolescent Girls.EthnoMed,2009,3(1):43-48.
- * Drubashayani Devi,K;Venkata Ramaiah, P:A study on menstrual hygiene among Rural Adolescents Girls.Indian Journal Medical Science, 1994,48:139-143.
- * Grover, V.L.: Final Report on a study of reproductive health awareness and sexual behaviours among adolescents in delhi:Report submitted to ICMR:Delhi,1998.
- * Guha Martin: The Gale Encyclopedia of Children's Health:Infancy through Adolescence,2006,20(4):39-41." Gupta,Sadhna;Sinha,Achala:Awareness about Reproduction and Adolescent Changes among School Girls of Different Socio-economic Status.Journal of Obstetrics and Gynecology,2006,56(4):324-328.
- * Hermansson, Evelyn: Transition to Puberty as Experienced by 12 year old Swedish Nursing, 2008, 24(5):326-334.
- * Jeanne;Brooks-Gunn,J and ruble,D.N: The development of menstrual realted beliefs and behaviours during early adolescence.child development,1982, 53:1567-1577.
- * Kalman, Melnie B:Taking A Different Path: Menstrual Preparation for Adolescent Girls Living Apart From Their Mothers. Health Carefor Women International, 2003,24(10): 868-879.
- * Kanyike,F.,Akankwasa,D. and Karungi, C. (2004). Menstruation as a barrier to gender equality in Uganda.Insights Education.
- * Khanna, Anoop; Goyal, R.S. and Bhawsar, Rahul: Menstrual Practices Reproductive Problems, 2002.
- * Mahajan,P;Sharma,N:Awareness Level of Adolescents Regarding Menarche.Journal of Human Ecology, 2004, 16(3):215-218.
- * Nair,P;Grover, V.L;Khanna, A.T.:Awareness and Practices of Menstruation and Pubertal Changes among Unmarried Female Adolescents in Rural Area of East Delhi.Indian Journal Community Medical Science,2007,32:156-157.
- * Narayana, K.A.:Srnivasa,D.K.;Pelto P.J. and Veeanmaal, S:Puberty, Ritual Reproductive Knowledge and Health of Adolescent school Girls in South India, 2001.
- * Paul,D:A Report on an ICMR Funded Project:Knowledge and Practices of adolescent Girls Regarding Reproductive Health with Special Emphasis on Hygiene During Menstruation New Delhi:National Institute of Public Cooperation and Child Development(NIPCCD),2007.
- * Reddy, P.J. and Reddy, M.V.S.: Reproductive Health: Concerns and Constraints of Adolescents, 2003.
- * Rogal, Alan D; Clark, Pamela A and Roemmich, James



- Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013
- N.Growth and Pubertal Development in Children and Adolescents: Effects of Diet and Physical Activity. American Journal of clinical Nutrition, 2007,72(2):521-528.
- Sharma, Pragya; Malhotra, Chetna; Taneja, D.K. and Saha, Renuka. A study of the types and frequency of problems related to menstruation in girls, department of community medicine,2008,72.
- Shukla, S. and Hora, N. Providing for pre adolescent girls in India Insights, 2004.
- Shukla, S.: Working on Menstruation with girls in Mumbai, India: Vacha Women's Resource Centre. EQUALS, 2005, 15 (5).
- Singh, A.J.: Place of Menstruation in the Reproductive Lives of Women of Rural North India. India Journal of community medicine,2006,31(1):10-14.

- Singh, S.P.; Singh, Maya; Arora, Meenakshi; Sen, P: Knowledge Assessment Rearding Puberty and Menstruation among School Adolescent Girls of District Varanasi, U.P.Indian Journal Prev.Soc.Med,2006,37(1&2).
- Stubbs, Margaret L: Cultural Perception and Practices around Menarche & Adolescent Menstruation in the United States. The Menstrual Cycle and Adolescent Health, 2008, 113(5):58-66.
- Talwar,R.:A study of the Health Profile of Adolescent Girls in an Urban Slum and their Knowledge about Reproductive Health, New Delhi, 1997.155.
- Tiwari, H; Oza, U.N. and Tiwari, R: Knowledge, Attitudes and Beliefs about Menarche of Adolescent Girls in Ananad District, Gujarat, 2006, 12(3&4).

Table 1. (Percentage distribution of respondents on "Awareness towards secondary sexual changes and menarche")

Parameters regarding awareness	Correct response	10years(N=42)		11years(N=58)		12years (N=60)	
		Rural (N=21)	Urban (N=21)	Rural (N=29)	Urban (N=29)	Rural (N=30)	Urban (N=30)
Pubertal change occur due to	Biological causes	0.00%	23.07%	13.79%	55.17%	26.66%	56.66%
Pubertal changes effects mood	Yes	4.76%	3.84%	31.03%	34.48%	63.33%	53.33%
Hormonal changes responsible for puberty	Yes	23.8%	11.53%	37.93%	10.34%	80.00%	30.00%
Preinformation about pubertal changes is essential	Yes	67.00%	31.00%	58.62%	68.96%	70.00%	73.33%
Secondary sexual changes in girls occur before as compared to boys	Yes	0.00%	3.84%	17.24%	13.79%	50.00%	23.33%
Duration of menstrual cycle	28 days	61.9%	11.53%	79.31%	51.72%	63.33%	76.66%
Menstruation cleans the body of dirty blood	No	0.00%	53.84%	3.44%	13.79%	6.66%	10.00%
Due to blood loss during periods girls become weak	No	0.00%	50.00%	0.00%	10.34%	0.00%	16.66%
Heavy exercise is dangerous during periods	Yes	0.00%	28.57%	34.48%	41.73%	60.00%	66.66%
Knowledge of complications during puberty	Yes	0.00%	14.28%	41.37%	51.72%	56.66%	63.33%

Table 2 (Distribution of respondents on "sources of information about menarche")

CATEG ORY	10year(N=	:42)	11year(N=58)		12year(N=60)		Total (N=160)	
	Rural(N =21)	Semi Urban(N	Rural(N =29)	Semi urban(N	Rural(N =30)	Semiur ban	Rural(N =80)	Semi urban(N
		=21)		=29)	· ·	(N=30)		=80)
Mother	14.28%	4.76%	34.48%	44.82%	76.66%	63.33 %	45.00%	41.25%
Peer	4.76%	61.90%	0.00%	48.27%	13.33%	53.33%	6.25%	53.75%
Relative	9.52%	14.28%	3.44%	17.24%	10.00%	6.66%	7.50%	12.50%
Warden	0.00%	0.00%	0.00%	13.80%	0.00%	3.33%	0.00%	6.25%
Televisio	0.00%	3.44%	3.44%	6.89%	6.66%	10.00%	3.75%	8.75%
n								
Books	4.76%	4.76%	10.34%	0.00%	33.33%	0.00%	17.50%	4.76%
Teachers	14.28%	0.00%	37.93%	17.24%	56.66%	0.00%	38.75%	17.24%



प्रथम संस्करण के सम्माननीय सदस्यों की सूची (1 Jan. to 31 Dec. 2013)

(01)	प्रो. डॉ.वी.के. जैन(मार्चा ११) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(02)	प्रो. डॉ.आर.सी. जैन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(03)	प्रो. डॉ.बी.के. दानगढ़ शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(04)	प्रो. डॉ.एल.एन.शर्मा(म.प्र.)
(05)	प्रो. डॉ.एन.के. डबकराशासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(06)	प्रो.डॉ.प्रकाशचंद्र रांकाशासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(07)	प्रो. डॉ.देवीलाल अहीरशासकीय महाविद्यालय, जावद (म.प्र.)
(80)	प्रो. डॉ.जी.के. कुमावत शासकीय महाविद्यालय, मनासा (म.प्र.)
(09)	प्रो. डॉ.अनिल जैन शासकीय महाविद्यालय, मनासा (म.प्र.)
(10)	डॉ.राजेंद्रकुमार पैन्सिया(म.प्र.)
(11)	प्रो. डॉ.डी.एस. फिरोजिया शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुरा (म.प्र.)
(12)	प्रो.डॉ. रवींद्रकुमार सोहोनीशासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(13)	प्रो. डॉ.नरेंद्रकुमार जैन श्री जवाहर लाल नेहरू विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(14)	प्रो.डॉ. पदमसिंह पटेल शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर (म.प्र.)
(15)	श्रीमती समता मेहता (कटारिया)शोधार्थी १११, धानमंडी, रतलाम (म.प्र.)
(16)	प्रो. डॉ.अजय भार्गव शासकीय महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.)
(17)	डॉ.स्मृति अग्रवालशोध सलाहकार, नई दिल्ली

द्वितीय संस्करण के सम्माननीय सदस्यों की सूची (1 Apr. 2013 to 31 March. 2014)

(01)	।) प्राचार्य (पदेन)शासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(02)	२) प्राचार्य (पदेन)शासकीय कन्य	ा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(03)	3) प्रो. डॉ. पूरालाल पाटीदारशासकीय कन्य	ा महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(04)	l) प्रो. शशांक दुबेजैन कला, वापि	गेज्य, विज्ञान महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(05)	5) डॉ. सुनीता बकावले अतिथि विद्वान	, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.)
(06)	S) प्रो. वीणा सिंहशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
(07)	?) प्रो. डॉ. कमल जैनशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(80)	3) प्रो. डॉ. महेश गुप्ताशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(09)	o) प्रो. सुनैना चौहानशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(10))) प्रो. राजेन्द्रसिंग चौहानशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(11)	।) प्रो. डॉ. रवीन्द्र बर्वेशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(12)	२) प्रो. डॉ. मंजीत अरोराशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(13)	3) प्रो. डॉ. पारसमणि गुप्ताशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(14)	l) प्रो. डॉ. वन्दना बर्वेशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(15)	5) प्रो. डॉ. शिंजिनी अवस्थीशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(16)	b) प्रो. डॉ. सेंवती डाबरशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(17)	⁷) प्रो. गायत्री चौहानशासकीय स्नात	कोत्तर महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(18)	B) प्रो. राजकुमार शिन्दे अतिथि विद्वान्	, शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगौन (म.प्र.)
(19)	a) प्रो. श्रीमती विजया वधवाशासकीय कन्य	ा महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(20)	o) प्रो. श्रीमती कमलेश उपाध्यायशासकीय कन्य	ा महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

(21)	प्रो. डॉ. रश्मि हरित (बृजवासी)	शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(22)	प्रो. डॉ.वी.के. ओझा	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(23)	प्रो. डॉ. देवेंद्र सिंह राठौड़	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)
(24)	प्रो. डॉ. प्रदीप शर्मा	शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
(25)	प्रो. डॉ. लता जैन	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(26)	प्रो. डॉ. संजय अग्रवाल	माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(27)	सुश्री यक्षीता मल्हौत्रा	शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
(28)	श्री विजय मावी	शोधार्थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
(29)	प्रो. डॉ. विश्वास शर्मा	SAIM & S इन्दौर (म.प्र.)
(30)	प्रो. डॉ. ऋषि मिश्रा	बी स्कूल, इन्दौर (म.प्र.)
(31)	प्रो. डॉ. हेमंत नामदेव	शासकीय माधव कला–वाणिज्य–विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(32)		शासकीय माधव कला–वाणिज्य–विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(33)	प्रो. डॉ. अरूणा सेठी	शासकीय माधव कला–वाणिज्य–विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(34)	प्रो. डॉ. अल्पना उपाध्याय	शासकीय माधव कला–वाणिज्य–विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(35)	प्रो. डॉ. राजश्री सेठ	शासकीय माधव कला–वाणिज्य–विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(36)	प्रो. डॉ. भीमसेन अखंड	शासकीय माधव कला–वाणिज्य–विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(37)	प्रो. डॉ. प्रकाशकुमार जैन	शासकीय माधव कला–वाणिज्य–विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(38)	प्रो. डॉ. वन्दना जैन	शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(39)	प्रो. डॉ. अरूणा दुबे	शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(40)	प्रो. डॉ. वंदना मालवीया	शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(41)	प्रो. डॉ. कमला चौहान	शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(42)	प्रो. डॉ.आभा दीक्षित	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
(43)	प्रो. डॉ. गणेशप्रसाद दावरे	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(44)	प्रो. डॉ.सुनीलकुमार शर्मा	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(45)	प्रो. डॉ. मंगला ठाकुर	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(46)	प्रो. डॉ. प्रेमलता तिवारी	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(47)	प्रो. डॉ. अरविन्द श्रीवास्तव	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(48)	प्रो. रवीन्द्रकुमार योधा	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(49)	प्रो. डॉ. अभय मूंगी	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(50)	प्रो. सुशीलचन्द्र जायसवाल	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(51)	प्रो. डॉ. मुकुन्दराव महाले	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(52)	प्रो. सबल सिंग रावत	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(53)	प्रो. गोविन्द वास्केल	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(54)	प्रो. जियालाल सोलंकी	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(55)	प्रो. रमेश ओचट	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(56)	प्रो. सारिता टुण्डले	शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह (म.प्र.)
(57)	प्रो. डॉ.जी.सी. मेहता	शासकीय महाविद्यालय, थांदला (म.प्र.)
(58)	प्रो. एस.एस. मुवेल	शासकीय महाविद्यालय, थांदला (म.प्र.)
(59)	प्रो. एम.एल. वास्केल	
(60)	प्रो. पीटर डोडियार	शासकीय महाविद्यालय, थांदला (म.प्र.)

प्रो. सेलिन मावी	. शासकीय महाविद्यालय, थांदला (म.प्र.)
प्रो. मीना मावी	. शासकीय महाविद्यालय, थांदला (म.प्र.)
प्रो. बी.एल. डाबर	. शासकीय महाविद्यालय, थांदला (म.प्र.)
प्रो. हेमता डुडवे	. शासकीय महाविद्यालय, थांदला (म.प्र.)
प्रो. सुनीलकुमार सिकरवार	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.)
प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल	. शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
प्रो. डॉ. विनोदकुमार शर्मा	. शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
प्रो. डॉ. मालसिंह चौहान	. शासकीय महाविद्यालय, सैलाना (म.प्र.)
प्रो. डॉ. दिलीपसिंह मण्डलोई	. शासकीय महाविद्यालय, सैलाना (म.प्र.)
प्रो. श्रीमती आशा जैन	. शासकीय महाविद्यालय, सनावद (म.प्र.)
डॉ.रामेश्वर गुप्ता	. EMRS कुक्षी (म.प्र.)
डॉ. अर्जुन सौलंकी	. अतिथि विद्वान, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
प्रो. डॉ.नटवरलाल गुप्ता	. शासकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता	. शासकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
प्रो. डॉ. सपना सोनी	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
प्रो. डॉ.आर. कान्हेरे	. शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.)
प्रो. डॉ. मंजुला जोशी	. शासकीय महाविद्यालय अंजड़ (म.प्र.)
प्रो. डॉ. पी.पी.पाण्डेय	. संकायाध्यक्ष वाणिज्य (डीन) अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
प्रो. डॉ. प्रभा पाण्डेय	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर, जिला– सतना (म.प्र.)
प्रो. डॉ.रविप्रकाश पाण्डेय	. शारदा महाविद्यालय, सरल नगर, मैहर, जिला– सतना (म.प्र.)
प्रो. बी.एस. सिसोदिया	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
डॉ. हेमसिंह मण्डलोई	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
प्रो. राजेश मईड़ा	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
प्रो. रायकू जमरा	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
प्रो. मीरा जामोद	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
डॉ. उदयसिंह निंगवाल	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
प्रो. आकाश ताहिर	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
प्रो. निर्भयसिंह सौलंकी	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
प्रो. रायसिंह मण्डलोई	. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
प्रो. डॉ. लक्ष्मी बघेल	. शासकीय रनातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.)
	, ,
प्रो. डॉ. ए.के. चौधरी	. राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
सुश्री नम्रता जैन	. शोधार्थी, पेसीफिक विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.)
	. अतिथि विद्वान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.)
सुश्री दीपिका जैन	. शोधार्थी, मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)
	. शोधार्थी, मेवाड़ विश्वविद्यालय, गंगरार, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)
डॉ. सुश्री कृष्णा पैन्सिया	. हरिश आंजना महाविद्यालय, छोटीसादड़ी (राज.)
डॉ. सरोज वर्मा	. आई.सी.पी.एस., जिन्द (हरियाणा)
प्रो. प्रदीपसिंग	. केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़
्डॉ. रवीन्द्र प्रजापति	. एन.ए.सी.ओ. न्यू दिल्ली
	प्रो. बी.एल. डाबर प्रो. हेमता डुडवे प्रो. सुनीलकुमार सिकरवार प्रो. डॉ. लक्ष्मण परवाल प्रो. डॉ. तक्ष्मण परवाल प्रो. डॉ. विनोवकुमार शर्मा प्रो. डॉ. विलोपिंह चौहान प्रो. डॉ. दिलीपिंह चौहान प्रो. डॉ. दिलीपिंह चौहान प्रो. डॉ. विलोपिंह मण्डलोई प्रो. श्रीमती आशा जैन डॉ. रामेश्वर गुप्ता डॉ. अर्जुन सौलंकी प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता प्रो. डॉ. आशा साखी गुप्ता प्रो. डॉ. सपना सोनी प्रो. डॉ. पी.पी.पाण्डेय प्रो. डॉ. पी.पी.पाण्डेय प्रो. डॉ. र्मिसहिया डॉ. हेमिंसह मण्डलोई प्रो. राजेश मईडा प्रो. राजेश मईडा प्रो. रायकू जमरा प्रो. औत्मार्थ तिर्मे हेमिंसह मण्डलोई प्रो. उदयसिंह निंगवाल प्रो. आकाश ताहिर प्रो. तिर्भयसिंह सौलंकी प्रो. रायसिंह मण्डलोई प्रो. रायसिंह मण्डलोई प्रो. रायसिंह मण्डलोई प्रो. रायसिंह मण्डलोई प्रो. उदयसिंह निंगवाल प्रो. आकाश ताहिर प्रो. हॉ. ए.के. चौधरी सुशी नम्रता जैन डॉ. प्रभाकर मिश्र प्री. डॉ. ए.के. चौधरी सुशी नम्रता जैन सुशी निशा मोड़ डॉ. सुशी कृष्णा पैन्सिया डॉ. सुशी कृष्णा पैन्सिया डॉ. सरोज वर्मा प्रो. प्रदीपरिंग



Naveen Shodh Sansar

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

RNI No.-MPHIN28519/12/1/2012-TC ISSN 2320 - 8767

MEMBERSHIP CUM AUTHOR'S BIO-DATA FORM

(Photocopy of this form may be used) (1 July 2013 - 30 June 2014)

NA	ME (Author / Member) : Mr/Mrs/Ms/Prof/Dr :
NA	ME of of Co-Author(s):
DE	SIGNATION:SUBJECT:
NA	ME OF College/University/Institution:
НС	DME / Official Address :
ST	ATE : COUNTRY :
Tel	. No. (Res. /Office) :
	mail Address :
	Sign
1.	MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION
1.	MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper.
1.	MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper.
1.	MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper. * Institutions Rs. 1,000/- per annum (without publication of paper)
1.	MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper. * Institutions Rs. 1,000/- per annum (without publication of paper) * Membership for Author Rs. 600/- for 1 Year.
1.	MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper. * Institutions Rs. 1,000/- per annum (without publication of paper) * Membership for Author Rs. 600/- for 1 Year. * Membership for Co-Author Rs. 600/- for 1 Year.
	MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper. * Institutions Rs. 1,000/- per annum (without publication of paper) * Membership for Author Rs. 600/- for 1 Year. * Membership for Co-Author Rs. 600/- for 1 Year. * Publication of paper each after membership Rs. 600/- (2000 Words / 4 Page) For Remittances can pay printing amount through DD/Cheque in favor of 'NAVEEN SHODH SANSAR'
	MEMBERSHIP will be valid for individual, University/College Institute Library-One Year SUBSCRIPTION RATES For printing/publication of one research paper. * Institutions Rs. 1,000/- per annum (without publication of paper) * Membership for Author Rs. 600/- for 1 Year. * Membership for Co-Author Rs. 600/- for 1 Year. * Publication of paper each after membership Rs. 600/- (2000 Words / 4 Page) For Remittances can pay printing amount through DD/Cheque in favor of 'NAVEEN SHODH SANSAR' payable at Neemuch (M.P) and send it by Registered Post. Fill information regarding Demand Draft.

Editor - Ashish Sharma

NAVEEN SHODH SANSAR

Bank Detail:-

Current A/c. no.:- 32768184328 Bank Name :- State Bank Of India

Branch:- Neemuch (M.P) IFSC code:- SBIN003005

Add:- "Shri Shyam Bhawan" 795, Vikas Nagar Extension 14/2, Neemuch (M.P) - 458441 Mob:- 09617239102

Email ID: nssresearchjournal@gmail.com

Website :- www.nssresearchjournal.com

(All disputes are subject to exclusive jurisdiction of NEEMUCH Court Only (M.P.))

Signature:----

150

Naveen Shodh Sansar

RNI No. - MPHIN28519/12/1/2012-TC ISSN 2320 - 8767

(An International Multidisciplinary Refereed Journal)

COPYRIGHT AGREEMENT FORM:

(Photocopy of this form may be used)

	the submission of an research paper. ention Title of Manuscript):		
Name	 me of Author :		
	me of Co-Author		
	reby declare, on behalf of myself and my co-a		
[1] [2]	conform to true facts and authentic formula No responsibility is assumed by NAVEEN S , its staff or members or the editorial board	ne and will not, if SHODH SANSAF I for any injury ar	all other statements contained in the research paper followed precisely, be detrimental to the user. R and the Publisher of NAVEEN SHODH SANSAR and/or damage to persons or property as a matter of
	advertisements or ideas contained in a pu NAVEEN SHODH SANSAR.	ublication by NA	or operation of any methods, products instruction, VEEN SHODH SANSAR and by the Publisher of
[3]	I/we permit the adaptation, preparation of commercial application of the work.	derivative work	s, oral presentation or distribution, along with the
[4]	The research paper contains no such mater		inlawful, defamatory, or which would, if published, in
[5] [6]	reviewed journal/ news paper/magazine/pethem. Also, the research paper does not contain	work of mine/our eriodical/book no ontravene any ex	rs and has neither been published in any other peer- or is under consideration for publication by any of kisting copyright or any other third party rights.
[~]			SANSAR ,Neemuch India and this does not infringe
COF	PYRIGHT TRANSFER		
forms SANS Publis	ns) is here by transferred to NAVEEN SHOD NSAR, Neemuch proprietary right other than blisher of NAVEEN SHODH SANSAR.	H SANSAR, Nen n copyright is pr	o publish the work in whole, or in part, in any and all emuch and to the Publisher of NAVEEN SHODH oclaimed by NAVEEN SHODH SANSAR and the original author must be acknowledged; (ii). In case of
	se or distribution, the agreement conditions make ignored on the consent of the author.	ust be clarified to	the user of this work; (iii) Any of these conditions
SIG	GN HERE FOR COPYRIGHT AGRE	EMENT & CC	PY RIGHT TRANSFER AGREEMENT :
have			n my own right or as an agent of my employer, and NAVEEN SHODH SANSAR and the Publisher of
Write	te Authors Name and Designation :		
•			Place:
Signa	nature:	Date:	Place:
-	Our above name research paper is originally w this research paper.	ritten by me/us a	and all information are true. I/we will fully responsible
Name	ne:		
Colle	lege/ University :		Subject:

-----Date:----

--Place:---



Guideline for Authors/Research Scholars

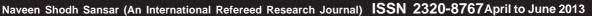
- * This is a national/international refereed NAVEEN SHODH SANSAR Research Journal for all subjects.
- * The selection and publication of research paper are done after recommendation of referees and subject experts.
- * Your research papers should be original and unpublished.
- * The research papers should be written according to **RESEARCH METHODOLOGY**. Although this is a national/international registered research journal but in any case or circumstances if any university/college/institute/society denies to accept or recognize author's/research scholar's published research papers in the journal, then it will not be the responsibility of editor, publisher, management, editorial board, referee or subject experts.
- * The research papers should have bibliography, footnotes, references, suggestions and findings.
- * Only one printed copy of research journal will be sent to the author. No extra or second copy for co-author will be sent but if anybody requires extra copy of issue then in that case individual has to give an amount of Rs. 400/- for each single issue.
- * The titles of your research papers should be appropriate.
- * If your research paper is not accepted in that case **NAVEEN SHODH SANSAR** will refund your amount without any interest rate within 90 days after rejection of paper.
- * You can also send your Research Papers by Website & Email id.
- * Authors/Researchers should sent hardcopy of research paper with copyright form at **NAVEEN SHODH SANSAR** official Address.

Double Blind Peer Review Policy

Review System: Every article is processed by a masked peer review of double blind or by three referees and edited accordingly before publication. The criteria used for the acceptance of article are: contemporary relevance, updated literature, logical analysis, relevance to the global problem, sound methodology, contribution to knowledge and fairly good command on language. Selection of articles will be purely based on the experts' views and opinion. Authors will be communicated within Two months from the date of receipt of the manuscript. The editorial office will endeavor to assist where necessary with English/Hindi language editing but authors are hereby requested to seek local editing assistance as far as possible before submission. Papers with immediate relevance would be considered for early publication. The possible expectations will be in the case of occasional invited papers and editorials, or where a partial or entire issue is devoted to a special theme under the guidance of a Guest /Advisor Editor.

Compulsory Guidelines for Research Scholar Lecturers and Professors

- * Research paper should be typed in MS Word 2007.
- * Paper should be typed in A4 Size paper with standard margins of (2 cm/0.787 inches in all four sides)
- * Title of Research Paper should be typed in 14 Size font and Bold with Underline.
- * Authors / Research Scholar Names with College Address should be typed in 12 Size Font and Bold.
- * Line Space Between should be 1.0 line spaces.
- * Reference should be in Vancouver style at End of the paper (Endnote).
- * For HINDI and SANSKRIT papers, use only these fonts: Kruti Dev-11 (Font size: 12)
- * For ENGLISH papers, use only these fonts: Times New Roman (Font size: 10).





डॉ. राधाकृष्णन् व

88, शिक्षक कॉलोनी, नीमच (म.प्र.) फोन: 07423-222353

मो. 9827325092 फैक्स: 07423-403711

FAX: 222353 E-MAIL: RKCNMH@YAHOO.COM

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन





ADMISSION OPEN

म.प्र. शासन द्वारा SC/ST/OBC/GEN. एवं अल्पसंख्यक, विकलांग, श्रमिक, आदि को छात्रवृत्ति का लाभ

LCD प्रोजेक्टर युक्त HI-TECH क्लास रूम

नि:शुल्क प्रशिक्षण कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं भैनेजमेन्ट

भारत सरकार नई दिल्ली SIDS (MES) द्वारा

GRADUCATION	12TH	10TH
OFFICE CO-ORDINATOR	TALLY	FUNDAMETALS, MS-OFFICE
MARKETING ASSOCIATE	BANKING &	INTERNET & SOFT SKILL
HUMAN RESOUCE ASSOCIATE	ACCOUNTING,	COMPUTER HARDWARE
FINANCE ASSOCIATE	WEB DESIGNING	COMPUTER NETWORIKNG

माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल

MSC (CS) MSC(CS)LE **DCA** BSC(IT) MSC(IT) **PGDCA BCA**

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, डिस्टेंस एज्यूकेशन (जबलपुर)

MBA BPP MA (EDU.H/E/S/D/Y/M/EG.) **B.LIB** BSC (CS) MSC (MATHS) M.COM M.S.W. **PGDCA DIPLOMA IN H & N** B.S.W. B.COM (CA) **ADCA MODERN OFF.MANAGEMENT** M.LIB **DCA** BA

नोट- डिग्री लेने हेतु कॉलेज में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं। नौकरी पढ़ाई साथ साथ अपने बजट में पढ़ाई। आयु का बंधन नहीं। परीक्षा केन्द्र नीमच। ओएमआर शीट पर परीक्षा



The Place of All Computers Laptops & Accoseries (Old & New)



Sales + Service + Spares

Computer Planet

(A Multibrand Computer & Laptop Showroom)

Hemu Kalani Chouraha, Sindhi Colony, Neemuch (M.P.) Cell - 9406640647, 9406640637 Tel.- 07423-403346

Email - computerplanet786@gmail.com



Naveen Shodh Sansar (An International Refereed Research Journal) ISSN 2320-8767April to June 2013 154



INDIA KA FAVOURITE PLAY SCHOOL



ISO 9001:2008 CERTIFIED • 800+ SCHOOLS NATIONWIDE



PLAY GROUP ● NURSERY ● K.G. ● ACTIVITY CEN

Facilities -

- * Good Teacher Student Ratio
- * Ball Room
- * Audio Visual Room
- * Doll Room
- * Modern Teaching Aids
- * Splash Pool
- * Gym
- * Affordable fee structure

Admissions Open

Office- 43, Hudco Colony, Near LIC Office, Neemuch (M.P.) 458 441 Mob.- 9993165001, 9977003404



Dynamic Personality Dr. Gyanchand Khimesara

"Principal- Govt. P.G. College, Mandsaur"

Noted academician Dr. Gyanchand Khimesara's personality is borne out of his experiences, incidents and events that helped him appreciate and depreciate the essence of life. Born on 3" April 1951, his journey of life has passed through many destinations. He currently serves as the Principal of Govt. P. G. College Mandsaur (M.P.). He started his long career studying economics and earned MA, Ph.D., and D.Litt. degrees with economics as subject. During his long 40-year professional career, he has played the role of a mile stone for many institutions. He has devoted himself to the mission of leading the youth towards a positive and glorious future.

Dr. Khimesara is the author of several books including Macro Economics, Money, Banking and Foreign Trade, Banking Law and Practice, Mandsaur Yeh Ek Varsh, Economic Thoughts of Ambedkar and Many others showing his astute insight in his subject. He has to his credit many research papers and articles published in renowned national and international journals. He has delivered key note addresses in many national and international seminars. Dr. Khimesara is a powerful signature in his field. Be it teaching, implementing academic policies or his supervising and management skills, he has always tried to enrich the society and his institutions by his humble efforts. As a multitasking personality, he plays the role of a counsellor, core faculty, course co-ordinator, subject expert, member of Staff Selection Committee, member of UGC XI plan, and member of NAAC. He is the member of many academic bodies. He has guided more than 30 Ph.D. scholars and evaluated Ph.D. thesis of economics in different universities. He has completed many UGC approved minor and major research projects.

But he has never denied being a part of a developing society. Apart from his duties as an academician, he has been the member of many social bodies and has been involved in active social service with Red Cross and many Literacy Programmes. He has got honour and appreciation by All India Jain Shwetamber Khartargach Sangh for the services to the society and nation on 30° Jan 2007. He proves the thought in line below---

"The praise that comes from love does not make us vain, but more humble."





COMPUTER EDUCATION CENTER



DISTANCE EDUCATION CENTER



(Run by : Maati Institute of Social Research & Development)



VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE



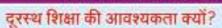
NGO SUPPORT CENTER



74, Jawahar Nagar, Behind Jangid Bhraman Dharamshala, NEEMUCH Ph. 07423-222110, 404849

Website: www.in misrad.org, Email: helpline@inmisrad.org
Distance Education Center Helpline - 9406684248





- " डिग्री लेने हेत् कॉलेज में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं ।
- * कॉलेज की पारंपरिक आयु का बंधन नहीं।
- ^{*} नौकरी, परिवार व पढाई साथ-साथ ।
- * सभी परीक्षा में 100% परिणाम ।
- ^क फोन पर ही विद्यार्थियों को सहयोग ।
- ^{कं} प्रोफेशनल, व्यावसायिक, जागरुकता, सृजन और कोशल केन्द्रित पाठयकम ।
- 🌣 अपने बजट में पढाई।
- ें डिग्री एवं डिप्लोमा राज्य व केन्द्र प्रशासन की नौकरियों में पूर्णत: मान्य ।
- े परीक्षा केन्द्र, नीमच ।

स्पेशल फीचर्स

- # न्यूनतम फीस
- लाईबेरी सुविधा उपलब्ध
- अन्य युनिवर्सिटी से उत्तीर्ण B.A.,

B.Com, BCA प्रथम वर्ष से उत्तीर्ण,

दितीय वर्ष में प्रवेश ले

O.M.R. Sheet परीक्षा प्रणाली

निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश (दूरस्थ शिक्षा विभाग) DEC द्वारा

Master Degree Courses

MBA, MSW, M.Com. M.Sc. (Maths), M.Sc. (Cs), MLis, M.A. (Hindi, English, Sanskrit, Yog, Darshan, Education, Maths) स्थापत्य येद आचार्य, ज्योतिष आचार्य, योग आचार्य

Bachelor Degree Courses

BBA, BSW, B.Com. B.Com (CA), B.Sc. (Cs), BLis, BCA, BA स्थापत्य वेद शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री, योग शास्त्री

Diploma Courses

Hardware & Networking, Multimedia & Animation, MOM, PGDCA, DCA, ADCA, स्थापत्य वेद, ज्योतिष , योग प्रमाण पत्र

Special Courses

PGDCA to M.Sc. (CS) III Sem, DCA to BCA III Sem, BPP